भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

नवंबर 2024

खंड 80 अंक 11

अध्यक्ष
माइकल देवब्रत पात्र

संपादक समिति
मनीष कपूर
अजीत आर जोशी
रेखा मिश्र
प्रज्ञा दास
सुनिल कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

सुदृढ़ निदेशक मंडलों के माध्यम से परिवर्तनकारी अभिशासन
श्री शक्तिकान्त दास 01

चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत
श्री शक्तिकान्त दास 05

मैक्रो वीक 2024 में वक्तव्य
श्री शक्तिकान्त दास 11

विचलन से अभिसरण की ओर पुनर्संतुलन: भारतीय अनुभव
माइकल देवब्रत पात्र 17

डिजिटल युग में विकास की नई सीमाओं को छूना
माइकल देवब्रत पात्र 23

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 29

भारत के लिए संतुलन विनिमय दरों के अनुमान हेतु एक उपागम समूह 81

भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार के बदलते परिदृश्य 93

भारतीय कृषि में कृषि-तकनीक स्टार्टअप और नवोन्मेष 105

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीता 121

वर्तमान सांख्यिकी **147**

हाल के प्रकाशन **201**

भाषण

सुदृढ़ निदेशक मंडलों के माध्यम से परिवर्तनकारी अभिशासन
श्री शक्तिकान्त दास

चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत
श्री शक्तिकान्त दास

मैक्रो वीक 2024 में वक्तव्य
श्री शक्तिकान्त दास

विचलन से अभिसरण की ओर पुनर्संतुलन: भारतीय अनुभव
माइकल देवब्रत पात्र

डिजिटल युग में विकास की नई सीमाओं को छूना
माइकल देवब्रत पात्र

सुदृढ़ निदेशक मंडलों के माध्यम से परिवर्तनकारी अभिशासन*

श्री शक्तिकान्त दास

आज निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के इस द्वितीय सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं प्रसन्न हूं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, हमने पिछले साल मई महीने में "बैंकों में अभिशासन: स्थाई विकास और स्थिरता को बढ़ावा" विषय पर पहला ऐसा सम्मेलन आयोजित किया था। निदेशक मंडलों के साथ रिज़र्व बैंक की उस बातचीत को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और आग्रह हुआ था कि इस तरह के सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

आज के सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए मैं बैंक बोर्डों से उन अपेक्षाओं को दोहराना चाहता हूं जिन्हें मैंने पिछले साल के सम्मेलन में 10-सूत्रीय चार्टर के रूप में साझा किया था। चार्टर में प्राथमिकता से एक मजबूत अभिशासन ढांचे के सिद्धांतों को शामिल किया गया था। आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वह प्राथमिक रूप से उसी नींव पर बना है। पिछले वर्ष मैंने जो अपेक्षाएँ साझा की थीं, वे इस संदर्भ में थीं: (i) अभिशासन और स्थिरता; (ii) बोर्ड में अपेक्षित योग्यता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करना; (iii) वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र बोर्ड; (iv) अध्यक्ष, बोर्ड समितियों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका; (v) कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य प्रणाली; (vi) सूचना की गुणवत्ता; (vii) वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रभावी निगरानी; (viii) व्यवसाय मॉडल और संचालन; (ix) वित्तीय विवरणों की सत्यता और पारदर्शिता; और (x) आश्वासन कार्यों की स्वतंत्रता। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे पिछले वर्ष के संबोधन को पढ़ें जो कि रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आज के सम्मेलन की बात करें तो आज का विषय परिवर्तनकारी अभिशासन पर केंद्रित है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? इस शब्द की कई व्याख्याएँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ एक ऐसा अभिशासन ढाँचा बनाना है जो न केवल वर्तमान विनियामक मानकों को पूरा करता हो बल्कि वित्तीय परिदृश्य में उभरते जोखिमों, अवसरों और परिवर्तनों को भी सक्रिय रूप से विचार में लेता हो। बोर्डों को पारंपरिक निगरानी भूमिकाओं से आगे बढ़ना चाहिए और सक्रियता को अपनाना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए और आज के गतिशील वातावरण के लिए स्थिरता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं आज आपके साथ इन पहलुओं पर कुछ विचार साझा करना चाहूँगा।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ऐसे दौर से गुज़र रहा है जो अवसरों के साथ-साथ जोखिमों और चुनौतियों से भरा हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र मज़बूत और स्थिर बना हुआ है[1]। पिछले साल मई में हुई हमारी बैठक के बाद से सभी वित्तीय संकेतकों में सुधार हुआ है, जो बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभागियों, जिसमें उनके प्रबंधन और बोर्ड शामिल हैं, के प्रयासों को दर्शाता है। मैं इस अवसर पर बैंकों के प्रबंधन और बोर्ड को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बरकरार रखने के लिए आज हमारे पास जो मज़बूत बुनियादी ढाँचे हैं उनका इस्तेमाल करके सुरक्षा को बेहतर और मजबूत किया जाना चाहिए। आखिरकार, अच्छा समय ही लचीलेपन को बेहतर बनाने और स्थिर तरीके से बढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है।

सुअभिशासन का मुख्य सिद्धांत स्थिरता के साथ विकास; स्थिरता के साथ लाभप्रदता है।

मजबूत अभिशासन के लिए परिस्थितिनुसार जागरूकता का महत्व

हमारे तेजी से बदलते और प्रौद्योगिकी-संचालित वातावरण में संगठनों को महत्वपूर्ण चुनौतियों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकीय प्रगति, नए जमाने की फिनटेक संस्थाओं का उदय, तीसरे पक्ष पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक आर्थिक परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। इन बदलती परिस्थितियों के बीच बोर्डों को बैंकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा 18 नवंबर 2024 को मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण।

[1] सितंबर 2024 के अंत तक सीआरएआर 16.7 प्रतिशत, सकल एनपीए 2.5 प्रतिशत, निवल एनपीए 0.6 प्रतिशत और प्रावधान कवरेज अनुपात 76.4 प्रतिशत (अनंतिम)।

रूप में काम करना चाहिए और इन चुनौतियों को पार करने और सुरक्षित तथा समृद्ध स्थिति की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए सतत मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

सबसे पहले बोर्डों को चाहिए कि वे संभावित चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। इसके लिए बाहरी परिस्थितियों के साथ-साथ संगठन के भीतर की आंतरिक परिस्थितियों की स्पष्ट समझ होना आवश्यकता है। बोर्ड को विनियामक परिवर्तनों, बाजार के बदलते रुख, समग्र व्यापक आर्थिक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों जैसे बाहरी कारकों का लगातार आकलन करने की आवश्यकता है। बोर्डों को संगठन की आंतरिक शक्तियों, कमजोरियों और परिचालन स्थितियों के बारे में भी पूरी तरह से अवगत होना चाहिए, ताकि वे परिस्थिति से पूरी तरह अवगत रहें। इस तरह के दृष्टिकोण से निदेशक मंडल को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रबंधन को उचित रूप से मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

दूसरा, बोर्ड को अपने व्यवसाय मॉडल में सांद्रता (कॉन्सनट्रेशन) निर्माण के बारे में पता होना चाहिए। विशिष्ट क्षेत्रों, बाजारों या ग्राहक वर्ग पर अत्यधिक निर्भरता बैंक के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकते हैं, खासकर आर्थिक दबाव या उद्योग में बदलाव के समय। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे कुछ ऋण खंडों में सांद्रता के निर्माण को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने पिछले साल कुछ प्रति-चक्रीय उपाय किए थे। इसी तरह, बोर्ड नियमित रूप से बैंक के पोर्टफोलियो की निगरानी करके, अधिक सांद्रता के संभावित क्षेत्रों की पहचान करके और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए पूर्व-निवारक कदम उठा कर एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

तीसरा, बोर्ड को परिचालन जोखिमों, विशेष रूप से आईटी आउटसोर्सिंग और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। जैसे-जैसे बैंक प्रमुख परिचालनों के लिए बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, व्यवधान की संभावना बढ़ती जा रही है, खासकर तब जब साइबर सुरक्षा में कमजोरियां उसके साथ जुड़ी हों। इस साल की शुरुआत में हुई क्राउडस्ट्राइक की घटना ने दिखाया कि कैसे एक दोषपूर्ण पैच अपडेट के कारण कई देशों में लाखों कंप्यूटर बाधित हो सकते हैं जिससे कई उद्योगों में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सुरक्षा और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीसरे पक्ष के संबंधों का गहन मूल्यांकन, निगरानी और संचालन किया जाए। इसमें मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना, नियमित रूप से जोखिम आकलन करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि तीसरे पक्ष संगठन के भीतर अपेक्षित सुरक्षा के समान ही उच्च मानकों का पालन करें।

चौथा, प्रौद्योगिकी ने अब प्रतिस्पर्धा के रूप में या फिनटेक के साथ सहयोग के रूप में बैंकों में नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल की सुविधा प्रदान की है। जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं, बैंक सेवाएँ देने, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के नए तरीके स्वयं तलाश रहे हैं। तथापि, सुरक्षा और स्थिरता के साथ नवाचार को संतुलित करने की आवश्यकता है। बोर्ड को प्रबंधन से जो मुख्य प्रश्न पूछने चाहिए, उनमें शामिल हैं: (i) प्रौद्योगिकीय समाधानों के संभावित नकारात्मक बाहरी प्रभावों (जैसे, एआई मॉडल में पूर्वाग्रह) को क्या बैंक समझता है, और क्या पर्याप्त शमन उपाय मौजूद हैं? (ii) क्या मौजूदा अभिशासन संरचनाएं, नीतियां और प्रक्रियाएं तीसरे पक्ष पर निर्भरता, उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त हैं? (iii) क्या ये नवाचार नियमों के अक्षरशः और भावना के अनुरूप हैं? (iv) क्या बैंक डाउनटाइम को न्यूनतम करने के लिए स्केलेबल समाधानों में पर्याप्त निवेश कर रहा है?

मजबूत अभिशासन के लिए आश्वासन कार्यों को सशक्त बनाना

आश्वासन कार्य - अर्थात जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन - बोर्ड निदेशकों के लिए अमूल्य संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं। वे संगठन के आंतरिक स्वास्थ्य और बाहरी जोखिमों के प्रति इसके जोखिम, दोनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन कार्यों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए, बोर्डों को इन कार्यों की स्वतंत्रता को सक्रिय रूप से

सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जुड़ी हुई टीमों को कुशल कर्मचारियों के साथ पर्याप्त संसाधन मिले और संगठन के भीतर उन्हें उचित महत्व दिया जाए। इन कार्यों के महत्व को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के सम्मेलन आयोजित कर रहा है और बैंकों के साथ पर्यवेक्षी बैठकों में उनकी उपस्थिति के लिए भी कह रहा है। इसलिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि बोर्ड इन पहलों पर और अधिक ध्यान दें।

भिन्न विचारों को प्रोत्साहन

किसी मुद्दे के संबंध में अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड के पास एक और तरीका है - किसी समूह-विचार से होने वाले नुकसान से बचना और एक ऐसा माहौल बनाना जो विचारों की विविधता को प्रोत्साहित और स्वागत करता हो। जब बोर्ड विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए अनुमति देते हैं, तो उन्हें संभावित चुनौतियों और अवसरों के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसके अलावा, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपरीत विचारों की जांच की जाए और उन पर निर्णय दर्ज किए जाएं। यदि बोर्ड समीक्षा या विचारों की विविधता के लिए खुला नहीं है तो वह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से चूकने का जोखिम उठाता है।

बोर्ड को चाहिए कि वह वरिष्ठ प्रबंधन, कर्मचारियों, व्हिसल-ब्लोअर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ग्राहकों के आलोचनात्मक विचारों पर उचित विचार करे। अक्सर, इन दृष्टिकोणों में संभावित मुद्दों के शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं जो अन्यथा किसी के ध्यान में नहीं आते। प्रबंधन और बोर्ड के बीच स्वस्थ संबंध और आपसी सम्मान होना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र के गतिशील और विकसित परिदृश्य को देखते हुए निदेशकों को चाहिए कि वे पूरी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करते रहें। जैसा कि पिछले साल मेरे भाषण में उल्लेख किया गया था नियमित रूप से चलाए जा रहे परिचयात्मक कार्यक्रम इसे सुविधाजनक बनाने में सहायक हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों को न केवल नवीनतम व्यवसायिक और विनियामक जानकारी तक सीमित रखना चाहिए पर बल्कि जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और अभिशासन प्रथाओं में विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मैं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड को समय पर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए, और बैठक की कार्यसूची को पर्याप्त पृष्ठभूमि के साथ पहले से ही प्रसारित किया जाए।

ग्राहक केन्द्रितता

सक्रिय अभिशासन के बारे में बात करने के बाद मैं अब एक अन्य पहलू पर बात करना चाहूँगा जो सु-अभिशासन के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है ग्राहक केन्द्रितता। बैंकिंग का आधार है - विश्वास, और बैंकिंग उद्योग मूल रूप से अपनी स्थिरता और विकास के लिए जमाकर्ताओं और निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करता है। इस विश्वास को बनाने और बनाए रखने के लिए बैंकों को अपने संचालन के केंद्र में ग्राहकों को रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पाद, सेवाएँ और नीतियाँ वास्तव में ग्राहकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करती हों।

इस संदर्भ में देखें तो हमारी निरीक्षण रिपोर्टों में कुछ ऐसी शिकायतें और टिप्पणियां है जिनका स्वरूप निराशाजनक है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ शिकायतों को ग्राहक प्रश्नों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हमें ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जहाँ अस्वीकृत शिकायतों को बैंकों के आंतरिक ओंबड्समैन तक नहीं पहुँचाया गया। मैं बोर्ड और उनकी ग्राहक सेवा समितियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे इन पहलुओं पर बारीकी से विचार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंकों में ग्राहक केन्द्रितता के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता है।

बैंकों को विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को तैयार करने के लिए उपलब्ध छूट और अधिकार का अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, खासकर जब इसका असर ग्राहकों पर पड़ता हो। बोर्ड को सेवा शुल्क और दंड राशि पर उस स्थिति में बारीकी से नज़र रखनी चाहिए, जब उसे लाभ के स्रोत के रूप में माना जाता हो या जब उत्पादों को जबरन जोड़कर दिया जाता हो, या जब ग्राहकों के लिए खुलासे गैर-पारदर्शी या चयनात्मक होते हैं। निष्पक्ष ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करना और मजबूत शिकायत निवारण प्रणालियों को लागू करना ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि ग्राहक जागरूकता प्रसार में प्रगति हुई है फिर भी विशेष रूप से हाशिए पर स्थित, बैंकिंग प्रक्रिया को कम समझनेवाले और ग्रामीण आबादी के संबंध में वित्तीय साक्षरता में सुधार करने की काफी संभावना अब भी है। इस समूह को अक्सर जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है और वे ऊंची ब्याज दरों, धोखाधड़ी और अन्य अनुचित प्रथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

निदेशक मंडल को बैंक के भीतर आंतरिक अभिशासन ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्पादों की गलत बिक्री (मिस सेलिंग) या उचित केवाईसी सत्यापन के बिना खाते खोलने जैसी अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के प्रोत्साहन प्रकारों को सावधानीपूर्वक संरचित किया जाना चाहिए ताकि गलत बिक्री या अनैतिक प्रथाओं को प्रोत्साहन न मिले। हो सकता है ऐसी प्रथाओं से अल्पकालिक लाभ मिले, लेकिन वे अंततः बैंक के लिए प्रतिष्ठागत नुकसान, पर्यवेक्षी जांच और वित्तीय दंड जैसे बड़े दीर्घकालिक जोखिमों उत्पन्न करते हैं।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मैं भविष्य के लिए हमारी सामूहिक आकांक्षाओं के पक्ष को भी छूना चाहूंगा। जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, यह जरूरी है कि हमारा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र - सार्वजनिक और निजी दोनों - अपनी रणनीतियों को हमारे लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं के साथ संरेखित करें। मैं बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन आकांक्षाओं का समर्थन करने वाले स्पष्ट और कार्रवाई योग्य उद्देश्य निर्धारित करें। हमें साथ मिलकर एक ऐसी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए लचीली, समावेशी और टिकाऊ हो।

इस वर्ष रिज़र्व बैंक का 90वां वर्ष भी है। हमने RBI@100 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, ऋण उपलब्धता का विस्तार करना, भारत के वित्तीय क्षेत्र का वैश्वीकरण करना और भारत की भुगतान प्रणालियों को सार्वभौमिक बनाना शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं इस विज़न को साकार करने में आपकी निरंतर सहायता की आशा करता हूँ।

संक्षेप में कहें तो एक सुचारु रूप से कार्य करने वाला निदेशक मंडल, जो अभिशासन की सक्रिय निगरानी करता हो, मजबूत आश्वासन कार्यों और ग्राहक केंद्रितता के पक्ष में निर्मित नीतियों द्वारा समर्थित हो, वही एक लचीले और चुस्त बैंक को एक साधारण बैंक से अलग करता है। ऐसा बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि संगठन परिवर्तन के प्रति अनुकूल बना रहे, उभरते जोखिमों का अनुमान लगाए और सतत विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाए। आंतरिक और बाहरी, दोनों चुनौतियों पर पैनी दृष्टि रखते हुए बोर्ड दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है और वित्तीय पारितंत्र के भीतर विश्वास निर्माण कर सकता है। इस ज्ञानवर्धक और समृद्ध सम्मेलन के लिए मेरी शुभकामनाएं।

धन्यवाद और नमस्कार।

*चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत**

श्री शक्तिकान्त दास

मैं सीएनबीसी टीवी18 की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित ग्लोबल लीडरशिप शिखर सम्मेलन में आकर बहुत खुश हूं। मैं सीएनबीसी टीवी18 की टीम को उसके वर्षों से सफल सफर के लिए बधाई देता हूं। भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन प्रतिष्ठित पूर्व गवर्नरों - डॉ. सी. रंगराजन, डॉ. बिमल जालान और डॉ. वाई.वी. रेड्डी को सम्मानित करने के इस अवसर पर शामिल होना मेरे लिए वास्तव में सम्मान की बात है। आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के नीति निर्माण में अपने असाधारण प्रदर्शन के साथ वे केंद्रीय बैंकिंग की कला और विज्ञान में अग्रणी स्थान रखते हैं। एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के संरक्षक के रूप में उन्होंने मौद्रिक ढांचे के अलावा देश की वित्तीय, विनिमय दर और बाह्य क्षेत्र की नीतियों में मौलिक बदलाव शुरू किए। मैं आज भारतीय रिज़र्व बैंक को आकार देने में डॉ. रंगराजन, डॉ. जालान और डॉ. रेड्डी द्वारा निर्मित समृद्ध परंपरा और विरासत को नमन करता हूं। उनके योगदान से प्रेरणा लेते हुए मैं आज 'चुनौतियों से गुजरते हुए: वित्तीय स्थिरता और भारत' विषय पर बात करूंगा।

हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर और नए-नए आघातों के दौर से गुज़री है। यह "अति अस्थिरता"[1] (ग्रेट वॉलेटिलिटी) का दौर था, जो "ग्रेट मॉडरेशन" के पिछले दौर से अलग था।[2] वैश्विक महामारी, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, युद्ध, भू-राजनीतिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के जटिल और विविध आघातों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। ये पाठ्यपुस्तकों में बताए गए सामान्य आघात नहीं थे या इनके लिए कोई मानक नीतिगत प्रतिक्रियाएँ नहीं थीं। इसलिए, इस अस्थिरता की अवधि से पार पाना भारत सहित हर देश के लिए एक कठिन चुनौती थी।

* K14 नवंबर 2024 को सीएनबीसीटीवी18 ग्लोबल लीडरशिप शिखर सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का मुख्य भाषण।

1 गवर्नर का वक्तव्य: 8 दिसंबर 2023।

2 'ग्रेट मॉडरेशन' 1980, 1990 और 2000 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक आर्थिक अस्थिरता में आई कमी की अवधि को दिया गया नाम है।

वर्तमान वैश्विक संदर्भ

महामारी के बाद विस्तारवादी नीतियों को लगभग सभी जगह एक साथ अपनाने के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और यूक्रेन युद्ध के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण समान रूप से एक साथ मौद्रिक नीति को सख्त करने के कदम उठाए। कुल मिलाकर इस नीति ने दुनिया भर में अच्छा काम किया।[3] मंदी रहित मौद्रिक सख्ती (सॉफ्ट लैंडिंग) सुनिश्चित की गई है, लेकिन मुद्रास्फीति के लौटने और संवृद्धि के धीमा होने का जोखिम बना हुआ है। भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं।

इस पूरी अवधि में कीमतों और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना मुश्किल काम रहा है जैसा कि 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र में हुई उथल-पुथल से दिखाई देता है। चुनौती हमेशा एक ओर कार्रवाई बहुत कम या बहुत देरी से करने और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी करने के बीच होती है। मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों और वित्तीय क्षेत्र में विकास के साथ-साथ उभरती स्थिति के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना और निर्णयों को समय पर लेना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। केंद्रीय बैंकों ने इस बार कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है।

इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में, मैं वैश्विक स्तर पर कुछ विरोधाभासों को उजागर करना चाहता हूँ जिन्हें हम इस समय देख रहे हैं। सबसे पहले, सरकारी बॉण्ड का प्रतिफल बढ़ रहा है, जबकि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ दरों में कटौती के माध्यम से नरमी का मार्ग अपना रही हैं, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ट्रेजरी बाज़ार वैश्विक और घरेलू, कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जो केवल नीति समायोजन से कहीं अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी डॉलर भी मज़बूत हो रहा है, जबकि फेड दरों में कटौती कर रहा है। दूसरा, मज़बूत अमेरिकी डॉलर और उच्च बॉण्ड प्रतिफल से अप्रभावित, सोने और तेल की कीमतें – ऐसी दो वस्तुएँ जिनका मूल्य आम तौर पर एक साथ घटता-बढ़ता है – भारी अंतर दिखा रही हैं। तीसरा, बढ़ते भू-राजनीतिक

3 अध्याय 2, वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, आईएमएफ, अक्टूबर 2024।

जोखिमों और वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास भी उभर रहा है। जबकि हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, वित्तीय बाज़ारों ने बढ़ती अनिश्चितताओं के होते हुए भी काफी सतुत्थानशीलता दिखाई है। चौथा, प्रतिबंधों, शुल्कों, आयात शुल्कों, बढ़ते सीमा-पार प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद वैश्विक व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने का अनुमान है। पांचवां, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने मौजूदा दौर में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की तुलना में अधिक समुत्थानशीलता दिखाई है।

भारतीय संदर्भ

इन प्रतिकूल परिस्थितियों और विरोधाभासों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक बुनियादी ढांचे, स्थिर वित्तीय प्रणाली और समुत्थानशील बाह्य क्षेत्र जैसे बफर द्वारा संचालित होकर सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास विवेकपूर्ण और सक्रिय नीतिगत दृष्टिकोण को अपना कर अपने मूल ढांचों को अधिक मजबूत करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना रहा है। हमारा मुख्य ध्यान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर रहा है, जो संवृद्धि और समृद्धि का मार्ग है।

2019 में, हमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में गंभीर दबाव का सामना करना पड़ा। चलनिधि संकुचित हो गई थी और वित्तीय बाजारों में विश्वास की कमी थी। हाल के वर्षों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग, दोनों क्षेत्रों में बैंक दबाव की कुछ घटनाएं घटी थीं। इन सभी आपातकालीन स्थितियों में रिज़र्व बैंक ने संकट के विस्तार को रोकने और बाजारों में स्थिरता और विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय किए। इसके साथ-साथ, हमने अपनी विनियामक संरचना और पर्यवेक्षी निगरानी को मजबूत किया ताकि कमज़ोरियों की पहचान की जा सके और भविष्य के लिए तैयार रहा जा सके। इसलिए, इस अवधि के दौरान हमारे अनुभव का विश्लेषण करना उचित है, न केवल एक सफलता की कहानी के रूप में - बल्कि, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य के लिए सबक के रूप में।

[4] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स, डब्ल्यूटीओ, अक्टूबर 2024 के अनुसार विश्व माल व्यापार की मात्रा 2024 में 2.7 प्रतिशत और 2025 में 3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2024 और 2025 में विश्व व्यापार की मात्रा क्रमशः 3.1 और 3.4 प्रतिशत बढ़ेगी (वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अक्टूबर 2024)।

जब कोविड-19 महामारी ने हमें प्रभावित किया, तो हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी। हमने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही कारोबार निरंतरता के उपाय लागू कर दिए थे। हमने वित्तीय बाज़ार संचालन और भुगतान प्रणालियों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ एक विशेष संगरोध केंद्र (क्वारंटीन केंद्र) स्थापित किया। सभी विनियमित संस्थाओं को व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने और अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तत्काल आकस्मिक उपाय करने की सलाह दी गई।

मौद्रिक नीति और चलनिधि संचालन

मौद्रिक नीति ने पिछले छह वर्षों में एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया है - 2019-22 के दौरान एक सहजता चक्र और उसके बाद समान स्तर का एक सख्त चक्र। हमने तत्समय की स्थितियों और परिदृष्य के अनुसार संवृद्धि अथवा मुद्रास्फीति, को प्राथमिकता देने के लिए लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) में निहित लचीलेपन को अपनाया। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधि गंभीर दबाव में आ गई, तो हमने मुद्रास्फीति के बजाय संवृद्धि को प्राथमिकता दी और नीति दरों में कटौती की और प्रणाली में भारी मात्रा में चलनिधि उपलब्ध कराई। ये उपाय भविष्य में उत्पन्न होने वाली कीमत और वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए काफी नपे-तुले थे। इसके अलावा, सहजता चरण के दौरान अग्रगामी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) मौद्रिक नीति और चलनिधि उपायों के लिए सहायक और पोषक सिद्ध हुआ। इसी के साथ-साथ, ऋणों के पुनर्भुगतान पर स्थगन और दबावग्रस्त ऋणों के लिए समाधान ढांचे सहित उचित विनियामक उपायों की भी घोषणा की गई।

बाद में, जब रूस-यूक्रेन युद्ध ने प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति में भारी व्यवधान पैदा किया और मुद्रास्फीति के नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा किया, तो हमने अपना ध्यान संवृद्धि से हटाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। हमने अपनी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को आरंभ में ही लागू कर दिया और अपने रुख को बदलकर समायोजन वापस ले लिया। हम अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में चुस्त और सक्रिय बने रहे। इसके

अलावा राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की बात करें तो रिज़र्व बैंक की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति पक्ष उपायों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में मदद की।

हाल की अवधि की बात करें तो, 7-9 अक्टूबर 2024 को अपनी बैठक में एमपीसी ने मौजूदा और अपेक्षित मुद्रास्फीति-संवृद्धि परस्पर गतिशीलता को ध्यान में लेते हुए मौद्रिक नीति के रुख को समायोजन को वापस लेने से बदलकर 'तटस्थ' करने का फैसला किया। एमपीसी ने संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को टिकाऊ रूप से लक्ष्य के पास लाने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिय। रुख में बदलाव से उभरती परिस्थितियों और दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक लचीलापन और विकल्प मिलता है।

कुल मिलाकर, 2021-24 के दौरान औसत संवृद्धि 8.0 प्रतिशत से अधिक रही तथा 2023-24 और 2024-25 (सितंबर तक) में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर सहनीय सीमा के भीतर रही जो रिज़र्व बैंक की नीतियों की सफलता का प्रमाण है। यह भी उतना ही उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। हमारी दरों में बढ़ोतरी से पहले या उसके साथ विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया गया था, जिसमें बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को रखने में अधिक छूट दी गई थी जिससे बाजार-चिह्नित नुकसान न्यूनतम हुआ। यह स्पष्ट है कि महामारी और मुद्रास्फीति में उछाल, दोनों के लिए हमारी कार्रवाई का स्वरूप निर्धारित करते समय हमारी नीतियां चुस्त, लचीली और संतुलित थीं। हम "संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता" के अपने अधिदेश के अनुरूप बने रहे। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के अंतर्निहित अधिदेश का भी पालन किया गया।

केंद्रीय बैंक संचार

इस पूरी अवधि के दौरान हमारी नीतिगत कार्रवाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए संचार एक महत्वपूर्ण साधन बना। महामारी के दौरान हमारा प्रयास व्यापक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारों और आम जनता को विश्वास दिलाना था। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में 17 अप्रैल 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य में मैंने कहा था "हालांकि सामाजिक दूरी हमें अलग करती है, हम एकजुट और दृढ़ हैं। आखिरकार, हम उबरेंगे; और हम टिके रहेंगे"। हमने महात्मा गांधी के उद्धरणों का उपयोग करना शुरू किया जैसे "...मृत्यु के बीच जीवन कायम है...अंधकार के बीच प्रकाश कायम है" (17 अप्रैल 2020); " जब क्षितिज सबसे अंधकारमय होता है और मानवीय तर्क धराशायी हो जाता है, तब विश्वास सबसे प्रकाशमान होता है और हमारी सहायता के लिए आता है" (22 मई 2020)। इसी तरह के और भी कथन थे।

विशेष रूप से मैं 16 नवंबर 2023 को किए गए मैक्रो प्रूडेंशियल उपायों के बाद अपने दिसंबर 2023 के बयान का उल्लेख करना चाहूंगा: "वित्तीय स्थिरता एक सार्वजनिक लाभ है[5]...हम संकट का इंतजार करके बाद में कार्रवाई करते नहीं करते हैं। विवेक ही हर समय हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।" इन कथनों के पीछे की भावना संकटों की अवधि को झेलने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे संचार को उचित नीतिगत कार्रवाइयों का समर्थन प्राप्त था। जाहिर है, हाल के दिनों के अस्थिर समय में स्थिरता बनाए रखने में संचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थिरता के लिए मजबूत विनियमन और पर्यवेक्षण

यह स्पष्ट है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के संबंध में एक मजबूत विनियामक ढांचा और एक मजबूत पर्यवेक्षी और निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण है। जहां तक रिज़र्व बैंक का संबंध है, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर संशोधित मानदंड; एनबीएफसी के लिए पैमाना आधारित विनियमन; माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए संशोधित विनियमन; शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए चार-स्तरीय विनियामक दृष्टिकोण; और असुरक्षित ऋणों में संभावित ऋण आधिक्य को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम हैं जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के हित में विनियमन के विवेकपूर्ण स्वरूप के कुछ उदाहरण हैं।

[5] वित्तीय स्थिरता को नानी पालकीवाला मेमोरियल व्याख्यान (दास, शक्तिकान्त), 16 जनवरी 2021 में भी सार्वजनिक लाभ (पब्लिक गुड) के रूप में वर्णित किया गया था।

आगे की ओर देखें तो वित्तीय प्रणाली के लिए नई चुनौतियां उभरती रहेंगी। वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को अपने पूंजी के स्तर और गुणवत्ता को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है, साथ ही जोखिम प्रबंधन मानकों को और भी कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक अब चरणबद्ध तरीके से संशोधित बेसल III मानकों को अपनाने; अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए दिशानिर्देश जारी करने; चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर); और परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए विवेकपूर्ण ढांचे जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। हमारा समग्र दृष्टिकोण परामर्शात्मक है। उदाहरण के लिए, ईसीएल ढांचे के संबंध में एक चर्चा पत्र जारी करने और हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद भी, जिसकी हमने एक बाहरी कार्य समूह द्वारा जाँच कराई, अब हम ईसीएल के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी करने का विचार कर रहे हैं। इसके पीछे सोच यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके महत्व को देखते हुए इस ढांचे की कुछ विशिष्टताओं पर हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करना है। हमारा प्रयास बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि दोनों आवश्यक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। हम जलवायु जोखिमों और वित्तीय क्षेत्र पर उनके प्रभाव पर भी काम कर रहे हैं। **जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचे** के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं की निगरानी प्रक्रिया को भी एकीकृत किया गया है और सक्रिय ऑन-साइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी तंत्रों के साथ इसे काफी हद तक मजबूत किया गया है। अब ध्यान प्रारंभिक पहचान और पूर्व-निवारक सुधार पर है। मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई), धोखाधड़ी संवेदनशीलता सूचकांक (एफवीआई), माइक्रो-डेटा विश्लेषण (एमडीए), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग के साथ उन्नत ऑफ-साइट मूल्यांकन ढांचा अधिक विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी है। ऑनसाइट पर्यवेक्षण अब अधिक गहराई से किया जाता है। पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ सीधे जुड़ाव में चर्चाओं और *दक्ष* पोर्टल माध्यम को भी शामिल किया गया है। *दक्ष* पोर्टल विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो समाधान के साथ एक सुपटेक पहल है।[6] कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, जिसे मई 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था, अब हमारे पर्यवेक्षकों को अपने कौशल को बेहतर बनाने और वित्तीय क्षेत्र में होने वाली नई और जटिल गतिविधियों के बारे में अवगत होने में मदद कर रहा है।

वित्तीय क्षेत्र वास्तव में अधिक जटिल हो गया है, जिसमें नए-नए डिजिटल उत्पाद, साझा बाजार अवसंरचना और आईटी सेवाओं के लिए साझा सेवा प्रदाता जुड़ रहे हैं। इन विकास क्रमों ने कई तरह के छोटे-बड़े जोखिम बढ़ा दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में बुनियादी साइबर सतर्कता, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण, आईटी आउटसोर्सिंग और आईटी गवर्नेंस से संबंधित विनियम जारी करके वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान सक्रियता के साथ किया है। डेटा के महत्व और उसकी भविष्य की क्षमता को समझते हुए भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। इसके साथ ही, एक डेटा सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र क्लाउड सुविधा स्थापित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।

कुल मिलाकर, भारत का वित्तीय क्षेत्र हाल ही के उथल-पुथल के दौर की शुरुआत की तुलना में अब अधिक मजबूत और समुत्थानशील है। लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है। विनियामक और विनियमित संस्थाओं को उभरती चुनौतियों के लिए सतर्क और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा।

बाह्य क्षेत्र स्थिरता

भारत के बाह्य क्षेत्र ने भी हाल की अवधि में मजबूती और स्थिरता दिखाई है। चालू खाता घाटा (सीएडी) स्वीकार्य सीमा के भीतर रहा है और 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत रहा है (वित्त वर्ष 2023-24 में 0.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 2.0 प्रतिशत)। भारत का व्यापारिक निर्यात, जो 2023-24 में कम हो गया था, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान उबर गया। सेवा निर्यात में उछाल रहा

[6] दक्ष उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, कभी भी-कहीं भी भूमिका-आधारित पहुँच प्रदान करता है। इसे सभी पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एकल इंटरफ़ेस के रूप में देखा जाता है। दक्ष में शामिल पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में निरीक्षण योजना और निष्पादन, स्कोपिंग और संसाधन आवंटन, रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और संस्थाओं को निरीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता शामिल है।

और 2024-25 की पहली छमाही के दौरान उसमें 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2023-24 में 4.8 प्रतिशत)। सेवाओं के निर्यात में मजबूत वृद्धि, और निजी विप्रेषण में उछाल, चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है।

वित्त पोषण के क्षेत्र को देखें तो निवल पूंजी प्रवाह आम तौर पर सीएडी से अधिक रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि में योगदान दे रहा है। 31 अक्टूबर 2024 को भारत के पास 682 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और जो पूरे विदेशी ऋण[7] और लगभग 12 महीने के व्यापारिक आयात का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है।[8] अन्य प्रमुख बाह्य क्षेत्र संकेतकों, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण, निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) और विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण के संदर्भ में भारत की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है।

हमारी विनिमय दर नीति अच्छी तरह से निर्धारित की गई है और पिछले कई वर्षों से कार्यक्षम रही है। भारत की विनिमय दर व्यवस्था बाजार द्वारा निर्धारित है, और रिज़र्व बैंक विनिमय दर के किसी स्तर या सीमा को निर्धारित नहीं करता है। विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप विनिमय दर की व्यवस्थित गति सुनिश्चित करने और अनुचित अस्थिरता को रोकने, बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर करने और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि विनिमय दर किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत का माप साधन भी है। यदि भारतीय रुपया (आईएनआर) 2022 और 2023 में फेड द्वारा सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सख्ती सहित गंभीर बाह्य आघातों के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, तो यह टेपर टैंट्रम के दिनों से हमारे व्यापक बुनियादी ढांचे में आए बड़े बदलाव के बारे में बहुत कुछ बताता है।

यदि हम रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के अन्य प्रमुख खंडों अर्थात मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार को देखें तो वास्तव में वे भी वैश्विक बाजारों के बड़े उतार-चढ़ाव और स्पिलओवर के बावजूद स्थिर रहे हैं। भारित औसत कॉल मनी दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) गलियारे के भीतर सीमित दायरे में रही है और नीति रेपो दर के करीब रही है। वैश्विक नीतिगत बदलाव, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बीच सख्ती के चक्र के दौरान 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल भी 6.72 से 7.61 प्रतिशत[9] के सीमित दायरे में रहा । रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों की समुत्थानशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में कई विनियामक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं: बेंचमार्क प्रशासकों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की स्थापना; ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में बाजार निर्माताओं के लिए मजबूत अभिशासन आवश्यकताएं; और गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव सुधारों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों में नवाचारों के लिए एक सक्षम पारितंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली की दक्षता और स्थिरता बढ़ी है। चौबीसों घंटे एनईएफटी और आरटीजीएस की शुरुआत;[10] एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता; और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना (e₹) का कार्यान्वयन व्यापक वित्तीय प्रणाली को बदल रहा है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण को रिज़र्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल - यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) से और बढ़ावा मिला है जिसे रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच), बेंगलुरु द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया गया है। आरबीआईएच की कुछ अन्य पहलें भी विचाराधीन हैं।

समापन टिप्पणियां

रिज़र्व बैंक को प्राप्त अधिदेश कई आयामों में व्याप्त है। हमारा निरंतर प्रयास स्थिरता का समग्र दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और निरंतर विकास

---

7 जून 2024 के अंत में।

8 भुगतान संतुलन के आधार पर वार्षिक व्यापारिक आयात।

9 16 जून 2022 तक, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल 7.61 प्रतिशत पर पहुँच गया। 10 वर्षीय जी-सेक की प्रतिफल दर 26 सितंबर 2024 तक कम होकर न्यूनतम 6.72 प्रतिशत हो गई।

10 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) 16 दिसंबर 2019 से सप्ताहांत और छुट्टियों सहित चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) 14 दिसंबर 2020 से सप्ताहांत और छुट्टियों सहित चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया।

शामिल है। हम इन बहु-उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई नीतिगत साधनों का प्रयोग करते हैं।

आज, भारत की आर्थिक संवृद्धि समुत्थानशील बनी हुई है; समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है; और बाह्य क्षेत्र मजबूत है। बिना किसी आत्मसंतुष्टि के, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अशांति के लंबे दौर से अच्छी तरह से गुजरी है और लगातार उभरती नई चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखाती है।

धन्यवाद। नमस्कार।

मैक्रो वीक 2024 में वक्तव्य*

श्री शक्तिकान्त दास

आज पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) द्वारा आयोजित मैक्रो वीक 2024 में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। संस्थान ने खुद को एक ऐसे अग्रणी मंच के रूप में स्थापित किया है जो उभरते व्यापक आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए लोक नीति से जुड़े व्यवसायियों, केंद्रीय बैंकरों, उद्योग जगत के नेताओं, अनुसंधान पेशेवरों और विद्वानों को एक साथ लाता है। इस तरह की चर्चाएँ, जो विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान हो रही हों, समकालीन नीतिगत प्रासंगिकता के मामलों पर गहनतापूर्वक और सार्थक बातचीत के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं।

आज अपने वक्तव्य में मैं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कार्यसूची और आर्थिक तथा वित्तीय विखंडन से जूझ रही दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर अपने कुछ विचार साझा करूंगा। मैं इस बात पर भी चर्चा करूँगा कि जलवायु परिवर्तन को केंद्रीय बैंक की विचारधारा का हिस्सा क्यों और कैसे होना चाहिए।

I. अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कार्यसूची

वैश्विक आर्थिक परिदृष्य तेजी से बदल हैं, जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, भू-आर्थिक बदलावों, पर्यावरणीय चुनौतियों और वर्तमान में चल रहे वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों जैसी शक्तियों द्वारा संचालित हैं। इस तेजी से बदलते दौर में, जी20 और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों पर वैश्विक स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए तेजी से अनुकूलन और निर्णायक रूप से कार्य करने का दायित्व है। मैं इस संदर्भ में छह प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिनका क्रम कोई माइने नहीं रखता।

पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना स्वरूप में सुधार** को दी जानी चाहिए। इसमें ऐसे समावेशी वैश्विक अभिशासन ढांचे को प्राथमिकता देना शामिल है जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। मौजूदा प्रणाली में, हालांकि आधारभूत है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समान स्तर और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए खुद को सुधारने की जरूरत है। संसाधनों तक बेहतर पहुंच और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों के अभिशासन में एक मजबूत भूमिका न केवल इन संस्थानों का महत्व बढ़ाएगी बल्कि व्यापक वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में अधिक गंभीर वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

दूसरा, कार्यसूची में **ऋण पुनर्गठन तंत्र** होना चाहिए। हालांकि जी20 की डेट सर्विस ससपेन्शन इनीशिएटिव (डीएसएसआई) और कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट सराहनीय उपाय थे, किंतु समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है। ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाएँ तदर्थ, धीमी औरकई मौकों पर पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं रहती हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक चलने वाले संकटों में होता है, जिससे ऋणी देशों को अनावश्यक आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। हमें ऋण समाधान संरचना में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और इसे ऐसे रूप में ढालना चाहिए जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के ऋणदाता शामिल हों, समय पर ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित हो और ऋण राहत को सतत विकास उद्देश्यों से जोड़ा जा सके। इस तरह के सुधार के बिना, कमजोर देशों को असहनीय ऋण बोझ का सामना करना पड़ेगा जिसका वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तीसरा, हमें वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, संस्थानों और बाजारों दोनों की कमज़ोरियों और कमियों को पहचानना चाहिए। हाल के वर्षों में उन्नत और उभरते बाजारों, दोनों में वित्तीय अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम सामने आए हैं। निजी पूंजी और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए **वैश्विक वित्तीय विनियमन में सुधार** करने की वास्तव में बहुत ज़रूरत है, जिनकी अब वैश्विक आस्तियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। शेडो बैंकिंग और फिनटेक का उदय, और विकेंद्रीकृत वित्त के बढ़ते पदचिह्नों से होने वाले संक्रामक प्रभावों को रोकने और वैश्विक सार्वजनिक हित के रूप में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक मज़बूत विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता है.

* पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) द्वारा आयोजित मैक्रो वीक 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का संबोधन, 25 अक्टूबर 2024, वाशिंगटन डीसी।

डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड) चिंता का चौथा क्षेत्र है। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल समावेशन के लिए बुनियादी ढांचे, कौशल और विनियामक ढाँचों की कमी वाले देशों के और पीछे छूटने का जोखिम है। जी20 और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय संस्थानों को एक ऐसे पारितंत्र को पोषित करने की दिशा में काम करना चाहिए जो साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा दे।

पाँचवाँ, भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक नीतियों को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण प्रतिबंध, वित्त का शस्त्रीकरण, व्यापार प्रतिबंध और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो रहे हैं। यह **आर्थिक विखंडन** का कारण बन रहा है, क्योंकि देश ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी रणनीतिक सामग्री वाले प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हैं। जी20 को खुले और नियम-आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देकर आर्थिक विखंडन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देशों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जी20 को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक सार्वजनिक हितों में निवेश और हरित संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

छठा है **जलवायु वित्त**, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह जी20 की प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय कार्यसूची में सबसे आगे होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण को निधि देने के लिए काफी अधिक संसाधन जुटाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जी20 को राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय भी करना चाहिए ताकि जलवायु नीतियों से संरक्षणवाद, एकतरफा व्यापार बाधाएँ या व्यापार संघर्ष न हों। अनावश्यक आर्थिक विखंडन से बचने के लिए सीमा कार्बन समायोजन (बीसीए) और इसी तरह के उपायों के उदय को सहकारिता के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे नवीन वित्तीय साधनों की तत्काल आवश्यकता है जो जलवायु संबंधी प्रयासों में निजी पूंजी को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। जब तक हम जलवायु वित्त को संबोधित करने के अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के तरीके में मौलिक बदलाव नहीं लाते हैं, पर्यावरणीय ह्रास और वैश्विक असमानता बढ़ने का जोखिम बना रहेगा।

हम अत्यधिक अनिश्चितता और उथल-पुथल के युग में रह रहे हैं, जहाँ नीति निर्माताओं का काम अशांत समुद्र के माध्यम से गुजर रहे एक विशाल, परस्पर जुड़े बेड़ों को चलाने जैसा है, जहाँ पुरानी कार्यपद्धति अब पर्याप्त नहीं प्रतीत होती। वृद्धिशील परिवर्तनों का समय अब चला गया है। अब जिस बात की ज़रूरत है वह एक परिवर्तनकारी प्रयास जो यह सुनिश्चित करे कि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था सभी देशों और लोगों के लिए हो न कि केवल कुछ चुनिंदा देशों अथवा लोगों के लिए। सामूहिक कार्रवाई और बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ, हम एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में 21वीं सदी के लिए उपयुक्त होगी।

II. आर्थिक और वित्तीय विखंडन

वैश्विक सहयोग और विशेष रूप से वैश्विक बाजारों का एकीकरण, दशकों तक विश्व विकास को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। कई कम आय वाले देशों और उभरते बाजारों के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह एकीकरण उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है। इसने उन्हें किफायती आयात, व्यापक निर्यात बाजारों और विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की। लेकिन, अब भू-आर्थिक विखंडन वैश्विक विकास के दृष्टिकोण पर बाधा साबित हो रहा है।[1] व्यापार निर्बंधनों और वित्तीय प्रतिबंधों में वृद्धि होने से 2024 में भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक[2] (दी जिओपोलिटिकल रिस्क इंडेक्स) तेज़ी से बढ़ा है। इससे वैश्विक आर्थिक एकीकरण से मिलने वाले बड़े लाभों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।[3] अब वि-वैश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण बढ़ने की आशंकाएँ हैं। यह उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर जीवन स्तर के समीप आने की गति को धीमा कर सकती हैं। भू-राजनीतिक जोखिम पूंजी प्रवाह और आस्ति कीमतों में भी अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। वे वैश्विक भुगतान प्रणालियों की दक्षता को भी कम कर रहे हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से माल, सेवाओं और पूंजी के सीमा पार प्रवाह में आगे कोई सुधार नहीं हुआ है। हाल की

[1] अगस्त 2023 में आईएमएफ स्टाफ द्वारा किया गया एक अध्ययन यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध की अवधि अधिक लंबी होने से वैश्विक आर्थिक उत्पादन 7 प्रतिशत तक घट सकता है, जो आज के डॉलर के रूप में लगभग 7.4 ट्रिलियन यूएसडी राशि हो सकती है। यह फ्रांस और जर्मन अर्थव्यवस्थाओं के संयुक्त आकार के बराबर है, और उप-सहारा अफ्रीका के वार्षिक उत्पादन का तीन गुना है (दी आई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकॉनोमिक फ्रेगमेंटेशन, आईएमएफ ब्लॉग, अगस्त 2023)।

[2] कैलडारा, डारियो और इकोविएलो, मैटेओ (2022), "मेजरिंग जिओपॉलिटिकल रिस्क", अमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू, खंड 112, संख्या 4, अप्रैल, पृष्ठ 1194 1225।

[3] वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई; जून 2024।

भू-राजनीतिक घटनाओं ने व्यापार और रसद व्यवधानों में वृद्धि के साथ-साथ संरक्षणवाद को और बढ़ावा दिया है[4]। वि-वैश्वीकरण के कारण कम आय वाले कई देशों और उभरते बाजारों के लिए संभावित नुकसान बहुत अधिक हो सकते हैं। इन नकारात्मक जोखिमों के बावजूद, हाल के अनुमान उत्साहजनक हैं जो बताते हैं कि वैश्विक माल व्यापार में इस वर्ष 2.7 से 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी[5]। भले ही यह निकट अवधि की समुत्थानशीलता आशा का एक स्रोत हो, लेकिन बढ़ते अनिश्चित समय के लिए तैयारी करते हुए बदलती परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण है।

हाल ही में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भू-राजनीतिक घटनाओं और महामारी तथा जलवायु संकट जैसे व्यापक मुद्दों के कारण बड़े व्यवधान भी देखे गए । इससे विकास के चालक के रूप में जीवीसी की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। 'फ्रेंड-शोरिंग' और 'रीशोरिंग' के बारे में चर्चाएँ विदेशी प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण उपायों की असंगति और भय फैला रही हैं। ऐसे व्यापार वातावरण में, जो इसमें शामिल नहीं हैं वे असमान रूप से प्रभावित होंगे।

विखंडन के अन्य रूप - जैसे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एकरूपता का न होना और बाधित पूंजी प्रवाह - भी अपने प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और लागत बढ़ाएंगे। वे बैंकों और घरेलू वित्तीय संस्थानों की वित्तपोषण लागत को भी प्रभावित कर सकते हैं, उनकी लाभप्रदता को कम कर सकते हैं, और उन्हें आर्थिक गतिविधि पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऋण देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के भीतर पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय भंडार के साथ-साथ पूंजी और चलनिधि बफर का निर्माण करना उभरती अर्थव्यवस्थाओं की इस तरह के प्रतिकूल बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अंत में, यह आशंका है कि यदि भू-आर्थिक विखंडन निरंतर जारी रहता है, तो देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बुनियादी ढांचे और वैश्विक मानकों पर कम निर्भर होने की कोशिश कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के विखंडन से बाजारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अंतर-संचालन की कमी वाली नई समानांतर प्रणालियाँ उभर सकती हैं, जिससे लेनदेन लागत और अन्य अक्षमताएँ बढ़ सकती हैं। ऐसे तनावों और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए संकट की तैयारी को मजबूत करना उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। देशों के बीच आपसी समझौतों के माध्यम से वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें रीजनल सेफ्टी नेट, मुद्रा स्वैप, राजकोषीय तंत्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से एहतियाती ऋण व्यवस्था शामिल हो सकती हैं। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने सेफ्टी नेट और बफर को काफी हद तक बढ़ाना होगा।

III. केंद्रीय बैंकिंग और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन नीति पर पारंपरिक दृष्टिकोणों ने चरम जलवायु घटनाओं से होने वाले परिणामों से निपटने के लिए अधिक अद्यतन बहु-नियामक दृष्टिकोण का मार्ग उपलब्ध कराया है। मांग-आपूर्ति आघातों, उत्पादकता हानि, आस्ति पुनर्मूल्यांकन और उच्च लागत पर कम कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण के माध्यम से इन जोखिमों के उभरने से वित्तीय, मौद्रिक और मूल्य स्थिरता बिगड़ सकती है[6]। मेरे विचार से, सवाल यह नहीं है कि केंद्रीय बैंकों को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इस विचार को उनके केंद्रीय अधिदेशों में किस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में शामिल उच्च लागत और अन्य संक्रमण जोखिमों को देखते हुए मूल्य स्थिरता पर प्रभाव को समझना शामिल है[7]। दूसरा, वित्तीय स्थिरता पर इसके सभी प्रकार के प्रभावों का आकलन करना महत्वपूर्ण है[8]। तीसरा, वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सूक्ष्म विवेकपूर्ण जिम्मेदारियों[9] को संतुलित करना आवश्यक है। चौथा, इस क्षेत्र में

[4] अध्याय 1, जिओइकॉनोमिक फ्रेगमेंटेशन: दी इकॉनोमिक रिस्क्स फ्रॉम ए फ्रेक्चर्ड वर्ल्ड इकॉनोमी। सीईपीआर और आईएमएफ, 2023।

[5] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, डब्ल्यूटीओ, अक्टूबर 2024 और वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, आईएमएफ, अक्टूबर 2024।

[6] जलवायु परिवर्तन विषय अब वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की कार्यसूची में प्रमुख मद है। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस), जिसे 2017 में आठ केंद्रीय बैंकों की पहल पर स्थापित किया गया था, में अब 141 सदस्य और 21 पर्यवेक्षक शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक अथवा प्रतिनिधि प्राधिकरण शामिल हैं।

[7] मोनिटरी पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज – की टेकअवेज़ फ्रॉम दी मेंबरशिप सर्वे एंड एरियाज़ फॉर फरदर एनालिसिस, जुलाई 2023 - एनजीएफएस।

[8] वित्तीय स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, 2020।

[9] प्रिंसिपल्स फॉर दी इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ क्लाइमेट-रिलेटेड फिनान्शियल रिस्क्स, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस), 2022।.

जागरूकता और विचार नेतृत्व[10] को सक्षम करने के लिए मजबूत विश्लेषण और शोध की आवश्यकता है[11]।

जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कोई स्पष्ट दायित्व नहीं है। यह इसके व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता अधिदेशों से प्राप्त एक अनुमानित जिम्मेदारी है। इसने उपयुक्त साधनों और कार्रवाई योग्य ढाँचों को पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के भीतर एक स्थायी वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की है और 2021 में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) में भी शामिल हो गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से उठाए गए कुछ कदमों में हरित वित्त पहलों को बढ़ावा देना शामिल है जैसे कि बैंकों द्वारा निर्देशित ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना; सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना; 'ग्रीन डिपॉजिट' की स्वीकृति के लिए एक ढाँचा स्थापित करना; और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढाँचा विकसित करना और जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन करना।

राष्ट्र स्तर पर, मेरा मानना है कि जलवायु-संबंधी जोखिमों से निपटने के दौरान केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को उचित रूप में विचार में लेना महत्वपूर्ण है। एक ओर केंद्रीय बैंकों को अपने विशिष्ट कानूनी ढाँचे के दायरे में काम करना पड़ता है और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह संस्थाओं के रूप में, उन्हें अपने सभी कार्यों के समर्थन में ठोस सबूत देने पड़ते हैं। दूसरी ओर, यह संभावना हो सकती है कि केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र पर पहले से ही जलवायु-संबंधी जोखिमों का असर पड़ा हो बाद में उन्हें उनका निराकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावी संस्था सरकार है, प्रत्येक देश को अपनी घरेलू परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना होगा- कि केंद्रीय बैंक के लिए स्पष्ट जलवायु अधिदेश रखा जाए या इसे अपने मूल्य और वित्तीय स्थिरता अधिदेश में शामिल किया जाए।

IV. निष्कर्ष

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं संक्षेप में भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यापक आर्थिक अनुभव पर बात करना चाहूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण निर्मित गंभीर संकुचन से उबर गई है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है। चालू वर्ष (2024-25) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें इस पूर्वानुमान के आसपास जोखिमों को समान रूप से संतुलित रखा गया है। घरेलू मांग में सुधार, कम इनपुट लागत और एक सहायक नीतिगत माहौल[12], विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। संवृद्धि दृष्टिकोण भारत के वृहद-बुनियादी सिद्धांतों की अंतर्निहित ताकत को दर्शाता है, जिसमें घरेलू चालक अर्थात निजी खपत और निवेश - प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर और बैंकों और कॉरपोरेट्स के स्वस्थ तुलन-पत्र से निजी निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है। निजी खपत, जो कुल मांग का मुख्य आधार है, अनुकूल कृषि दृष्टिकोण और ग्रामीण मांग में तेजी के कारण मजबूत सुधार के लिए अपने मार्ग पर है। सेवाओं में निरंतर प्रगति से शहरी मांग को भी समर्थन मिलेगा।

लचीली संवृद्धि ने हमें मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया है, ताकि इसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक स्थायी रूप से कम किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही से हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी आने का अनुमान है। अप्रत्याशित मौसमी घटनाएं और भू-राजनीतिक संघर्षों का और गंभीर होना मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

[10] ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने जलवायु संबंधी कार्यों पर काम करने के लिए समर्पित केंद्रीय बैंक इकाइयाँ बनाई हैं।

[11] मई 2021 में, रिज़र्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और सतत वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में विनियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए बैंक के भीतर एक टिकाऊ वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की।

[12] उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) [3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए विस्तारित], प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) [चरण IV का शुभारंभ], राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसी सरकारी योजनाएँ पूंजी निर्माण को गति प्रदान करेंगी।

वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना रिज़र्व बैंक की निरंतर प्राथमिकता रही है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्वास्थ्य मानदंड अब बहुत मजबूत हैं। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा प्राप्त वाले क्षेत्रों में निरंतर ऋण प्रवाह हुआ है जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा था, आज, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती की तस्वीर पेश करती है। मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है। बाह्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था की ताकत दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार नए शिखर छू रहा है। राजकोषीय समेकन चल रहा है। वित्तीय क्षेत्र मजबूत और समुत्थानशील बना हुआ है। भारत की संभावनाओं में वैश्विक निवेशक आशावाद शायद अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इन सबके बावजूद हम आत्मसंतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।

धन्यवाद।

*विचलन से अभिसरण की ओर पुनर्संतुलन: भारतीय अनुभव**

माइकल देवब्रत पात्र

आप सभी को सुप्रभात!

भारतीय परंपरा में, नमस्कार, जिसका अर्थ है कि मैं आप में विद्यमान दिव्यता को प्रणाम करता हूँ।

न्यूयॉर्क के फेडरल रिज़र्व बैंक के वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग सेमिनार में यहाँ उपस्थित होना हमेशा संतोषप्रद होता है। पिछले कुछ वर्षों में यह सेमिनार दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों के बीच विचारों और अनुभवों के पारस्परिक संबंध और आदान-प्रदान के लिए एक ऐतिहासिक मंच बन गया है। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे एक पसंदीदा मंच के रूप में माना जाता है जहाँ पेशे के व्यवसायी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और केंद्रीय बैंकिंग में सामयिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ मिलकर समाज की समग्र भलाई में योगदान के बारे में सीखते हैं।

मैं न्यूयॉर्क फेड के अंतर्राष्ट्रीय नीति और रणनीति के प्रमुख डॉ. नरहरि फाटक - हरि - का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस वर्ष के सेमिनार में आमंत्रित किया। जब जुलाई में हरि ने मुझसे संपर्क किया, तो दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक मार्ग में काफी भिन्नता थी। इसलिए उस समय केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन की परिभाषित विशेषता विचलन थी, जिसने इस वर्ष के सेमिनार के विषय के चयन को प्रेरित किया। हालांकि, तब से, बहुत पानी बह चुका है और दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। इस साल 18 सितंबर को अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफएमओसी) ने अपने दर में कटौती चक्र आक्रामक करने के बाद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) द्वारा वर्ष की दूसरी दर में कटौती और उसके बाद चीन द्वारा प्रोत्साहन उपायों की बौछार के बाद, जापान, ब्राजील और रूस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर, अभिसरण प्रमुख विषय बन गया है। इसलिए, मैंने अपने संबोधन के विषय के रूप में "विचलन से अभिसरण की ओर पुनर्संतुलन" को चुना, जिसके अंतर्गत मैं आपके साथ भारतीय अनुभव के कुछ पहलुओं को साझा करना चाहता हूँ (कृपया प्रासंगिक चार्ट और सारणियों के लिए अनुलग्नक देखें)।

II. आघात और खौफ

दुनिया अनिश्चितता के सागर में डूबी हुई है, जो भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और समग्र नीति अनिश्चितता के रूप में तूफ़ानों से घिरी हुई है, जिसमें बड़े चुनाव वर्ष के दौरान राजनीतिक प्रभाव-विस्तार भी शामिल है, जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी मतपेटी का सामना करती है। वित्तीय बाज़ार नीतिगत परिवर्तनों के स्वरूप और समय तथा उनके परिणामों के बारे में केंद्रीय बैंकों से आगे निकलने और उनका अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। 31 जुलाई को बैंक ऑफ़ जापान द्वारा दर में वृद्धि और 2 अगस्त को यू.एस. गैर-कृषि पेरोल डेटा जारी होने के बाद 5 अगस्त को उत्साह चरम पर पहुँच गया। येन कैरी ट्रेड के कम होने के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाज़ारों में 1987 के ब्लैक मंडे की याद दिलाने वाला खूनी संघर्ष देखने को मिला। फियर गेज़ – सीबीओई[1] अस्थिरता सूचकांक या वीआईएक्स 50 फीसदी से ज्यादा उछलकर 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

एक बार फिर, 3 सितंबर को जारी एकल डेटा पर - यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट (यूएस आईएसएम) मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स - मंदी की आशंकाएं फिर से उभरीं, जिससे यूएस इक्विटी बाजारों में भगदड़ मच गई जो जल्दी ही एशिया और यूरोप में फैल गई। इस प्रकार, बाजार विचलन से अभिसरण की ओर - हालांकि अव्यवस्थित तरीके से - पुनःसंतुलित हो रहे हैं। प्रत्येक आने वाला डेटा आसान लैंडिंग की बढ़ती भावना को दूर करता हुआ और मुद्रास्फीति रहित मौद्रिक नीति के अंत की आशंकाओं को जगाता हुआ प्रतीत होता है। कुल मिलाकर, हालांकि, बाजारों ने पर्याप्त लचीलापन प्रदर्शित किया है। मैंने जिन आघातों का वर्णन किया है, उनसे उबरने की गति उल्लेखनीय रही है। विनिमय दर में परिवर्तन की तीव्रता पिछले प्रकरणों की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। यह अनुमान लगाया गया है कि

* 21 अक्टूबर, 2024 को न्यूयॉर्क, यूएसए में फेडरल रिज़र्व बैंक, न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क फेड सेंट्रल बैंकिंग सेमिनार में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। बिनोद बी भोई, हरेंद्र बेहरा, भानु प्रताप, सुब्रत सीट, सुजाता कुंडु, धीरेंद्र गजभिये, संगीता मैथ्यूज, स्नेहार्थी गायेन, आशीष थॉमस जॉर्ज से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से संपादकीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

[1] शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज।

येन कैरी ट्रेड का लगभग आधा या 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर अप्रभावित था।[2] लीवरेज् पोजीशन फिर से बनाई गई हैं। जोखिम उठाना फिर से शुरू हो गया है, हालांकि अक्टूबर में मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने से इक्विटी बाजार की धारणा को कम कर दिया है और पण्य खासकर सोने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है।

III. वैश्विक जोखिमों का आकलन:

III.1. भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार और समग्र नीति अनिश्चितता

हम भारतीय रिज़र्व बैंक में, वैश्विक जोखिमों की (1) समाचार पत्रों के आलेखों के माध्यम से प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखनेवाले भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक[3]; (2) व्यापार नीति अनिश्चितता और बढ़े हुए व्यापार तनावों का उल्लेख करने वाले आलेखों की आवृत्ति को शामिल करनेवाले व्यापार नीति अनिश्चितता (टीपीयू) सूचकांक[4]; और (3) वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) सूचकांक[5] जो पीपीपी-समायोजित आधार पर वैश्विक उत्पादन का लगभग 71 प्रतिशत और बाजार विनिमय दरों पर लगभग 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करनेवाले 21 देशों के लिए राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांकों का जीडीपी-भारित औसत है - के माध्यम से बारीकी से निगरानी रखते हैं। जीईपीयू सूचकांक वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर नीति-संबंधी अनिश्चितता के प्रभाव का आकलन करता है।

ये सूचकांक[6] सामूहिक रूप से इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि व्यापार, भू-राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक नीति उपायों से उत्पन्न अनिश्चितता वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थितियों को कैसे प्रभावित कर सकती है, जो संभावित रूप से भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को प्रभावित कर सकती है।

2024 के मध्य तक, जीईपीयू सूचकांक ऊंचा बना हुआ है, जो दुनिया भर में आर्थिक नीतियों के बारे में चल रही चिंताओं को दर्शाता है। नवंबर 2023 से टीपीयू सूचकांक भी बढ़ रहा है जो विशेष रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव और नीतिगत परिवर्तनों से प्रभावित है। इस बीच, जीपीआर सूचकांक महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिमों की ओर इशारा करता है, जिसमें हाल ही में चल रहे संघर्षों के कारण वृद्धि हुई है।

मध्य पूर्व में तनाव ने महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक - स्वेज नहर (यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग) के माध्यम से व्यापार को बाधित कर दिया है। वैश्विक समुद्री व्यापार की मात्रा का लगभग 15 प्रतिशत सामान्य रूप से स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इसके बजाय, कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के आसपास मोड़ दिया है, जिससे डिलीवरी का समय औसतन 10 दिन या उससे अधिक बढ़ गया है। इन व्यवधानों के कारण चीन-यूरोप और चीन-अमेरिका पश्चिमी तट जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों पर माल ढुलाई की दरें भी बढ़ गई हैं, जो महामारी से पहले के स्तर से 3 गुना बढ़ गई हैं।

III.2. वैश्विक वित्तीय स्थितियां

वैश्विक वित्तीय स्थिति सूचकांक (जीएफसीआई) वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ऋण की लागत और उपलब्धता का प्रतिनिधित्व करता है[7]। जीएफसीआई ऋण प्रसार, आस्ति कीमतों और मुद्रा, बॉन्ड और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता में आम अव्यक्त कारकों के सह-आंदोलन को दर्शाता है - वे तनाव की अवधि के दौरान एक साथ चलते हैं। जीएफसीआई ने 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट, 2011-12 के दौरान यूरोजोन ऋण संकट और कोविड-19 महामारी के दौरान हाल के अनुभव के दौरान देखी गई सख्त वित्तीय स्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले प्रकरणों के विपरीत, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान सख्त वित्तीय स्थितियों को तुरंत उलट दिया गया, जो समकालिक मौद्रिक नीति कार्यों को दर्शाता है।

[2] https://www.ft.com/content/c6596fdd-d184-4dee-b6ff-f70c7081003a

[3] कैलडारा, डी., और लैकोविएलो, एम. (2022)। भू-राजनीतिक जोखिम को मापना। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 112(4), 1194-1225.

[4] कैलडारा, डी., लैकोविएलो, एम., मोलिगो, पी., प्रेस्टिपिनो, ए., और रैफ़ो, ए. (2020). व्यापार नीति अनिश्चितता के आर्थिक प्रभाव. जर्नल ऑफ़ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, 109, 38-59.

[5] प्रत्येक राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांक आर्थिक नीति अनिश्चितता पर चर्चा करने वाले समाचार पत्र लेखों की आवृत्ति को मापता है, जिसे 1997 से 2015 तक 100 के औसत पर सामान्यीकृत किया जाता है. कृपया बेकर, एस.आर., ब्लूम, एन., और डेविस, एस.जे. (2016) देखें। आर्थिक नीति अनिश्चितता को मापना। दी क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 131(4), 1593-1636.

[6] 6 ये सभी सूचकांक https://www.policyuncertainty.com / द्वारा बनाए गए हैं।

[7] सूचकांक को Z-स्कोर के रूप में बनाया गया है, जैसे कि सकारात्मक मूल्य आसान वित्तीय स्थितियों द्वारा रेखांकित सुस्थिर समय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कम लागत और वित्तपोषण की आसान उपलब्धता, जबकि नकारात्मक मूल्य सख्त वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है।

III.3. वित्तीय बाजार प्रभाव-विस्तार

वैश्विक प्रभाव-विस्तार आमतौर पर वित्तीय बाजार चैनल के माध्यम से भारत में मुख्य रूप से इक्विटी और मुद्रा खंडों में प्रेषित होते हैं। इसलिए, इन बाजार खंडों में अस्थिरता प्रभाव-विस्तार को डाइबोल्ड-यिलमाज़ कनेक्टेडनेस दृष्टिकोण (2009; 2012)[8] के आधार पर 21 प्रमुख इक्विटी बाजारों और 22 प्रमुख मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मापा गया) पर उच्च आवृत्ति डेटा का उपयोग करके निर्मित समय-भिन्न सूचकांकों के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। सूचकांकों का मार्ग मोटी रेखाओं (यानी, माध्यिका) द्वारा दिखाया गया है जबकि सूचकांकों के आसपास का छायांकित क्षेत्र बाजारों में प्रभाव-विस्तार की सीमा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, इक्विटी और मुद्रा बाजार दोनों खंडों में वैश्विक अस्थिरता प्रभाव-विस्तार 2020 के दौरान दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के फैलने से और पुनः रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया।

IV. भारत के लिए आशय

IV.1. आर्थिक नीति अनिश्चितता

इन वैश्विक सूचकांकों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत के लिए एक नया टेक्स्ट माइनिंग-आधारित नीति अनिश्चितता सूचकांक तैयार किया गया है और उसे अद्यतन किया गया है। यह सूचकांक घरेलू और वैश्विक दोनों घटनाओं के कारण नीति अनिश्चितता का एक माप बनाने के लिए गूगल ट्रेंड से इंटरनेट खोज डेटा का उपयोग करता है। सूचकांक वास्तविक समय में अद्यतन किया जाता है।[9]

भारत के लिए तिमाही आंकड़ों पर संरचनात्मक वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (एसवीएआर) ढांचे में सूचकांक पर एक मानक विचलन आघात लागू करने से एक दिलचस्प परिणाम मिलता है। अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, शोध से पता चलता है कि अनिश्चितता के झटके कम उत्पादन और कम कीमतों का कारण बनते हैं।[10] हालाँकि, भारतीय संदर्भ में, अनिश्चितता के झटके कुल आपूर्ति झटकों की नकल करते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई अनिश्चितता धीमी वृद्धि लेकिन उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है। विभिन्न उपायों और पहचान दृष्टिकोणों का उपयोग करके कई अध्ययनों द्वारा इन परिणामों की पुष्टि की गई है।[11] यह मौद्रिक नीति के लिए एक दुविधा प्रस्तुत करता है: उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए से कड़ा करें या कम वृद्धि की प्रतिक्रिया में इसे आसान करें।

IV.2. आपूर्ति श्रृंखला दबाव

फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 27 से अधिक चरों को एकीकृत करके विकसित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) भी भारतीय परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक पाया गया है। हमने 19 घरेलू और वैश्विक चरों से सामान्य कारकों को निकालकर भारत को प्रभावित करने वाले आपूर्ति श्रृंखला दबावों को ट्रैक करने के लिए जीएससीपीआई में प्रयुक्त कार्यप्रणाली के आधार पर भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबावों का एक सूचकांक (आईएसपीआई) विकसित किया है। आईएसपीआई औद्योगिक उत्पादन और जीडीपी का कुशलतापूर्वक पूर्वानुमान लगाता है और निर्यात मात्रा एवं मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है - आपूर्ति श्रृंखला दबाव औद्योगिक उत्पादन और कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। महामारी के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद की अवधि में महत्वपूर्ण उछाल देखने के बाद, वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला दबाव 2023 की शुरुआत से सामान्य या सामान्य से कम स्तर के आसपास मँडरा रहे हैं। उनकी सापेक्ष नरमी ने वैश्विक और दोनों स्तरों पर मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

IV.3. भू-आर्थिक विखंडन और व्यापार प्रवाह

वैश्विक अनिश्चितता विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि पर भी असर डालती है। बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम के एपिसोड के दौरान, विशेष रूप से फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और अक्टूबर 2023 से मध्य पूर्वीय क्षेत्रों में तनाव के

[8] डाइबोल्ड, एफ. एक्स., और यिलमाज़, के. (2009)। वैश्विक इक्विटी बाजारों में अनुप्रयोग के साथ वित्तीय आस्ति विवरणी और अस्थिरता प्रभाव-विस्तार को मापना। आर्थिक जर्नल, 119 (534), 158-171।

- डाइबोल्ड, एफ. एक्स., और यिलमाज़, के. (2012)। लेने की तुलना में देना बेहतर है: अस्थिरता प्रभाव-विस्तार का पूर्वानुमानात्मक दिशात्मक माप। इंटरनैशनल जर्नल ऑफ फोरकास्टिंग, 28(1), 57-66।

[9] जब अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो आर्थिक एजेंटों के लिए अधिक जानकारी के लिए 'खोज' करना आम बात है। गूगल ट्रेंड्स-आधारित अनिश्चितता सूचकांक (भारत-जीयूआई) भारत में राजकोषीय, मौद्रिक और व्यापार नीति से संबंधित कीवर्ड की सूची के लिए इंटरनेट खोज मात्रा का उपयोग करके समग्र अनिश्चितता को मापने के लिए इस व्यवहार का लाभ उठाता है। नीति-संबंधी कीवर्ड केंद्रीय बैंक के नीति वक्तव्यों में उल्लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रेस में कवरेज के आधार पर क्यूरेट किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रताप, बी., और प्रियरंजन, एन. (2023) देखें। अनिश्चितता के मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभाव: भारत के लिए गूगल ट्रेंड्स-आधारित विश्लेषण। अनुभवजन्य अर्थशास्त्र, 65(4), 1599-1625।

[10] लेडुक, एस., और लियू, जेड. (2016)। अनिश्चितता के झटके समग्र मांग के झटके हैं। मौद्रिक अर्थशास्त्र की पत्रिका, 82, 20-35; कुमार, ए., मलिक, एस., और सिन्हा, ए. (2021)। क्या अनिश्चितता हर जगह एक जैसी है? उन्नत बनाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं। आर्थिक मॉडलिंग, 101, 105524.

[11] प्रताप, बी., और प्रियरंजन, एन. (2023), ऑप सीआईटी।

बढ़ने के बाद भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात की मात्रा में वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। भारत के व्यापारिक निर्यात में 2023-25 (सितंबर 2024 तक) के दौरान औसतन 1.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

IV.4. जोखिम विश्लेषण पर पूंजी प्रवाह

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत में इक्विटी प्रवाह द्वारा प्रेरित पूंजी प्रवाह अपेक्षाकृत मजबूत रहा है, है। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने से ऋण प्रवाह में भी सुधार हुआ है।

जोखिम पर पूंजी प्रवाह (सीएआर) दृष्टिकोण विशिष्ट आघातों के प्रत्युत्तर में अपेक्षित पूंजी बहिर्वाह की मात्रा का आकलन करने के लिए एक उपयोगी संकेतक है।[12] पुश एंड पुल कारकों की प्रतिक्रिया में समय के साथ कर्नेल घनत्व कार्य या पूंजी प्रवाह का वितरण दर्शाता है कि सामान्य समय में, मजबूत पुल कारकों के मद्देनजर भारत से पूंजी पलायन की संभावना नगण्य है। वैश्विक वित्तीय संकटों की नकल करने वाले यूएस सीबीओई वीआईएक्स को लगा एक झटका पूंजी प्रवाह के वितरण को एकसमान करता है और वितरण की परिमितता को बढ़ाता है। यह जीएफसी जैसी उच्च तीव्रता वाली सामान्येतर जोखिम घटनाओं में पूंजी बहिर्वाह की उच्च संभावना को इंगित करता है।

भारत के मामले में पूंजी प्रवाहों के लिए अनुमानित सामान्येतर जोखिम (5 प्रतिशत पर सीएआर) उच्च पाई गई हैं और वे जीएफसी और टेपर टैंट्रम अवधि के दौरान वास्तविक पूंजी बहिर्वाह के साथ मेल खाते हैं। यह विश्लेषण हमें आरक्षित निधि की पर्याप्तता का यथार्थवादी मूल्यांकन करने में मदद करता है।

IV.5. वित्तीय बाजार में अस्थिरता का प्रभाव-विस्तार और वापसी

शेष विश्व से भारतीय इक्विटी और मुद्रा बाजारों में निवल अस्थिरता के प्रभाव - विस्तार के समय-भिन्न माप दर्शाते हैं कि निवल आधार पर, किसी भी अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था की तरह, भारत वैश्विक जोखिम बाह्यताओं के प्रभाव में है।[13] कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के छिड़ने के बाद, ये प्रभाव - विस्तार और बढ़ गए। हाल ही में, अलग-अलग मौद्रिक नीतियों ने इक्विटी बाजारों में कम गंभीर प्रभाव - विस्तार पैदा किए हैं, लेकिन वे मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण बने रहे। "स्पिलबैक" के उदाहरण - भारत द्वारा बाकी दुनिया में अस्थिरता संचारित करना - दुर्लभ बने हुए हैं।

IV.6. वैश्विक घटनाक्रम और वित्तीय प्रणाली दबाव

हम भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र तनाव स्तर की निगरानी के लिए एक वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक (एफएसएसआई) भी संकलित करते हैं। एफएसएसआई में पाँच वित्तीय बाज़ार खंडों - इक्विटी; विदेशी मुद्रा; मुद्रा; सरकारी ऋण; और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार और वित्तीय मध्यस्थ खंडों के तीन समूहों - बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी); और म्यूचुअल फ़ंड से संबंधित जोखिम कारक शामिल हैं।[14] इसमें वास्तविक क्षेत्र घटक भी शामिल है, जिसमें वास्तविक चर शामिल हैं, जिनका वित्तीय क्षेत्र के साथ उनके मजबूत अंतर्संबंधों के कारण वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। कुल मिलाकर, नौ बाज़ारों/क्षेत्रों में फैले 39 जोखिम कारकों पर विचार किया जाता है। एफएसएसआई का उद्देश्य (ए) दबाव की अवधि की पहचान करना; (बी) वित्तीय प्रणाली में दबाव की तीव्रता और अवधि का आकलन करना; और (सी) वित्तीय बाज़ारों और मध्यस्थों की आघातों और असंतुलनों को झेलने की क्षमता का आकलन करना है। एफएसएसआई ने अतीत में प्रमुख दबाव घटनाओं पर नज़र रखी है। नवीनतम

[12] इस ढांचे में, सबसे पहले, विभिन्न क्वांटाइल्स के लिए पूंजी प्रवाह का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्वांटाइल रिग्रेशन का उपयोग करके पूंजी प्रवाह के विभिन्न क्वांटाइल्स और उनके चालकों के बीच एक लिंक स्थापित किया जाता है। दूसरे चरण में, भविष्य के पूंजी प्रवाह के अनुभवजन्य वितरण को प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमानित पूंजी प्रवाह का उपयोग किया जाता है। फिर अनुभवजन्य वितरण से एक निश्चित संभावना (यानी, आमतौर पर 5 प्रतिशत) के लिए बहिर्वाह के आकार का अनुमान लगाकर पूंजी प्रवाह के जोखिमों को निर्धारित किया जाता है। कम और उच्च क्वांटाइल्स के पूर्वानुमानित पूंजी प्रवाह समय के साथ सीएआर की गतिशीलता को दर्शाते हैं। विवरण के लिए, कृपया पात्र, एम.डी., बेहरा, एच. और मुदुली, एस. (2022) देखें। जोखिम में पूंजी प्रवाह: भारत का अनुभव। आरबीआई बुलेटिन, जून।

[13] जबकि माप के नकारात्मक मूल्य यह दर्शाते हैं कि भारत बाकी दुनिया से प्रभाव-विस्तार "प्राप्त करता है"; सकारात्मक मूल्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत बाकी दुनिया में प्रभाव-विस्तार "संचारित" करता है। कृपया गुप्ता, आर. के., प्रताप बी., राउत एस., और सोना, टी. (2024) देखें। वैश्विक वित्तीय बाजारों के बीच अंतर-संबंध को मापना: भारत के लिए एक अध्ययन। आरबीआई मासिक बुलेटिन, भारतीय रिज़र्व बैंक (आगामी)।

[14] जोखिम कारकों को उन चरों में परिवर्तित करके न्यूनतम-अधिकतम विधि द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है जो इकाई मुक्त होते हैं और शून्य और एकता के बीच क्रमिक पैमाने पर मापे जाते हैं। प्रत्येक बाजार/क्षेत्र के लिए परिवर्तित जोखिम कारकों को एक उप-संकेतक 'y_i' में समान भार का उपयोग करके एकत्रित किया जाता है, जो i^{th} बाजार/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। समग्र एफएसएसआई की गणना उप-संकेतकों को एकत्रित करके की जाती है, जो फिर से समान विचरण भारित औसत विधि पर आधारित होती है, जहां प्रत्येक उप-संकेतक 'y_i' का भार 'w_i' उसके नमूना मानक विचलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसे $w_i = \frac{\frac{1}{si}}{\sum_{i=1}^{9}(\frac{1}{si})}$ रूप में निर्धारित किया जाता है। समग्र एफएसएसआई को $FSSI_t = \sum_{i=1}^{9} w_i y_{it}$. रूप में प्राप्त किया जाता है। एफएसएसआई के उच्च मूल्य अधिक दबाव का संकेत देते हैं। [विवरण के लिए बॉक्स 1.1 देखें: वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2022, आरबीआई)।

एफएसएसआई अपडेट के अनुसार, भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद से वित्तीय प्रणाली दबाव में लगातार गिरावट देखी है।

V. भारत के लिए दृष्टिकोण

V.1. संवृद्धि

इस पृष्ठभूमि में, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण की ओर मुड़ता हूँ। हमारा मानना है कि वैश्विक जोखिमों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धान्तों को मजबूत करना और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों द्वारा समर्थित पर्याप्त बफर का निर्माण करना है।

जैसा कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो ने कहा था: एक विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया है। उस प्रभावशाली टिप्पणी से प्रेरणा लेते हुए, मैं अपने दृढ़ विश्वास से मानता हूं कि भारत का समय आ गया है। भारत 28 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया की सबसे युवा आबादी के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के कई देशों के विपरीत, भारत में कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ रही है - हर छठा कामकाजी उम्र का व्यक्ति भारतीय है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से, भारत के संवृद्धि पथ में प्रवृत्ति संवृद्धि में 2002-2019 के दौरान 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ तीन संरचनात्मक बदलाव हुए हैं । महामारी में तीव्र संकुचन के बाद, 2021-24 के दौरान औसतन 8 प्रतिशत की एक नई संवृद्धि दर गति बनती दिख रही है। भारत को अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था माना जाता है। बाजार विनिमय दरों के मामले में यह पहले से ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2030 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

क्रय शक्ति समता के मामले में यह पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे अनुमानों से पता चलता है कि महामारी से उबरने के चक्रीय सुधार में भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 2024-25 में 7.2 प्रतिशत और 2025-26 में लगभग 7.0 प्रतिशत होगी। इसके बाद, इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत की संवृद्धि 8 प्रतिशत की प्रवृत्ति पर वापस आ जाएगी।

V.2. मुद्रास्फीति

वर्ष 2016 से भारत ने अपनी मौद्रिक नीति रूपरेखा के रूप में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) को अपनाया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हेडलाइन मुद्रास्फीति के संदर्भ में +/- 2 प्रतिशत की सहनशीलता बैंड के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यूक्रेन में युद्ध के बाद, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। नीति दर में संचयी 250 बीपीएस वृद्धि और समायोजन वापसी की प्रवृत्ति के साथ फ्रंटलोडेड मौद्रिक नीति सख्त होने से मुद्रास्फीति 2023-24 में औसतन 5.4 प्रतिशत तक गिर गई, यानी सहनशीलता बैंड में वापस आ गई। 2024-25 में इसके औसतन 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जुलाई-अगस्त के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे गिर गई, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी और वर्ष-दर-वर्ष माप में निहित प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण सितंबर में यह बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई। हमारा अनुमान दर्शाता है कि ये मूल्य दबाव अक्टूबर और नवंबर में बने रहेंगे, इससे पहले कि हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 से लक्ष्य के साथ फिर से संरेखित हो जाए और 2025-26 में संरेखित रहे।

V.3. वित्तीय सुदृढ़ता और बफर में सुधार

वर्ष 2018 से भारत वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता को मज़बूत करने तथा पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर बनाने में गहन रूप से लगा हुआ है। मान्यता, पुनर्गठन, समाधान और बट्टे खाते में डालने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंकों की तुलन पत्रों में हानि को कम किया गया है। जून 2024 के अंत में सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ कुल आस्तियों का केवल 2.7 प्रतिशत थीं। प्रावधानों के लिए समायोजित, निवल गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात केवल 0.6 प्रतिशत था। भारत में बेसल न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8 प्रतिशत के मुकाबले टियर I पूंजी के लिए कम से कम 7 प्रतिशत के साथ 9 प्रतिशत का न्यूनतम अनुपात लागू किया जाता है। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होगा, जिससे समग्र विनियामक पूंजी आवश्यकता कुल जोखिम भारित आस्तियों का 11.5 प्रतिशत हो जाएगी। जून 2024 के अंत में, भारत में बैंकों ने 13.9 प्रतिशत की टियर I पूंजी के साथ 16.7 प्रतिशत का पूंजी अनुपात बनाए रखा। अन्य बफर में चलनिधि कवरेज अनुपात शामिल है, जो 100 प्रतिशत से काफी ऊपर है, और प्रावधान कवरेज अनुपात जो 80 प्रतिशत के करीब है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से

पता चलता है कि भारत में कोई भी बैंक गंभीर दबाव के तहत भी विनियामक न्यूनतम पूंजी से नीचे नहीं जाएगा।

V.4 बाह्य क्षेत्र संकेतक

चूँकि बाह्य क्षेत्र को वैश्विक प्रसार-प्रभाव से पहला झटका लगता है, इसलिए बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता का निर्माण करने का नीतिगत प्रयास रहा है। चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग मामूली 1 प्रतिशत है। भारत अपने मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और स्थिरता के कारण पूंजी प्रवाह का प्राप्तकर्ता रहा है। इसलिए बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जाता है। भारत ने विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का निर्माण करने के लिए सुप्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के हितों से प्रेरित अवसर का उपयोग किया है। वर्तमान में, दुनिया में चौथे सबसे बड़े आरक्षित निधि रखने वाले देश के रूप में, भारत की आरक्षित निधियां पूरी तरह से बाहरी ऋण स्तर को कवर करती हैं, सभी ऋण सेवाएं आवश्यकताओं को आसानी से कवर करती हैं और 12 महीने के आयात के बराबर या उसके करीब हैं। भारत की विनिमय दर दुनिया में सबसे कम अस्थिर है। हम विनिमय दर के स्तर पर किसी भी दृष्टिकोण के बिना वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने और अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में दोनों तरफ से हस्तक्षेप करते हैं - बेचते और खरीदते हैं।

VI. निष्कर्ष

अंत में, मैं कुछ ऐसे अवसरों के बारे में संक्षेप में बात करूँगा जो भारतीय संदर्भ में हाल ही में खुले हैं। भारत परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में एक विश्व नेता के रूप में उभर रहा है। जेएमए की त्रिमूर्ति - जन धन (बुनियादी नो-फ्रिल्स खाते); आधार (सार्वभौमिक विशिष्ट पहचान); और मोबाइल फोन कनेक्शन - औपचारिक वित्त के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लक्ष्यीकरण सक्षम बना रहे हैं। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), एक निरंतर प्रणाली है जो किसी भी सहभागी बैंक के एकल मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है, अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन को निर्बद्ध रूप से आगे बढ़ा रही है। भारत में भुगतान प्रणाली 24x7x365 आधार पर काम करती है। ऑफ़लाइन भुगतान, फीचर फोन के माध्यम से भुगतान और संवादात्मक भुगतान जैसी कार्यक्षमताएँ शामिल की गई हैं। यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इन विकासों को ध्यान में रखते हुए, डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके भारत के लिए डिजिटलीकरण का सारांश माप तैयार किया गया है।[15] सूचकांक बढ़ रहा है, जो निर्बाध डिजिटल क्रांति को दर्शाता है।

डिजिटलीकरण के प्रसार ने अर्थव्यवस्था पर डिजिटलीकरण के प्रभावों और मौद्रिक नीति के संचरण के आकलन पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। भारत के लिए शुरुआती परिणाम फिलिप्स वक्र के तेज होने और कारक उत्पादकता में सुधार का संकेत देते हैं, जो मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता में सुधार का संकेत देते हैं।

भारत आगे बढ़ रहा है जो अपनी आकांक्षाओं की खोज में तेजी से बदल रहा है। जैसा कि मैंने विभिन्न ताकतों का यहां पर एकत्रित वर्णन किया है, यह सदी विश्व मंच पर भारत के उत्थान को चिह्नित कर सकती है।

धन्यवाद।

---

[15] यह सूचकांक डिजिटल भुगतान, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या, मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या, प्रति 100 व्यक्तियों पर उत्पन्न क्यूआर कोड की संख्या, सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण, आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) में निवेश और आईसीटी क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर आधारित है।

*डिजिटल युग में विकास की नई सीमाओं को छूना**

माइकल देवब्रत पात्र

I.भूमिका

भौतिक विज्ञान में इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार ने हमारे काम करने और जीने के तरीके में क्रांति लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका को महत्व दिया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एआई और रोबोटिक्स निरपेक्ष नवाचार की एक नई लहर की शुरुआत करेंगे, जैसे भाप शक्ति और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में हुआ।[1] चुपचाप, नई प्रौद्योगिकियाँ भिन्न-भिन्न व्यापक आर्थिक और नीतिगत मार्गों, भू-राजनीतिक तनावों, भू-आर्थिक विखंडन और जलवायु परिवर्तन की विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता सुझा रही हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था उलझी हुई है। तदनुसार, ये प्रौद्योगिकियाँ एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर रही हैं, जो यकीनन कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यम-आय के जाल से बाहर निकलने की कुंजी है।[2] यह अनुमान लगाया गया है कि जनरेटिव एआई अगले तीन वर्षों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7-10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकता है।[3] बड़े भाषा मॉडल से श्रमिकों के उत्पादकता स्तर में 8 से 36 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।[4]

पिछले तीन दशकों में, डिजिटल क्रांति ने दुनिया को बदल दिया है, और पिछली सभी क्रांतियों को पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।[5] डिजिटल प्रौद्योगिकियां आर्थिक वृद्धि, रोजगार, उपभोक्ता कल्याण और जीवन स्तर पर अपने प्रभाव के माध्यम से हमारे जीवन को नया आकार दे रही हैं। ये प्रौद्योगिकियां नवाचार और उद्यमशीलता का लोकतंत्रीकरण कर रही हैं, पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में इनका विस्तार कम खर्चीला है और इन्हें नवप्रवर्तकों को उद्यमियों में बदलने के रूप में देखा जाता है।[6]

भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) डिजिटल भुगतान को गति दे रही है। इंडिया स्टैक वित्तीय समावेशन का विस्तार कर रहा है, बैंकिंग बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कर संग्रह दोनों शामिल हैं। जीवंत ई-बाजार उभर रहे हैं और अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का दसवां हिस्सा है; पिछले दशक में देखी गई वृद्धि दरों के अनुसार, यह 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद का पाँचवाँ हिस्सा बनने के लिए तैयार है।[7]

भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई), एक जीवंत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र और सबसे बड़ी एआई प्रतिभा आधारों में से एक सहित बढ़ती युवा आबादी के साथ नए विकास के रास्ते खोलने और मौजूदा लोगों को अनुकूलित करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। पूर्वानुमान बताते हैं कि जनरेटिव एआई वर्ष 2029-30 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 359-438 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा।[8] उत्पादन प्रक्रियाओं में एआई का भारतीय फर्मों का एकीकरण 2023 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 25 प्रतिशत हो गया।[9] भारत ने अपने सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए 1.25 ट्रिलियन रुपये की भी प्रतिबद्धता की है।[10]

* 13 नवंबर 2024 को जयपुर में 'भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और आर्थिक विकास' पर डीईपीआर सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। साक्षी अवस्थी, श्रीरूपा सेनगुप्ता, आशीष खोबरागड़े, हिमानी शेखर, अक्षरा अवस्थी, स्वास्तिक यादव, राजीब दास से प्राप्त बहुमूल्य टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव की संपादकीय सहायता के लिए आभार।

1 ब्रायनजॉल्फसन, ई., और मैकफी, ए. (2014)। दूसरा मशीन युग: शानदार प्रौद्योगिकियों के समय में काम, प्रगति और समृद्धि। डबल्यूडबल्यू नॉर्टन एंड कंपनी; हल्डेन, ए (2017)। उत्पादकता पहेलियाँ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भाषण।

2 वर्ल्ड बैंक। (2024)। मध्यम-आय जाल। वर्ल्ड डेव्लपमेंट रिपोर्ट।

3 जेपी मॉर्गन। (2024)। क्या जनरेटिव एआई एक गेम चेंजर है?

4 कल्याणी और होगन (2024) एआई और उत्पादकता वृद्धि: अन्य प्रौद्योगिकियों में ऐतिहासिक विकास से साक्ष्य। सेंट लुइस का फेडरल रिज़र्व बैंक।

5 संयुक्त राष्ट्र (2023)। वैश्विक विकास पहल डिजिटल सहयोग मंच का उद्घाटन सत्र।

6 पनगढ़िया, ए. (2022)। डिजिटल क्रांति, वित्तीय अवसंरचना और उद्यमिता: भारत का मामला। एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था, 2(2), 100027.

7 चंद्रशेखर, आर. (2023). इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री का संबोधन। 12 जून को पुणे में जीपीआई वैश्विक शिखर सम्मेलन।

8 अर्न्स्ट एंड यंग. (2023)। क्या जनरेटिव एआई भारत में अपने वादे को पूरा करना शुरू कर रहा है? भारत का एआई आइडिया अपडेट।

9 बिजनेस स्टैंडर्ड (2024)। एआई-नेतृत्व वाली फर्मों ने उच्च विकास की रिपोर्ट की, राजस्व, उत्पादकता में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल गईं. 15 अक्टूबर।

10 प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024)। प्रधानमंत्री ने 'इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में भाग लिया।

फिर भी, नई प्रौद्योगिकियों में चुनौतियां भी शामिल हैं: पारंपरिक प्रौद्योगिकियों और श्रम बाजार के संबंध में व्यवधान; संसाधन-तीव्रता - प्रौद्योगिकी, सीखने और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की मांग; संभावित साइबर खतरे और डेटा उल्लंघन; नैतिक चिंताएं, डेटा गोपनीयता और संभावित दुर्भावनापूर्ण उपयोग।

इन्हीं अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में मैंने अपने संबोधन के विषय के रूप में 'डिजिटल युग में विकास की नई सीमाओं को छूना' चुना है।

II. डिजिटलीकरण और उत्पादकता: विरोधाभास से निपटना

विकास में डिजिटलीकरण के योगदान को उत्पादकता पर इसके प्रभाव के माध्यम से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस गठजोड़ ने एक एनिमेटेड बहस छेड़ दी है। एक विचार है कि तकनीकी नवाचारों से मूर्त लाभ मायावी रहते हैं; जैसा कि रॉबर्ट सोलो ने कहा, "आप हर जगह कंप्यूटर युग देख सकते हैं लेकिन केवल उत्पादकता के आंकड़ों में।"[11] यह विरोधाभास केवल माप के मुद्दों तक ही सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि जनसांख्यिकीय रुझानों और धीमी गति से प्रसार से परे हो सकता है। "यथार्थवादी" दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि अकेले प्रौद्योगिकी उत्पादकता और प्रगति को नहीं चला सकती है; बल्कि, जो मायने रखता है वह वास्तविक अर्थव्यवस्था में इसका एकीकरण है। प्रगतिशील संस्थानों द्वारा समर्थित कौशल और रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त नीतियों के साथ एक विषम दृष्टिकोण, शायद भविष्य की ओर बढ़ने का सही तरीका होगा।

उत्पादकता पैटर्न डिजिटल सेवाओं और अमूर्त पूंजी की बढ़ती भूमिका से तेजी से आकार लेने की संभावना है। डिजिटल तकनीकों पर व्यावसायिक खर्च बढ़ रहा है।[12] डिजिटल आस्तियों (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या आईसीटी सहित) की कीमतों में तेजी से गिरावट जारी है, जिसने व्यवसायों को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाया है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति मिली है। तकनीकी नवाचार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विस्तार, सेवा वितरण में दक्षता लाभ और जोखिमों को कम करने के लिए डिजिटल नवाचारों का उपयोग करने के संदर्भ में वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। डिजिटलीकरण में गति और पारदर्शिता को बढ़ाते हुए प्रेषण भेजने की लागत को कम करके सीमा पार वित्तीय प्रवाह में सुधार करने की क्षमता भी है।

केएलईएमएस ढांचा मूल्य वर्धित और कुल कारक उत्पादकता में इसके प्रत्यक्ष योगदान के अलावा, श्रम और पूंजी की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसके योगदान को मापकर डिजिटलीकरण के प्रभावों का पता लगाने में मदद करेगा। एकत्रित पूंजी और श्रम को आईसीटी पूंजी, मानव पूंजी और अन्य पूरक निवेशों में अलग करना होगा जिसमें डिजिटल रूप से सक्षम निवेश और सेवाएं उत्पादन का इनपुट बनाती हैं। यह विघटन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जिसमें व्यापक जानकारी की अनुपलब्धता भी शामिल है।

केएलईएमएस वृद्धि लेखांकन अपघटन को लागू करते हुए, भारत के कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में आईसीटी क्षेत्र की हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ी है, विशेष रूप से आईसीटी का उपयोग करने वाली सेवाओं के लिए। उत्पादन वृद्धि में आईसीटी पूंजी का योगदान, जो 1981-91 के दौरान 5.0 प्रतिशत था, 1992-2000 के दौरान लगभग 16.0 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई। जीवीए में आईसीटी पूंजी का योगदान 2001-2010 के दौरान 14.3 प्रतिशत और 2011-2023 के दौरान 10.3 प्रतिशत हो गया। नई डिजिटल प्रौद्योगिकियां केएलईएमएस फ्रेमवर्क के भीतर श्रम उत्पादकता वृद्धि को भी प्रभावित करती हैं। भारत में श्रम उत्पादकता वृद्धि में प्रति व्यक्ति आईसीटी निवेश का हिस्सा वर्ष 1981-90 में 8.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 1992-2000 के दौरान बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गया लेकिन 2001-2010 के दौरान 17.4 प्रतिशत और 2011-23[13] के दौरान 11.3 प्रतिशत तक कम हो गया, जो जीएफसी अवधि के बाद के लिए सोलो के उत्पादकता विरोधाभास के कुछ प्रमाण दर्शाता है, जो वैश्विक स्तर पर समान रुझानों के साथ व्यापक रूप से संगत है।

[11] सोलो, आर., (1987) वी'ड बेटर वॉच आउट, न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू, 12 जुलाई, पृष्ठ 36।

[12] वैन आर्क, बी. (2016). नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का उत्पादकता विरोधाभास। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता मॉनिटर, 31, 3-18.

[13] चट्टोपाध्याय, एस. सेनगुप्ता, एस और जोशी, एस. (2024): नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास, आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर 2024.

2000 के दशक की शुरुआत में प्रौद्योगिकी बूम अवधि के अंत के बाद से, वैश्विक कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली बनी हुई है, वर्ष 2010-2024 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 0.2 प्रतिशत औसत रही।[14] वैश्विक उत्पादकता वृद्धि में कमजोरी ज्यादातर परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं, मुख्य रूप से यूरोप तक ही सीमित है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर एशिया में। कई परस्पर जुड़े कारकों ने उत्पादकता में मंदी को बढ़ा दिया है, जिसमें बढ़ती उम्र के समाज, सर्वकालिक उच्च ऋण स्तर, विशेष रूप से छोटी फर्मों के बीच व्यापार गतिशीलता में गिरावट और कोविड-19 महामारी के डरावने प्रभाव शामिल हैं।[15] नई बाधाएं - कमजोर निवेश; आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स व्यवधान; व्यापार और निवेश विखंडन - भी आवंटन दक्षता में लाभ के खिलाफ काम कर सकते हैं, जिससे वैश्विक उत्पादकता परिदृश्य के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

भारत के लिए, वर्ष 2021 से 2024 तक औसत श्रम उत्पादकता वृद्धि 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह 2.1 प्रतिशत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 0.6 प्रतिशत है।[16] भारत ने आईसीटी सेवाओं में अपनी आधारभूत ताकत का लाभ उठाते हुए डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति देखी है। जो आईटी सेवाओं की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ था, वह अब शक्तिशाली शाखा में बदल गया है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे मॉडल सक्षमकर्ता और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पुल के रूप में काम कर रहे हैं। वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पहले से ही भारत की तकनीकी प्रगति का फायदा उठा रहे हैं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार में भारत के पदचिह्न का विस्तार कर रहे हैं।

आईसीटी क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि, आईसीटी-उत्पादक और आईसीटी-उपयोग करने वाले दोनों उद्योगों ने वर्ष 1980 से 2020 के दौरान गैर-आईसीटी क्षेत्र से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, उत्पादकता पर आईसीटी का प्रभाव वर्ष 1980 से 2010 तक सबसे महत्वपूर्ण था।[17] अगले दशक में, यानी 2010 से 2020 तक, आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों के बीच उत्पादकता का अंतर काफी कम हो गया, जो वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद दुनिया भर में व्यापक उत्पादकता मंदी को दर्शाता है। इन निष्कर्षों की गहन जांच की आवश्यकता है, लेकिन वे डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बदलती गतिशीलता को रेखांकित करते हैं और इस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि हम तेजी से डिजिटल होती दुनिया में उत्पादकता वृद्धि को कैसे नवीनीकृत कर सकते हैं।

III. भारतीय वित्त का डिजिटलीकरण

भारतीय बैंकों के सर्वेक्षणों के सूक्ष्म-स्तरीय साक्ष्य से पता चलता है कि जबकि उन सभी ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को लागू किया है, 75 प्रतिशत ऑनलाइन खाता खोलने, डिजिटल केवाईसी और डिजिटल रूप से सक्षम डोरस्टेप बैंकिंग की पेशकश करते हैं। इसके अतिरिक्त, 60 प्रतिशत डिजिटल ऋण प्रदान करते हैं, 50 प्रतिशत भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करते हैं, 41 प्रतिशत चैटबॉट का उपयोग करते हैं, 24 प्रतिशत ने ओपेन बैंकिंग को अपनाया है, और 10 प्रतिशत ने एकीकृत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तकनीक को अपनाया है।[18] निजी क्षेत्र के बैंक इस प्रौद्योगिकी को अपनाने का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारतीय बैंकों की नवीनतम वार्षिक रिपोर्टों की एआई-सहायता प्राप्त समीक्षा से डिजिटलीकरण से एससीबी द्वारा उत्पादकता लाभ के विभिन्न उदाहरण सामने आए हैं। उदाहरणों में 14,500 व्यक्ति-दिनों की मासिक बचत, ग्राहक अधिग्रहण लागत में 25-30 प्रतिशत की कमी, 84 टन कागज के उपयोग में कमी, ग्राहकों द्वारा बैंकों तक आने-जाने में चार लाख लीटर ईंधन की बचत, शाखाओं में ग्राहकों के प्रतीक्षा समय में 40 प्रतिशत की कमी, अनुपालन निगरानी समय में 50 प्रतिशत की कमी और खाता खोलने के समय को एक दिन से भी कम करना शामिल है।[19] आधार - भारत की विशिष्ट पहचान संख्या - ने भारत में अपने ग्राहक को जानें प्रक्रिया के संचालन की लागत को आधा कर दिया है।[20]

[14] कुल अर्थव्यवस्था डेटाबेस (2024), सम्मेलन बोर्ड, https://data-central.conference-board.org/ के माध्यम से एक्सेस किया गया।

[15] डिएप्पे, ए. (एड.). (2021). वैश्विक उत्पादकता: रुझान, चालक और नीतियाँ। वर्ल्ड बैंक प्रकाशन।

[16] टोटल इकोनॉमी डेटाबेस (2024), कॉन्फ्रेंस बोर्ड, https://data-central.conference-board.org/ के माध्यम से एक्सेस किया गया।

[17] चट्टोपाध्याय, एस. सेनगुप्ता, एस और जोशी, एस. (2024): नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास, आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर 2024।

[18] भारतीय रिज़र्व बैंक। (2024)। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24: भारत की डिजिटल क्रांति.

[19] चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) से स्रोत।

[20] भारत सरकार, 2024 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अक्टूबर 2024 में एक महीने में 16.6 बिलियन लेनदेन की उपलब्धि हासिल की, जिसमें 86 प्रतिशत (पिछले साल इसी महीने में 77 प्रतिशत) पर सफल इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल जैसी क्षमताओं में सुधार हुआ। डिजिटल क्रेडिट परिदृश्य में नवाचारों जैसे खाता एग्रीगेटर, ओसीईएन,[21] और ओएनडीसी[22] पर वित्तीय सेवाओं ने भी उत्पादकता लाभ में योगदान दिया है। मार्च 2024 तक, ओएनडीसी 49.72 मिलियन ऑर्डर के साथ 720 से अधिक शहरों में काम करता है।[23] ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) लगभग 52.2 ट्रिलियन अनुमानित एमएसएमई के ऋण अंतराल को बैंकों और ग्राहकों के साथ जोड़कर संबोधित करता है, जिसमें फंडिंग लागत में 2.5 प्रतिशत अंक तक की कमी होती है।[24] टीआरईडीएस के माध्यम से वित्तपोषित चालानों का मूल्य 23 गुना से अधिक बढ़ गया है। अक्टूबर 2024 तक, लगभग 5,000 सक्रिय फिनटेक एमएसएमई सहित व्यवसायों को विभिन्न वित्तीय और तकनीकी समाधान प्रदान करने में शामिल हैं, जो व्यवसायों को अपने संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और आपूर्ति श्रृंखला वित्त में सुधार करने में मदद करते हैं।[25]

भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40 प्रतिशत और कुल आबादी में 20-30 वर्ष आयु वर्ग के 78 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लगभग एक तिहाई परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी में लगे हुए हैं, एक चौथाई उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद में और लगभग दसवां हिस्सा खाद्य पदार्थों की खरीद में लगे हुए हैं।[26] एम्बेडेड फाइनेंसिंग का बढ़ता महत्व फिनटेक फंडिंग में इसकी हिस्सेदारी में परिलक्षित होता है, जो 2020 में दो प्रतिशत से बढ़कर 2024 में नौ प्रतिशत हो गया है।[27] एम्बेडेड फाइनेंस के लिए वैश्विक बाजार का अनुमान 2022 में 66.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2023 से 2032 तक 25.4 प्रतिशत की सीएजीआर का अनुभव करने का अनुमान है।[28]

डिजिटलीकरण सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में बदलाव ला रहा है। 2024 में, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए दैनिक ई-लेनदेन की औसत संख्या में 56 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है। 29 वर्ष 2023-24 के दौरान, 314 योजनाओं के तहत डिजिटल रूप से संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹6.9 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे 176 करोड़ लाभार्थियों को लाभ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, इन डीबीटी के परिणामस्वरूप मार्च 2023 तक ₹3.5 लाख करोड़ की अनुमानित संचयी लागत बचत हुई है।[30]

IV. डिजिटलीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) डिजिटलीकरण के मामले में सबसे आगे रहा है, जिसका लक्ष्य वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। डिजिटल भुगतान में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्रमशः 2004 और 2005 में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र (एनईएफ़टी) की शुरुआत हैं - जो अब 365*24*7 संचालित होते हैं - इसके बाद 2008 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) की स्थापना की गई।

2016 में यूपीआई का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके सकारात्मक बाहरी प्रभाव हमारी राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पायलटों परियोजनाओं को पेश करके और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करके वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देना जारी रखा है। रिज़र्व बैंक ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (यूएलआई) नामक एक नए प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म की भी घोषणा की है, जो दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करके और ऋण आवेदन प्रक्रिया को

[21] ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क।

[22] डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क।

[23] और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24।

[24] बिजनेस स्टैंडर्ड, 2024 आरबीआई का 'TReDS' प्लेटफॉर्म छोटी फर्मों के लिए $600 बिलियन के फंडिंग गैप को पाट रहा है। 22 अक्टूबर।

[25] डेटाबेस पर आधारित, 17 अक्टूबर, 2024 तक एक्सेस किया गया।

[26] उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 यूनिट स्तर के आंकड़ों के आधार पर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[27] 22 अक्टूबर को एक्सेस किए गए ट्रक्सन डेटाबेस के आधार पर।

[28] पीडब्ल्यूसी, 2024. एम्बेडेड फाइनेंस: एक रणनीतिक दृष्टिकोण।

[29] आरबीआई स्टाफ का अनुमान एटाल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2024 के मुकाबले 2023 के लिए है।

[30] प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)। 2024 होमपेज। https://dbtbharat.gov.in से लिया गया

सरल बनाकर छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उधारकर्ताओं जैसी वंचित आबादी के लिए ऋण को अधिक सुलभ बनाकर भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है।

भारत उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी निकटता से जुड़ा हुआ है जो प्रोजेक्ट नेक्सस और एमब्रिज जैसी पहलों के माध्यम से बहुपक्षीय निर्माण में विभिन्न देशों के ओपन फाइनेंस एपीआई-आधारित ढाँचों के जुड़ाव की खोज कर रहे हैं। भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी को जी20 सदस्यों और अतिथि देशों के वास्तविक अनुभवों से उपलब्ध प्रमुख सबक और ज्ञान के लिए संसाधन आधार के रूप में पेश किया गया है।

समग्र दृष्टिकोण जोखिम न्यूनीकरण और वित्तीय नवाचार के बीच संतुलन बनाना, हितधारकों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखना और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना रहा है[31] पांच नीतिगत प्राथमिकताएं रिज़र्व बैंक की भागीदारी को संचालित करती हैं: डिजिटल वित्तीय समावेशन; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई); ग्राहक संरक्षण और साइबर सुरक्षा; टिकाऊ वित्त; और वैश्विक एकीकरण और सहयोग।[32]

V. निष्कर्ष

डिजिटलीकरण का आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता के साथ संबंध जटिल है, जिसे अभी पूरी तरह से समझा जाना बाकी है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, श्रमिकों और पूंजी के बीच तालमेल बढ़ाकर और स्वचालन को बढ़ावा देकर टीएफ़पी लाभ उत्पन्न कर सकती हैं। अगर मजबूत संस्थानों, नीतियों और कौशलों द्वारा समर्थित किया जाए जो नवाचार का समर्थन करते हैं और प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करते हैं, तो उत्पादकता लाभ को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता कहीं अधिक हो सकती है। डिजिटलीकरण और नई प्रौद्योगिकियों की विकास-बढ़ाने वाली क्षमता का दोहन करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से जोखिम और प्रोत्साहन का कुशल संतुलन बनाना होगा ताकि व्यवधानों को कम करते हुए लाभ को बढ़ाया जा सके।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादकता लाभों का लाभ उठाकर नई वृद्धि ऊर्जा को अनलॉक करने में पूरक नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनमें प्राथमिकताएं निर्धारित करना शामिल होगा जैसे (i) फर्म की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार करके ज्ञान की सीमा का विस्तार करना; (ii) बाजार की एकाग्रता को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; और (iii) कुशल संसाधन पुनर्वितरण।[33] जैसा कि पॉल क्रुगमैन ने सटीक रूप से कहा, "उत्पादकता सब कुछ नहीं है, लेकिन लंबे समय में यह लगभग सब कुछ है।"[34]

धन्यवाद।

[31] रिज़र्व बैंक (2024)। मुद्रा और वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट: भारत की डिजिटल क्रांति।

[32] दास, एस. (2024)। भारत के लिए फिनटेक नवाचार @100: भारत के वित्तीय परिदृश्य के भविष्य को आकार देना। आरबीआई भाषण। 28 अगस्त, 2024।

[33] ओईसीडी, ई. (2019)। डिजिटलीकरण और उत्पादकता: पूरकताओं की कहानी।

[34] क्रुगमैन, पी. आर. (1997)। कम होती उम्मीदों का युग: 1990 के दशक में अमेरिकी आर्थिक नीति। एमआईटी प्रेस।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के लिए संतुलन विनिमय दरों के अनुमान हेतु एक उपागम समूह

भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार के बदलते परिदृश्य

भारतीय कृषि में कृषि-तकनीक स्टार्टअप और नवोन्मेष

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीता

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

कमज़ोर आत्मविश्वास और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच 2024 की चौथी तिमाही के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधि आघात-सहनीय रही। भारत में, 2024-25 की दूसरी तिमाही में देखी गई गति में कमी अब नहीं रही क्योंकि निजी खपत तीसरी तिमाही में वास्तविक गतिविधि को रोशन करने वाले त्योहारी व्यय के साथ घरेलू मांग का वाहक बनने के लिए तैयार है। घरेलू वित्तीय बाजारों में अमेरिकी डॉलर के लगातार बढ़ने और लगातार पोर्टफोलियो बहिर्वाह से इक्विटी के दबाव में आने से सुधार देखा जा रहा है। मध्यम-अवधि का परिदृश्य तेज बना हुआ है क्योंकि समष्टि-विवेकपूर्ण की ताकत खुद को फिर से स्थापित करती है। हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में ऊपरी सहनशीलता बैंड से ऊपर पहुंच गई, जिसमें कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य कीमतों की गति में तेज उछाल आया।

भूमिका

जैसा कि दुनिया के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर अक्टूबर 2024 के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक के लिए वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए, धीमी मुद्रास्फीति करना और चक्रीय असंतुलन में सहजता वैश्विक अर्थव्यवस्था की सॉफ्ट लैंडिंग का रास्ता साफ कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलिप्स वक्र के तीव्र होने से उत्पादन के आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन को सक्षम करते हुए मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक तेजी से गिरावट आई है।

हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2024 की चौथी तिमाही के दौरान अब तक मोटे तौर पर अपरिवर्तित परिदृश्य के साथ थोड़ी कम हुई है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में विनिर्माण गतिविधि के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में गिरावट आई, जबकि सेवाओं में मजबूती बनी रही। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, पीएमआई मिश्रित संकेत दे रहे हैं। एशिया के लिए, निर्यात में तकनीक-संचालित वृद्धि के साथ, वृद्धि को अपेक्षाओं के सापेक्ष मजबूती मिली है। इस मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, आईएमएफ का आकलन है कि एशियाई दृष्टिकोण के लिए जोखिम बढ़ गया है, मुख्य रूप से कमजोर बाहरी वातावरण और प्रतिकूल जनसांख्यिकी के कारण। मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है और कई क्षेत्रों में 2025 तक लक्ष्य तक पहुंचने का अनुमान है। एशिया में ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति मोटे तौर पर स्थिर रही है या पीछे हट रही है, लेकिन लैटिन अमेरिका में यह लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है क्योंकि सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी उनके महामारी-पूर्व औसत से लगातार मजबूत रही है।

फिर भी, बढ़ते ऋण स्तर - सार्वजनिक ऋण इस वर्ष 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संचालित है – परिदृश्य को धूमिल कर रहे हैं। आईएमएफ को उम्मीद है कि भविष्य में ऋण का स्तर वर्तमान अनुमान से अधिक हो सकता है। इसके विचार में, हाल के दशकों में राजकोषीय मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तेजी से उच्च सरकारी व्यय की ओर झुक गई है। राजकोषीय नीति में अनिश्चितता बढ़ गई है, और कराधान पर राजनीतिक सीमाएँ अधिक मजबूत हो गई हैं। हरित परिवर्तन, जनसंख्या की उम्र बढ़ने, सुरक्षा चिंताओं और लंबे समय से चली आ रही विकास चुनौतियों से निपटने के लिए व्यय का दबाव बढ़ रहा है। ऋणग्रस्तता के टिक-टिक टाइम बम के साथ-साथ, संभावित प्रभाव-विस्तार और बढ़ते युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की दोष रेखाओं को बदल रहे हैं।

परिणामस्वरूप, परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता का स्तर बढ़ गया है। व्यापार और राजकोषीय नीतियों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव की संभावना को लेकर चिंताएँ बहुत अधिक हैं। वित्तीय बाजार में अस्थिरता की वापसी ने छिपी हुई कमजोरियों और कुछ उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए राष्ट्रिक उधार के प्रसार के बारे में पुरानी आशंकाओं को जन्म दिया है। जैसा कि खंड II में चर्चा की गई है, वैश्विक वृद्धि की स्थिर होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी आघात-सहनीयता के बावजूद यह बराबर से नीचे है, अभी भी उच्च उधार लागत के कारण निजी ऋण और निवेश में बाधा आ रही है। यदि राजकोषीय समेकन शुरू किया जाता है, तो शुरुआती वर्षों में वृद्धि धीमी होने की संभावना है, लेकिन दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज़ ख़ान, बिस्वजीत मोहंती, बजरंगी लाल गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, हरेंद्र बेहरा, के एम नीलिमा, रिग्ज़िन यांगडोल, ऋषभ कुमार, राशिका अरोड़ा, मधुरेश कुमार, एट्टम अभिन्नू यादव, हर्षिता यादव, शैलजा भाटिया, शिवम, अंजली मारिया जोस, सुक्ति खांडेकर, सुभ्रदीप पॉल, श्रेया गुप्ता, अभिनंदन बोरड, सुनील कुमार, धीरेंद्र गजभिये, खुशी सिन्हा, युवराज कश्यप, सोनल यादव, कार्तिकेय भार्गव, अक्षरा अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

हालाँकि विश्व व्यापार अब तक स्थिर बना हुआ है और माल बाजारों में स्थिरता लॉजिस्टिक्स डील को पुनर्जीवित कर रही है, एक अधिक खंडित वैश्विक व्यापार परिदृश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आघात-सहनीयता को कम कर सकता है जो अब तक भूराजनीतिक तनावों के कारण कायम है। इसके अलावा, जैसे-जैसे संरक्षणवाद बढ़ता है, पूंजी का प्रवाह बाधित होता है। तदनुसार, कमजोर वैश्विक वृद्धि परिदृश्य मध्यम अवधि तक फैला हुआ है, जिससे पता चलता है कि संभावित उत्पादन स्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अधिक स्थायी निशान दिखा रही हैं। "वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम वृद्धि, उच्च ऋण पथ पर फंसने का खतरा है। इसका मतलब है कम आय और कम नौकरियाँ।"[1]

निकट अवधि की वित्तीय स्थिरता के जोखिम नियंत्रित हैं और वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल हैं। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण दीर्घकालिक सरकारी प्रतिफल में वृद्धि हुई और अमेरिकी डॉलर सितंबर में अपने हालिया निचले स्तर से मजबूत हुआ। अमेरिकी चुनाव से पहले की अस्थिरता को छोड़कर इक्विटी बाजारों में उछाल के साथ-साथ, क्रेडिट बाजार की स्थितियां सौम्य बनी हुई हैं, और स्प्रेड पूर्व-महामारी के औसत के मुकाबले बहुत कम हो गया है। हालाँकि, आय के प्रदर्शन की तुलना में मूल्य-निर्धारण बढ़ा हुआ है और विशेष रूप से गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों के बीच लीवरेज का उपयोग अनिश्चितता के साथ अस्थिरता की बढ़ती संभावना के साथ बढ़ गया है।

जैसे ही अमेरिकी चुनाव का परिणाम स्पष्ट हो गया, दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी आई, अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में उछाल आया, और अमेरिकी डॉलर ने 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी एक दिवसीय छलांग लगाई, जो व्यापार के बाद के दिनों में और भी अधिक हो गई। टैरिफ प्रस्तावों और संभावित प्रतिशोध के परिदृश्य में भयंकर व्यापार युद्धों की आशंका है - आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में चेतावनी दी है कि उच्च टैरिफ 2025 में 0.8 प्रतिशत और 2026 में 1.3 प्रतिशत आउटपुट को मिटा सकता है। अमेरिकी डॉलर में उछाल के सामने, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक उभरते बाजारों की मुद्राएं कमजोर होकर नए निचले स्तर पर पहुंच गईं और उन्होंने अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद चीन से प्रोत्साहन के एक नए दौर की तैयारी की, लेकिन घोषणाएं निराशाजनक रहीं और इसलिए अधिक की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में रिकॉर्ड स्तर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, जिसमें अमेरिकी खज़ाने में चुनाव पूर्व बिकवाली भी शामिल है, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी के दबाव में स्वर्ण की कीमतें गिर गईं, जबकि तांबे की कीमतों से चीनी युआन में भारी गिरावट आई। बिटकॉइन में रिकॉर्ड-तोड़ रैली ने भविष्य में व्युत्पन्नी में आसन्न जोखिम के नियमित आवर्तन का संकेत दिया। क्या ट्रंप के व्यापार का उत्साह बरकरार रहेगा जिसने व्यापारियों को ब्याज दरों के रास्ते पर अपनी अपेक्षाओं को फिर से खींचने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है? वर्ष की फेड की दूसरी ब्याज दर में कटौती का मुख्य कारण इक्विटी और अमेरिकी डॉलर में थोड़ी कमी और बॉण्ड में वृद्धि थी। स्वैप बाज़ारों से संकेत मिलता है कि वर्ष के शेष भाग में फेड द्वारा दरों को अपरिवर्तित रखने की एक महत्वपूर्ण संभावना है, विशेष रूप से अक्टूबर से अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इन सभी घटनाओं से पहले, ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में नियोजित वृद्धि को एक महीने के लिए पीछे धकेलने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जो कमजोर वैश्विक मांग पर व्यापक चिंताओं के बीच सावधानी का संकेत देता है, भले ही भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम हाल में कम हो गया हो। कुल मिलाकर, एक कमज़ोर आत्मविश्वास और संरक्षणवाद की ओर संभावित झुकाव पूर्ण वैश्विक सुधार में बाधा डालता है।

भारत में, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देखी गई गति में कमी पीछे रह गई है। निजी निवेश कमजोर है, जैसा कि कॉरपोरेट आय में कमी के कारण जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान अचल और गैर-चालू आस्तियों में क्रमिक रूप से कम निवेश में परिलक्षित होता है। फिर भी कर्मचारियों की लागत में वृद्धि में कमी और गैर-परिचालन आय में वृद्धि ने समाप्त होने के कगार पर तेल और गैस क्षेत्र और उच्च प्रदर्शन वाले वित्तीय सेवा क्षेत्र को छोड़कर भी निवल लाभ को बढ़ावा दिया। निजी उपभोग हालांकि मिश्रित स्थिति के साथ फिर से घरेलू मांग का वाहक बन गया है। त्योहारी खर्च ने तीसरी तिमाही में वास्तविक गतिविधि को बढ़ा दिया है, जैसा कि खंड III में बताया गया है जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तात्कालिक पूर्वानुमान के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों को ट्रैक करता है। मॉल में लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन नई पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ई-कॉमर्स कई तरह की मार्केटिंग रणनीतियों और ब्रांड रिकॉल पहलों के साथ बढ़ रहा

[1] वैश्विक नीति एजेंडा अक्टूबर 2024 प्रेस ब्रीफिंग आईएमएफ, 24 अक्टूबर 2024।

है। एफएमसीजी और ऑटो कंपनियां मांग को पुनर्जीवित करने के लिए विज्ञापन खर्च बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही, इस त्योहारी सीजन में ग्रामीण भारत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सोने की खान बनकर उभर रहा है; उम्मीद है कि ख़रीफ़ उत्पादन में तेज़ वृद्धि और रबी उत्पादन को लेकर आशावाद के कारण वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) ब्रांड अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और क्विक-कॉमर्स (क्यू-कॉम) प्लेटफार्मों-एक इको-सिस्टम जिसका मूल्य 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और वर्ष 2029-30 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसके माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए धन की तलाश कर रहे हैं।[2] खुदरा विक्रेता दूसरी तिमाही के सापेक्ष बिक्री वृद्धि में तेजी रिपोर्ट कर रहे हैं। इस दिवाली ई-दोपहिया वाहनों की धूम रही, हालांकि इसमें एक अलग प्रीमियमीकरण देखने को मिला है, जो कि लक्जरी कार सेगमेंट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश भर में नए शहर बढ़ रहे हैं और शहरी आबादी चार गुना बढ़ जाएगी - 2025 तक, भारत की आधी आबादी की शहरों में रहने की उम्मीद है, जिससे शहरी मांग बढ़ेगी। बस जरूरत इस बात की है कि मुद्रास्फीति को कम किया जाए ताकि भारत अपनी क्षमता के साथ फिर से जुड़ सके।[3]

सितंबर में बढ़ोतरी की चेतावनी के बाद अक्टूबर सीपीआई मुद्रास्फीति की रीडिंग एक बड़ा आघात साबित हुई, जिससे जुलाई और अगस्त के लिए उप-लक्ष्य परिणामों पर आरबीआई की चेतावनियों को बल मिला। चिंता की बात यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज उछाल के अलावा, कोर मुद्रास्फीति भी बढ़ी है। दूसरे क्रम के प्रभाव या उच्च प्राथमिक खाद्य कीमतों के प्रभाव-विस्तार के शुरुआती संकेत हैं - खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के बाद, प्रसंस्कृत खाद्य कीमतों के संबंध में मुद्रास्फीति में तेजी देखी जाने लगी है। घरेलू नौकरों/रसोइयों जैसी घरेलू सेवाओं की कीमतों में वृद्धि भी भोजन की ऊंची कीमतों के कारण जीवनयापन के उच्च दबाव को दर्शाती है, जो इन विशिष्ट मजदूरी तक पहुंचने लगी है।[4] इस माहौल में, वस्तुओं और सेवाओं में इनपुट लागत के बढ़ने और बिक्री कीमतों में उनके प्रवाह को ध्यान से देखने की जरूरत है, जैसा कि खंड III में विश्लेषण किया गया है। मुद्रास्फीति पहले से ही शहरी उपभोग मांग और कॉरपोरेट्स की कमाई और पूंजीगत व्यय को प्रभावित कर रही है। यदि इसे अनियंत्रित रूप से चलने दिया गया, तो यह वास्तविक अर्थव्यवस्था, विशेषकर उद्योग और निर्यात की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

जैसा कि खंड III में विस्तार से बताया गया है, भारत के निर्यात का दृष्टिकोण उज्ज्वल है। पिछले कुछ महीनों की धीमी वृद्धि प्रोफ़ाइल के तहत, भारत प्रमुख विनिर्माण वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। वास्तव में, भारत वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 13 प्रतिशत या छठा हिस्सा रखता है, जो बढ़ती रिफाइनिंग क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की क्षमता का प्रमाण है। यह बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का सबसे बड़ा निर्यातक, कीटनाशकों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक, रबर वायवीय टायरों में आठवां सबसे बड़ा और अर्धचालकों में नौवां सबसे बड़ा निर्यातक है।

2024-25 की पहली छमाही में, एप्पल ने लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत निर्मित आईफोन का निर्यात किया, जबकि ऑटोमोबाइल निर्यात में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों के कारण रहा। कई वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। समग्र निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में प्रीमियम मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों की संख्या का विस्तार करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पहले से ही, 1100 से अधिक जीआई उत्पाद एक-जिला-एक-उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से वैश्विक कुल लगभग 70,000 जीआई उत्पादों में से 640 का निर्यात किया जाता है।[5]

उत्पत्ति के नियमों और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। अनेक द्विपक्षीय समझौते भारत को वैश्विक विनिर्माण में 'चाइना प्लस वन' प्रवृत्ति का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। बाजार पहुंच में सुधार करना महत्वपूर्ण है - पिछले पांच वर्षों में, यह अनुमान लगाया गया है कि एफटीए भागीदारों (आसियान, संयुक्त अरब अमीरात, साफ्टा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मॉरीशस)

[2] बिजनेस स्टैंडर्ड, "डी2सी ब्रांड क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए धन जुटाते हैं", 23 अक्टूबर 2024।

[3] आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2024।

[4] सीपीआई (2012=100) ऑल इंडिया आइटम इंडेक्स, https://cpi.mospi.gov.in

[5] "चीन पर नज़र रखते हुए, भारत जीआई लिस्टिंग का विस्तार करेगा", मिंट, 20 अक्टूबर 2024।

से भारत का कुल आयात 37.9 प्रतिशत बढ़ा है जबकि निर्यात केवल 14.5 प्रतिशत बढ़ा है।[6]

भारत समुद्री व्यापार के लिए अपने लॉजिस्टिक्स में एक शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो मात्रा के हिसाब से भारत के व्यापार का 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 65 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में बंदरगाह क्षमता 745 मिलियन टन से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1,600 मिलियन टन से अधिक हो गई है। प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया है। टर्नअराउंड समय 2010 में 127 घंटे से गिरकर हाल ही में 53 घंटे हो गया है, न्हावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में केवल 21 घंटे है। इस अवधि में, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 54वें से बढ़कर 38वां हो गया है। भारत निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ी में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब की योजना बना रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक पर स्थित है। वधावन में एक नए बड़े बंदरगाह की भी योजना बनाई गई है।[7] चौगुनी बंदरगाह क्षमता के साथ-साथ, भारत को एक अग्रणी जहाज निर्माता बनने, भीतरी इलाकों के साथ विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी विकसित करने और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने का लक्ष्य रखना होगा ताकि आयात और निर्यात का काम वहाँ कम हो। लाल सागर संकट के बीच उछाल का लाभ उठाने के लिए एयर कार्गो में भी वृद्धि जरूरी है।

घरेलू वित्तीय बाज़ारों में सुधार देखा जा रहा है। अमेरिकी डॉलर की लगातार सख्ती ने अन्य सभी मुद्राओं पर नीचे की ओर दबाव डाला है, साथ ही भारतीय रुपये में भी राजनीतिक और भू-राजनीतिक दोनों कारणों से गिरावट देखी जा रही है, लेकिन वैश्विक अशांति कम होने और व्यापक-बुनियादी सिद्धांतों की अंदरूनी ताकत फिर से मजबूत होने के कारण मध्यम अवधि का दृष्टिकोण तेज बना हुआ है। हाल की अवधि में, भारतीय रुपये की विनिमय दर पर कुछ चर्चा हुई है, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से और समकक्षों के संबंध में इसकी सापेक्ष स्थिरता पर कुछ असंतोष है। जैसा कि बॉक्स 2 में बताया गया है, भारतीय रुपये का स्तर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो अंतिम विश्लेषण में, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित व्यापक-बुनियादी सिद्धांतों की स्थिति को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप से अनुचित अस्थिरता को सुचारू किया जाता है ताकि बाजार व्यवस्थित तरीके से साफ हो सके। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भू-राजनीतिक तनाव, अलग-अलग मौद्रिक नीति मार्ग, भू-आर्थिक विखंडन और राजनीतिक फैलाव और अन्य अतिव्यापी संकटों के बीच वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अभूतपूर्व रूप से अधिक है। दुनिया भर में मुद्रा बाजार घरेलू आर्थिक गतिविधियों में इन वैश्विक आघातों के प्रसार के माध्यम बन गए हैं। भारतीय रुपये में स्थिरता प्रदान करके, अर्थव्यवस्था कई वैश्विक प्रभाव-विस्तार और सहायक वित्तीय स्थिरता जोखिमों से अपेक्षाकृत अछूती रहती है। बॉक्स 2 में यह भी बताया गया है कि कैसे अर्थव्यवस्था को बफर करने के इस दृष्टिकोण ने भारत के बुनियादी सिद्धांतों की जन्मजात ताकत को एक शत्रुतापूर्ण और अत्यधिक अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय वातावरण में निर्मित करने में सक्षम बनाया है।

क्रेडिट बाज़ार में, व्यष्टि-वित्तीय संस्थानों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने ऋण पर अत्यधिक ब्याज दरों के कारण विनियामकों का ध्यान आकर्षित किया। बताया गया है कि कई निजी बैंक छोटे टिकट अग्रिमों, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिक ऋणों में दबाव का सामना कर रहे हैं, साथ ही अति-लाभ वाले ग्राहकों के साथ-साथ प्रावधान में भी वृद्धि हुई है। आम तौर पर, बैंकों ने खुदरा और सेवाओं को ऋण देने में सावधानी बरती है। दूसरी ओर, उन्होंने उद्योग - छोटे, मध्यम और बड़े - को ऋण में मजबूती से वृद्धि की है, जो भारतीय उद्योग की अंतर्निहित विकास गति में उछाल को दर्शाता है। कुल मिलाकर, जमा और ऋण वृद्धि के बीच एक बेहतर संतुलन उभर रहा है, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात पहले समतापमंडलीय ऊंचाइयों से सामान्य स्तर पर गिर रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निरंतर बिकवाली के बावजूद, इक्विटी बाज़ार घरेलू समर्थन पर एक नई बढ़त के लिए तैयार हो रहे हैं, खासकर प्रमुख म्यूचुअल फंड इक्विटी योजनाओं के लिए। मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण कुछ सुधारों के बावजूद, 2024 में भारतीय मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में अब तक बढ़त सबसे अच्छी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से बेपरवाह, कुछ बड़े टिकट सौदों में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी द्वारा फंडिंग बढ़ रही है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह अक्टूबर और नवंबर की पहली छमाही भारत में सबसे गर्म रिकॉर्ड के रूप में दर्ज

[6] भारत की पण्य वस्तु व्यापार रिपोर्ट की पंचवर्षीय समीक्षा, वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल, मई 2024।

[7] "भारत ने चुपचाप अपने बंदरगाहों को बदल दिया", द इकोनॉमिस्ट, 09 मई 2024।

की गई। ला नीना की संभावना और समुद्र की सतह के तापमान में समय-समय पर होने वाली ठंडक को अब दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है, जो ठंडी सर्दी का संकेत देता है। फिर भी, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयास दिखाई दे रहे हैं। पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द्वारा समर्थित, 2027 तक 30 गीगा वाट जोड़ने के लक्ष्य के साथ, छत पर सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत को विकास के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ मार्ग की दिशा में की गई प्रगति की मान्यता में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। चुनौतियों के बावजूद, भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में इस वर्ष 4.5-5.0 गीगा वाट जुड़ने की उम्मीद है, 2026 में संभावित वार्षिक स्थापना 10 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। स्थापित पवन क्षमता का 70-80 प्रतिशत स्थानीयकृत है। डिस्कॉम द्वारा दीर्घकालिक बिजली खरीद अनुबंधों ने नवीकरणीय ऊर्जा में निजी डेवलपर्स के निवेश को जोखिम से मुक्त कर दिया है। भंडारण में निवेश करना समय की मांग है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रही गतिविधियों को शामिल करता है। घरेलू समष्टिआर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में दिया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम खंड निष्कर्ष टिप्पणियाँ निर्धारित करता है।

II. वैश्विक व्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद आघातसहनीय बनी हुई है, भले ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास का परिदृश्य अलग-अलग है। मौद्रिक नीति सामान्यीकरण एई में नीतिगत कार्रवाई को चला रहा है, भले ही कई देशों में अवस्फीति की गति असमान बनी हुई है। अपने अक्टूबर 2024 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट में, आईएमएफ ने 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि के अपने अनुमान को 3.2 प्रतिशत पर बनाए रखा, जो जुलाई के समान ही था (चार्ट II.1)। हालाँकि, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए दृष्टिकोण में गिरावट के कारण 2025 के लिए वृद्धि के अनुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया गया क्योंकि चरम मौसम की घटनाओं और आपूर्ति व्यवधानों से उनके उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में वार्षिक औसत 6.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.8 प्रतिशत और 2025 में 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, साथ ही एई द्वारा ईएमडीई की तुलना में मुद्रास्फीति को जल्द ही लक्ष्य पर वापस लाने की उम्मीद है।

वैश्विक जीडीपी का हमारा मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान, बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण 2024 की तीसरी तिमाही और 2024 की चौथी तिमाही में गति में कुछ कमी का संकेत देता है (चार्ट II.2)।

चार्ट II.1 आईएमएफ़ वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान

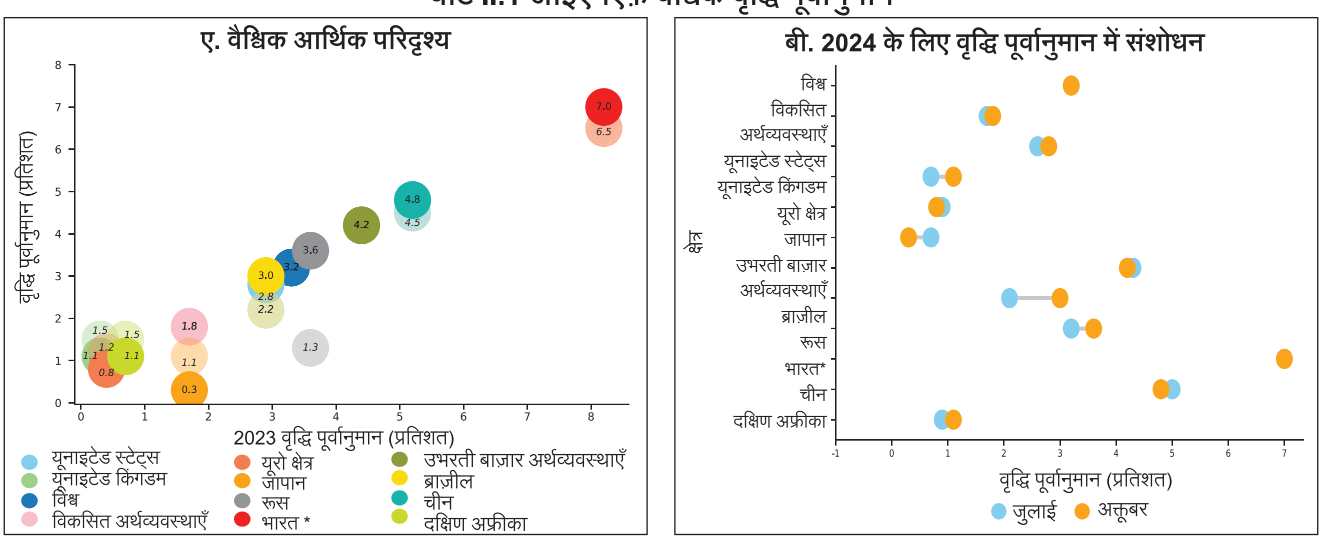

टिप्पणियाँ: 1. *: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।
2. गहरे (हल्के) छायांकित वृत्त चार्ट II.1a में 2024 (2025) के पूर्वानुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत: आईएमएफ।

चार्ट II.2: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)

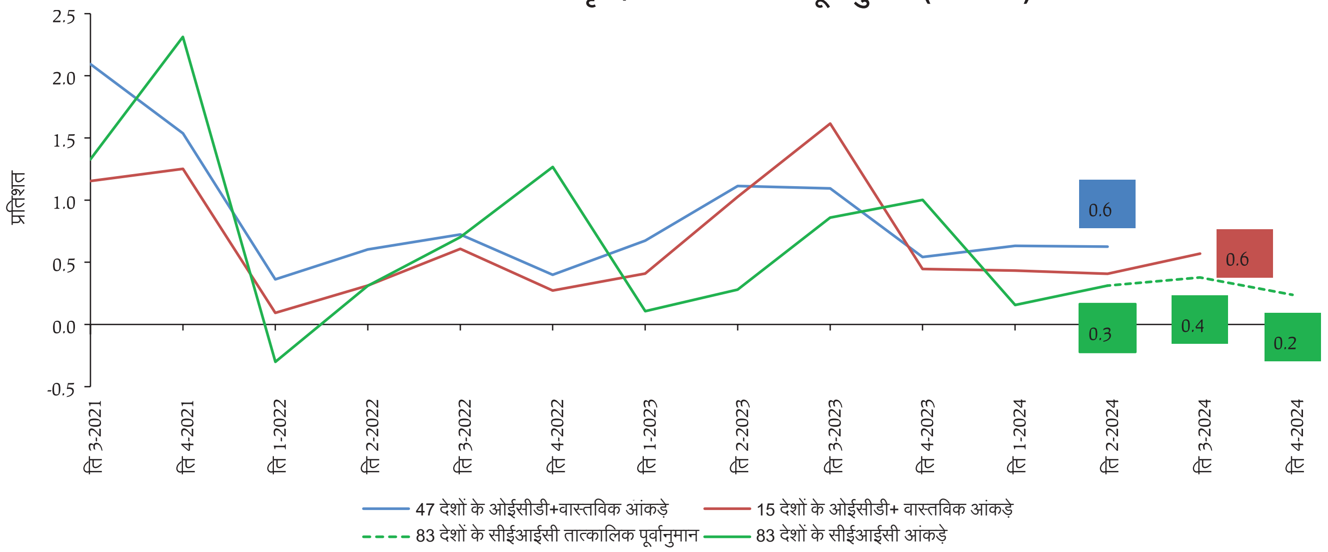

स्रोत: सीईआईसी; ओईसीडी; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) अक्टूबर 2024 में लगातार दूसरे महीने कम हुआ, और अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे गिर गया (चार्ट II.3ए)। आपूर्ति में व्यवधान के कारण कंटेनर शिपिंग लागत बढ़ी हुई है, हालांकि

चार्ट II.3: भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में रुझान

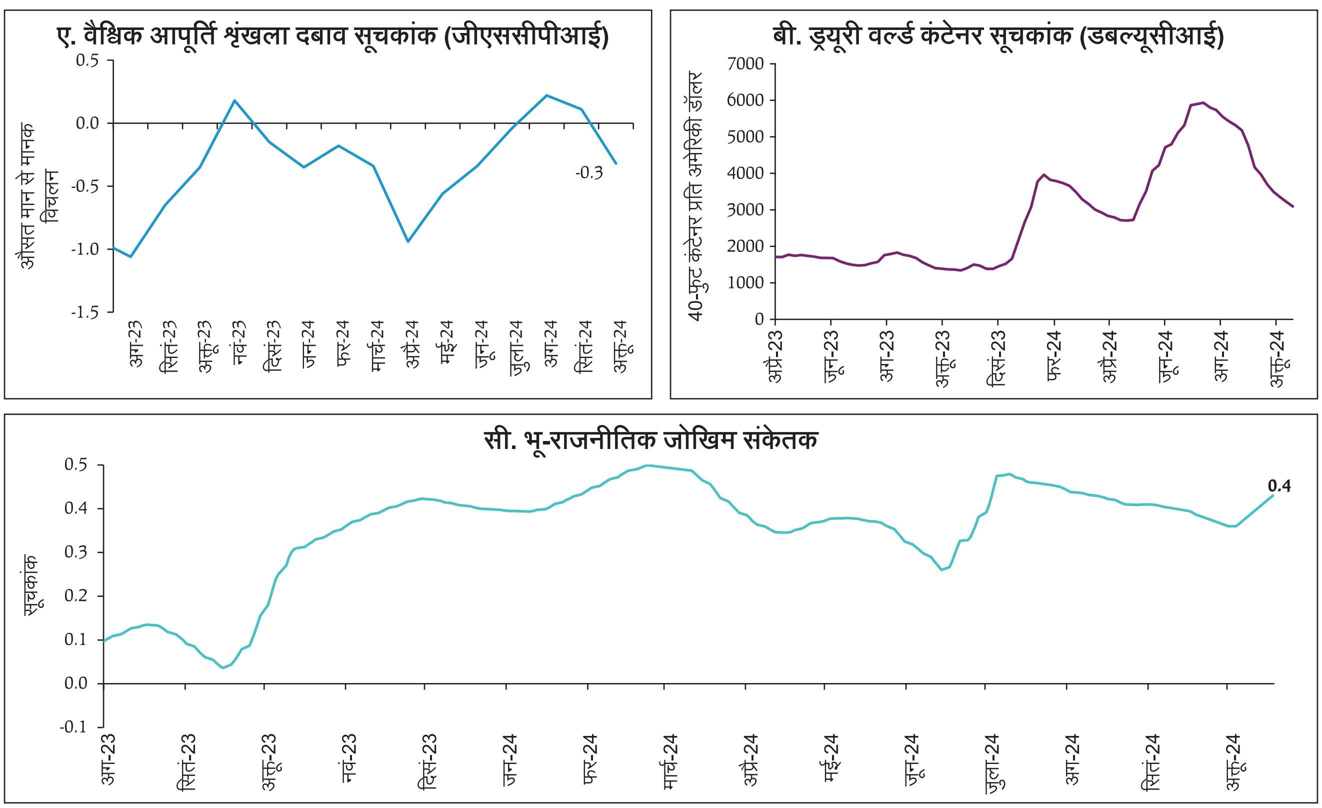

टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।

2. ड्र्यूरी द्वारा साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र 8 शिपिंग मार्गों की मात्रा के भारित औसत को 40-फुट कंटेनर प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप में दर्शाता है।

स्रोत: फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, अक्टूबर 2024; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.4: उपभोक्ता भाव और वित्तीय स्थितियां

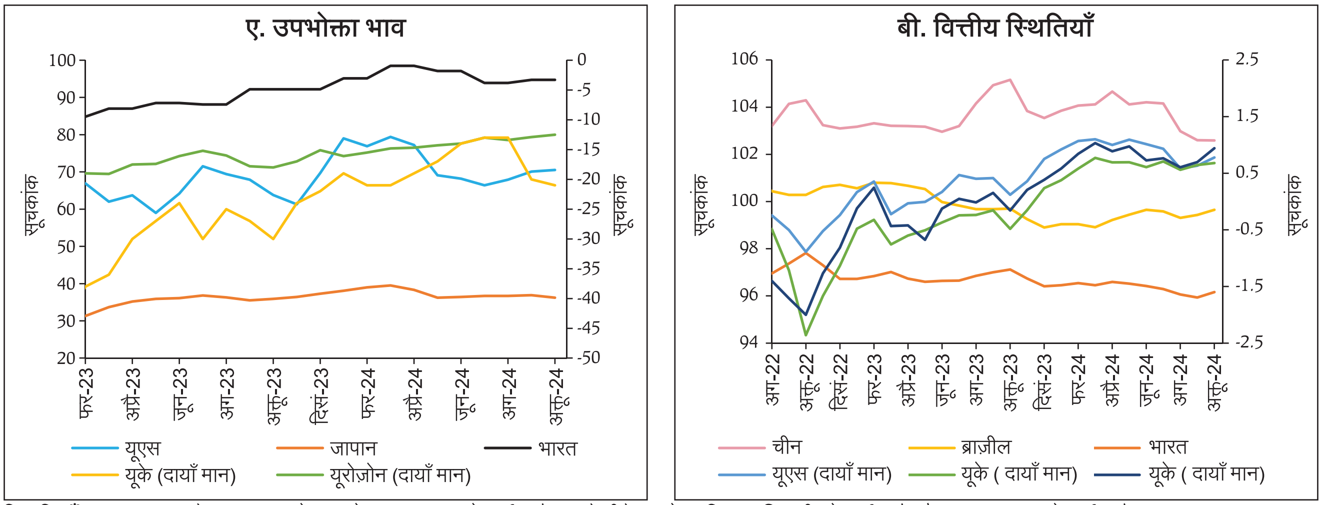

टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।

2. यूरोजोन और यूके: -100 आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी का संकेत देता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।

3. भारत और अमेरिका: सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान इसमें कुछ कमी दर्ज की गई (चार्ट II.3बी)। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण अक्टूबर में भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ गए, जो जुलाई के मध्य से देखी गई नरमी के विपरीत है (चार्ट II.3सी)।

अक्टूबर 2024 में, अमेरिका, यूरो क्षेत्र और भारत में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ लेकिन यूके में यह खराब हो गया (चार्ट II.4ए)। प्रमुख एई और ईएमई में वित्तीय स्थितियां सहज हुई (चार्ट II.4बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर में दर्ज आठ महीने के निचले स्तर से अक्टूबर में बढ़ गया और लगातार बारहवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा (चार्ट II.5)। व्यापार, उपभोक्ता और वित्तीय सेवाओं में उत्पादन में विस्तार के साथ सेवा गतिविधियों में एक मजबूत पुनरुद्धार विनिर्माण में सुस्त प्रदर्शन की भरपाई करता है। नए ऑर्डर, रोजगार वृद्धि और खरीद के स्टॉक में कमी के कारण वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अक्टूबर में लगातार चौथे महीने तटस्थ स्तर से नीचे रहा।

निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई अक्टूबर में बढ़ी, लेकिन जून 2024 से यह संकुचन क्षेत्र में बनी हुई है क्योंकि विनिर्माण निर्यात में गिरावट सेवा निर्यात में वृद्धि की तुलना में अधिक है। हालाँकि, अनुक्रमिक आधार पर, विनिर्माण निर्यात ऑर्डरों में कम संकुचन देखा गया, जबकि सेवा निर्यात ऑर्डरों में गिरावट आई (चार्ट II.6)।

अक्टूबर में वैश्विक कमोडिटी कीमतों में कमी आई क्योंकि धातु की कीमतों में गिरावट से ऊर्जा कीमतों में बढ़त की भरपाई

चार्ट II.5 : वैश्विक पीएमआई

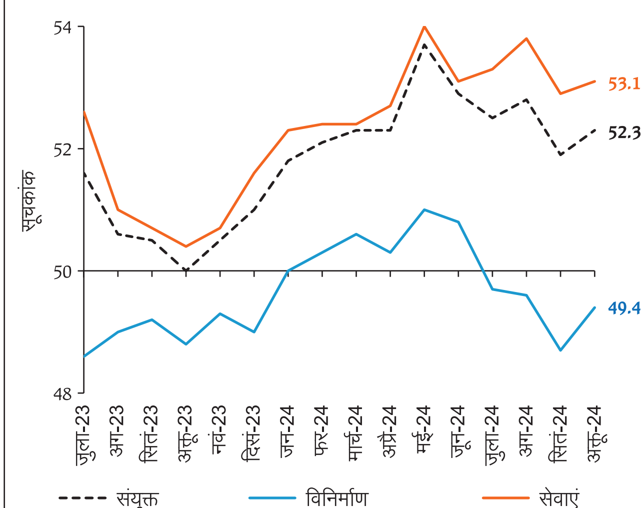

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।

स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: निर्यात आदेश

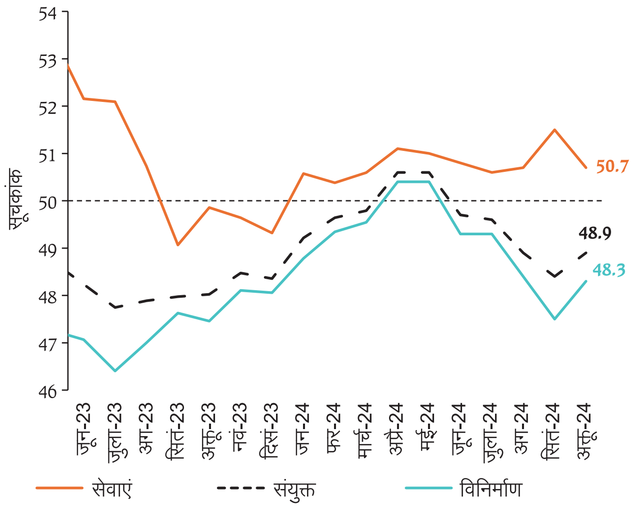

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

हो गई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक अक्टूबर में 2.2 प्रतिशत (म-द-म) गिर गया (चार्ट II.7ए)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में अक्टूबर में 2.0 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मांस को छोड़कर सभी श्रेणियों में कीमतें बढ़ गईं; सब्जियों की कीमतों में विशेष रूप से तेज वृद्धि देखी गई (चार्ट II.7बी)। अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में धातु की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि प्रोत्साहन उपायों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के कारण आधारभूत धातु के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन की मांग में कमी आई।

अमेरिकी चुनावों को लेकर अनिश्चितताओं और मध्य पूर्व में संघर्षों के बीच सुरक्षा-कवच की मांग के कारण अक्टूबर में स्वर्ण की कीमतों में 4.6 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई, जो पहली बार 2700 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गई। हालाँकि, नवंबर के पहले पखवाड़े में स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि बढ़ते प्रतिफल और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने स्वर्ण रखने की अवसर लागत को बढ़ा दिया (चार्ट II.7सी)। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें

चार्ट II.7: कमोडिटी और खाद्य कीमतें

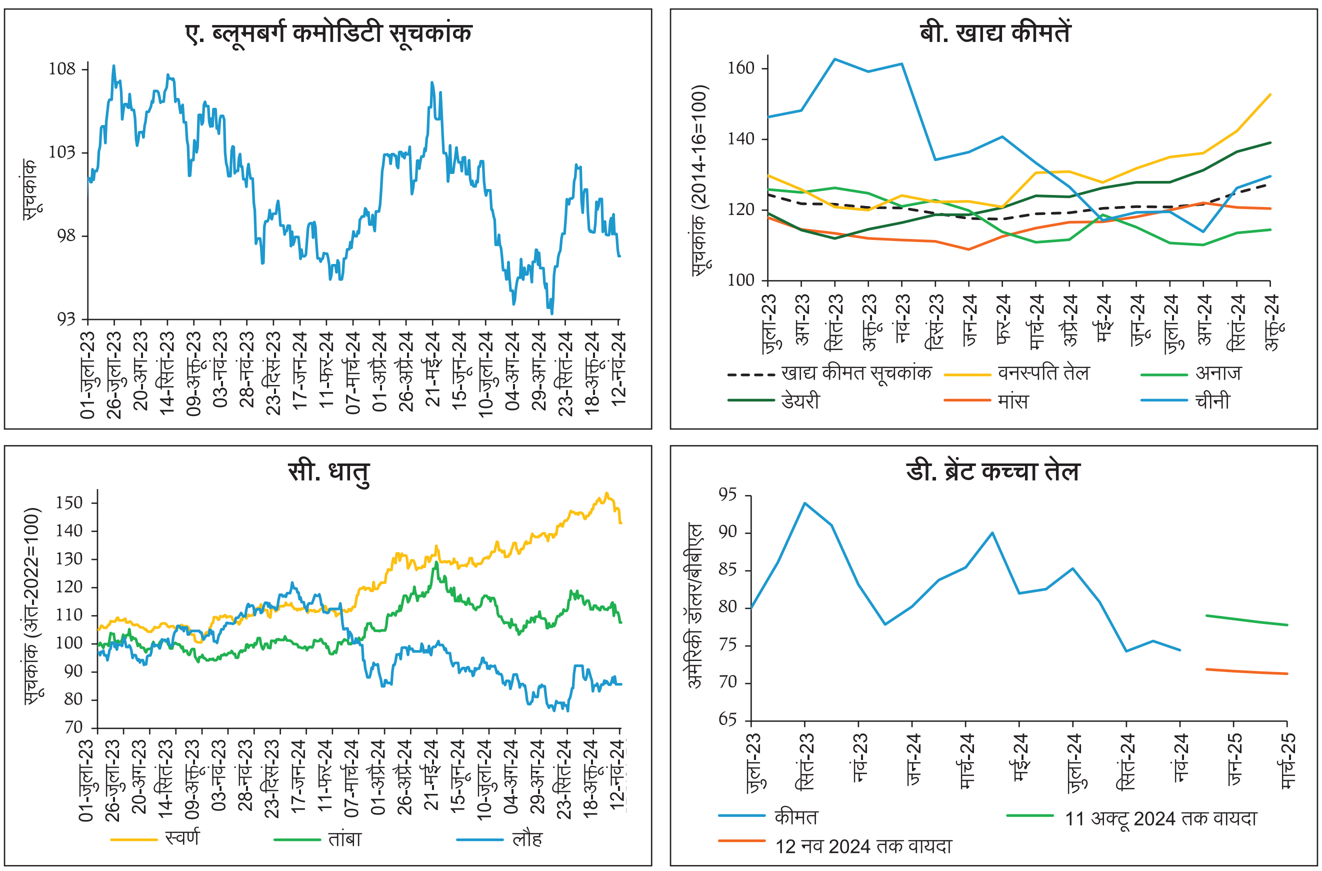

स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

अक्टूबर की शुरुआत में बढ़ीं क्योंकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद बाजार निशाने पर थे। हालाँकि, 2025 में आपूर्ति की संभावनाओं में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनाव में आंशिक कमी को देखते हुए, महीने के उत्तरार्ध में तेल की कीमतों में गिरावट आई। कुल मिलाकर, अक्टूबर में कीमतों में 2.3 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई। नवंबर की पहली छमाही में, कमजोर मांग परिदृश्य के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई (चार्ट II.7डी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही, यद्यपि असमान रूप से, हालांकि सेवाओं की मुद्रास्फीति अभी भी ऊंची बनी हुई है, खासकर एई में। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2024 में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) 2.6 प्रतिशत हो गई। व्यक्तिक उपभोग व्यय (पीसीई) डिफ्लेटर के संदर्भ में मुद्रास्फीति अगस्त में 2.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 2.1 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर में 1.7 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 2.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8ए)। ईएमई के बीच, ब्राजील और रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन अक्टूबर में चीन में कम हो गई (चार्ट II.8बी)। अधिकांश एई में कोर और सेवा मुद्रास्फीति हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट II.8सी और 8डी)।

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के साथ-साथ अमेरिका और जापान में चुनाव परिणामों को देखते हुए अक्टूबर में वैश्विक इक्विटी बाजारों में गिरावट आई। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वैश्विक सूचकांक में अक्टूबर में 2.3 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट दर्ज की गई, जबकि उभरते बाजारों के सूचकांक में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट II.9ए)। ईएमई इक्विटी बाजारों में गिरावट चीन में

चार्ट II.8: मुद्रास्फीति – एई और ईएमई

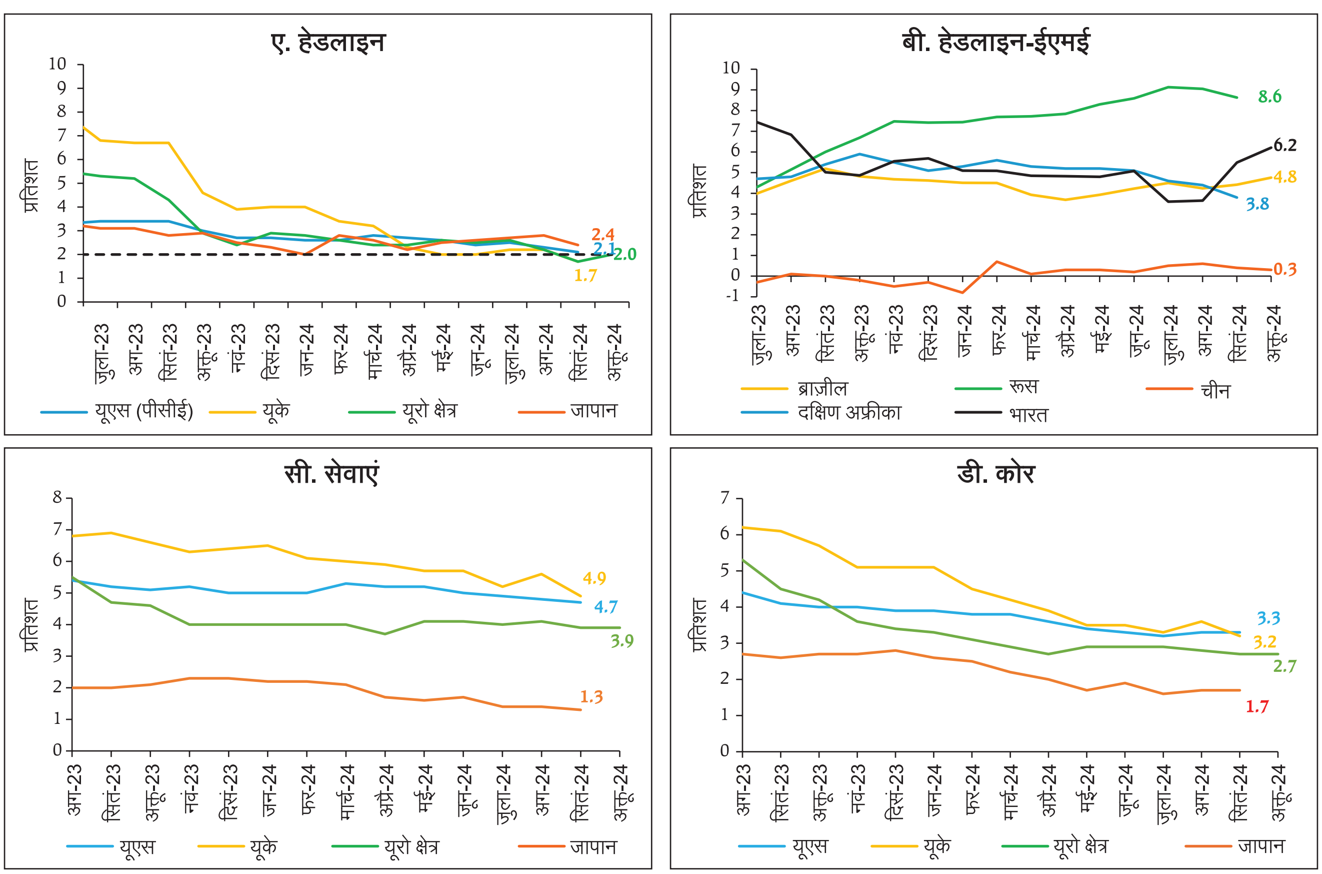

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

गिरावट के कारण हुई क्योंकि सितंबर में घोषित प्रोत्साहन उपायों के बाद बाज़ार में तेज़ी से गिरावट आई। अमेरिकी चुनाव नतीजों (5 से 12 नवंबर के बीच) के बाद, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त के कारण इक्विटी बाजारों में काफी तेजी आई, एमएससीआई वैश्विक सूचकांक में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अक्टूबर में 10-वर्षीय और 2-वर्षीय बॉण्ड दोनों में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल क्रमशः 50 बीपीएस और 53 बीपीएस तक बढ़ गए, क्योंकि विभिन्न डेटा रिलीज के बीच यूएस जीडीपी सहित प्रमुख दर में कटौती की उम्मीद कम हो गई, जो अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित ताकत का संकेत देती है (चार्ट II.9बी)। नवंबर में प्रतिफल और बढ़े क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद बाज़ार ने अमेरिका में उच्च बजट घाटे को ध्यान में रखना शुरू कर दिया। 05 नवंबर से (12 नवंबर तक) 10-वर्षीय और 2-वर्षीय दोनों प्रतिफल में क्रमशः 16 बीपीएस और 17 बीपीएस की वृद्धि हुई।

मुद्रा बाजारों में, अक्टूबर में अमेरिकी डॉलर में 3.2 प्रतिशत (म-द-म) वृद्धि हुई, जबकि ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में अक्टूबर में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण इक्विटी सेगमेंट में पूंजी का बहिर्वाह था। नतीजों के बाद, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

एई केंद्रीय बैंकों में, यूएस फेडरल रिज़र्व ओपन मार्केट्स कमेटी (एफओएमसी) ने 07 नवंबर 2024 को फेडरल फंड्स रेट के लिए लक्ष्य सीमा को 25 आधार अंकों तक कम करने का फैसला किया और संकेत दिया कि "मुद्रास्फीति ने समिति के 2 प्रतिशत उद्देश्य की ओर प्रगति की है लेकिन कुछ हद तक अधिक बनी हुई है"।[8] यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर में अपनी नीति दरों

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार

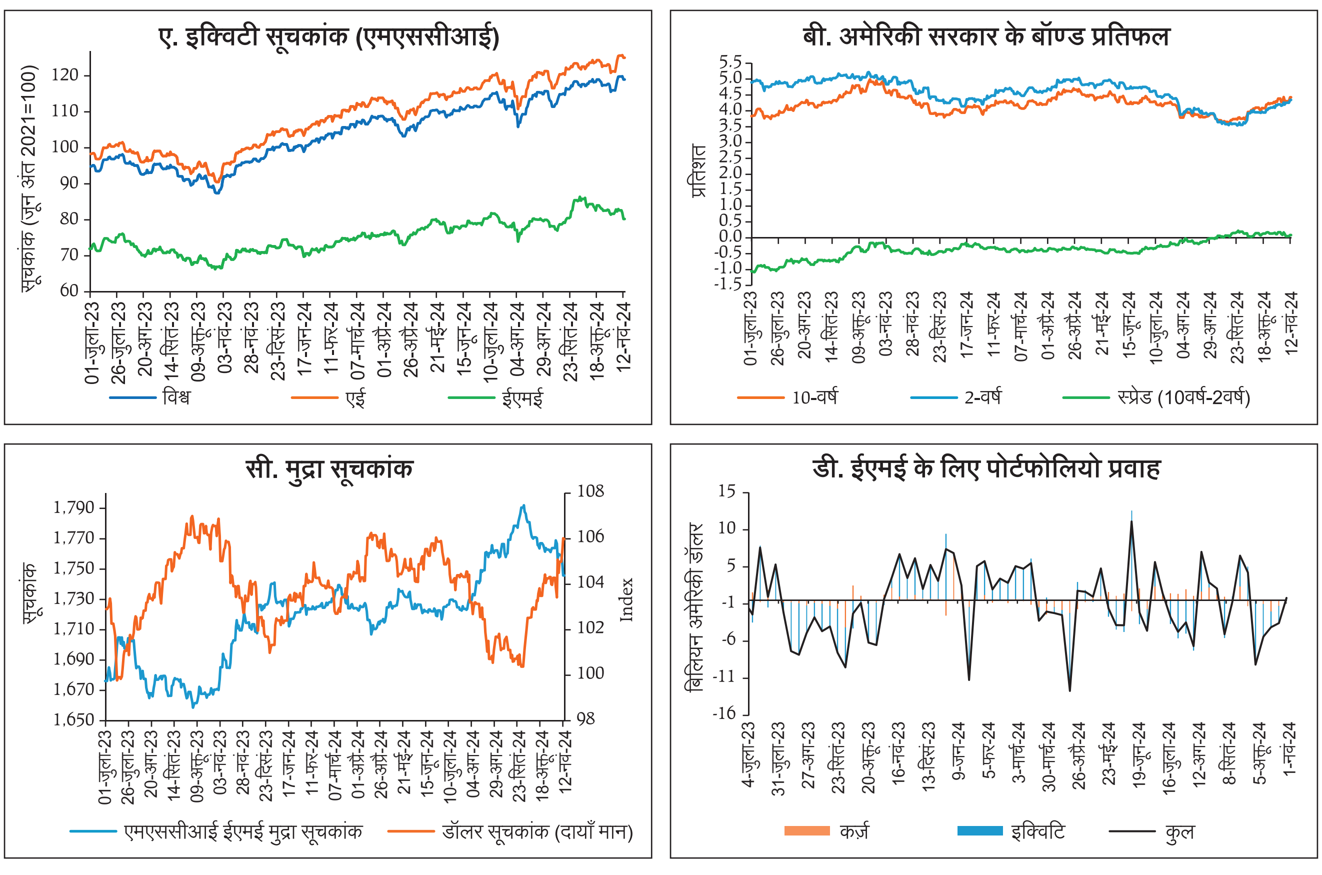

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ)।

8 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20241107a.htm

चार्ट II.10: नीतिगत दरों में परिवर्तन

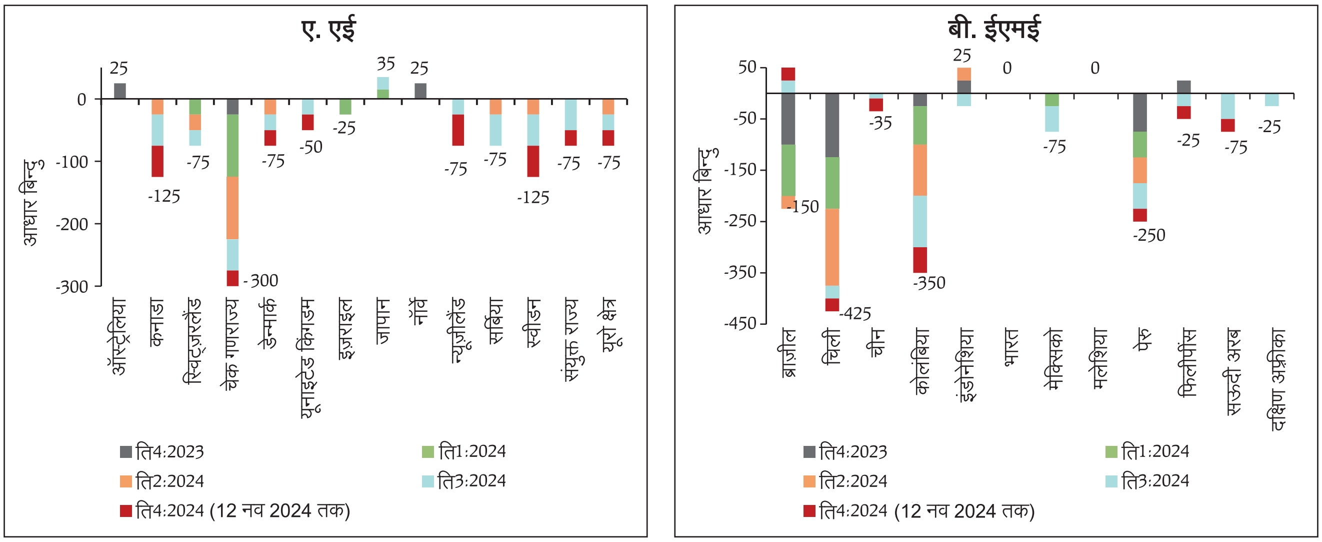

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

में 25 बीपीएस की कटौती की, जबकि स्वीडन और कनाडा ने क्रमशः नवंबर और अक्टूबर में अपनी बेंचमार्क दरों में 50 बीपीएस की कटौती की। जापान, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया ने विराम जारी रखा (चार्ट II.10 ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, पेरू और मेक्सिको ने नवंबर में अपनी नीति दरों में 25 बीपीएस की कमी की (चार्ट II.10 बी)। चल रहे प्रोत्साहन उपायों के हिस्से के रूप में, चीन ने अपने एक वर्ष के लोन प्राइम रेट (एलपीआर) और पांच वर्ष के एलपीआर को क्रमशः 25 बीपीएस घटाकर 3.10 प्रतिशत और 3.60 प्रतिशत कर दिया। इसके विपरीत, रूस ने अक्टूबर में अपनी नीति दर को 200 आधार अंक बढ़ाकर 21.0 प्रतिशत कर दिया तथा ब्राजील ने मुद्रास्फीति दबावों से निपटने के लिए नवंबर में अपनी दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 11.25 प्रतिशत कर दिया।

III. घरेलू गतिविधियां

बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद, भारत के सामने आने वाले आपूर्ति श्रृंखला दबाव अक्टूबर में कम हो गए, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे गिर गए (चार्ट III.1ए)। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई)[9], उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक श्रृंखला के आधार पर, 2024-25 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाता है। (चार्ट III.1बी और III.1सी)।

सकल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में कुल मांग ने फिर से ज़ोर पकड़ा, जो त्योहारी सीजन की मांग से बढ़ा था। ई-वे बिलों में वर्ष-दर-वर्ष 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उच्च आपूर्ति श्रृंखला गतिविधि को दर्शाती है (चार्ट III.2ए)। मूल्य के संदर्भ में टोल संग्रह में 10.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और मात्रा के संदर्भ में 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

ऑटोमोबाइल की बिक्री में 11.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई क्योंकि त्योहारी सीजन के खर्च और वाहन निर्माताओं से छूट ने मांग को बढ़ावा दिया (चार्ट III.3ए)। विशेष रूप से, यात्री वाहन खंड और दोपहिया वाहनों में बिक्री ने समग्र वृद्धि को गति दी। घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में भी 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मई 2011 के बाद से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई। (चार्ट III.3बी)। परिवहन और गैर-परिवहन दोनों क्षेत्रों में वाहन पंजीकरण में वृद्धि हुई (चार्ट III.3सी)। विमानन टरबाइन ईंधन और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की मांग में वृद्धि से प्रेरित लगातार

[9] सूचकांक उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक को निकालता है।

चार्ट III.1 : आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान

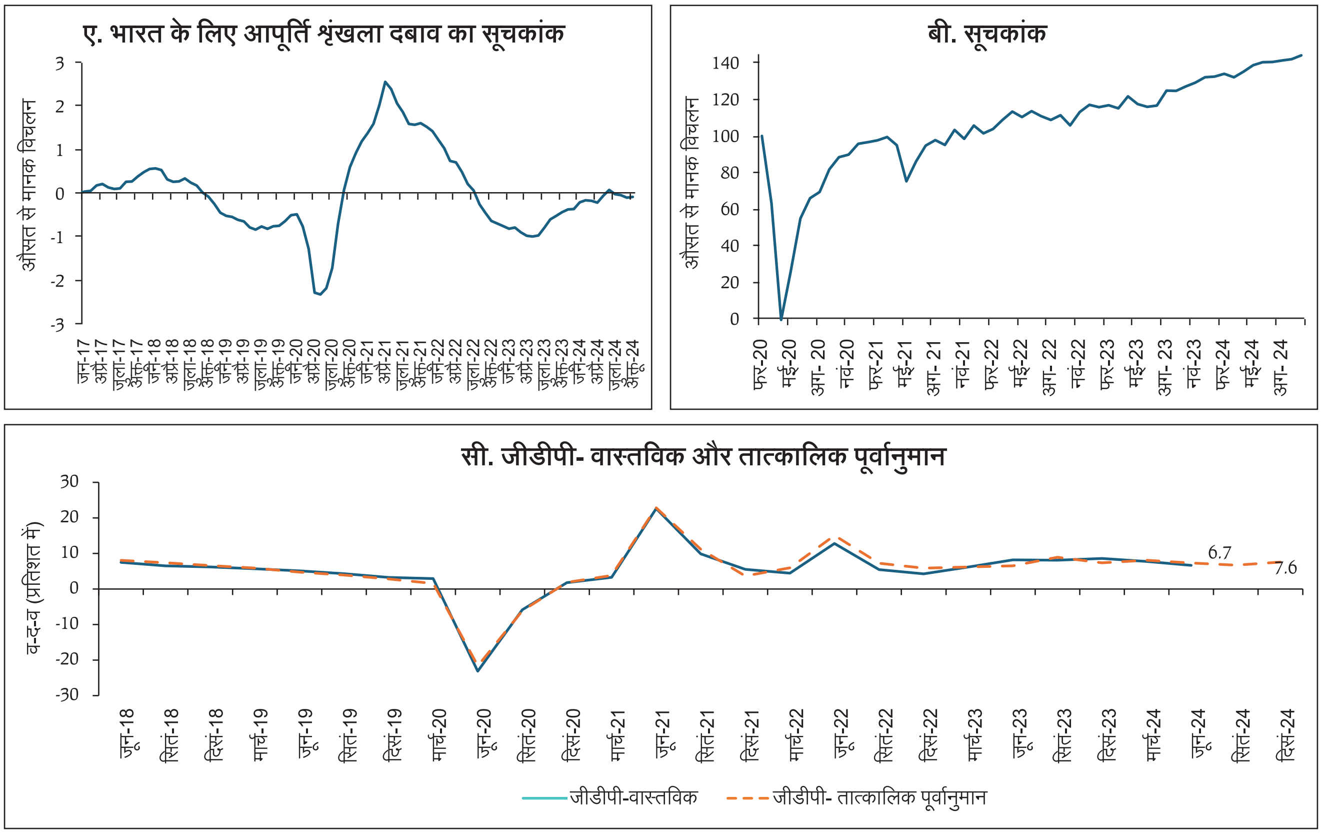

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों को अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 तक बढ़ाया गया, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

दो महीनों के संकुचन के बाद पेट्रोलियम की खपत में तेजी आई [चार्ट III.3डी]।

अक्टूबर 2024 में 55.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की अब तक की सबसे अधिक

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल संग्रह

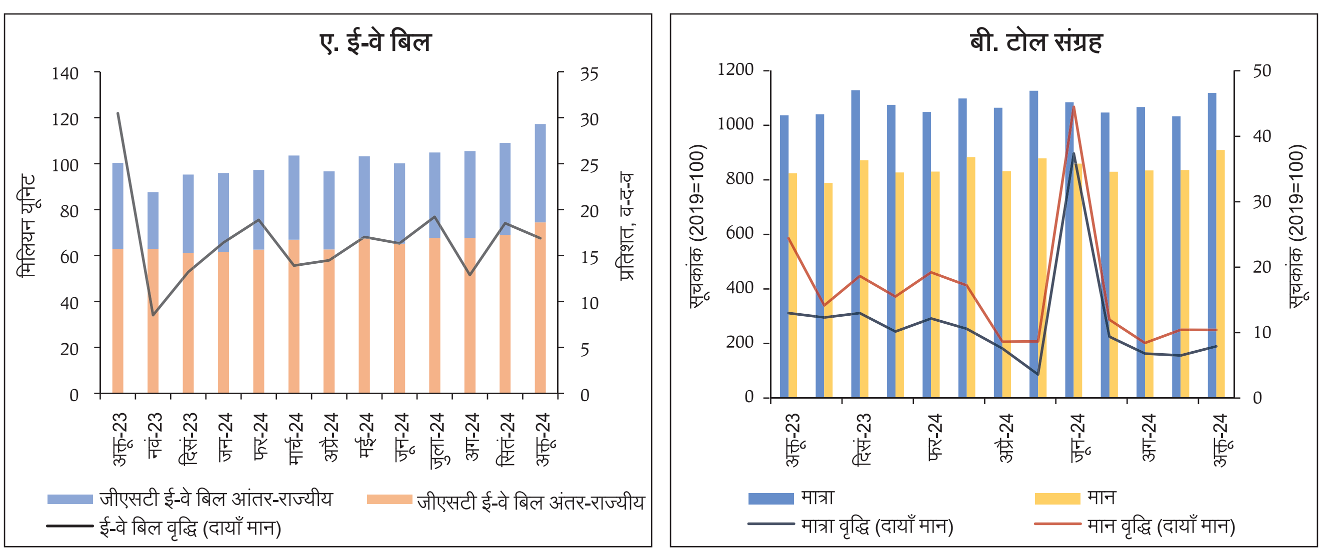

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

चार्ट III.3: ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकेतक

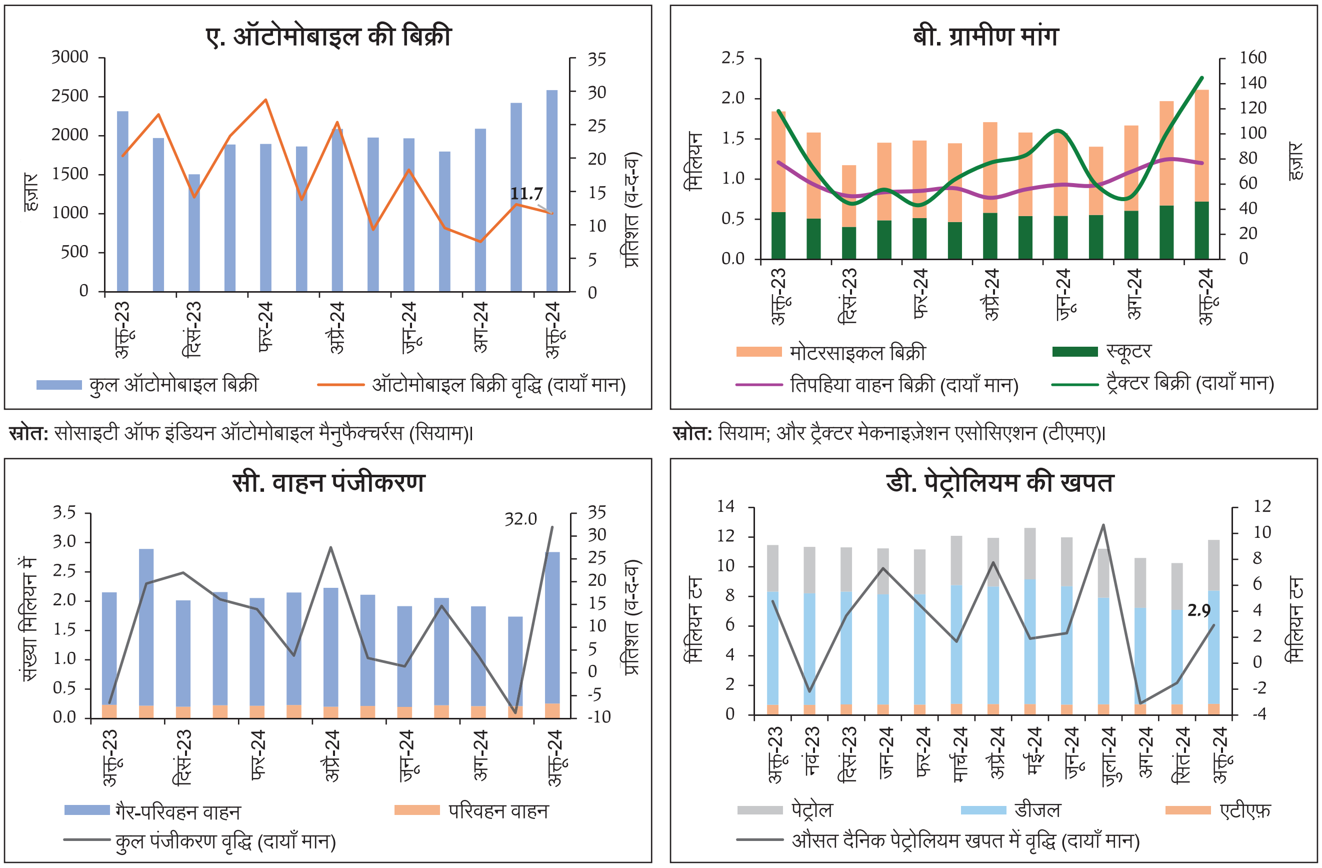

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्रस (सियाम)।

स्रोत: सियाम; और ट्रैक्टर मेकनाइज़ेशन एसोसिएशन (टीएमए)।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

बिक्री भी देखी गई (चार्ट III.4)। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान कुल ईवी बिक्री पहले ही 2023 में कुल ईवी बिक्री को पार कर चुकी है। नीति समर्थन पहल के साथ ईवी अपनाने में दृढ़ता से वृद्धि हो रही है (बॉक्स 1)।

चार्ट III.4 इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री

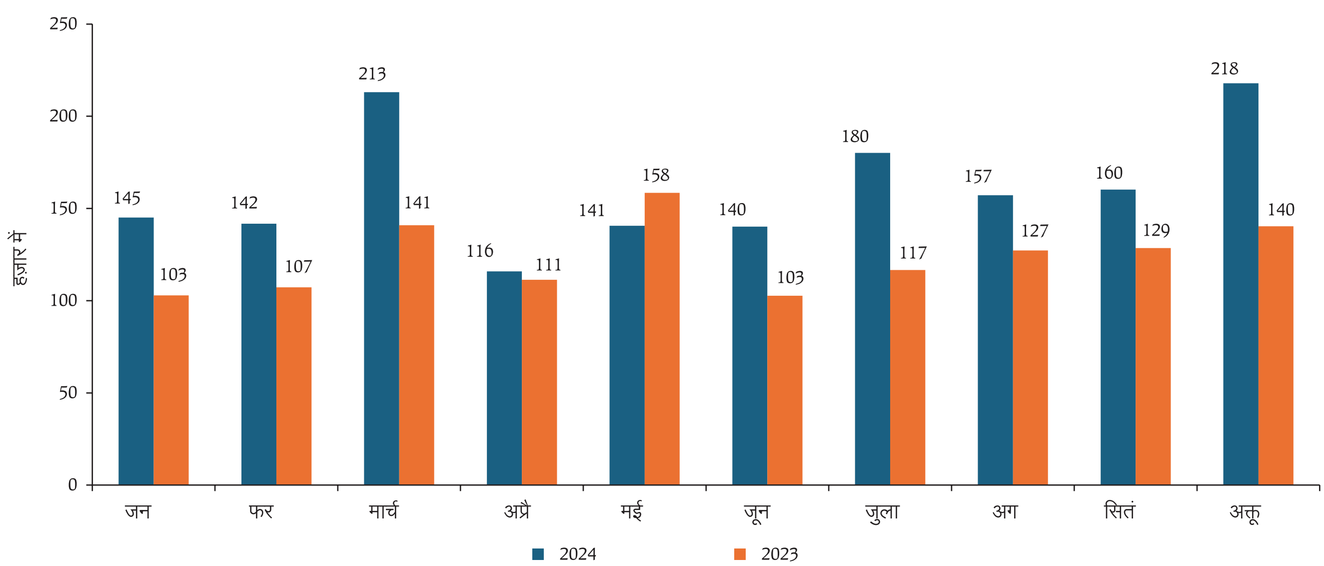

स्रोत : वाहन पोर्टल।

बॉक्स 1: भारत में 2डबल्यू-ईवी अपनाने पर राज्य-स्तरीय नीतियों के प्रभाव का आकलन

भारत में ईवी नीति के विकास को इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पहलों (प्रोत्साहन, सब्सिडी और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं) की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है (सारणी 1 ए)। केंद्र सरकार की पहल पर निर्माण करते हुए, अधिकांश राज्यों ने अपनी ईवी नीतियां पेश की हैं।[10] केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित अभिनव वाहन संवर्द्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में और तेजी लाना है।[11]

उच्च अग्रिम लागत को देखते हुए, अध्ययनों से पता चला है कि छूट, कर क्रेडिट और कम पंजीकरण शुल्क जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभिक खरीद लागत को कम करके ईवी अपनाने को बढ़ाते हैं (जेन एवं अन्य., 2018; और सिएर्ज़चुला एवं अन्य., 2014)।

2-व्हीलर ईवी (2डबल्यू-ईवी) को अपनाने पर राज्य-स्तरीय ईवी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, एक एडॉप्शन रैशियो (एआर) का निर्माण निम्नानुसार किया गया:

$$AR = \frac{\text{2W-EVs registered during a period}}{\text{Total non-electric 2Ws registered during a period}} *100$$

एक उच्च एआर गैर-ईवी के सापेक्ष ईवी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है और इसलिए एक गहरी बाजार पैठ है। सहायक ईवी नीतियों के कार्यान्वयन ने ईवी अपनाने को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जैसा कि एआर में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है (चार्ट 1ए)।

मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक 23 भारतीय राज्यों के तिमाही आंकड़ों पर विचार किया गया। प्रत्येक राज्य के लिए नीति प्रोत्साहन के लिए एक चर बनाया गया जो नीति लागू होने के बाद की अवधि के लिए 1 का मान लेता है और अन्यथा 0। बाइनरी-स्तरीय नीति संकेतक नीतिगत उपायों के विविध सेट को समाहित करता है, जिसमें मांग प्रोत्साहन, अवसंरचना गतिविधियों की लागत , आर एंड डी, और संबंधित पहलू शामिल हैं जो समग्र रूप से ईवी नीति के प्रभाव को इंगित करते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरण का अनुमान लगाया गया:

$$AR_{\{it\}} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Policy.Indicator}_{\{it\}} + \alpha_i + \epsilon_{\{it\}}$$

सारणी 1ए: भारत में ईवी नीति का विकास

नीति	लक्ष्य	प्रोत्साहन
भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन (एएफएसटी) (2011)	स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।	प्रत्यक्ष अंतिम उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता; अनुसंधान एवं विकास तथा घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 (2013 में लॉन्च)	वर्ष 2020 से वर्ष दर वर्ष इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करना।	कर प्रोत्साहन; चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन; पायलट परियोजनाएं; बाजार निर्माण; और आर एंड डी समर्थन।
भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण I (2015) (एनईएमएमपी के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया)	चार मुख्य क्षेत्र: ● मांग निर्माण ● प्रौद्योगिकी मंच ● पायलट परियोजनाएं ● चार्जिंग के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर।	ईवीएस के खरीदारों के लिए अग्रिम रूप से कम खरीद मूल्य, पायलट परियोजनाओं के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, आर एंड डी / प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के रूप में मांग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन।
फेम इंडिया योजना चरण- II (2019) (फेम इंडिया योजना चरण- I का विस्तार)	ईवी को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना; ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना; विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का संचालन।	खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश करके खरीदारों को वित्तीय सब्सिडी; केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन; और आर एंड डी समर्थन।
अभिनव वाहन वृद्धि में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) [2024]	विद्युत गतिकी को बढ़ावा देना, परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार; ईवी को अपनाने में तेजी लाना; कुशल, प्रतिस्पर्धी और आघात-सहनीय ईवी विनिर्माण।	2डबल्यू-ईवी, 3डबल्यू-ईवी, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन; उच्च ईवी प्रवेश और राजमार्गों के साथ चुनिंदा शहरों में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना।

स्रोत: पीआईबी; बीईई[12]; और लेखकों का संकलन।

(Contd.)

[10] https://evyatra.beeindia.gov.in/state-govt/

[11] https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/docs/policy_document/257594.pdf

[12] https://evyatra.beeindia.gov.in/central-govt-initiatives/

चार्ट 1ए: भारत में 2डबल्यू-ईवी को अपनाना (राज्य ईवी नीति लागू होने से पहले और बाद में)

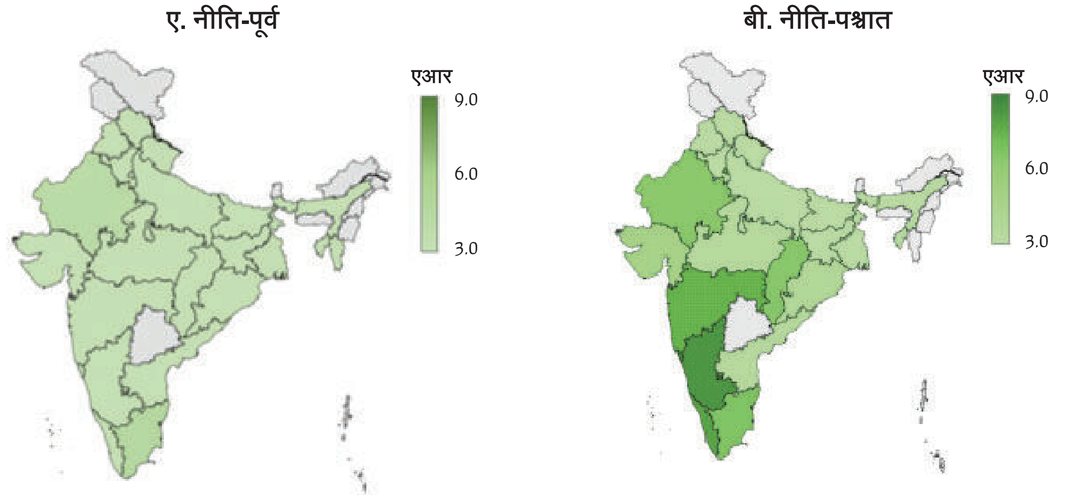

टिप्पणीयां: 1. प्रत्येक राज्य के लिए नीति-पूर्व अंगीकरण के अनुपात की गणना ईवी नीति अधिसूचना तिमाही से पहले की पांच तिमाहियों के औसत जकरण के अनुपात के रूप में की जाती है।
2. इसी तरह, प्रत्येक राज्य के लिए नीति-पश्चात अंगीकरण के अनुपात को ईवी नीति घोषणा तिमाही के बाद की तिमाहियों के लिए अंगीकरण के अनुपात का औसत निकालकर निर्धारित किया जाता है।
3. उन राज्यों के लिए जहां अध्ययन अवधि से पहले ईवी नीति लागू की गई थी, नीति-पश्चात अंगीकरण के अनुपात की गणना मार्च 2021 तिमाही से शुरू होने वाले अंगीकरण के अनुपात के औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो; और लेखकों की गणना।

जहां β_1 नीति अपनाने के बाद अपनाने के अनुपात में परिवर्तन को मापता है।

नीति संकेतक के लिए एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण मूल्य इंगित करता है कि भारत में 2डबल्यू-ईवी को अपनाने में एक सहायक ईवी नीति व्यवस्था में तेजी आई है (सारणी 1बी)।[13]

सारणी 1 बी: पैनल प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर: अंगीकरण अनुपात (23 राज्यों के लिए राज्य-वार)

	अवधि (मार्च 2021- दिसंबर 2023) नमूना आकार = 276
व्याख्यात्मक चर	
नीति संकेतक	3.1***(0.52)

टिप्पणी: *, ** और *** 10, 5 और 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व दर्शाते हैं। कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियां हैं।

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

संदर्भ:

Jenn, A., Springel, K., and Gopal, A. R. (2018). Effectiveness of electric vehicle incentives in the United States. *Energy Policy, 119*, 349-356.

Sierzchula, W., Bakker, S., Maat, K., and Van Wee, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. *Energy Policy, 68*, 183-194.

Atal Singh, Satyam Kumar, Abhyuday Harsh and Tista Tiwari (2024). Impact of State-Level Policies on 2W-EV Adoption in India, *Mimeo.*

नवीनतम तिमाही शहरी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट[14] के अनुसार, भारत में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई – जो जून 2018 में पीएलएफएस श्रृंखला की स्थापना के बाद से सबसे कम है – जो पिछली तिमाही में 6.6 प्रतिशत थी(चार्ट III.5)। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) दोनों में वृद्धि के साथ पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों के लिए बेरोजगारी में गिरावट आई। समग्र रोजगार में नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी तिमाही में बढ़ी जबकि स्व-नियोजित श्रमिकों और

[13] हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि नीति अपनाने से पहले और बाद में अपनाने की दर में अंतर के लिए कई अन्य कारकों की भी भूमिका हो सकती है, जो आगे के अध्ययन की गुंजाइश प्रदान करता है।

[14] तिमाही बुलेटिन पीएलएफ़एस_जुलाई_सितंबर_2024.पीडीएफ़।

चार्ट III.5: पीएलएफएस तिमाही (आयु 15 वर्ष और उससे अधिक)

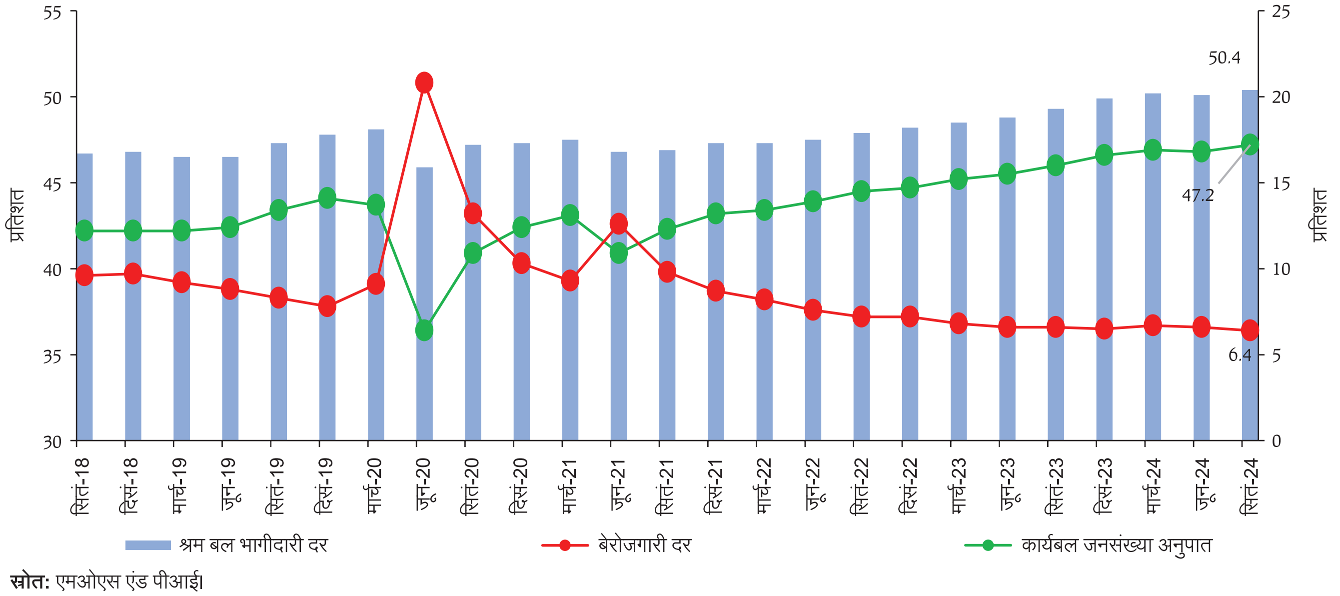

स्रोत: एमओएस एंड पीआई।

आकस्मिक श्रमिकों की हिस्सेदारी में पिछली तिमाही से गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.6ए)। भारत में नगरीय क्षेत्रों के लगभग दो-तिहाई श्रमिक सेवा क्षेत्रक की गतिविधियों में नियोजित हैं (चार्ट III-6बी)।

पीएमआई रोजगार सूचकांकों के अनुसार, संगठित विनिर्माण रोजगार ने अक्टूबर में त्वरण दर्ज किया और लगातार आठवें महीने विस्तारवादी क्षेत्र में बना रहा (चार्ट III.7)। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर में दो वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

2024-25 के दौरान अब तक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत परिवारों की काम की मांग आम तौर पर महामारी के बाद के अधिकांश

चार्ट III.5: पीएलएफ़एस तिमाही (श्रेणी और क्षेत्र के आधार पर रोजगार)

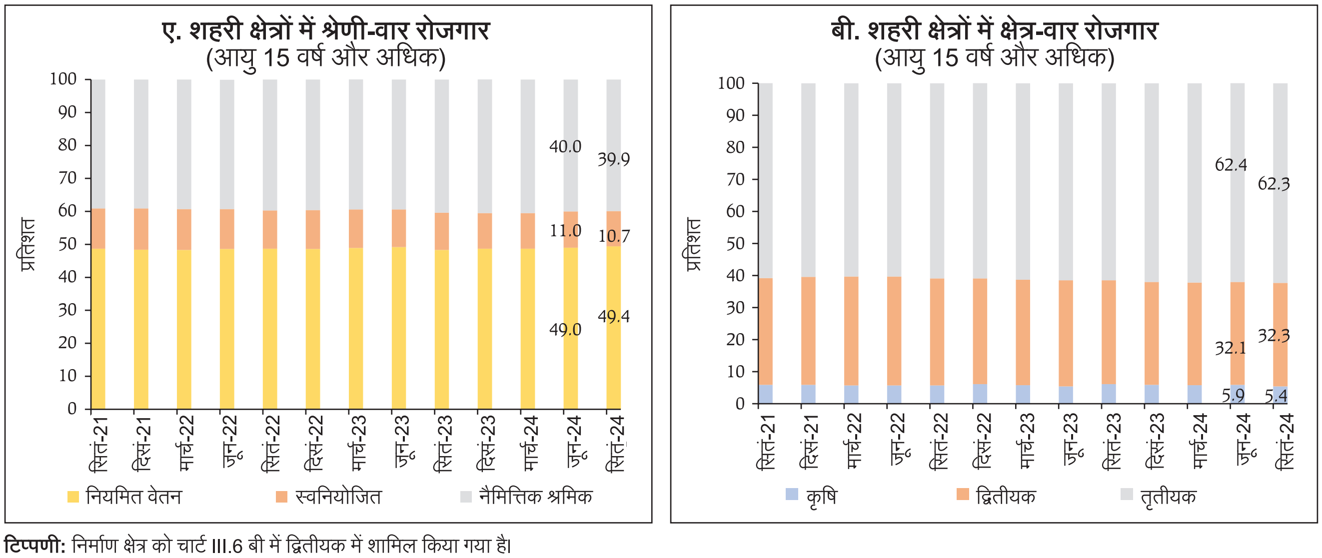

टिप्पणी: निर्माण क्षेत्र को चार्ट III.6 बी में द्वितीयक में शामिल किया गया है।
स्रोत : एमओएसपीआई।

चार्ट III.7: पीएमआई रोजगार सूचकांक

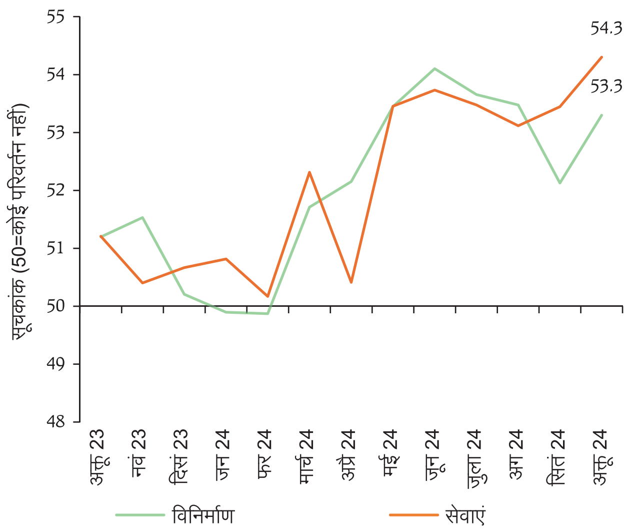

टिप्पणी: 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य विस्तार को इंगित करता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.8: मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले परिवार

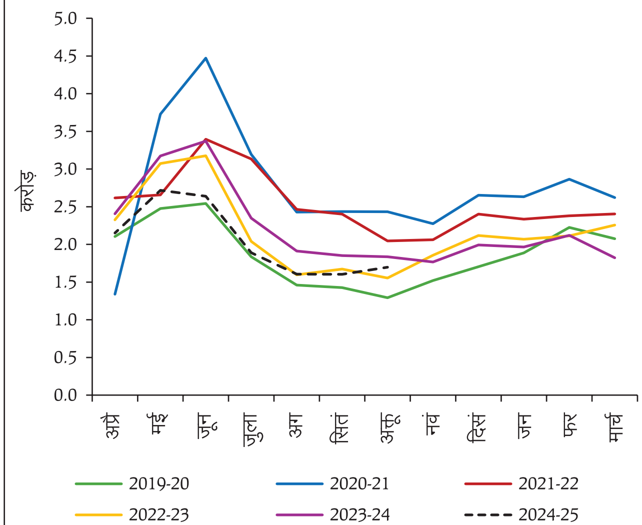

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

वर्षों की तुलना में कम रही है (चार्ट III.8)। हालांकि अक्टूबर में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई थी, यह एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही है, जो वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देती है।

अक्टूबर 2024 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मजबूत गति और अनुकूल आधार प्रभाव दोनों से प्रेरित है (चार्ट III.9)।

अक्टूबर में 30 प्रमुख जिंसों में से 25 (निर्यात बास्केट का 72.8 प्रतिशत हिस्सा) का निर्यात सालाना आधार पर बढ़ा। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, चावल और सभी वस्त्रों के रेडीमेड वस्त्र (आरएमजी) निर्यात वृद्धि के मुख्य वाहक रहे, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, लौह अयस्क, और सिरेमिक उत्पादों और कांच के बने पदार्थ ने कमी दर्ज की (चार्ट III.10)। अप्रैल-अक्टूबर 2024

चार्ट III.9: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

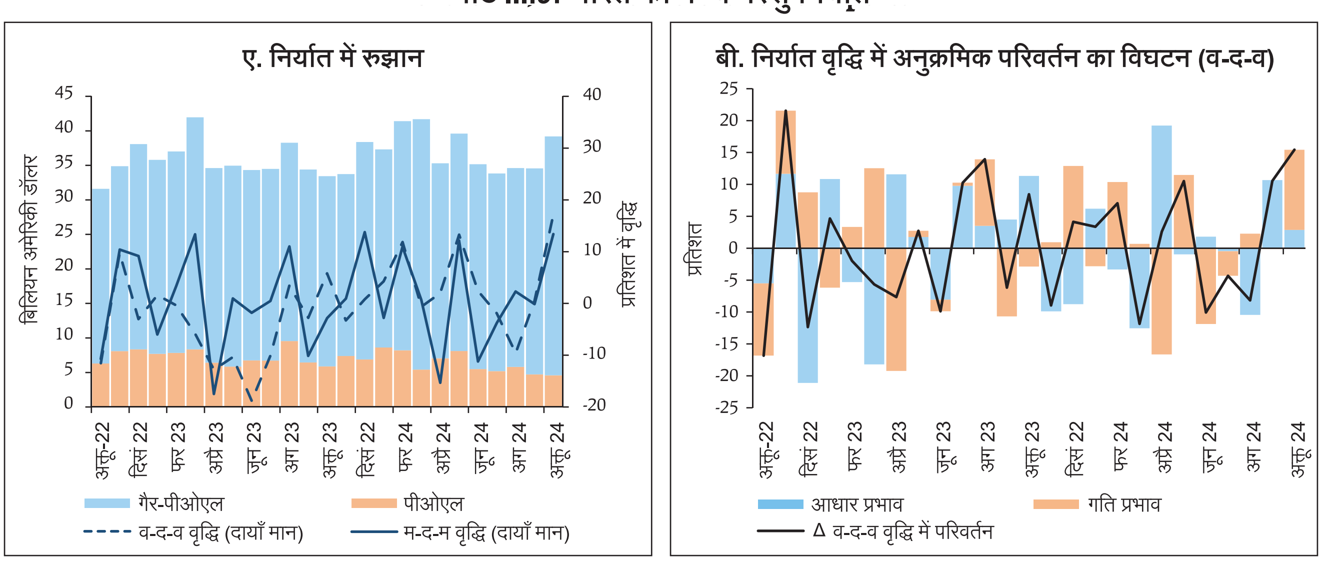

टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); डीजीसीआई एंड एस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.10: भारत का पण्य वस्तु निर्यात – सापेक्ष योगदान (अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024)

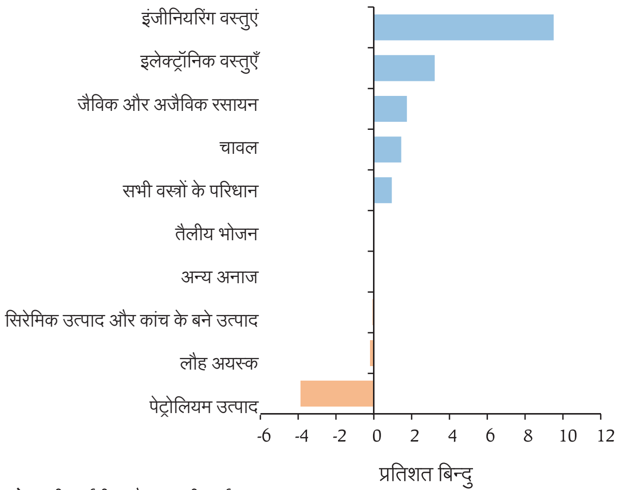

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

के दौरान, भारत का पण्य निर्यात 3.2 प्रतिशत बढ़कर 252.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका कारण मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा और औषधि, रसायन और सभी वस्त्रों के रेडीमेड ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क और समुद्री उत्पादों ने निर्यात वृद्धि को कम कर दिया।

अक्टूबर में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 17 का निर्यात वार्षिक आधार पर बढ़ा। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 के निर्यात में विस्तार देखा गया, जिसमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य थे।

पण्य वस्तुओं के आयात में अक्टूबर में लगातार सातवें महीने विस्तार हुआ और यह सकारात्मक गति के कारण 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ 66.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.11)। 30 प्रमुख जिंसों में से 20 जिंसों (आयात बास्केट का 68.4 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया गया।

पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, अलौह धातु, और मशीनरी ने सकारात्मक योगदान दिया, जबकि चांदी, कोयला, कोक और ब्रिकेट, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, परिवहन उपकरण और स्वर्ण ने अक्टूबर में आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.12)। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, 416.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के पण्य आयात में 5.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका कारण मुख्य रूप से पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण, अलौह धातु और मशीनरी रहे। मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला, कोक और ब्रिकेट,

चार्ट III.11: भारत का पण्य वस्तु आयात

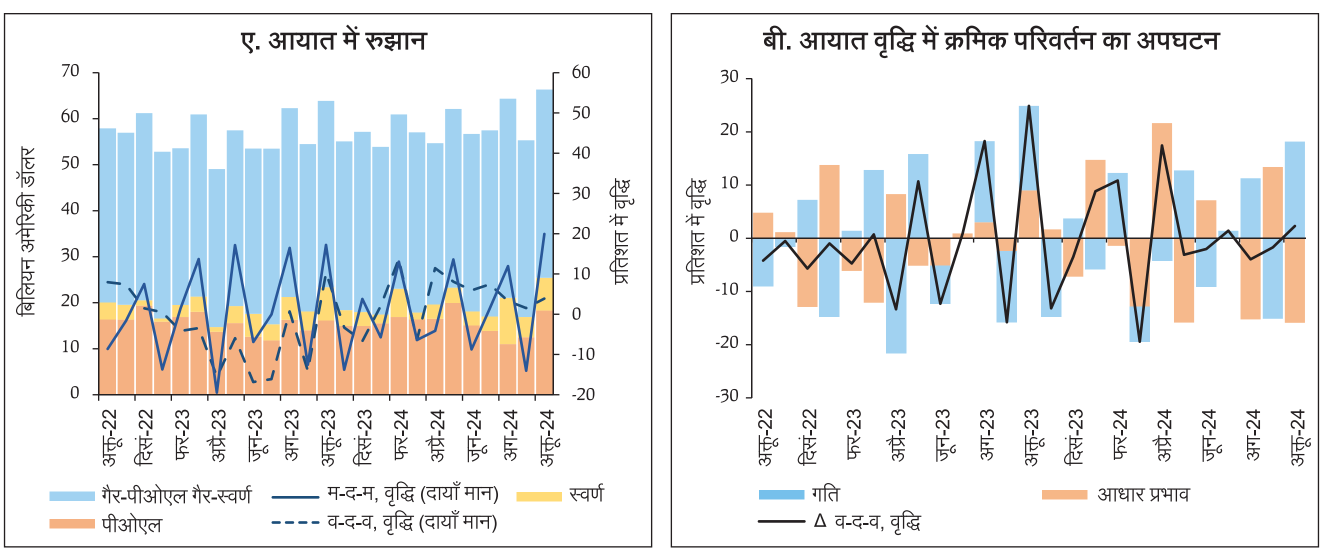

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान.

चार्ट III.12 भारत का पण्य वस्तु आयात-सापेक्ष योगदान
(अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024)

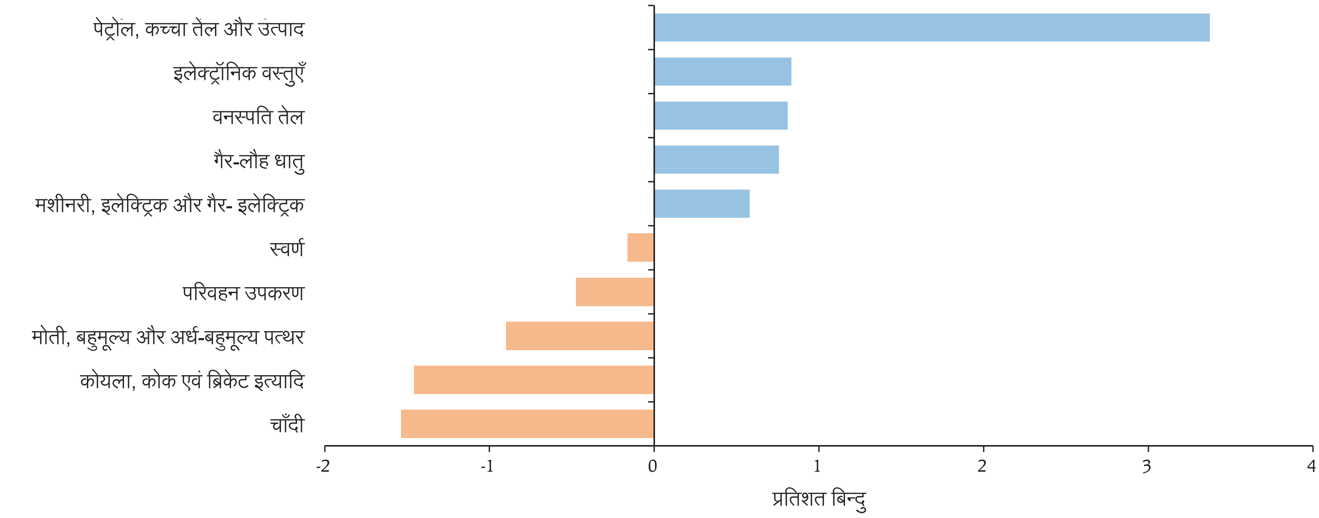

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

रासायनिक सामग्री और उत्पाद, उर्वरक, और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री ने नकारात्मक योगदान दिया।

अक्टूबर में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 11 से आयात में विस्तार हुआ, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में वृद्धि हुई।

अक्टूबर 2024 में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पण्य वस्तु व्यापार घाटा अक्टूबर 2023 में 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था, जबकि पिछले महीने से इसमें क्रमिक वृद्धि हुई थी। अक्टूबर में तेल घाटा एक वर्ष पहले के 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नतीजतन, पण्य वस्तु व्यापार घाटे में तेल घाटे का हिस्सा एक वर्ष पहले के 33.7 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 50.5 प्रतिशत हो गया। गैर-तेल घाटा एक वर्ष पहले के 20.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अक्टूबर में 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.13)।

चार्ट III.13: भारत के पण्य वस्तु व्यापार घाटे का अपघटन

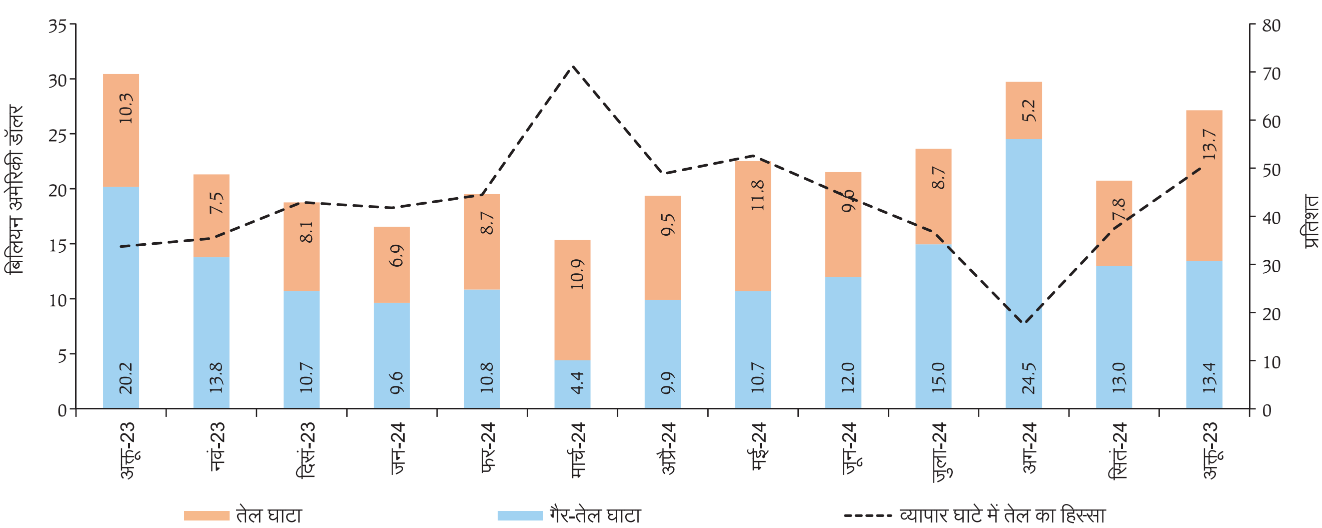

स्रोत: पीआईबी; और डीजीसीआईएस।

चार्ट III.14: कमोडिटी-वार पण्य वस्तु व्यापार घाटा

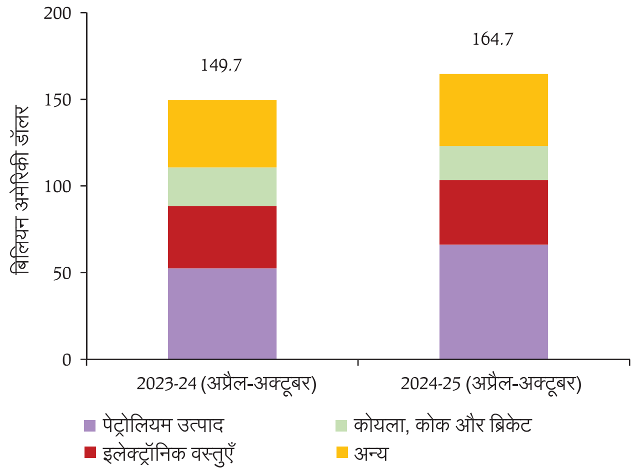

टिप्पणी: अक्टूबर 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट निर्यात सितंबर 2024 के समान रहे।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 149.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 164.7 बिलियन हो गया। घाटे का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.14)।

सितंबर 2024 के दौरान सेवा निर्यात 14.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 32.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का आयात 13.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.15)। इससे निवल सेवा निर्यात आय में 16.1 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई और यह इस माह के उच्चतम स्तर 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान, भारत की निवल सेवा निर्यात आय एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 75.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 84.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

केंद्र सरकार के सभी प्रमुख प्रमुख घाटे के संकेतक, अर्थात, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफ़डी), राजस्व घाटा (आरडी), और प्राथमिक घाटे (पीडी) ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि (यानी, 2023-24 की पहली छमाही) की तुलना में सुधार दर्ज किया [दोनों निरपेक्ष रूप से और साथ ही बजट अनुमानों (बीई) का प्रतिशत]। जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 29.4 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 39.3 प्रतिशत था (चार्ट III.16ए और 16बी)। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान यह सुधार राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि के कारण दर्ज किया गया। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कुल व्यय (लगभग ₹21.1 लाख करोड़) पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष सामान्य रहा।

चार्ट III.15: सेवा निर्यात और आयात: वृद्धि दर

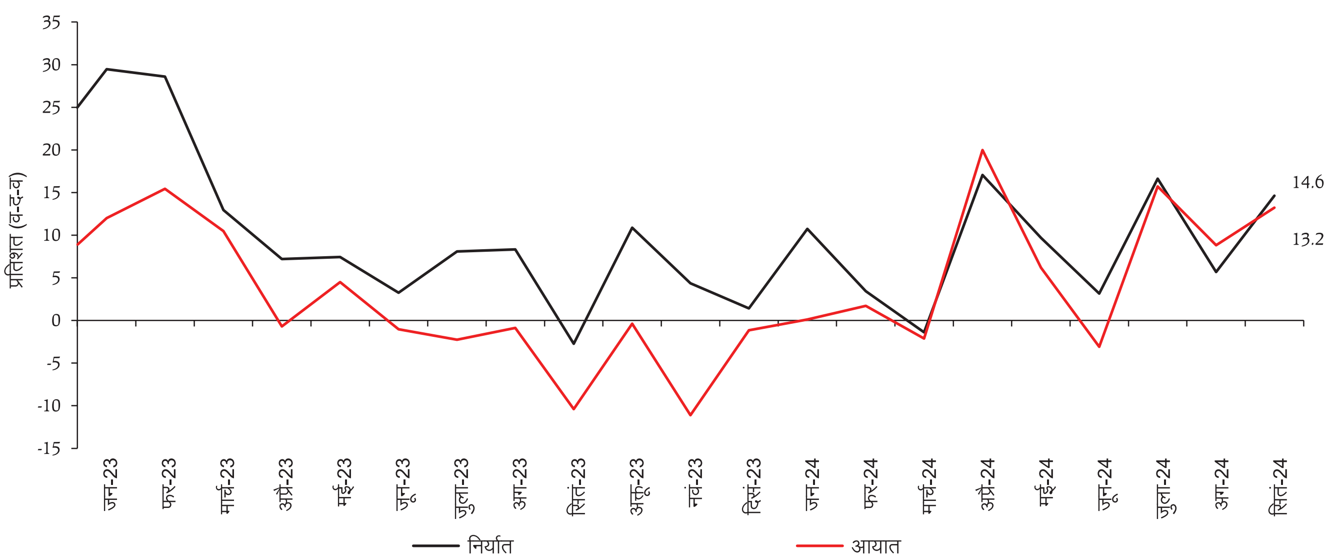

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट III.16: बजटीय घाटा (अप्रैल-सितंबर)

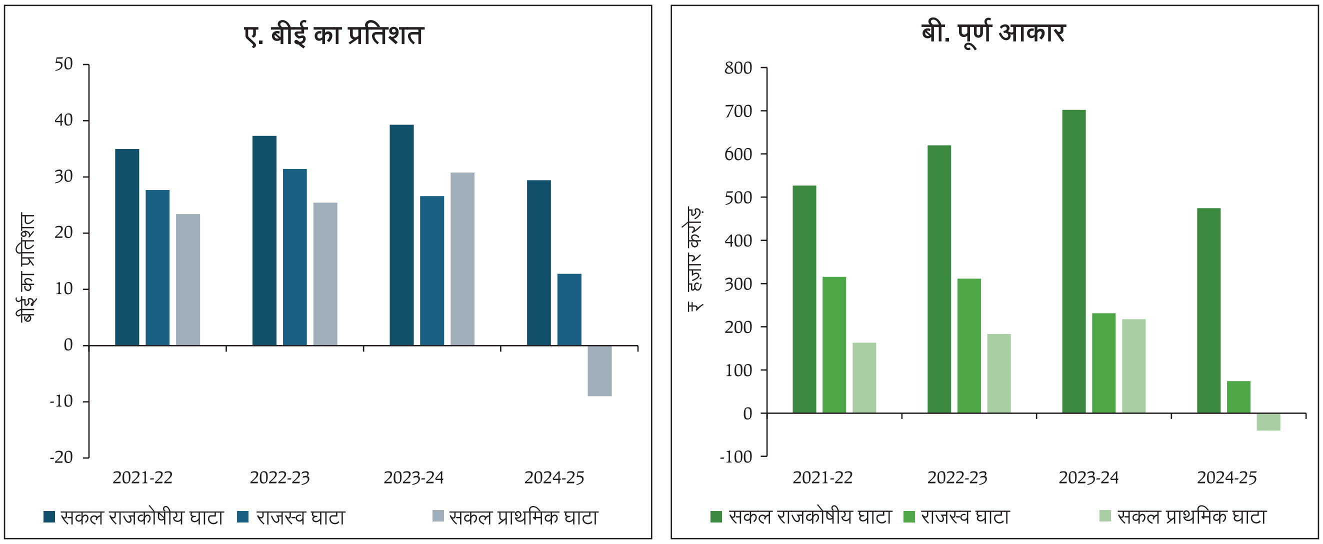

स्रोत : स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व व्यय वृद्धि घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई, जो 2023-24 की पहली छमाही में दर्ज 10.0 प्रतिशत थी, जबकि पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पूंजीगत व्यय में संकुचन को आंशिक रूप से 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के साथ-साथ जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान भारी मानसून की बारिश के प्रभाव के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान, हालांकि, पूंजीगत व्यय में 10.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ उछाल आया। प्रमुख सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) पर व्यय में 2024-25 की पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो खाद्य सब्सिडी व्यय में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है, जबकि आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में गिरावट के कारण उर्वरक सब्सिडी 18.8 प्रतिशत तक संकुचित हुई।

प्राप्तियों के पक्ष में, सकल कर राजस्व में 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह मुख्य रूप से आयकर (25.0 प्रतिशत) और माल और सेवा कर (जीएसटी) [10.4 प्रतिशत] में मजबूत वृद्धि से प्रेरित था। इसी प्रकार, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह जैसे अप्रत्यक्ष करों में भी उच्च वृद्धि देखी गई (चार्ट III.17ए)। रिज़र्व बैंक द्वारा ₹2.1 लाख करोड़ के उच्च अधिशेष अंतरण के कारण गैर-कर राजस्व में 50.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.17बी)। विनिवेश प्राप्तियों और ऋणों की वसूली में गिरावट के कारण गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वार्षिक आधार पर 27.6 प्रतिशत की गिरावट आई। कुल मिलाकर, कुल प्राप्तियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

अक्टूबर 2024 के माह के लिए सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र संग राज्य) 1.87 लाख करोड़ रुपये (अप्रैल 2024 के बाद दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह) था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.18)। रिफंड के लिए लेखांकन के बाद, सितंबर 2024 के लिए निवल जीएसटी संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.9 प्रतिशत बढ़ रहा था। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के लिए संचयी सकल जीएसटी संग्रह 12.7 लाख करोड़ रुपये (अप्रैल-अक्टूबर 2023 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) रहा।

राज्यों का जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमानों का 43.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर से कम है (चार्ट III.19)।[15]

[15] आंकड़े 22 राज्यों से संबंधित हैं।

चार्ट III.17: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-सितंबर)

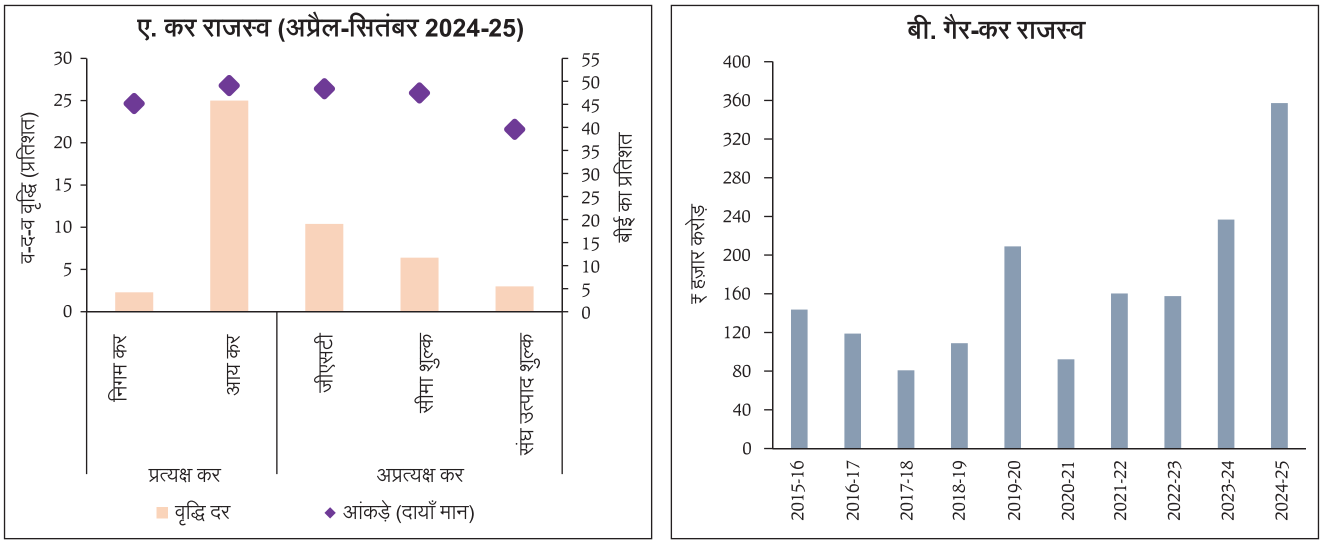

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

कर राजस्व में दोहरे अंकों की वृद्धि से प्रेरित राजस्व प्राप्तियों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि केंद्र सरकार से गैर-कर राजस्व और अनुदान संकुचित हुए (चार्ट III.20ए)। इस अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में तेजी आई, जबकि पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.20बी)। हालांकि, पूंजीगत व्यय ने वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान सुधार के संकेत दिखाए।

सकल आपूर्ति

वर्ष 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों (एई) के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न (चावल, मोटे अनाज और दलहन) का उत्पादन रिकॉर्ड 164.7 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 5.7 प्रतिशत अधिक है, जो इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडबल्यूएम) के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा गतिविधि के

चार्ट III.18: मासिक जीएसटी राजस्व

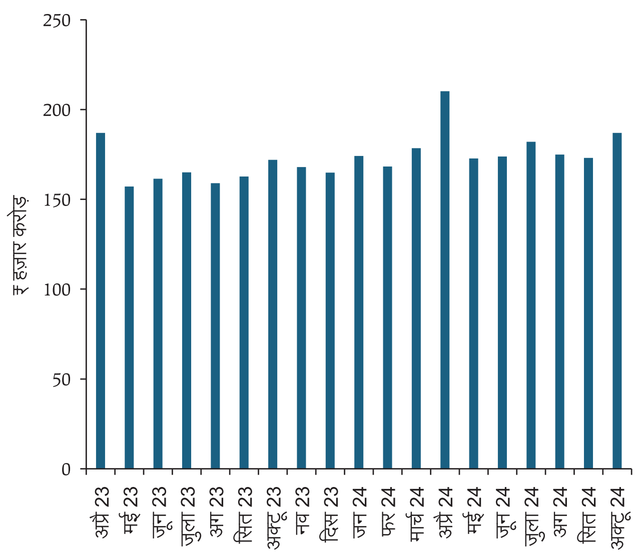

स्रोत: पीआईबी; और जीएसटी पोर्टल।

चार्ट III.19: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-सितंबर)

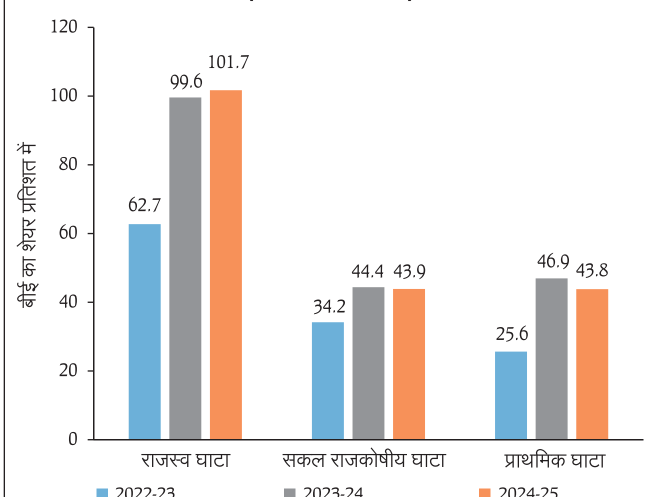

टिप्पणियाँ: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।

चार्ट III.20: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-सितंबर)

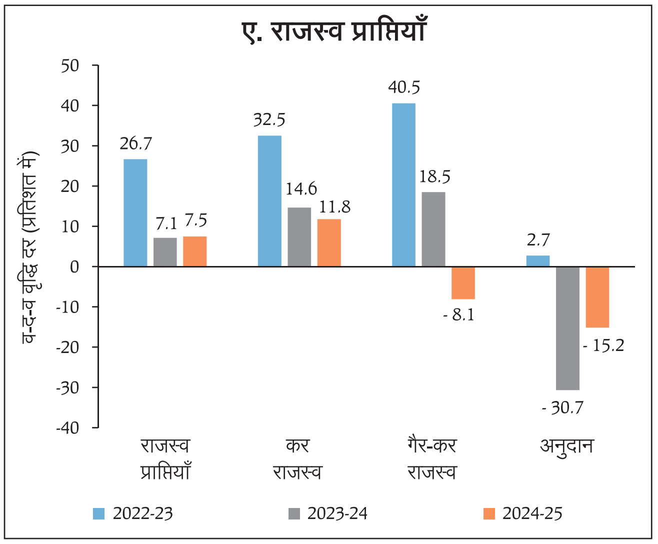

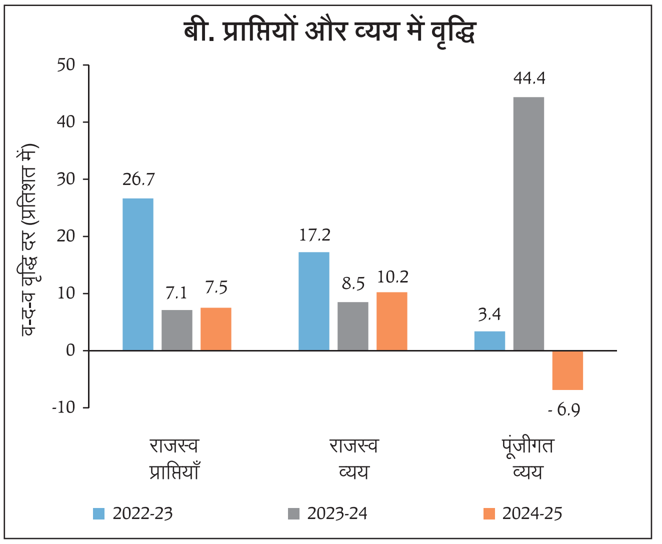

टिप्पणी: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट III.21)। प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, मक्का और मूंगफली के उत्पादन का भी रिकॉर्ड स्तर पर अनुमान लगाया गया है।

एसडबल्यूएम 15 अक्टूबर 2024 को पूरे देश से हट गया, जिसने दक्षिण-पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) वर्षा गतिविधि की एक साथ शुरुआत को भी चिह्नित किया। 01 अक्तूबर-नवम्बर 2017 के दौरान एनईएम की संचयी वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 10 प्रतिशत कम थी जबकि पिछले वर्ष यह एलपीए से 27 प्रतिशत कम थी। 07 नवंबर 2024 तक, अखिल भारतीय औसत जल भंडारण (155 प्रमुख जलाशयों पर आधारित) कुल क्षमता का 86 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष और दशकीय औसत की तुलना में क्रमशः 25.2 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.22ए)। पर्याप्त बारिश और जलाशयों के स्तर से रबी उत्पादन की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं।

चार्ट III.21 *खरीफ* उत्पादन

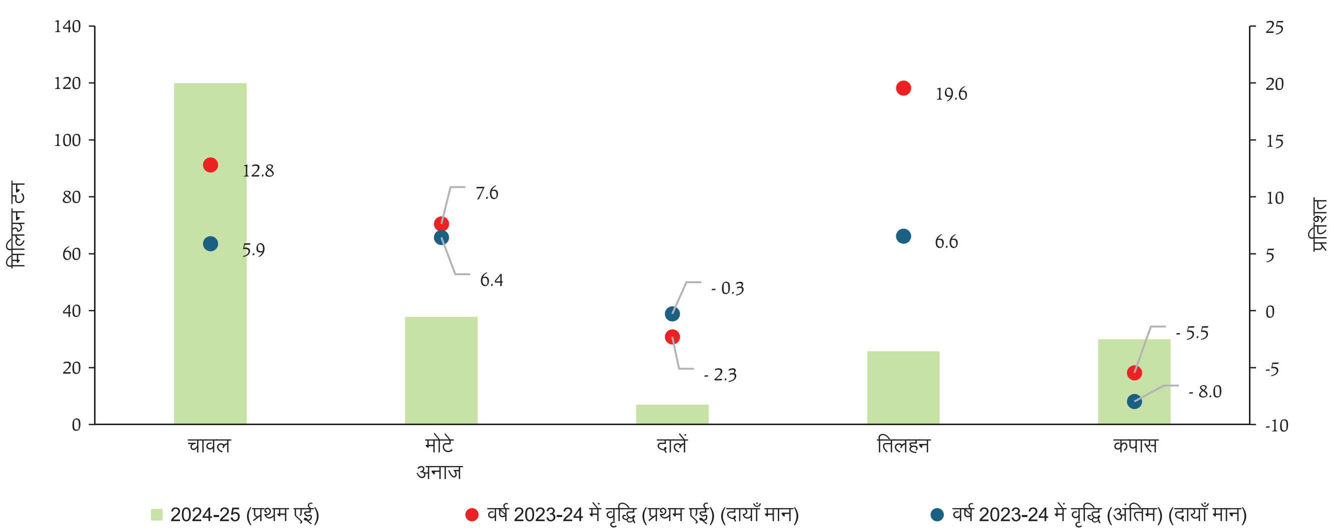

टिप्पणी: कपास को प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों के रूप में मापा जाता है।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट III.22: रबी सीजन के लिए परिदृश्य

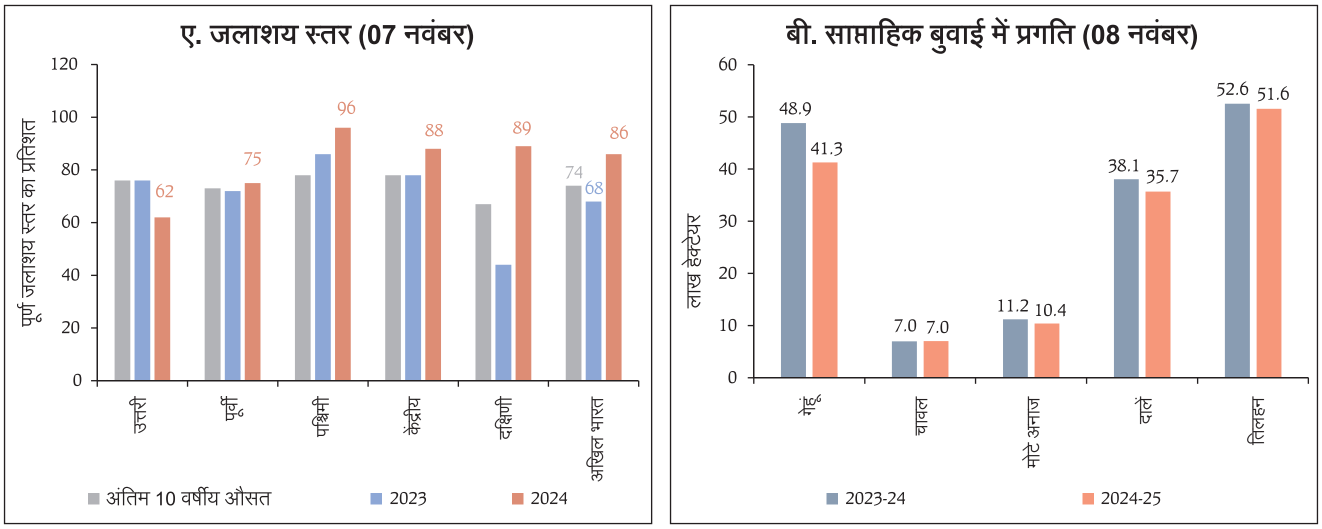

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग। **स्रोत:** https://agriwelfare.gov.in/Documents/CWWGDATA/mom21_0.doc

08 नवंबर 2024 तक कुल रबी बुवाई क्षेत्र 146.1 लाख हेक्टेयर (पूर्ण मौसम सामान्य क्षेत्र का 23.0 प्रतिशत) था, जो पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के दौरान बोए गए 157.7 लाख हेक्टेयर से कम था (चार्ट III.22बी)।

खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) वर्ष 2024-25 के लिए चावल की खरीद 30 सितंबर 2024 को शुरू हुई। 12 नवंबर तक, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 151.4 लाख टन की तुलना में 133.2 लाख टन था (चार्ट III.23)। चावल का बफर स्टॉक[16] 01 नवंबर 2024 तक 440.8 लाख टन (मानक का 4.3 गुना) था, जबकि गेहूं का स्टॉक 222.6 लाख टन (मानक का 1.1 गुना) रहा।

चार्ट III.23: केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली: खरीद और स्टॉक

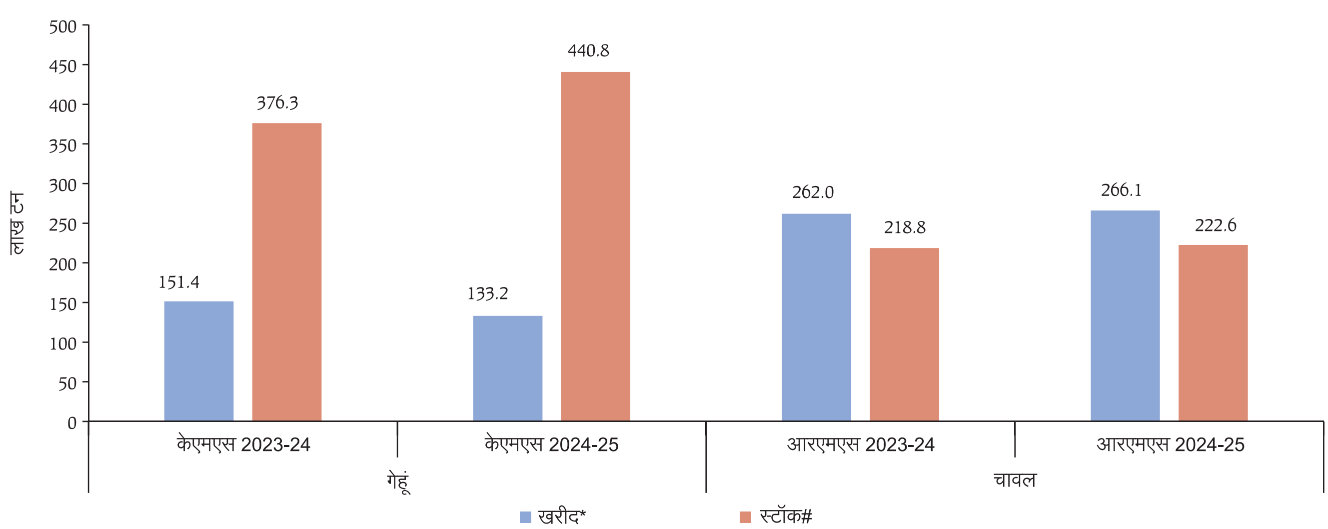

टिप्पणी: *: 12 नवंबर तक; #: 01 नवंबर तक।

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम।

[16] जिसमें अनमिल्ड धान समकक्ष भी शामिल है।

चार्ट III.24: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

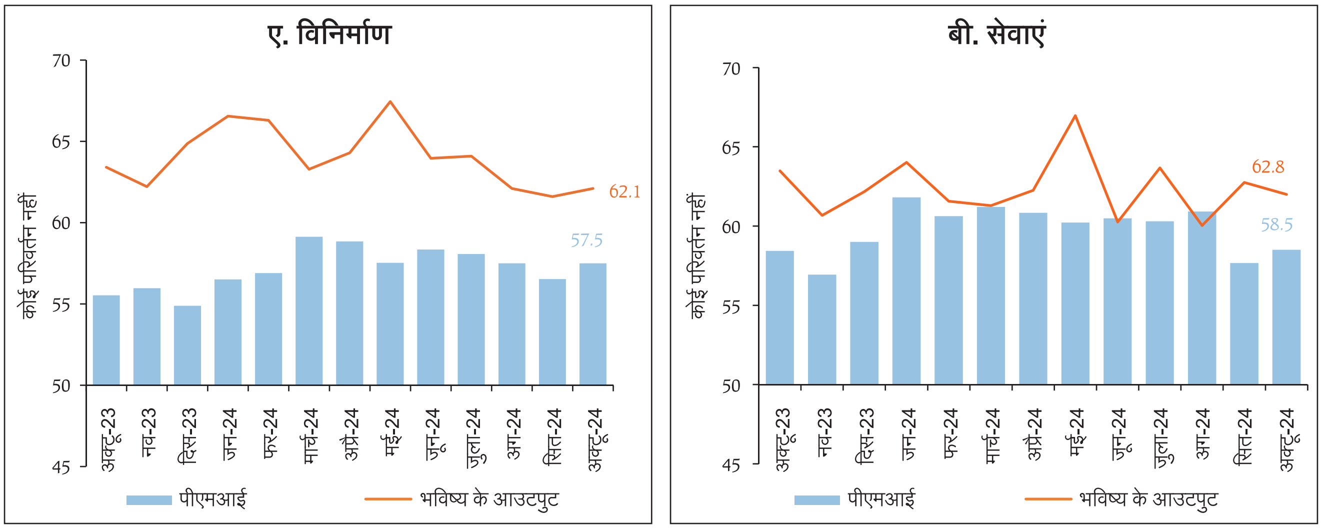

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

ऑर्डर, रोजगार और नए आउटपुट में वृद्धि के कारण अक्टूबर 2024 में भारत का विनिर्माण पीएमआई तेज हुआ (चार्ट III.24ए)। सेवा पीएमआई भी अक्टूबर 2024 में बढ़कर 58.5 हो गया, जो सितंबर में 10 महीने के निचले स्तर 57.7 पर था, जो मजबूत मांग की स्थिति से प्रेरित था (चार्ट III.24बी)। विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक अपेक्षाओं में सुधार प्रदर्शित हुआ, जबकि भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि सेवाओं में कमी हुई।

स्वच्छ ऊर्जा संचरण की दिशा में भारत की प्रगति ने अक्टूबर 2024 में अक्षय उत्पादन क्षमता 200 गीगावाट (जीडबल्यू) को पार करने के साथ एक उपलब्धि हासिल की, जो कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है (चार्ट III.25)।

चार्ट III.25: नवीकरणीय स्थापित क्षमता

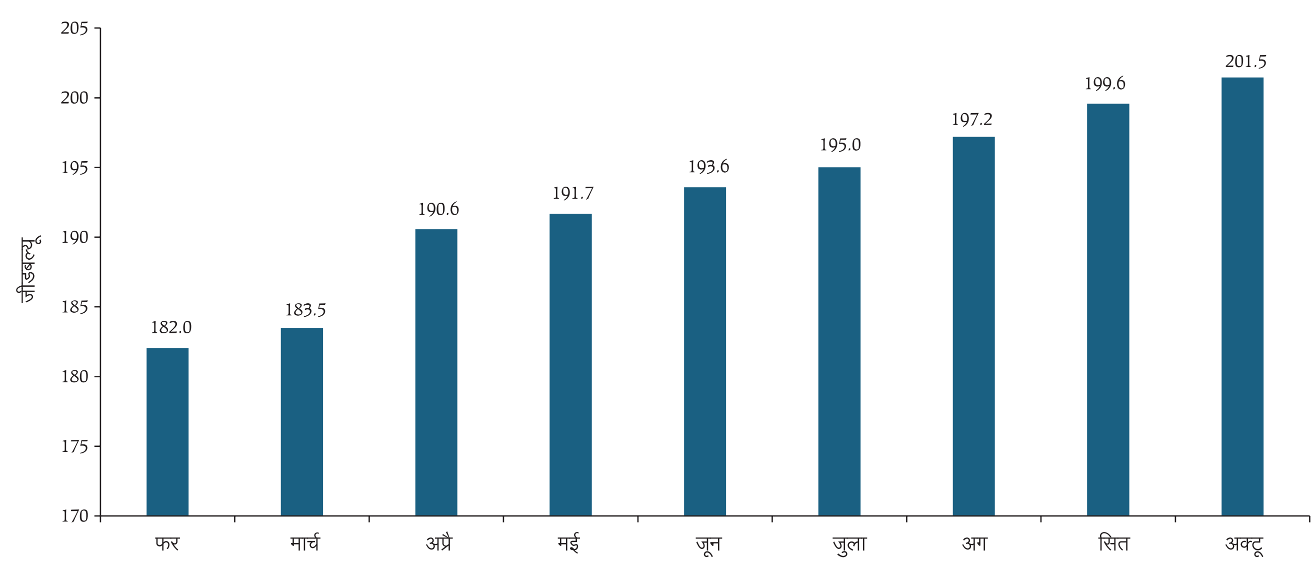

स्रोत: नीति आयोग डैशबोर्ड।

चार्ट III.26: पोर्ट कार्गो

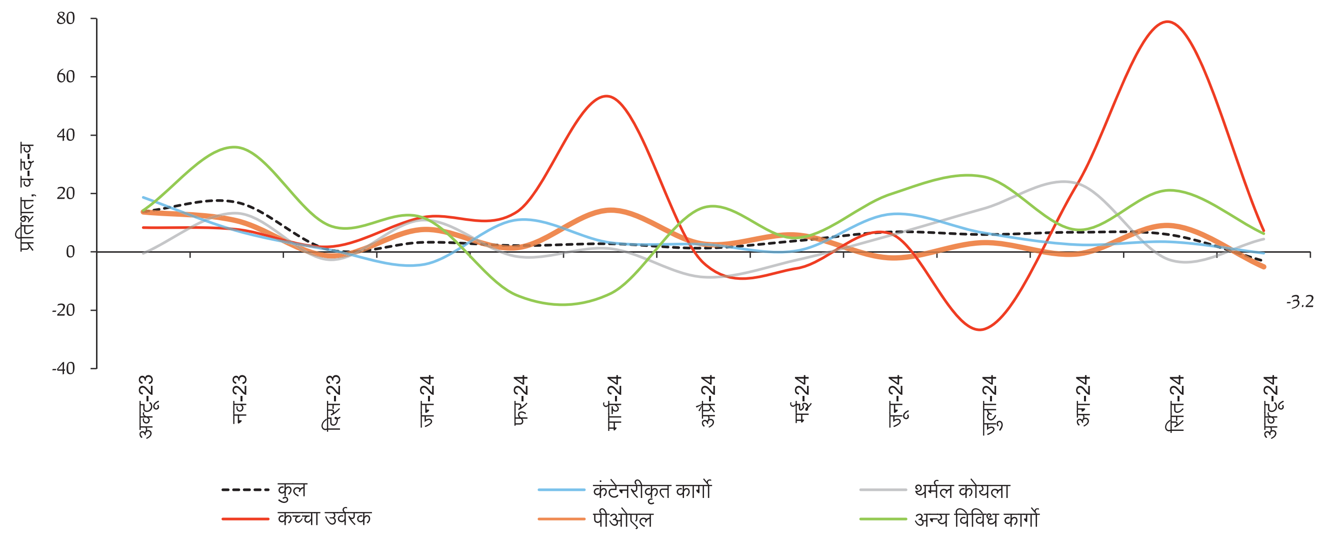

स्रोत: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।

जैसा कि परिचयात्मक खंड में वर्णित है, हाल के वर्षों में सौर और पवन क्षमता परिवर्धन के कारण, भारत अक्षय क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। चार राज्यों, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने भारत में अक्षय क्षमता का लगभग आधा हिस्सा लिया।

अक्टूबर 2024 में पोर्ट ट्रैफिक संकुचित हुआ, जो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक द्वारा संचालित था (चार्ट III.26)।

अक्टूबर में इस्पात की खपत में 9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि और सितंबर 2024 में सीमेंट उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्माण क्षेत्र ने गति पकड़ी (चार्ट III.27)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक सितंबर/अक्टूबर 2024 में आर्थिक गतिविधि में कर्षण को दर्शाते हैं। त्योहारी सीजन और एसडब्ल्यूएम की मंदी के कारण, लॉजिस्टिक्स गतिविधि में वृद्धि हुई जैसा कि ई-वे बिल और

चार्ट III.27: इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन

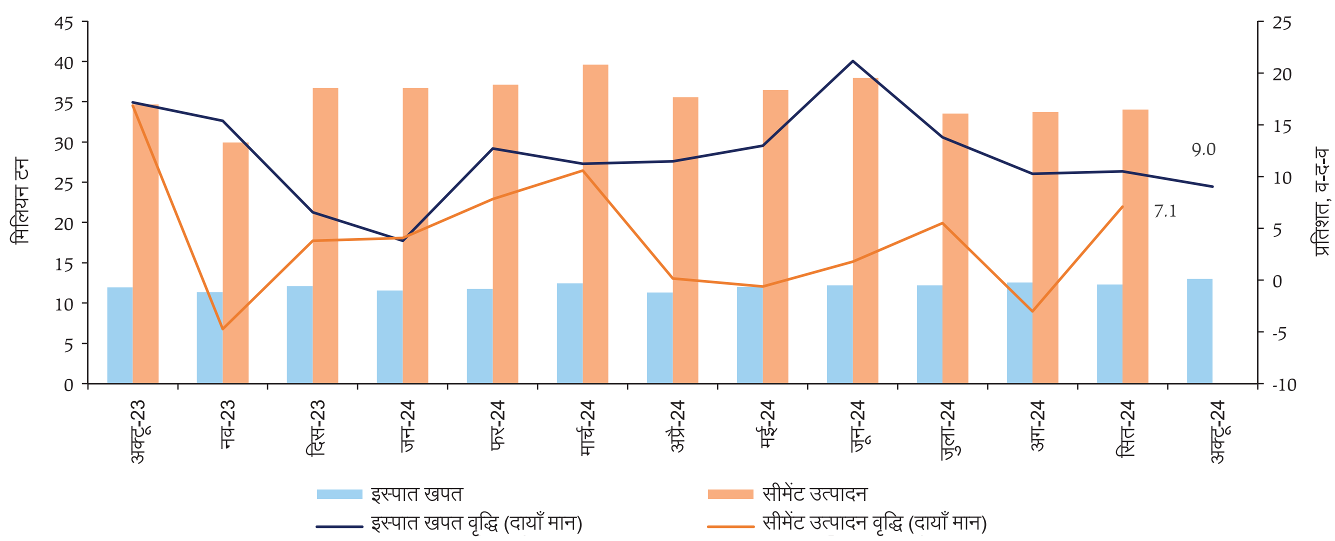

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक - सेवाएं

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सित-24	अक्टू-24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	33.9	21.0	21.7	31.9	27.0	26.0	1.3	4.0	3.1	-2.5	-1.8	-1.4	0.9
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	7.1	-0.2
	ट्रैक्टर की बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	3.2			-3.8			3.5			-11.0			
	रेलवे मालभाड़ा यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0		
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.2
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात *	10.6	9.0	8.7	10.0	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	-13.7
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात *	15.0	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	-0.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात *	10.7	8.7	8.1	5.0	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	10.0
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	17.5	19.8	18.1	17.0	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	9.3
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4
	होटल अधिवास	9.3	-8.6	1.6	2.6	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7		
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2		
	पर्यटकों का आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3			
निर्माण	इस्पात की खपत	15.3	14.5	13.7	12.3	7.0	12.5	11.5	13.0	21.1	13.8	10.3	10.5	9.0
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	-3.0	7.1	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5

<< संकुचन ------------------------------------ विस्तार >>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों में है।

*: अक्टूबर 2024 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत के आधार पर है। जुलाई 2021 से अब तक के लिए प्रत्येक संकेतक का हीट-मैप बनाया गया है।

स्रोत: एसआईएएम; रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; भारतीय पोर्ट संघ; वित्तीय सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनरॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

टोल संग्रह में परिलक्षित होता है। निर्माण ने भी गति पकड़ी जैसा कि इस्पात की खपत और सीमेंट की मांग में देखा गया है (सारणी III.1)

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय सीपीआई[17] में वर्षानुवर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.28)। लगभग 70 आधार अंकों (बीपीएस) की मुद्रास्फीति में वृद्धि लगभग 135 बीपीएस की सकारात्मक गति से हुई, जिसे 65 आधार अंकों के अनुकूल आधार प्रभाव द्वारा आंशिक रूप से संतुलित किया गया था। सीपीआई खाद्य और सीपीआई कोर (यानी, सीपीआई खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों ने क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत की म-द-म वृद्धि दर्ज की, जबकि सीपीआई ईंधन सूचकांक अपरिवर्तित रहा।

अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 8.4 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों और खाद्य तेलों ने म-द-म और व-द-व दोनों आधार पर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.29)। फलों, अनाजों और उत्पादों, मांस और मछली, गैर-मादक पेय पदार्थों

[17] एनएसओ द्वारा 12 नवंबर 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.28: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

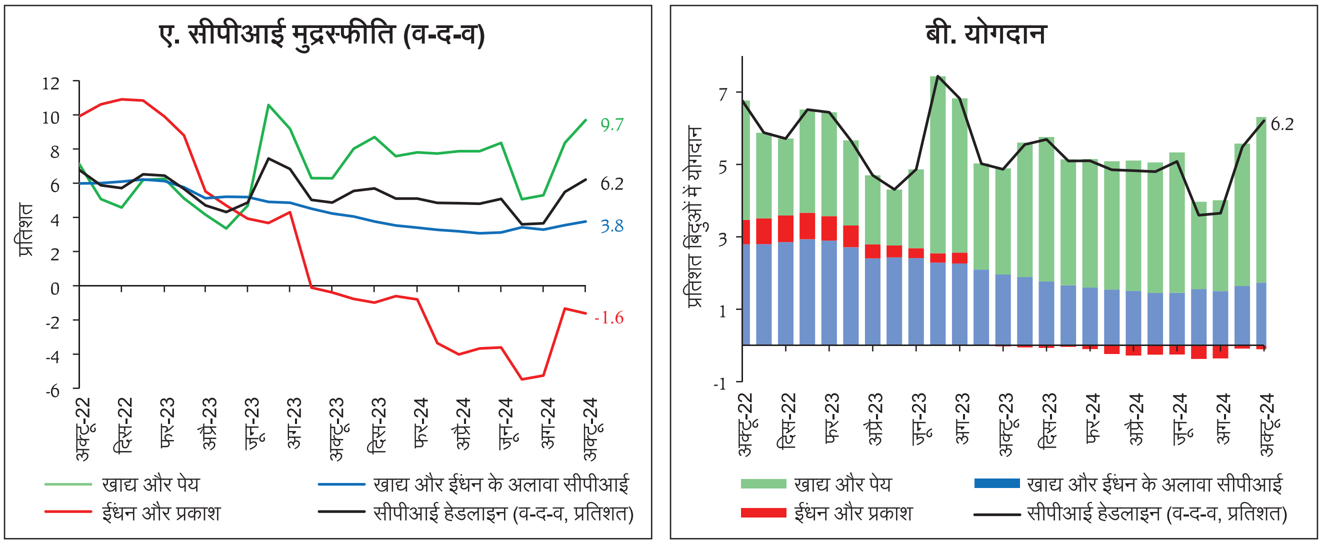

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

और तैयार भोजन के संबंध में कीमतें बढ़ीं, जबकि वे दालों और उत्पादों, अंडे और चीनी में सामान्य रहीं (चार्ट III.30)। दूध और उससे बने उत्पादों की मुद्रास्फीति में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि मसालों की कीमतों में गिरावट आई।

केरोसिन में अपस्फीति बढ़ने से ईंधन व प्रकाश अवस्फीति अक्टूबर में बढ़कर शून्य से 1.6 प्रतिशत नीचे हो गई, जो सितंबर में शून्य से 1.4 प्रतिशत नीचे थी। दूसरी ओर, विद्युत, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में

चार्ट III.29: उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (एम-ओ-एम)

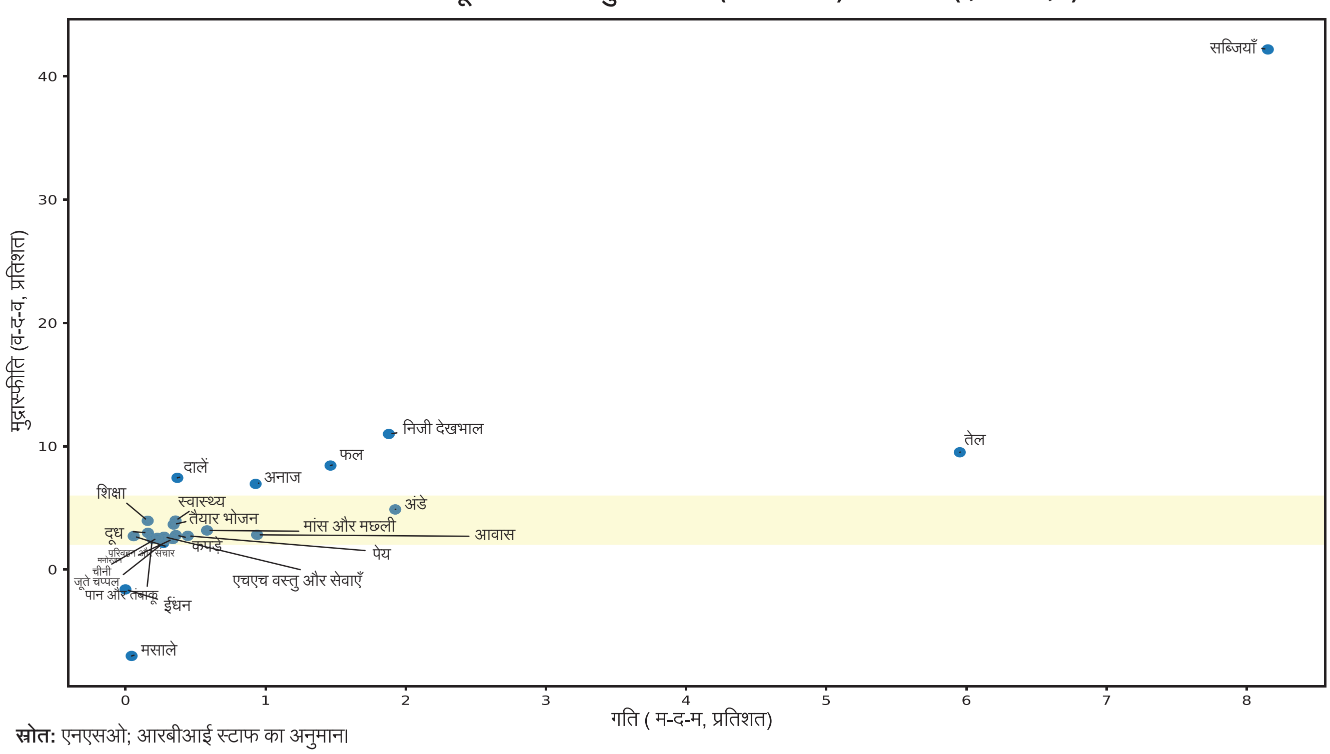

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.30 : उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024)

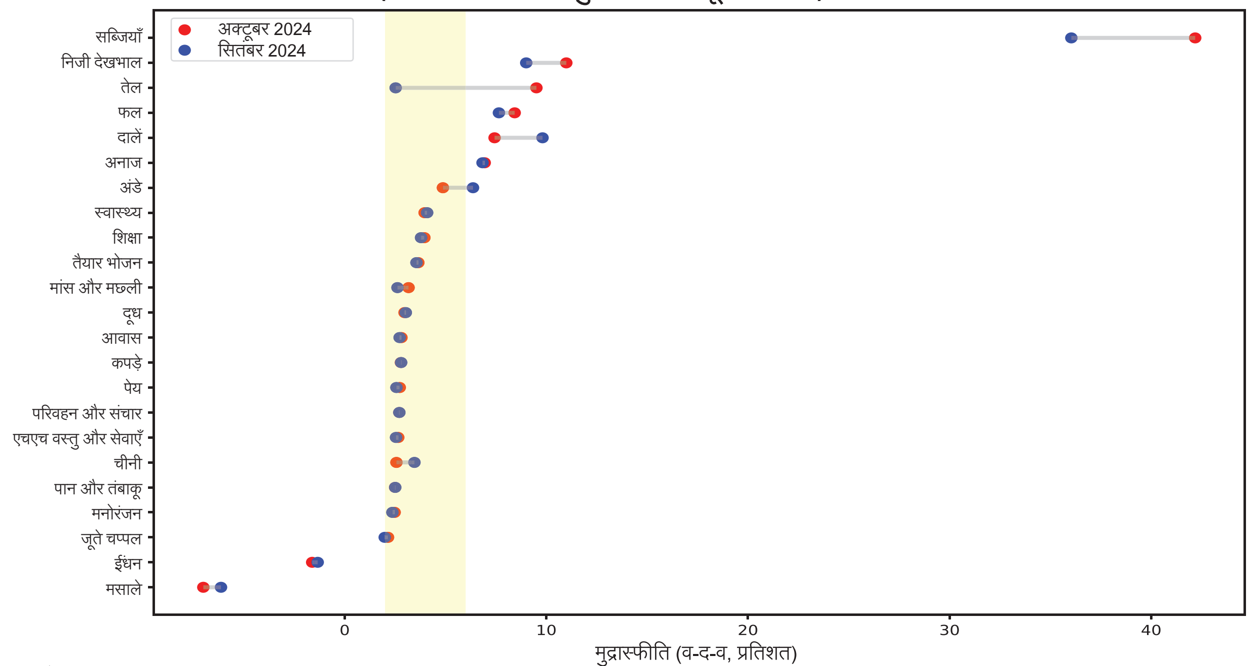

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। एलपीजी मूल्य मुद्रास्फीति स्थिर रही।

अक्टूबर में कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 3.8 फीसदी हो गई, जो सितंबर में 3.6 फीसदी थी। जबकि मुद्रास्फीति उप-समूहों जैसे कपड़े और जूते, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, और परिवहन और संचार के लिए स्थिर रही, यह खेल-कूद और मनोरंजन, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, शिक्षा और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों के संबंध में बढ़ी। स्वास्थ्य उप-समूह की कीमतों में मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, अक्टूबर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत थी, जो शहरी मुद्रास्फीति से 5.6 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकांश राज्यों ने मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की (चार्ट III.31)।

नवंबर के लिए अब तक (12 तारीख तक) खाद्य मूल्य के उच्च आवृत्ति के आंकड़े अनाज में वृद्धि (मुख्य रूप से गेहूं और आटे द्वारा संचालित) और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक दबाव दिखाते हैं। दालों की कीमतों में भी तेजी देखी गई (तुअर को छोड़कर)। प्रमुख सब्जियों में, आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि टमाटर की कीमतों में तेज़ी से कमी दर्ज की गई (चार्ट III.32)।

चार्ट III.31 : मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: अक्टूबर 2024 (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

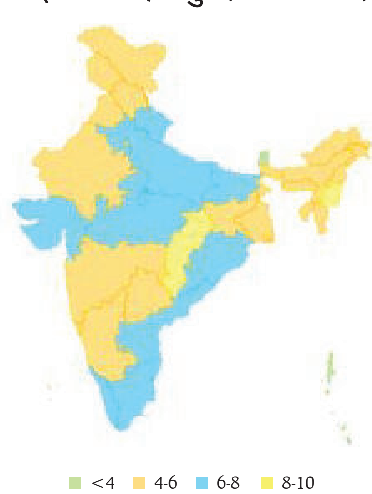

टिप्पणी: मानचित्र केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.32: डीसीए आवश्यक कमोडिटी की कीमतें

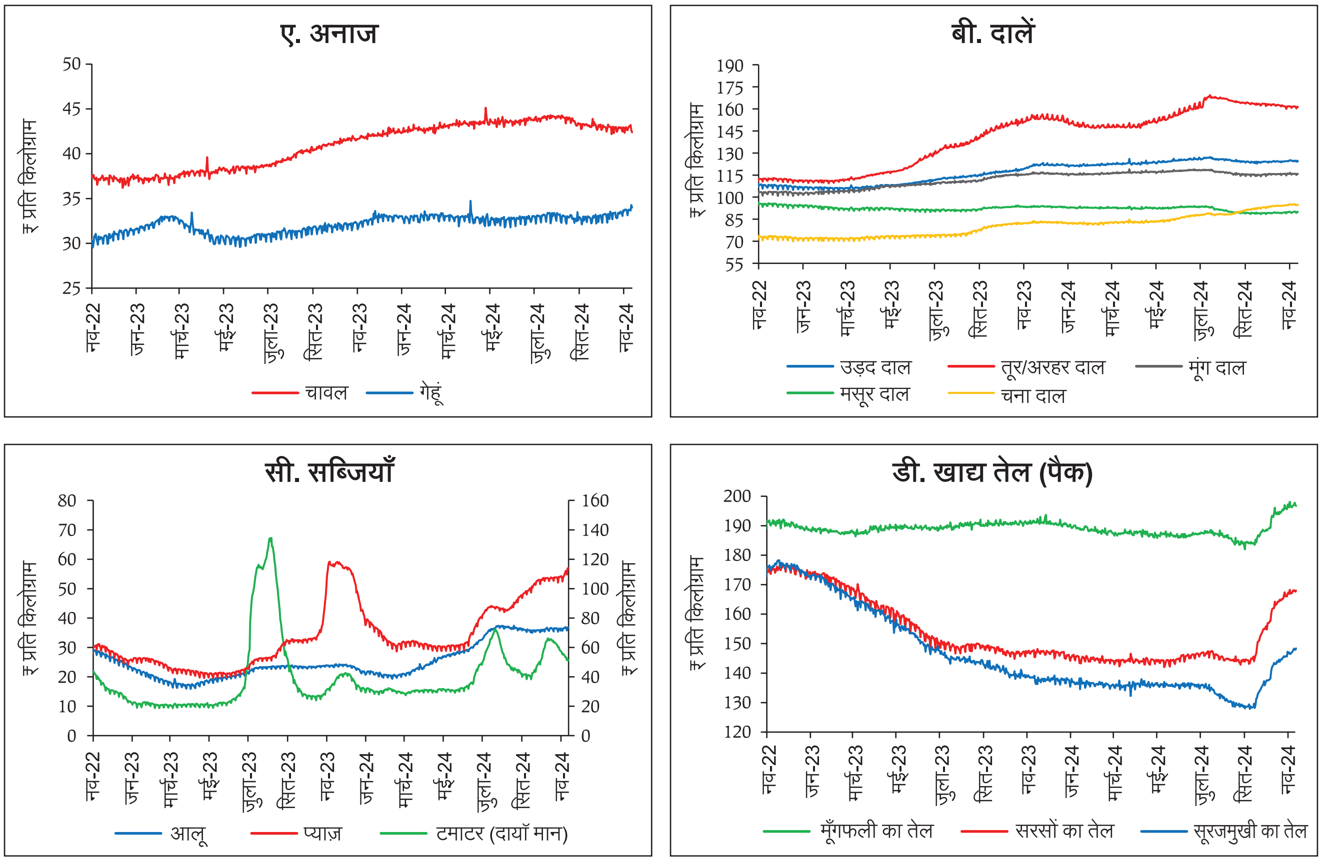

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य नवंबर में अब तक (12 तारीख तक) मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहे। जबकि मिट्टी के तेल की कीमतों में दो महीने की कमी के बाद वृद्धि हुई, एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया (सारणी III.2)।

अक्टूबर 2024 के लिए पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में विस्तार की दर में और वृद्धि का संकेत दिया। पिछले दो महीनों में विस्तार की दर में मंदी के बाद, विनिर्माण और सेवा फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव भी बढ़ गए (चार्ट III.33)।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		नव-23	अक्तू-24	नव-24^	अक्तू-24	नव-24^
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.97	100.99	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.42	90.45	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी)	₹/लीटर	55.21	42.93	43.95	-6.2	2.4
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0.0	0.0

^: 1-12 नवंबर 2024 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.33: पीएमआई इनपुट और आउटपुट कीमतें

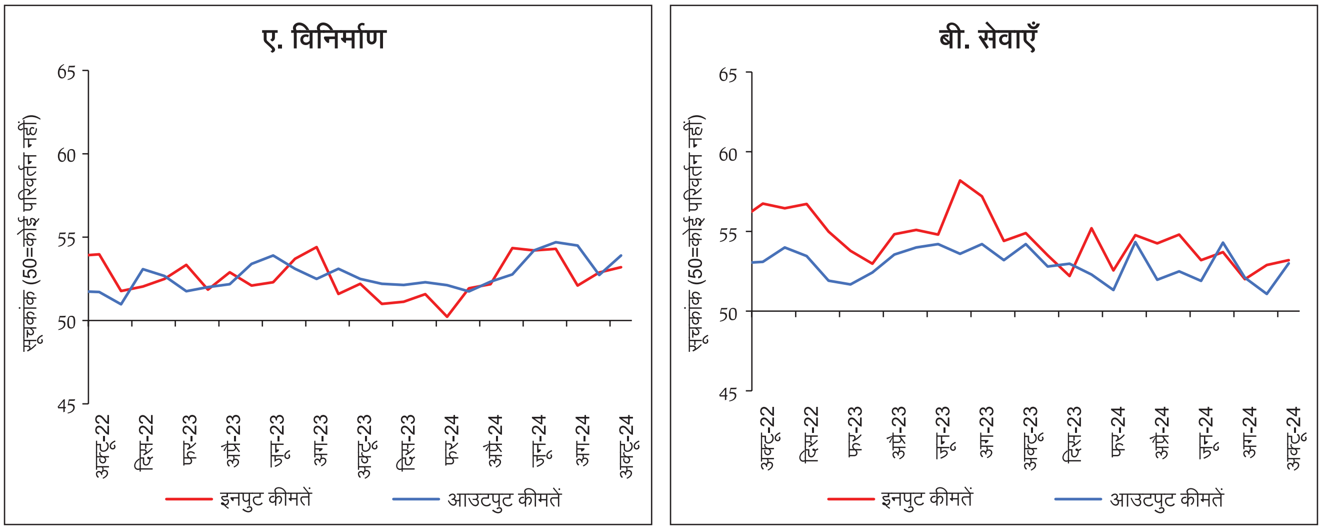

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

IV. वित्तीय स्थितियां

उच्च जीएसटी संग्रह[18] और संचलन में मुद्रा में त्योहार संबंधी विस्तार के कारण सरकारी नकद शेष में वृद्धि के साथ अक्टूबर के उत्तरार्ध में व्यवस्था में चलनिधि में कमी आई। सरकारी व्यय ने नवंबर की शुरुआत में चलनिधि की स्थिति को सहज बना दिया। कुल मिलाकर, अक्टूबर की दूसरी छमाही और नवंबर की शुरुआत के दौरान व्यवस्था चलनिधि अधिशेष में रही, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 16 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 के दौरान 1.14 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.1)। रिज़र्व बैंक ने 16 अक्टूबर से 19 नवंबर 2024 के दौरान तीन मुख्य और

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

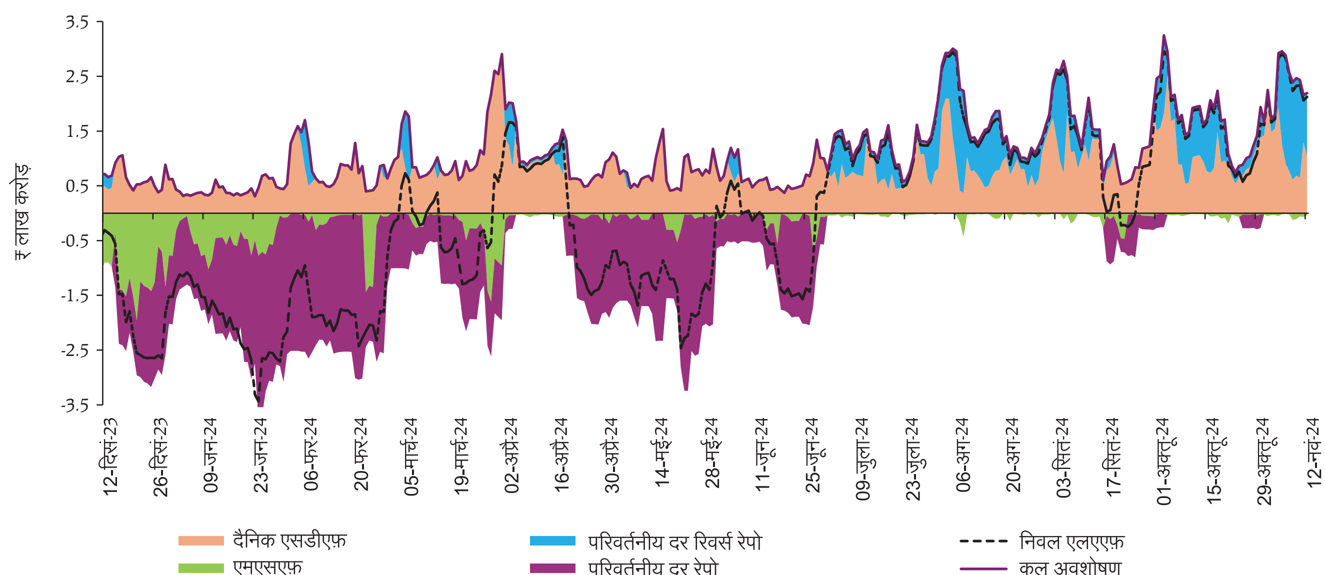

स्रोत: आरबीआई।

[18] अक्टूबर 2024 के लिए जीएसटी संग्रह ₹1.87 लाख करोड़ था, जो 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद दूसरा उच्चतम स्तर था।

सोलह सही ताल-मेल से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन किए, जिसमें बैंकिंग प्रणाली से संचयी रूप से 8.38 लाख करोड़ रुपये अवशोषित करने के लिए एकदिवस से 4-दिन तक की परिपक्वता अवधि थी। हालांकि, महीने के अंत में चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए, 25 अक्टूबर को 6 दिनों की परिपक्वता वाला एक सही ताल-मेल से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन आयोजित किया गया।

16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का निवेश लगभग 61 प्रतिशत था। जैसे-जैसे चलनिधि की स्थिति सहज हुई, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत औसत दैनिक उधारी 16 सितंबर और 15 अक्टूबर 2024 के दौरान ₹0.08 लाख करोड़ से घटकर 16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान ₹0.05 लाख करोड़ रह गई।

एकदिवसीय मुद्रा बाज़ार में, भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) एलएएफ़ कॉरिडोर के भीतर रही, जो 16 अक्टूबर और 18 नवंबर, 2024 के दौरान औसतन 6.48 प्रतिशत रही, जो 16 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2024 के दौरान लगभग समान थी(चार्ट IV.2ए)। हालांकि, डबल्यूएसीआर, अपेक्षाकृत तंग चलनिधि स्थितियों के कारण थोड़े समय (22-28 अक्टूबर) के लिए मजबूत हुई, हालांकि यह नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही। संपार्श्विक खंड में, त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो दरें क्रमशः 15 बीपीएस और 13 बीपीएस औसत रहीं, जो उसी अवधि के दौरान नीतिगत रेपो दर से कम थीं (चार्ट IV.2बी)।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल 16 अक्टूबर और 18 नवंबर के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3-माह के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3

चार्ट IV.2 : नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

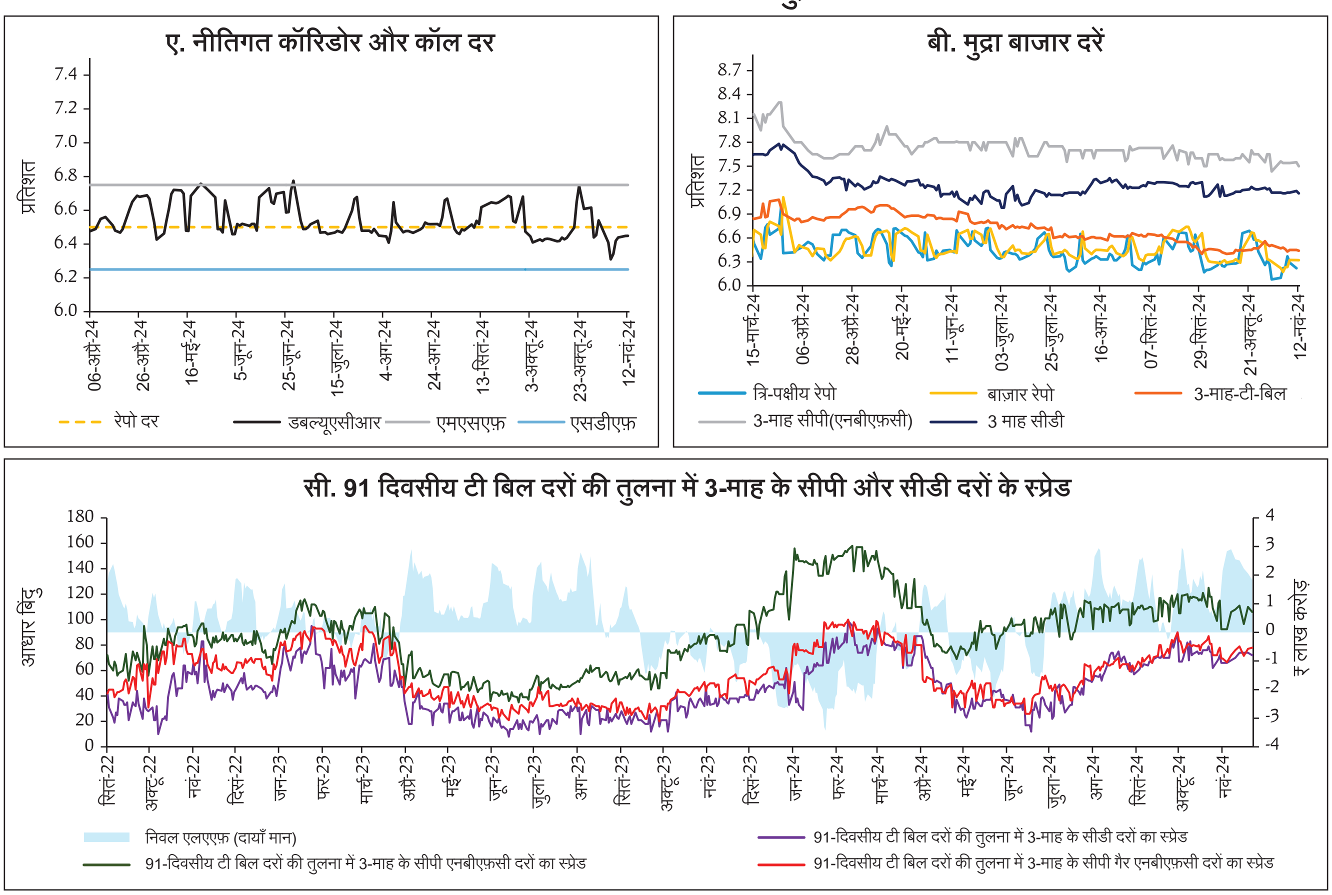

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग।

महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर दरें कम हुई (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-माह के सीपी और 91-दिवसीय टी-बिल दरों के बीच स्प्रेड) में 4 बीपीएस की गिरावट आई।

द्वितीयक बाजार में, 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3-माह के सीपी (एनबीएफसी) और सीडी दरों का स्प्रेड नवंबर 2024 (12 नवंबर तक) के दौरान क्रमशः 103 बीपीएस और 71 बीपीएस रहा - जो एक वर्ष पहले 85 बीपीएस और 36 बीपीएस से अधिक था (चार्ट IV.2सी)। हालाँकि अधिशेष चलनिधि की अवधि के दौरान स्प्रेड कम हो जाता है, लेकिन हाल के महीनों में वे मुख्य रूप से 91-दिवसीय टी-बिल दरों में गिरावट के कारण बढ़े हैं।

नवंबर 2024 (12 नवंबर तक) में सीपी की भारित औसत छूट दर (डबल्यूएडीआर) 7.44 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.70 प्रतिशत से कम है, क्योंकि एनबीएफसी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में उच्च वृद्धि की स्थिरता पर चिंताओं और भविष्य में कम ब्याज दरों की अपेक्षाओं के कारण निर्गमों को कम कर दिया (चार्ट IV.3)। ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर कम होने के कारण सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डबल्यूएईआईआर) एक वर्ष पहले के 7.39 प्रतिशत से कम होकर 7.34 प्रतिशत (12 नवंबर तक) हो गई।

प्राथमिक बाजार में, वर्ष 2024-25 में (1 नवंबर तक) के दौरान सीडी जारी करने की मात्रा 57 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹6.01 लाख करोड़ हो गई, ताकि वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹3.91 लाख करोड़ से काफी अधिक है (चार्ट IV.4)। वर्ष 2024-25 (31 अक्टूबर तक) के दौरान सीपी जारी करने की मात्रा ₹8.70 लाख करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹7.84 लाख करोड़ से अधिक थी। रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के साथ, ये संस्थाएं वित्तपोषण में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक बाज़ार लिखतों पर निर्भर हो रही हैं।

10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई, जो अमेरिकी खजाना प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को दर्शाता है (चार्ट IV.5ए)। 16 अक्टूबर - 18 नवंबर के दौरान, औसत अवधि स्प्रेड (10-वर्षीय से 91-दिवसीय टी-बिल घटाकर) 16 सितंबर - 15 अक्टूबर के दौरान 29 बीपीएस से बढ़कर 36 बीपीएस हो गया। जी-सेक प्रतिफल वक्र अवधि संरचना के लघु से मध्यम अवधि में ऊपर की ओर बढ़ा, हालांकि यह बहुत लंबे समय तक मोटे तौर पर स्थिर रहा (चार्ट IV.5बी)।

चार्ट IV.3: डबल्यूएडीआर और डबल्यूएईआईआर

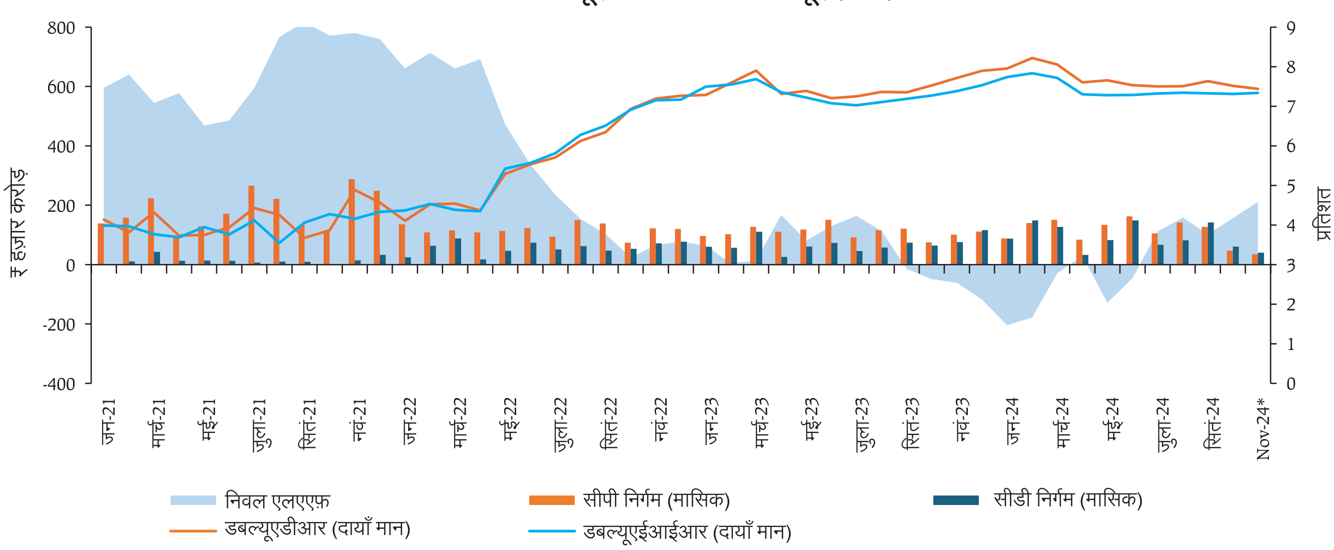

टिप्पणी: *: 12 नवंबर 2024 तक।
स्रोत: आरबीआई; और सीसीआईएल-एफटीआईआरएसी।

चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

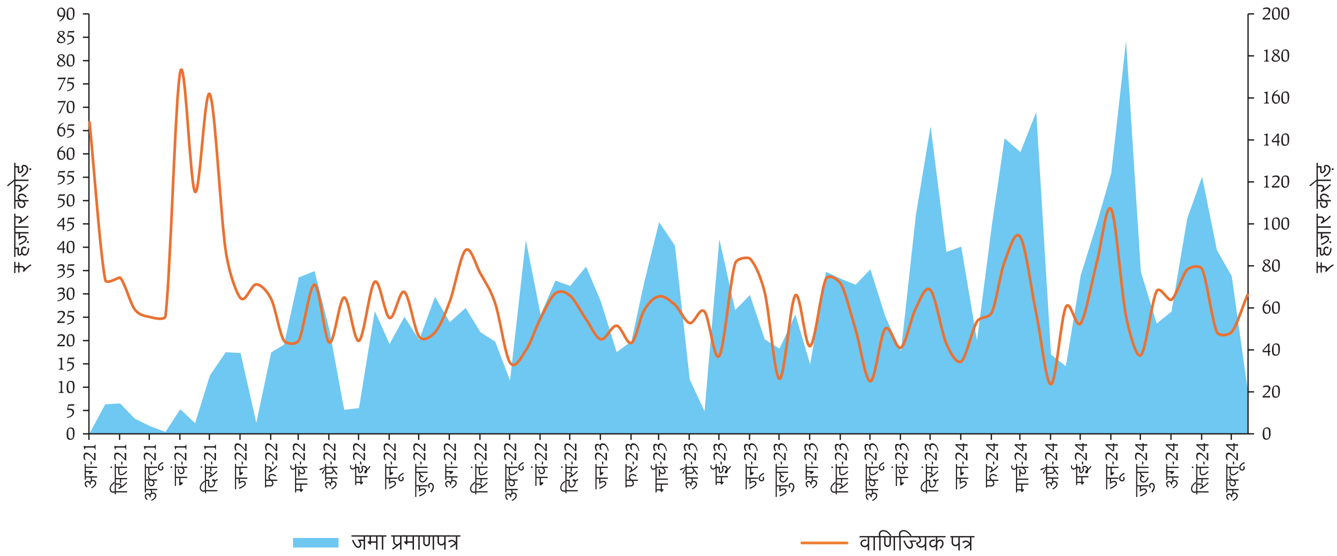

स्रोत: आरबीआई

10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर स्प्रेड 12 नवंबर 2024 को 240 बीपीएस तक गिर गया, जो सितंबर के मध्य में 310 बीपीएस और एक वर्ष पहले 264 बीपीएस था। अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में तेजी भारतीय जी-सेक प्रतिफल की तुलना में बहुत तेज रही है। भारतीय बॉण्ड बाज़ार में प्रतिफल की अस्थिरता भी अमेरिकी खजाना के सापेक्ष कम रही है (चार्ट IV.6)।

सितंबर 2024 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की संख्या बढ़कर ₹1.30 लाख करोड़ हो गई (जो कि चालू वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है) क्योंकि कॉरपोरेट्स ने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने के लिए कम प्रतिफल का लाभ उठाया। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 (सितंबर तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹3.92 लाख करोड़ की तुलना में ₹4.62 लाख

चार्ट IV.4: जी-सेक बाजार में गतिविधियां

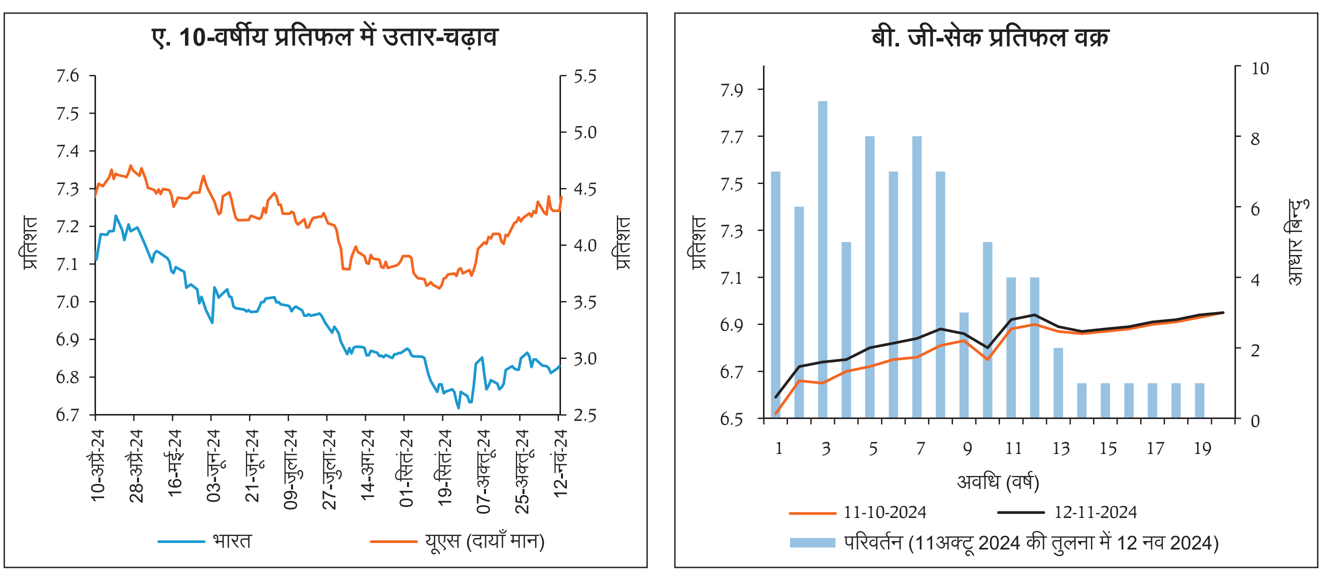

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.6: अस्थिरता और स्प्रेड – बॉण्ड मार्केट

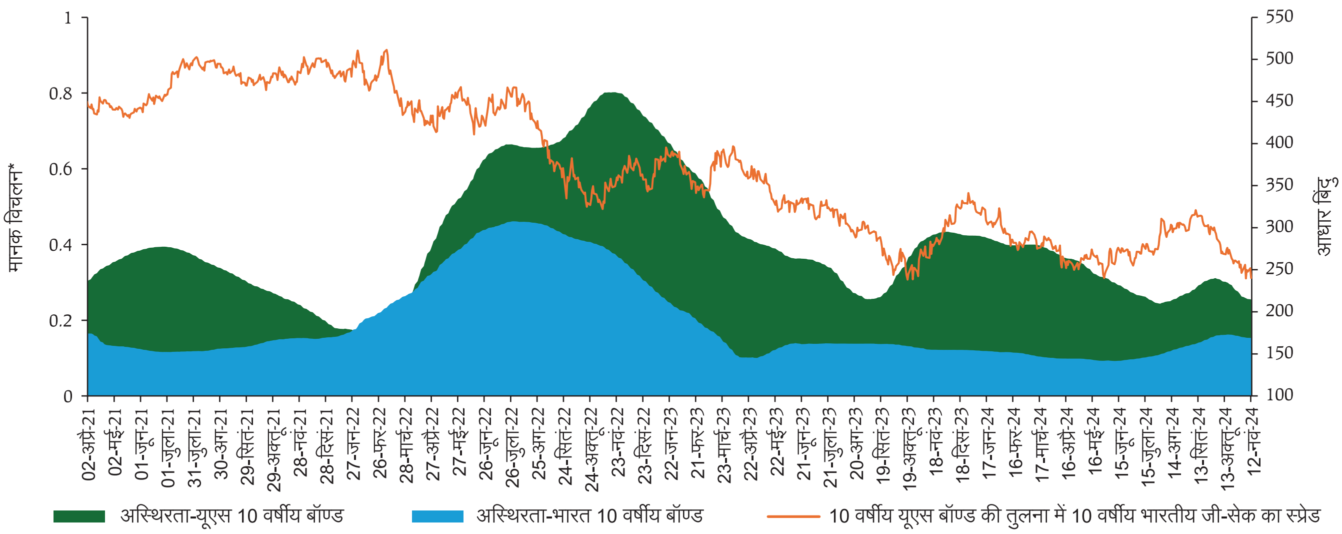

टिप्पणी: *: 12 महीने का रोलिंग मानक विचलन।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

करोड़ अधिक थी। रेटिंग और अवधि स्पेक्ट्रम में कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल ने मिश्रित गति दिखाई, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम आम तौर पर अक्टूबर की दूसरी छमाही से नवंबर 2024 की शुरुआत तक कम हो गया (सारणी IV.1)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 8 नवंबर 2024 तक 6.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 7.0 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 8 नवंबर 2024 को 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी, जो सितंबर 2024 के अंत में 5.9 प्रतिशत से अधिक थी, जो मौसमी त्यौहार-संबंधी मांग में वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 8 नवंबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 13.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.8)। स्वर्ण - एनएफए का एक प्रमुख घटक - में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण स्वर्ण की कीमतों पर पुनर्मूल्यांकन लाभ है,

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 सित 2024 – 15 अक्टू 2024	16 अक्टू 2024 – 18 नव 2024	विभिन्नता	16 सित 2024 – 15 अक्टू 2024	16 अक्टू 2024 – 18 नव 2024	विभिन्नता
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.83	7.82	-1	117	113	-4
(ii) एएए (3 वर्ष)	7.74	7.77	3	95	93	-2
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.65	7.63	-2	83	75	-8
(iv) एए (3 वर्ष)	8.49	8.52	3	170	169	-3
(v) बीबीबी- (3 वर्ष)	12.07	12.17	10	528	533	5

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और संचलन में मुद्रा

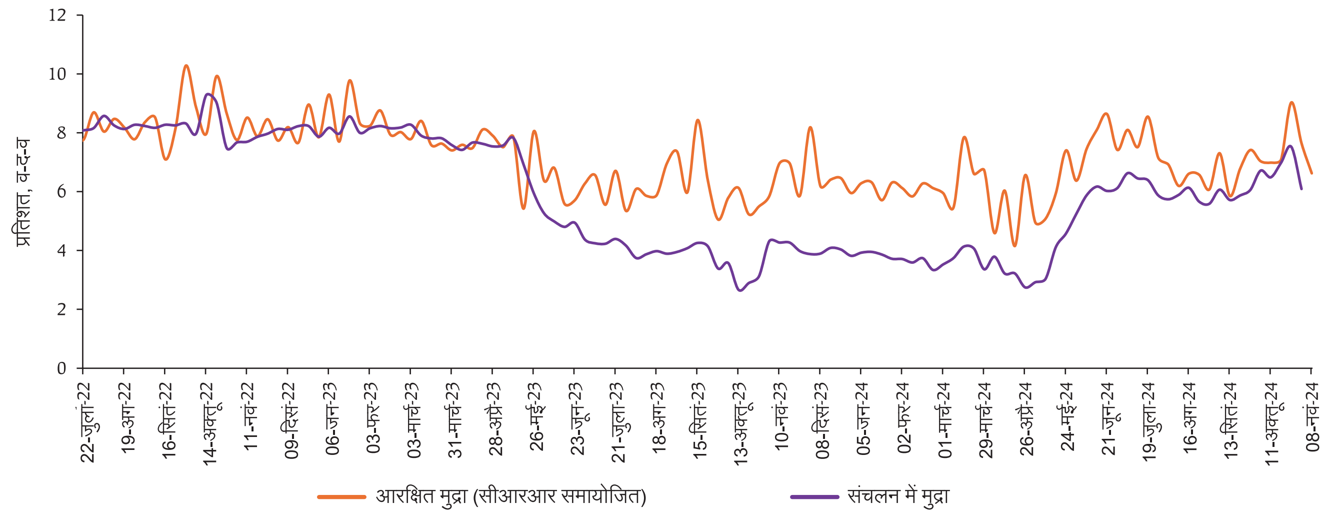

टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 8 नवंबर 2024 से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

जिसके कारण अक्टूबर 2023 के अंत तक एनएफए में इसकी हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8 नवंबर 2024 तक 10.3 प्रतिशत हो गई।

1 नवंबर 2024 तक मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में 11.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.0 प्रतिशत)।[19] बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम$_3$ का लगभग 86 प्रतिशत है, में 11.6 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 01 नवंबर 2024 तक 13.2 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 16.0 प्रतिशत) तक कम हो गई (चार्ट IV.9)।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) अगस्त 2024 के अंत में 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 01 नवंबर

चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि

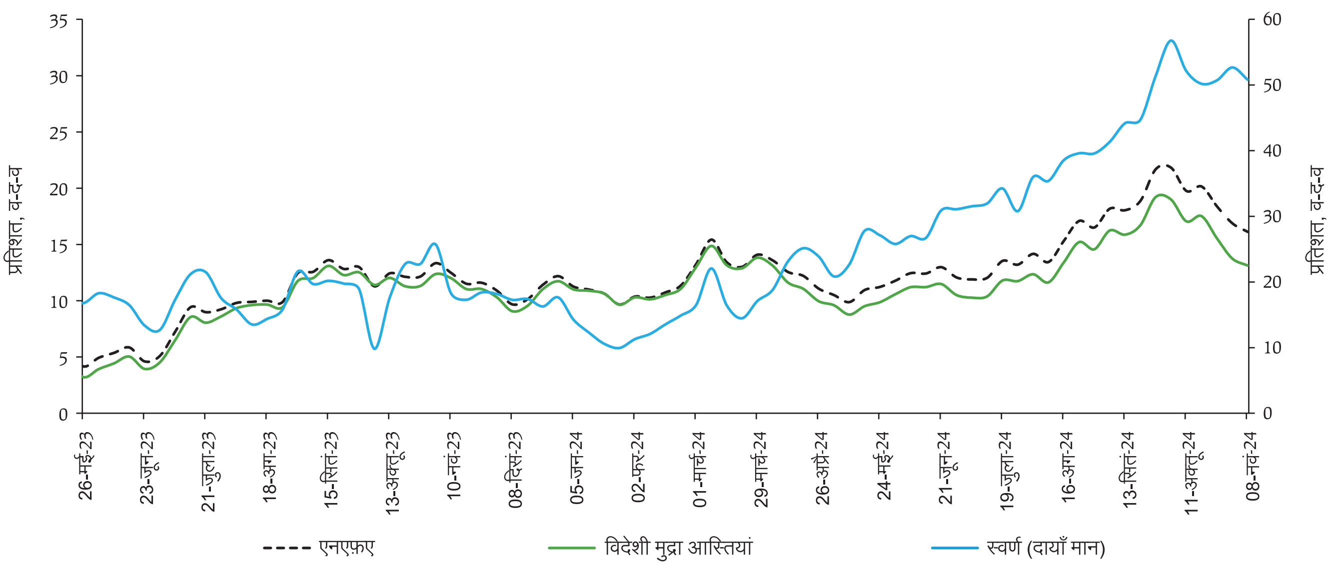

स्रोत: आरबीआई।

[19] बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.9: एससीबी की एमउ वृद्धि और ऋण वृद्धि - आधार प्रभाव और संवेग

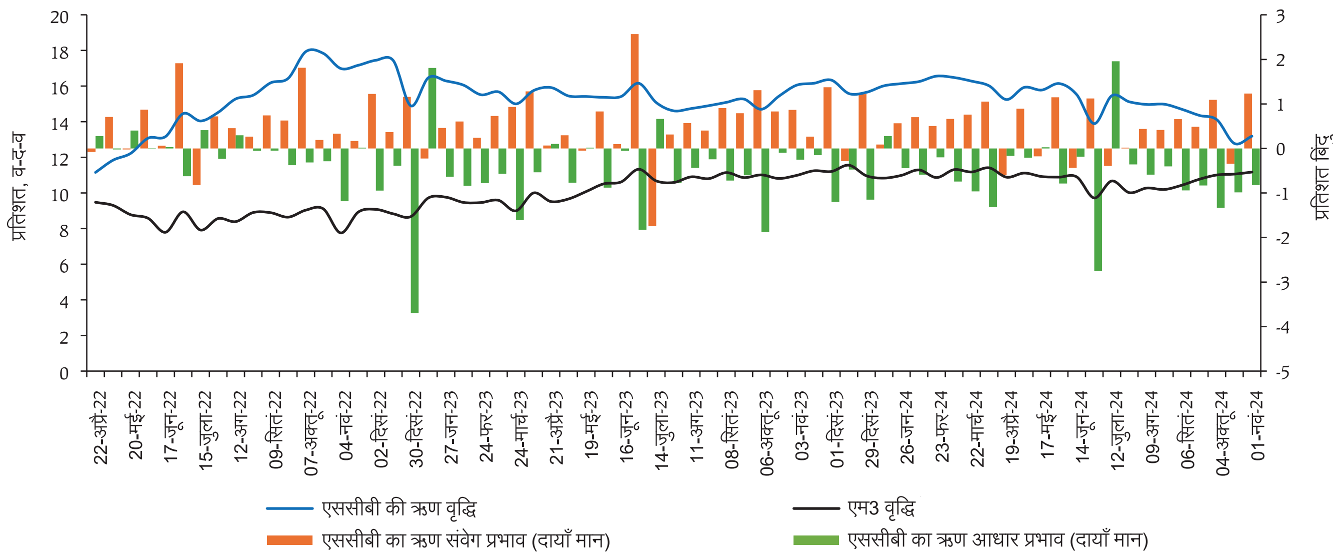

स्रोत: आरबीआई।

2024 को 12.2 प्रतिशत हो गई, जिसे मजबूत गति और कम आधार प्रभाव का समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट IV.10)।

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 01 नवंबर 2024 को 82.7 हो गया, जिसमें वृद्धिशील जमा अगस्त-अक्टूबर 2024 के दौरान वृद्धिशील ऋण से आगे निकल गया (चार्ट IV.11)। सीआरआर और एसएलआर के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ, 01 नवंबर 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में लगभग 77 प्रतिशत जमा उपलब्ध थे।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी के जवाब में, बैंकों ने अपने रेपो-आधारित बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान

चार्ट IV.10: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि – आधार प्रभाव और गति

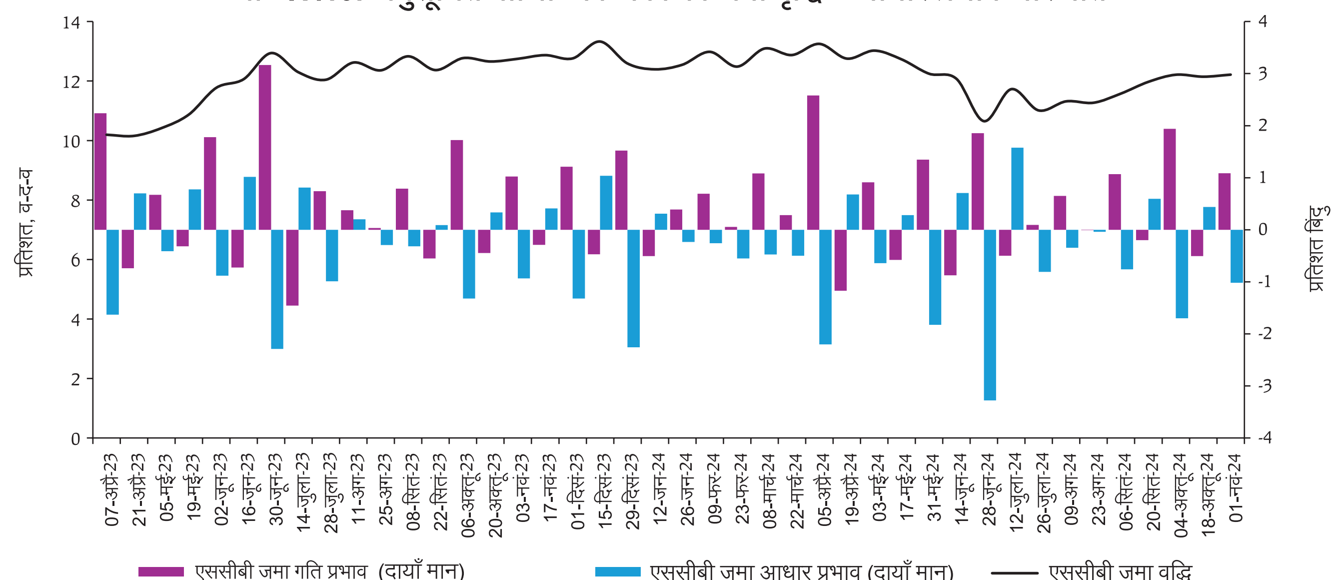

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.11: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

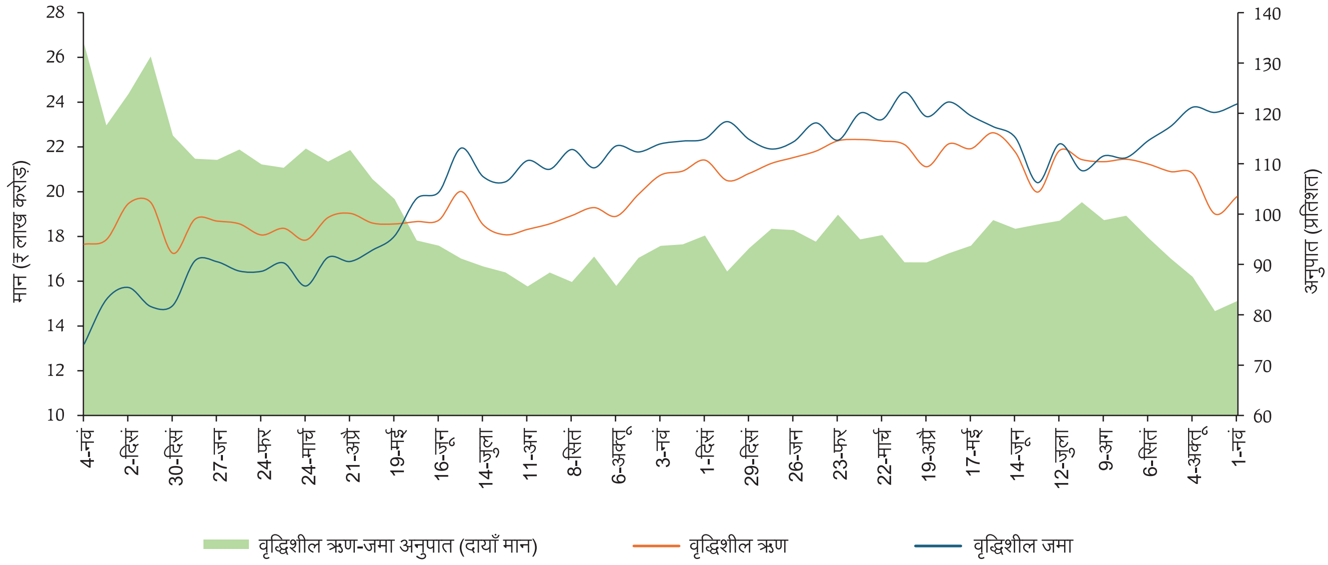

स्रोत: आरबीआई।

परिमाण से संशोधित किया। एससीबी की औसत 1-वर्षीय सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2022 से अक्टूबर 2024 के दौरान 170 बीपीएस बढ़ गई। नतीजतन, नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में मई 2022 से सितंबर 2024 के दौरान क्रमशः 186 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा दरों के मामले में, एससीबी की नई और बकाया रुपया मियादी जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 251 बीपीएस और 192 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

बैंक समूहों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में जमा दरों में वृद्धि निजी बैंकों की तुलना में अधिक थी; तथापि, बकाया रुपया ऋणों के मामले में, इसी अवधि के दौरान नीतिगत दर वृद्धि का संचरण निजी बैंकों के लिए अधिक था (चार्ट IV.12)।

गैर-वित्तीय निजी कॉरपोरेट्स की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), यानी, प्रारंभिक रिपोर्टिंग सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि पिछली तिमाही में 7.1 प्रतिशत से वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 प्रतिशत तक कम हो गई। प्रमुख क्षेत्रों में, विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि घटकर 3.3 प्रतिशत (पिछली तिमाही में 6.3 प्रतिशत) रह गई, जबकि

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दरें: डब्ल्यूएडीटीडीआर – नया जमा	मीयादी जमा दरें: डब्ल्यूएडीटीडीआर- बकाया जमा	उधार दरें: ईबीएलआर	उधार दरें: 1-वर्ष एमसीएलआर (माध्यिका)	उधार दरें: डब्ल्यूएएलआर- नया रुपया ऋण	उधार दरें: डब्ल्यूएएलआर- बकाया रुपया ऋण
सहजता चरण फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्त अवधि मई 2022 से सितंबर* 2024	+250	251	192	250	170	186	118

टिप्पणियाँ: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा अक्टूबर 2024 से संबंधित है।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर;
एमसीएलआर: फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत; **ईबीएलआर:** बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.12: बैंक समूहों में संचरण (मई 2022 से सितंबर 2024)

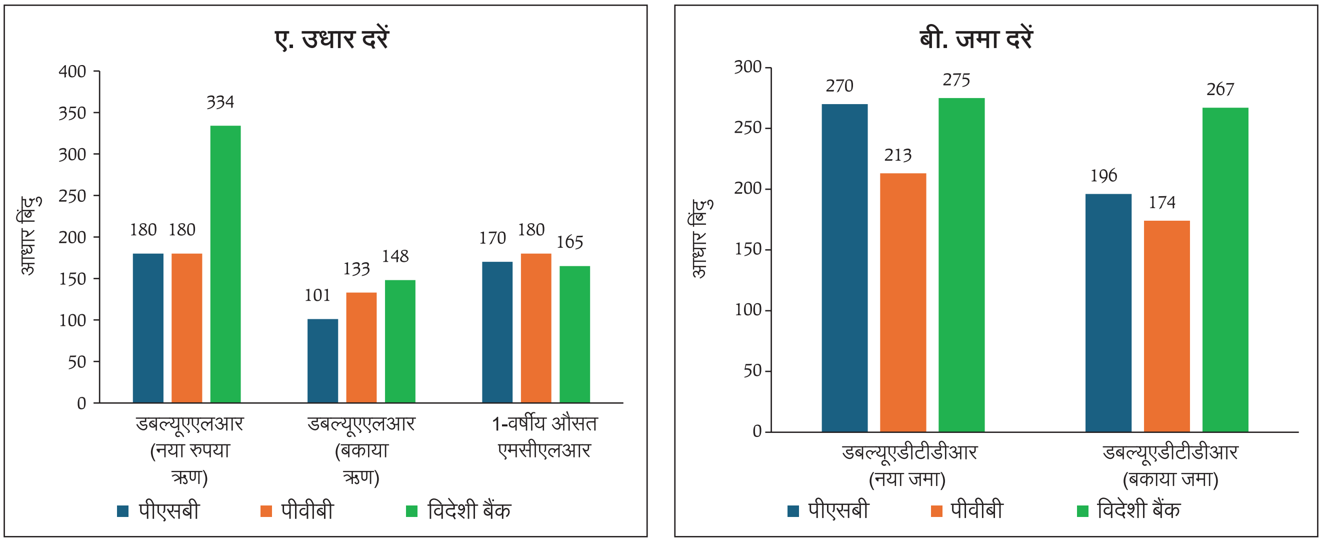

टिप्पणी: *1-वर्ष के माध्यिका एमसीएलआर पर डेटा मई 2022 से अक्टूबर 2024 तक से संबंधित है.
स्रोत: आरबीआई।

आईटी और गैर-आईटी सेवा कंपनियों के लिए यह क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 11.3 प्रतिशत रही (चार्ट IV.13ए)।

विनिर्माण कंपनियों के लाभ मार्जिन में वार्षिक और क्रमिक दोनों आधार पर कमी आई। गैर-आईटी सेवा कंपनियों ने भी कम लाभ मार्जिन दर्ज किया, लेकिन लागत युक्तिकरण ने आईटी कंपनियों को अपने परिचालन लाभ मार्जिन को बनाए रखने में मदद की (चार्ट IV.13बी)।

सूचीबद्ध बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने कुछ कंपनी-विशिष्ट विशिष्टताओं के बावजूद स्थिर और स्वस्थ आय की सूचना दी। राजस्व, जिसमें मुख्य रूप

चार्ट IV.13: कॉर्पोरेट प्रदर्शन

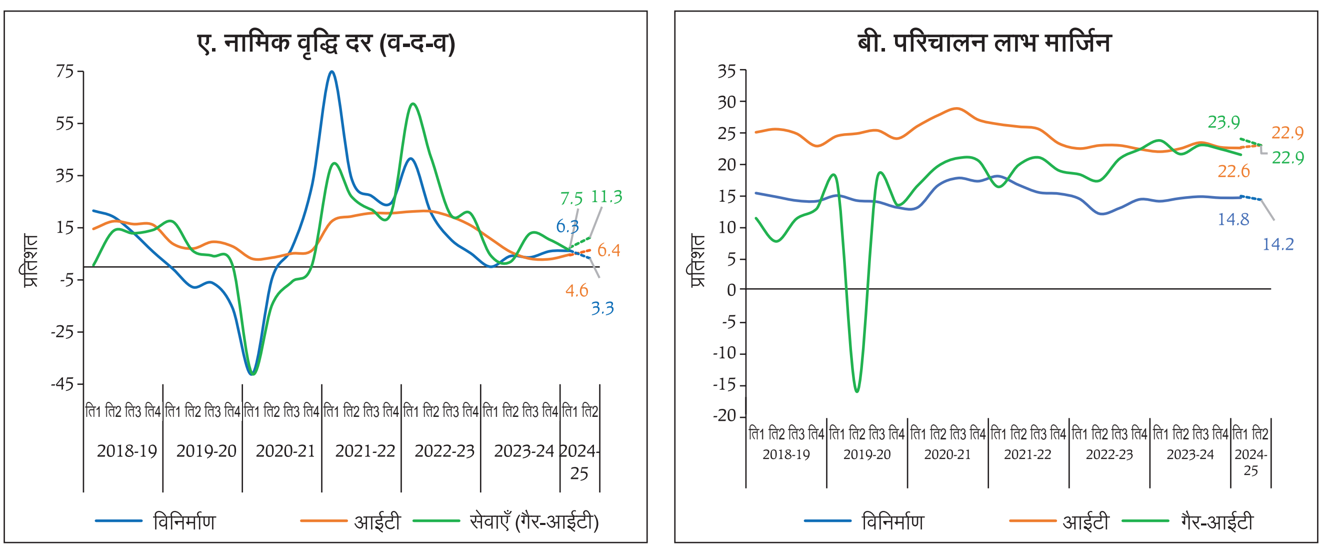

टिप्पणी: 2014 के शुरुआती परिणामों के आधार पर सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियां।
स्रोत: सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के तिमाही वित्तीय परिणाम; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[20] वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए 329 बैंकिंग और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के परिणामों के आधार पर, इस क्षेत्र के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 79.1 प्रतिशत है।

चार्ट IV.14: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

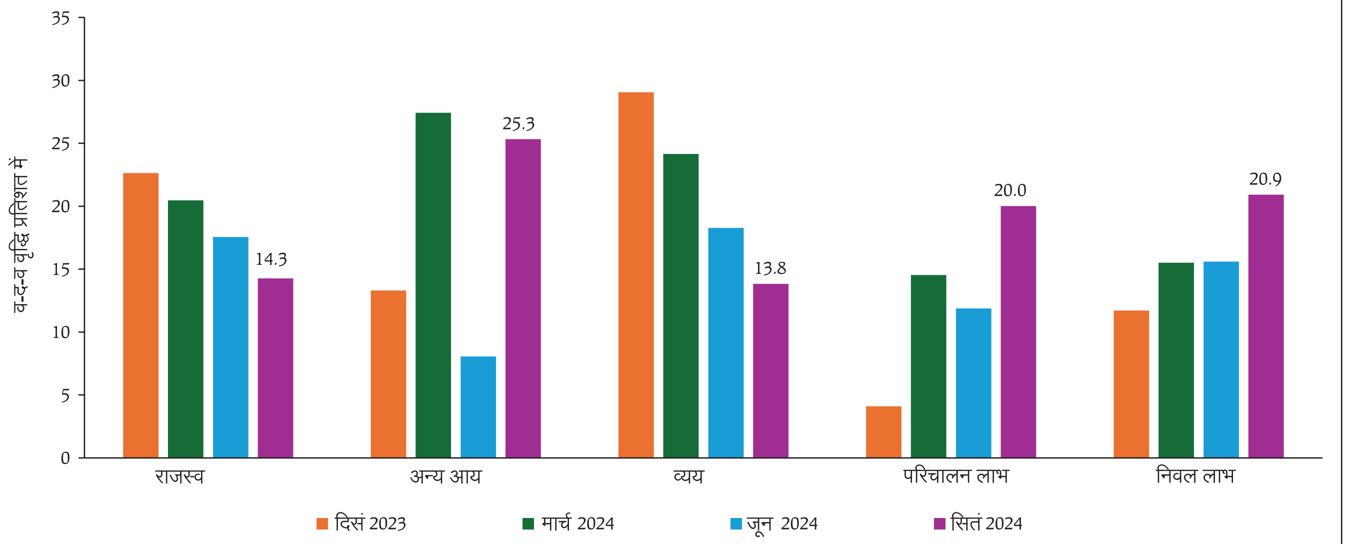

टिप्पणी: इसमें जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित डेटा शामिल नहीं है।
स्रोत: सीएमआईई प्रोवेस्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

से बैंकों के मामले में ब्याज आय शामिल है, ने कुछ क्रमिक कमी देखने के बावजूद दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। अन्य आय, जिसमें शुल्क/कमीशन से आय, निवेश की बिक्री से लाभ और हानि शामिल है, ने भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिससे कुल आय में वृद्धि हुई। व्यय में वृद्धि थोड़ी धीमी रही, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के लिए परिचालन लाभ वृद्धि में सुधार हुआ। तिमाही के दौरान प्रावधान लागत में तेजी से वृद्धि हुई; हालांकि, कर व्यय में मामूली वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों के निवल लाभ (कर के बाद) में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट IV.14)।

सूचीबद्ध गैर-वित्तीय विनिर्माण कंपनियों का लीवरेज, जैसा कि उनके ऋण-से-इक्विटी अनुपात में परिलक्षित होता है, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान मध्यम[21] बना रहा, जिसका मुख्य कारण लाभ का उच्च पूंजीकरण था। पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात, तथा सीमेंट उद्योग विनिर्माण कंपनियों की अचल आस्तियों में वृद्धि का कारण रहे, जो कुल अचल संपत्तियों में लगभग 47 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी (चार्ट IV.15)।

प्रतिधारित आय निधि का प्रमुख स्रोत बनी रही। पहली छमाही के दौरान जुटाए गए फंड का उपयोग मुख्य रूप से गैर-वर्तमान निवेश[22], अचल आस्तियों और व्यापार प्राप्तियों को बढ़ाने में किया गया (चार्ट IV.16ए और 16बी)।

भारतीय इक्विटी बाजार में अक्टूबर 2024 के दूसरे पखवाड़े और नवंबर की शुरुआत में लगातार एफपीआई बिकवाली के बीच गिरावट दर्ज की गई (चार्ट IV.17)। भू-राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च मूल्यांकन और अपेक्षाओं से कम वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के आय परिणामों ने निवेशकों की भावनाओं को कमज़ोर कर दिया। अक्टूबर 2024 के लिए उम्मीद से ज़्यादा घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट ने भी धारणा को प्रभावित किया। कुल मिलाकर, सितंबर के अंत से बीएसई सेंसेक्स में 8 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 14 नवंबर 2024 को 77,580 पर बंद हुआ।

इक्विटी बाजार में हालिया गिरावट एफपीआई द्वारा सितंबर के अंत से लेकर 14 नवंबर 2024 तक इक्विटी से लगभग ₹1.2 लाख करोड़ के संचयी निवल बहिर्वाह का परिणाम

[21] 1689 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त तुलन-पत्र के आधार पर।

[22] गैर-चालू निवेश दीर्घकालिक आस्तियां हैं जिनमें निवेश आस्तियों में इक्विटी उपकरण, वरीयता शेयर, सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियां, डिबेंचर या बांड, म्यूचुअल फंड, साझेदारी फर्मों में निवेश; सहायक कंपनियों आदि में निवेश शामिल हैं।

चार्ट IV.15: विनिर्माण

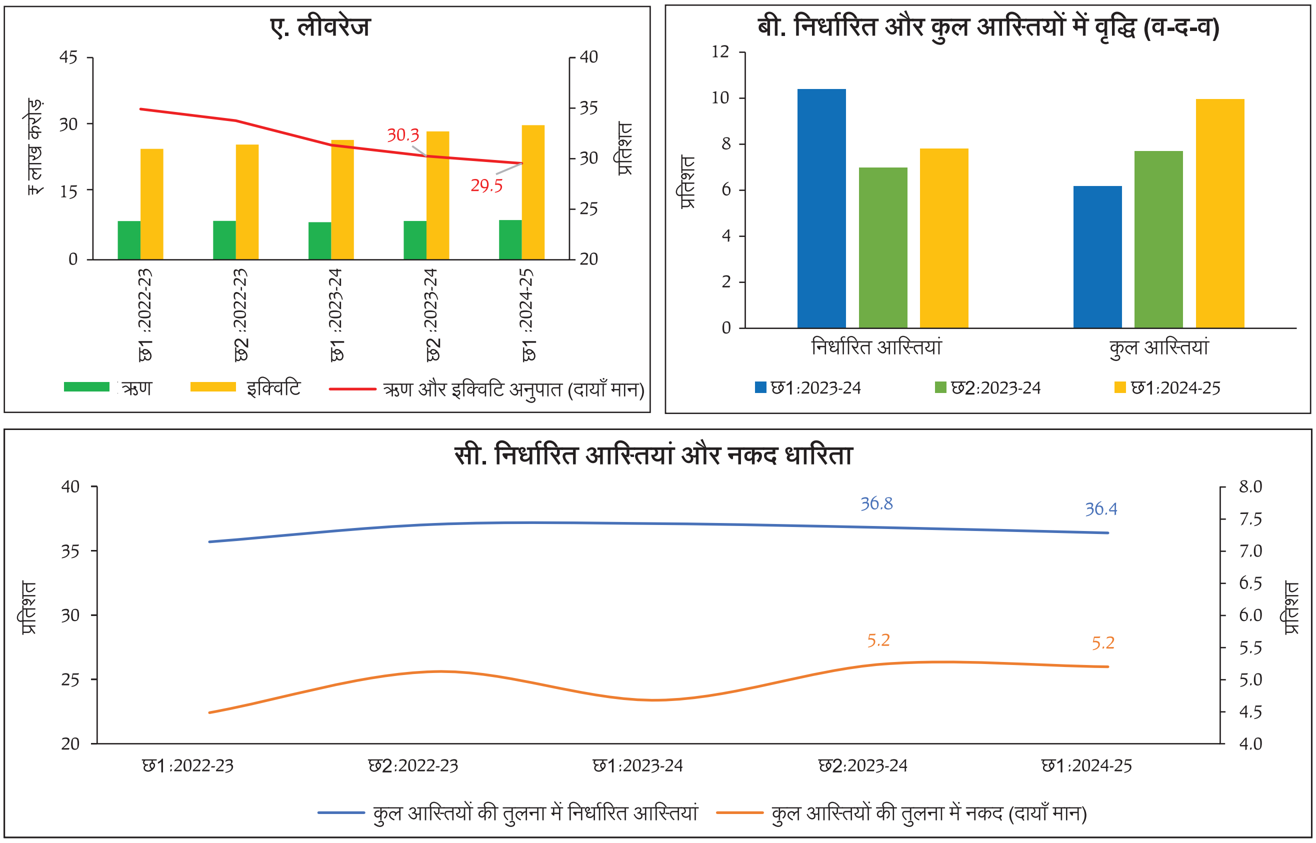

टिप्पणी: प्रारंभिक परिणाम 1689 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों पर आधारित हैं।
स्रोत: सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों का छमाही तुलन पत्र; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

थी - जो निरपेक्ष रूप से अब तक का सबसे अधिक है। सापेक्ष आधार पर, यानी, जब एफपीआई बहिर्वाह को कुल बाजार पूंजीकरण के संबंध में मापा जाता है, हालांकि, पिछले प्रकरणों में हुई बिकवाली की तुलना में बहिर्वाह का यह प्रकरण अब

चार्ट IV.16ए: निधियों के स्रोत (अर्ध-वार्षिक परिवर्तन)

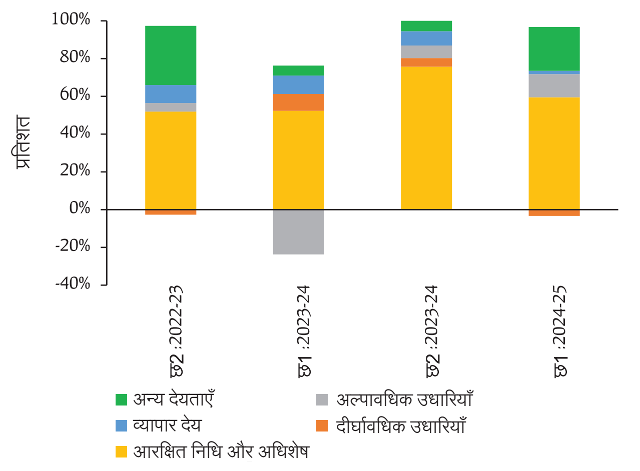

चार्ट IV.16बी: निधियों का उपयोग (अर्ध-वार्षिक परिवर्तन)

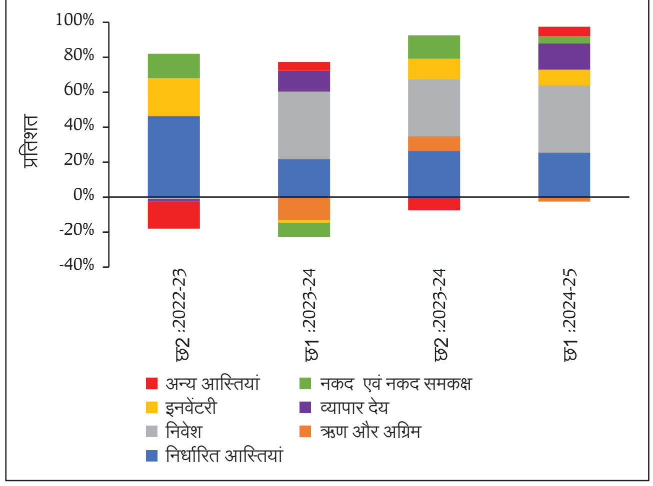

स्रोत: सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों का छमाही तुलन पत्र; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

चार्ट IV.17: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

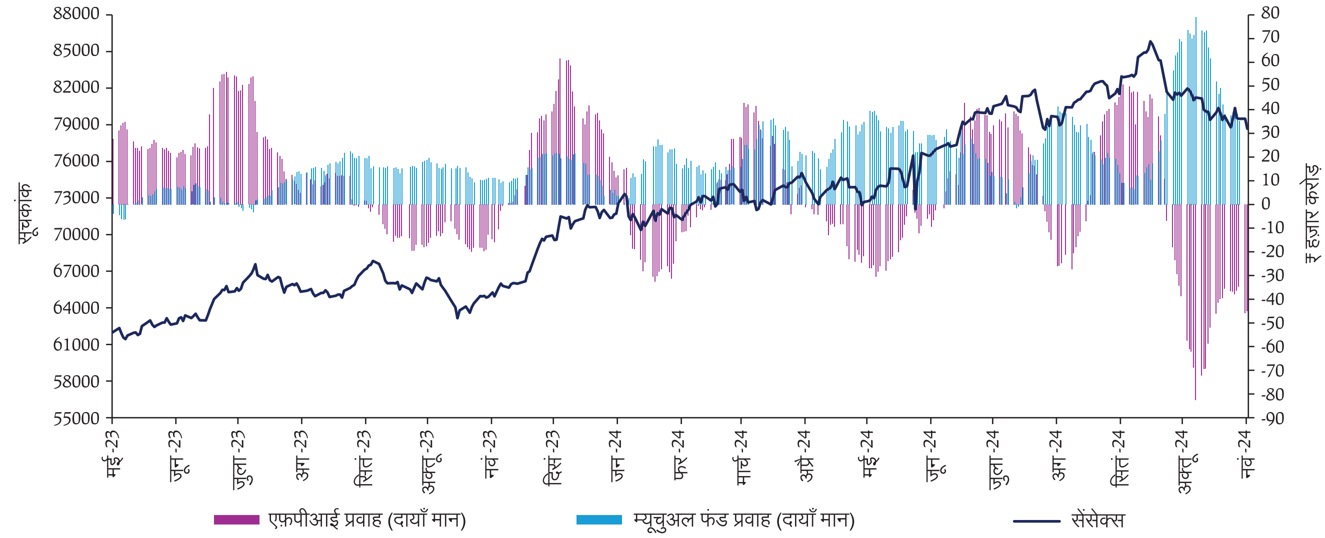

टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह 15-दिनों के रोलिंग योग के आधार पर दर्शाए जाते हैं।
स्रोत: एनएसडीएल; और बीएसई।

तक मामूली बना हुआ है (चार्ट IV.18)। बाजार में गिरावट के बीच, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों ने अक्टूबर 2024 के महीने में ₹41,865 करोड़ के उच्चतम निवल अंतर्वाह को देखा, क्योंकि घरेलू निवेशकों ने बाजार में गिरावट का लाभ उठाने की कोशिश की।

सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत वृद्धि देखी गई क्योंकि यह अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान एक वर्ष पहले के 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान निवल एफडीआई एक वर्ष पहले के 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन और बाहरी एफडीआई में वृद्धि है (चार्ट IV.19ए)। विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्र, और संचार सेवाओं ने

चार्ट IV.18: भारतीय इक्विटी बाजारों से एफपीआई बहिर्वाह के एपिसोड

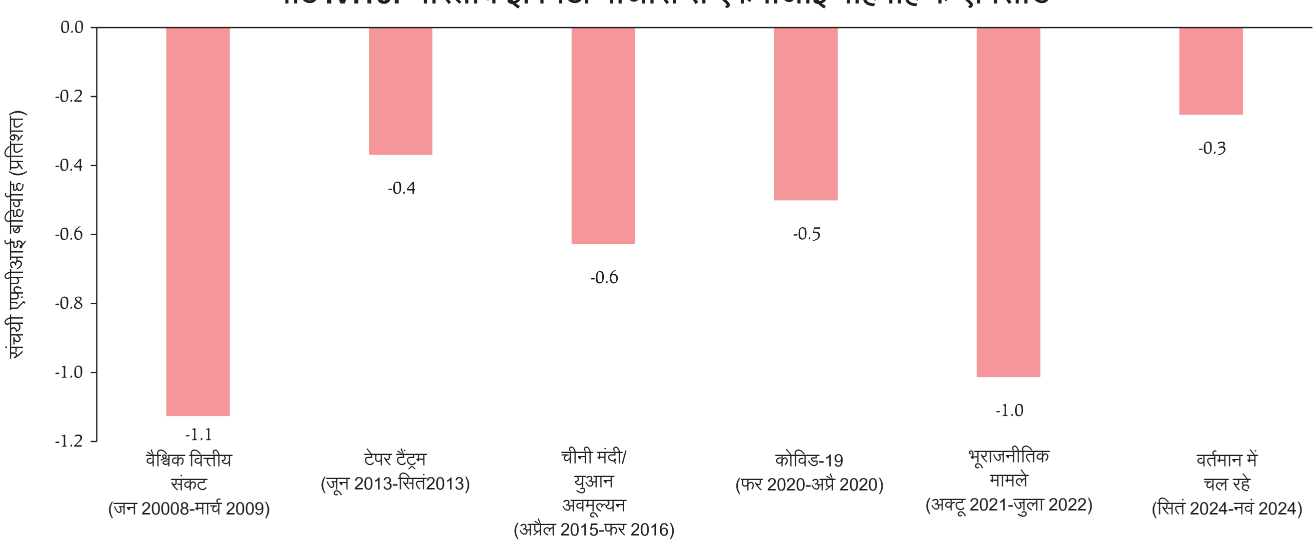

टिप्पणी: एफ़पीआई बहिर्वाह को बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
स्रोत: एनएसडीएल; बीएसई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.19: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह

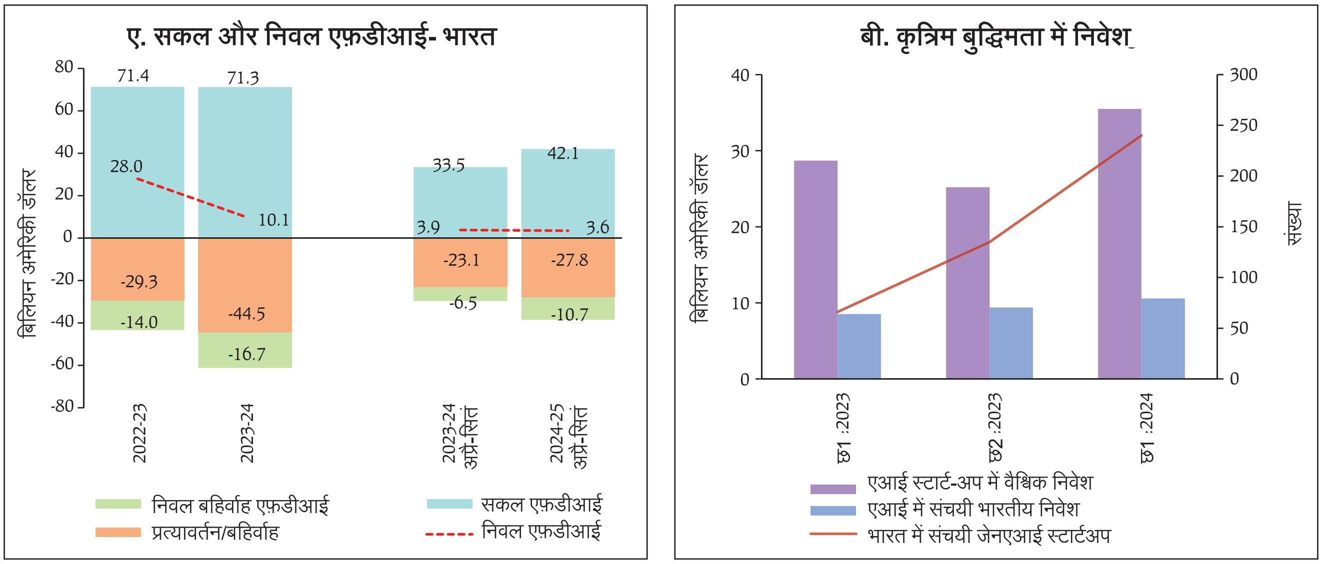

स्रोत: आरबीआई; नैसकॉम; और क्रंचबेस।

सकल एफडीआई अंतर्वाह में लगभग दो-तिहाई का योगदान दिया। सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, यूएई और अमेरिका लगभग तीन-चौथाई प्रवाह के स्रोत थे।

दुनिया भर में एआई स्टार्ट-अप में बढ़ते निवेश के साथ, भारत अपने तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है ताकि आगे और निवेश आकर्षित किया जा सके और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके (चार्ट IV.19बी)। 2023 से (छ1:2024 तक), भारत ने जनरेटिव एआई स्टार्टअप में निवेश के मामले में खुद को दुनिया की शीर्ष छह अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया है।[23] भारत वर्ष 2013-2023 के दौरान संचयी निजी एआई निवेश में शीर्ष दस देशों में भी शुमार है।[24]

अक्टूबर 2024 में भारतीय पूंजी बाजारों में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह चार महीने बाद नकारात्मक हो गया, जो भू-राजनीतिक तनावों से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और हाल ही में चीन द्वारा उठाए गए प्रोत्साहन उपायों और अमेरिका में चुनाव परिणामों के मद्देनजर वैश्विक पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा पुनर्संतुलन से प्रभावित हुआ। अक्टूबर 2024 में 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल एफपीआई बहिर्वाह कोविड-19 महामारी के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो मुख्य रूप से इक्विटी वाले भाग में पर्याप्त बहिर्वाह से प्रेरित थे (चार्ट IV.20ए)।

इक्विटी की बिक्री उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में व्यापक रूप से दिखाई देती है क्योंकि विदेशी निवेशकों ने पूंजी को अन्य ईएमई से हटा कर चीनी इक्विटी की ओर स्थानांतरित कर दिया और (चार्ट IV.18बी)। अक्टूबर 2024 के दौरान ऋण खंड में अपने पांच महीने के लगातार प्रवाह में विराम देखा, हालांकि निवल बहिर्वाह अपेक्षाकृत सीमित रहा। क्षेत्रों में, वित्तीय सेवाओं, तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन, और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं ने अक्टूबर के दौरान सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया। नवंबर 2024 (14 नवंबर तक) में, निवल एफपीआई बहिर्वाह 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा।

अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान गैर-निवासी जमाराशियों में निवल अंतर्वाह 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सभी तीन खातों में उच्च अंतर्वाह दर्ज किया गया, अर्थात् गैर-निवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], गैर-निवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा गैर-निवासी [एफसीएनआर(बी)] खाते।

23 नैसकॉम- भारत का जनरेटिव एआई स्टार्टअप लैंडस्केप 2024।

24 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2024।

चार्ट IV.20: निवल पोर्टफोलियो निवेश

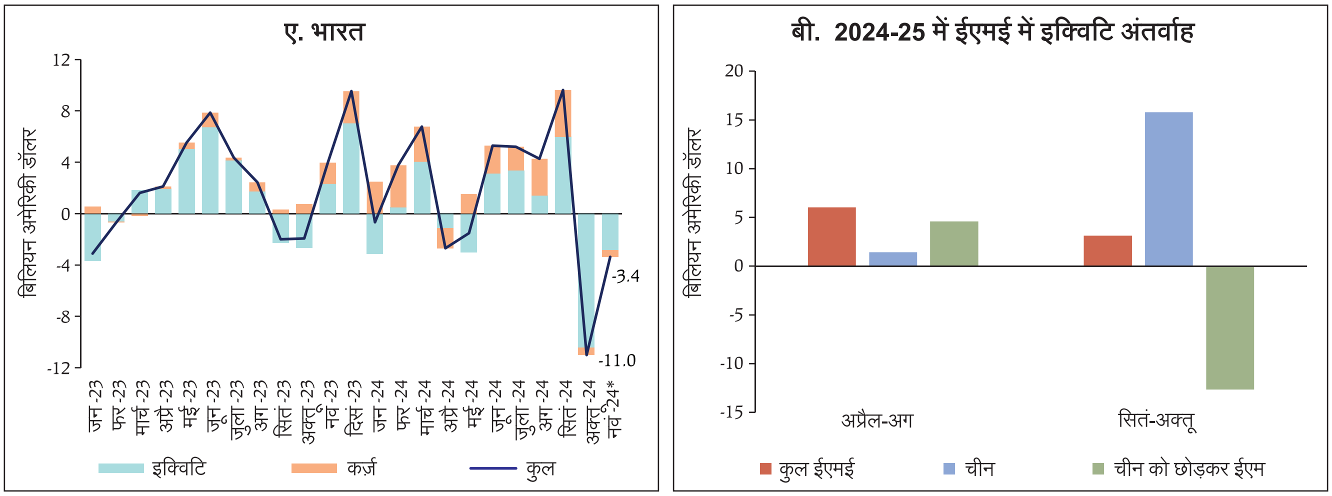

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग और हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।
2. *: 14 नवंबर 2024 तक का डेटा।

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत छ1:2024-25 के दौरान ₹1,97,659 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष के ₹1,75,217 करोड़ से काफी अधिक है। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक निवेश 'विद्युत' और 'सड़क और पुल' क्षेत्रों के लिए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि ति2:2024-25 के दौरान ₹26,308 करोड़ थी, जो पिछली तिमाही में ₹36,489 करोड़ से अधिक थी (चार्ट IV.21)।

2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान नए ईसीबी ऋण पंजीकरण (14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछली तिमाही के साथ-साथ एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे। वर्ष 2024-

चार्ट IV.21: निजी कॉर्पोरेट निवेश के इरादे

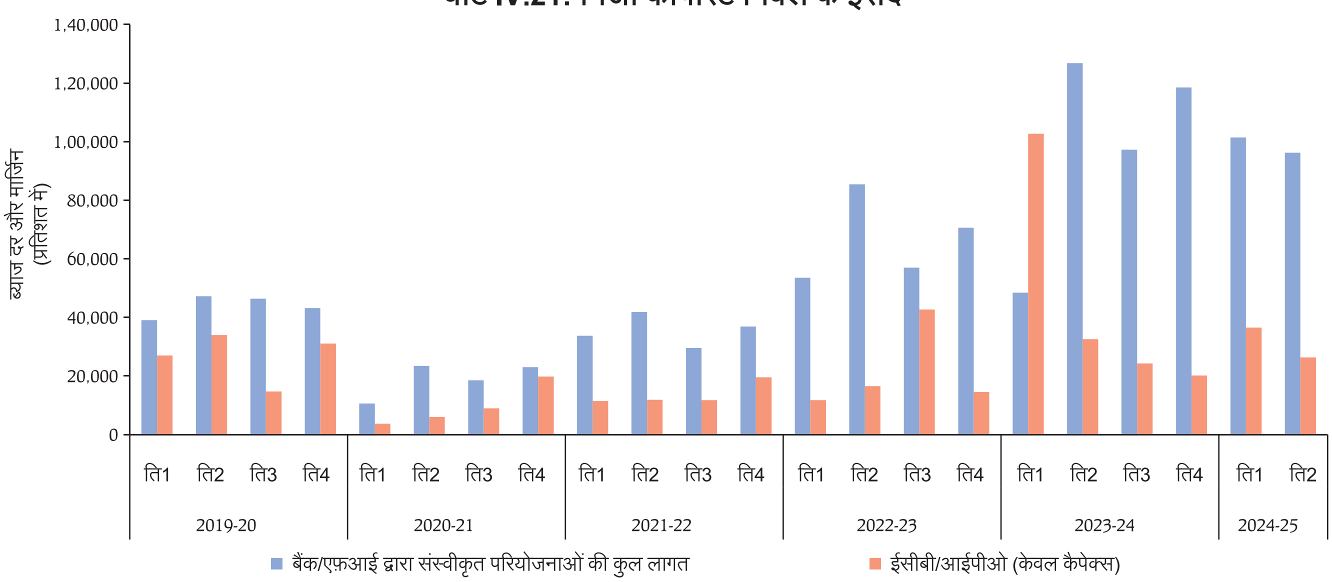

स्रोत: आरबीआई; बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट IV.22: बाह्य वाणिज्यिक उधार

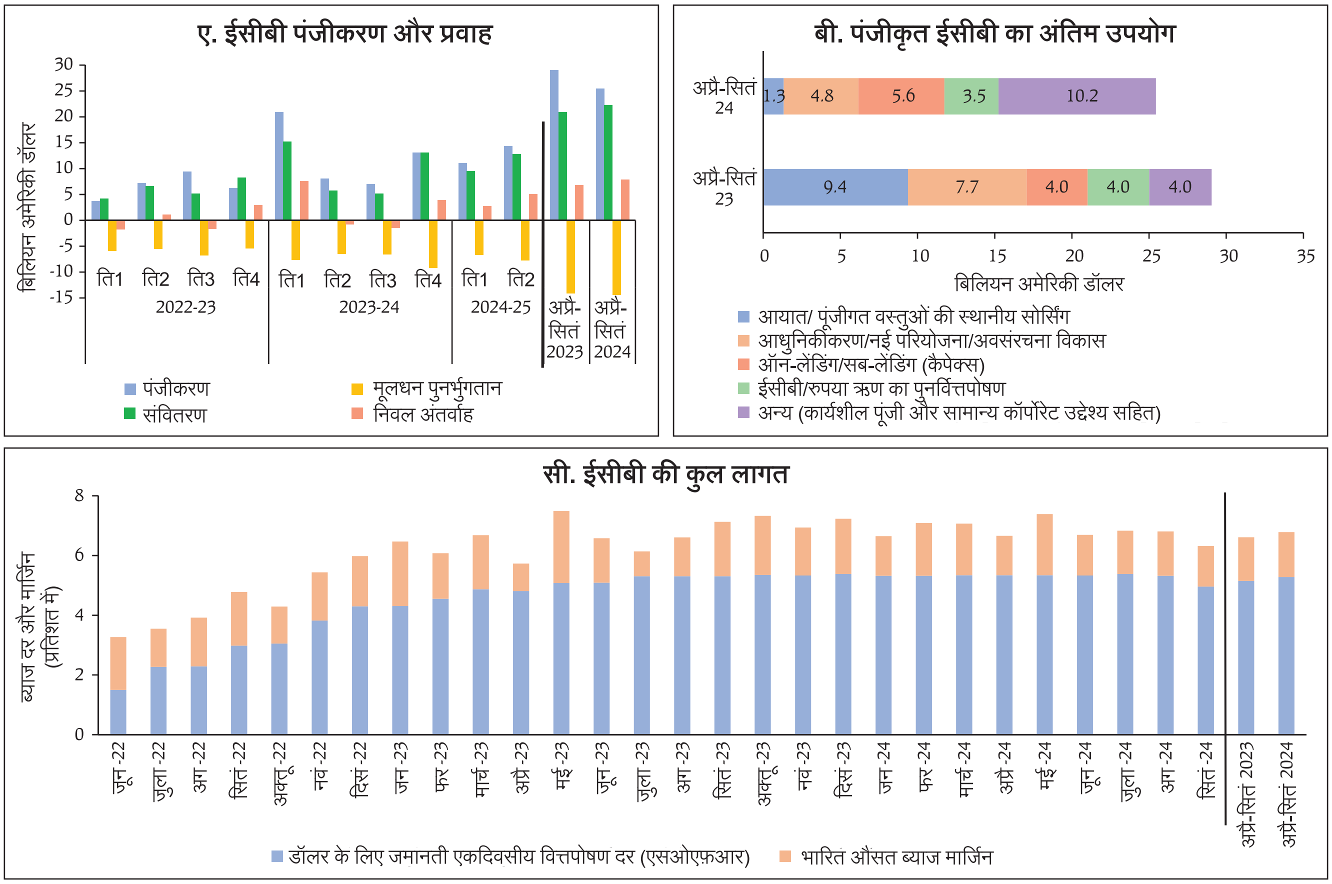

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

25 की पहली छमाही के दौरान निवल अंतर्वाह (7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा (चार्ट IV.22ए)। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पंजीकृत नए ईसीबी में से लगभग आधे पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय के लिए ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग सहित) के लिए थे [चार्ट IV.22बी]।

हाल ही में वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरों जैसे कि जमानती एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में ढील के परिणामस्वरूप सितंबर 2024 के दौरान जुटाए गए ईसीबी की कुल लागत में गिरावट आई है। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बेंचमार्क दरों पर भारित औसत ब्याज मार्जिन (डबल्यूएआईएम) 2023-24 की पहली छमाही) की तुलना में 5 बीपीएस अधिक था (चार्ट IV.22सी)।

वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पंजीकृत ईसीबी में से तीन-चौथाई से अधिक को स्पष्ट हेजिंग, रुपया-वर्गीकृत ऋण और विदेशी अभिभावकों से ऋण में प्रभावी रूप से हेज किया गया था, जो इस तरह के जोखिमों की ब्याज और विनिमय दर संवेदनशीलता को काफी हद तक संतुलित करता है (चार्ट IV.23)।

अक्टूबर 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.3 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई, क्योंकि अधिकांश ईएमई को मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मूल्यह्रास दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि, माह के दौरान आईएनआर ने प्रमुख मुद्राओं में सबसे कम अस्थिर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी (चार्ट IV.24, बॉक्स 2)।

सकारात्मक मुद्रास्फीति अंतर के साथ-साथ नाममात्र प्रभावी शर्तों में आईएनआर की वृद्धि के कारण अक्टूबर 2024 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में आईएनआर में 1.8 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.25)।

बॉक्स 2: भारत की विनिमय दर व्यवस्था

मार्च 1993 से भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए दो-तरफ़ा विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप (एफ़एक्सआई) करता है, बिना विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर को लक्षित किए। यह नीति उद्देश्य 1993 से अपरिवर्तित रहा है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अस्थिर पूंजी प्रवाह के प्रभावों को सुचारू बनाने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वास्तविक क्षेत्र में प्रभाव विस्तार को कम करने में मदद मिली है।

वर्ष 2023 के लिए विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंधों (एआरईएआर) पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की विनिमय दर नीति को दिसंबर 2022-अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए एक वास्तविक 'स्थिर व्यवस्था' करार दिया है, जबकि वास्तविक वर्गीकरण 'अस्थिर' बना हुआ है। आईएमएफ ने खुद स्वीकार किया है कि पुनर्वर्गीकरण पद्धति एक पिछड़े-दिखने वाले सांख्यिकीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और बहुत कम समय क्षितिज के आधार पर निष्कर्ष निकालती है।[25]

विनिमय दर व्यवस्था को स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आईएमएफ़ की +/- 2 प्रतिशत उतार-चढ़ाव सीमा तदर्थ, विषयपरक, सदस्य देशों की नीतियों की निगरानी के अपने केंद्रीय उद्देश्य का अतिक्रमण और लेबलिंग के समान है। इसके अलावा, अवधि (दिसंबर 2022-अक्टूबर 2023) का चयन विवेकाधीन है और इस प्रकार, पुनर्वर्गीकरण पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। वास्तव में, विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप (एफ़एक्सआई) पर आईएमएफ़ के हालिया शोध पत्र का निष्कर्ष है कि आरबीआई बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने, बाजार की अस्थिरता को कम करने, अव्यवस्थित बाजार स्थितियों के उद्भव को रोकने और अवसरवादी रूप से अपने एफ़एक्स भंडार को फिर से भरने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है।[26]

हाल ही में, मीडिया में आईएनआर की विनिमय दर नीति पर कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। इसमें उठाए गए मुद्दे पर बात करना उचित है, लेकिन भावनाओं, असंतोष या पूर्व-प्रतिबद्ध सैद्धांतिक स्थितियों से मुक्त होना चाहिए जो वास्तविक तथ्यों के साथ परखे नहीं गए हैं।

वर्ष 2020 से, भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले संकटों के विपरीत, अनिश्चितता के लंबे दौर से जूझ रही है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट (2008) और टेपर टैंट्रम (2013) जिसमें भारत या तो मूकदर्शक था या केवल 'बातचीत' कर रहा था। 2020 से अनुभव किए जा रहे एक के बाद एक तरह-तरह की समस्याओं के बावजूद, रिज़र्व में कमी, निवल मूल्यांकन घाटा, वास्तव में इन सभी घटनाओं में तुलनीय है।

इसके अलावा, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप (एफएक्सआई) को अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है[27]। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, यह पाया गया है कि फरवरी से अक्टूबर 2022 के दौरान जीडीपी में आरबीआई का निवल हस्तक्षेप औसतन 1.6 प्रतिशत था, जबकि पहले के संकटों के दौरान यह 1.5 प्रतिशत था, जो बहुत कम परिमाण के थे।

आरबीआई के हस्तक्षेप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार तरल और जमा हुआ हो, और व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा हो। परिणामस्वरूप, आईएनआर की अस्थिरता - जैसा कि विकल्प कीमतों के साथ-साथ जीएआरसीएच[28] अनुमानों और 30 दिनों के रोलिंग मानक विचलन से निकाला गया है - लगातार कम हो रही है (चार्ट 2ए)। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के मामले में इसका लाभकारी प्रभाव पड़ा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 2023-24 के लिए 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपये में गिरावट का निम्न क्रम भारत के व्यापक-आधार की मजबूती को दर्शाता है।

(Contd.)

25 आईएमएफ़ अनुच्छेद IV परामर्श - भारत (2023)।

26 लिंडे, जेस्पर, एवं अन्य (2024), "एकीकृत नीतिगत ढांचे के तहत विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप: भारत का मामला", आईएमएफ, वर्किंग पेपर, 24/236

27 अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1994-2018 के दौरान औसतन 1,186 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019-2024 के दौरान 3,248 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

28 सामान्यीकृत स्वत:प्रतिगमन सशर्त विषमता (जीएआरसीएच)।

29 (i) अमेरिका और भारत के बीच सीपीआई मुद्रास्फीति का अंतर 2023 में केवल 1.6 प्रतिशत अंक पर मामूली था; (ii) भारत के चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.7 प्रतिशत था); (iii) वर्ष 2023-24 में निवल पूंजी प्रवाह 89.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022-23 में 57.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है; और (iv) 8.2 प्रतिशत (2022-23 में 7.0 प्रतिशत से ऊपर) की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

चार्ट 2ए: आईएनआर बाज़ार निर्धारित: एफ़एक्सआई अस्थिरता को सुचारू करना

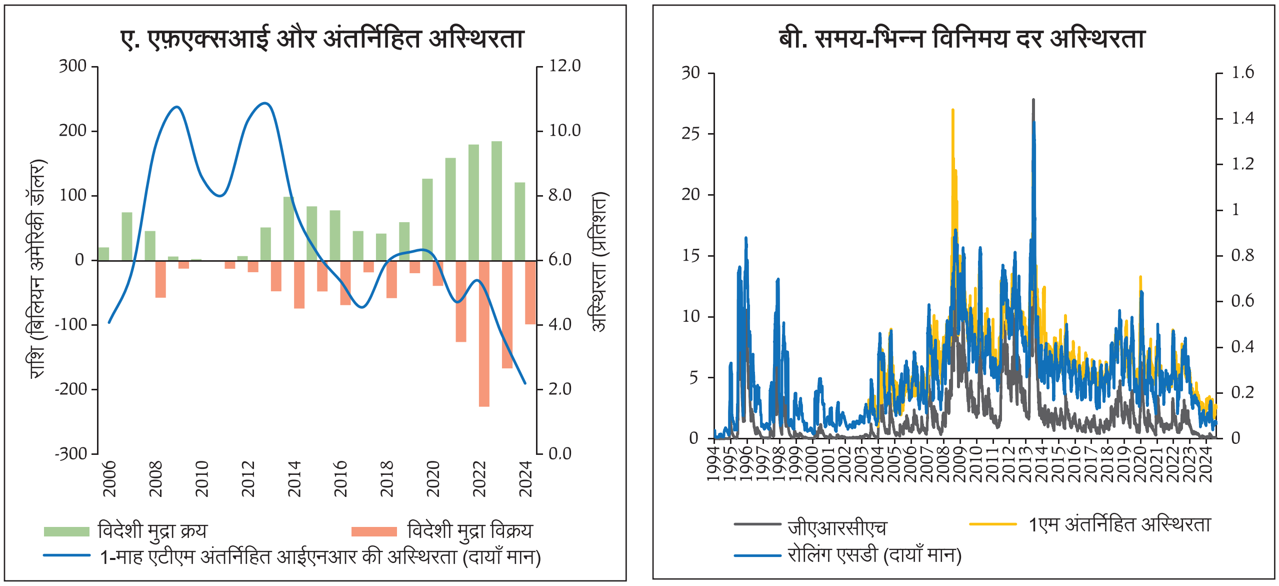

कुछ टिप्पणीकारों का यह अनुमान कि विनिमय दर नीति के रुख ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता। निर्यात प्रदर्शन को पैमाने- 2018-19 और 2023-24 के बीच के हिसाब से समायोजित किया जाना चाहिए, वैश्विक पण्य वस्तु निर्यात ने 4.0 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की, जबकि भारत के पण्य वस्तु निर्यात ने 5.8 प्रतिशत की उच्च सीएजीआर दर्ज की। इस अवधि में, भारत के पण्य वस्तु निर्यात की वृद्धि कई क्षेत्रीय समकक्षों की तुलना में अधिक थी।[30]

इसके अलावा, भारत की निर्यात संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है - सेवा निर्यात ने वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान 10.4 प्रतिशत की मजबूत सीएजीआर दर्ज की, जो उनकी बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। वर्तमान में, भारत 4.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में सेवाओं का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि पण्य वस्तु के वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 1.8 प्रतिशत है, जिसमें यह अठारहवें स्थान पर है। वर्ष 1994-2018 के दौरान, भारत के पण्य वस्तु निर्यात में 11.1 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, लेकिन वैश्विक पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि भी 6.3 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ अधिक रही।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक विनिमय दर परिवर्तनों के प्रति भारत के पण्य वस्तु निर्यात की संवेदनशीलता में कमी आई है, जो बाजारों और निर्यात वस्तुओं में विविधीकरण, विनिर्माण निर्यात में बढ़ती प्रौद्योगिकी गहनता और उच्च मूल्य संवर्धन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है।[31] इस प्रकार, भारत के निर्यात प्रयास में जोर कम मूल्यांकित विनिमय दर जैसे कृत्रिम सहारे की आवश्यकता के बिना गुणवत्ता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सुधार के आधार पर बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण सभी मौजूदा और पूंजीगत वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद किया जाता है, ताकि कमज़ोर समय में यह सहायक साबित हो। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि विदेशी मुद्रा बाजार तरल और गहरा बना रहे, खासकर जब बड़ी पूंजी बहिर्वाह हो, और वित्तीय स्थिरता जोखिमों को कम करने के लिए, जिनमें से सभी का वास्तविक क्षेत्र पर प्रभाव हो सकता है।

30 थाईलैंड (2.5 प्रतिशत), मलेशिया (4.6 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (3.2 प्रतिशत) और चीन (6.3 प्रतिशत) के बराबर।

31 निर्यात की विनिमय दर लोच यह मापती है कि किसी देश का निर्यात अपनी विनिमय दर में बदलाव के प्रति कितना संवेदनशील है। विनिमय दर लोच में गिरावट का मतलब है कि मुद्रा मूल्यह्रास अब निर्यात मात्रा में आनुपातिक वृद्धि की ओर नहीं जाता है।

चार्ट IV.23: ईसीबी करार - हेजिंग स्थिति

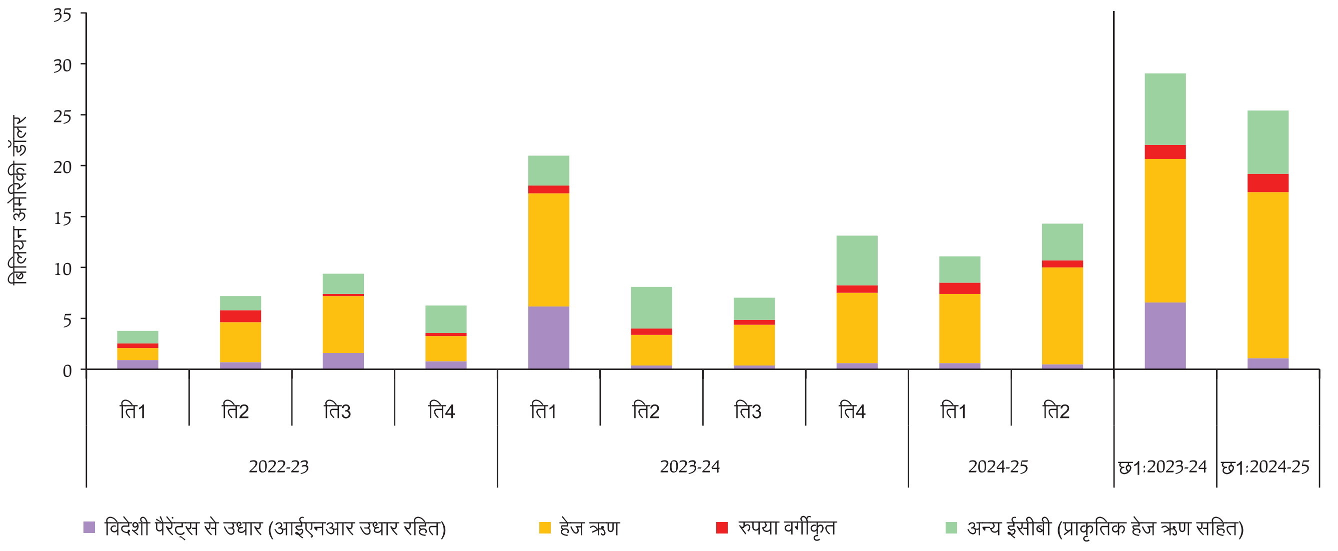

स्रोत: फॉर्म ईसीबी; आरबीआई।

8 नवंबर 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 675.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2024 के अंत में दर्ज 705.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर से पीछे हट गया। वर्तमान स्तर पर, भंडार 11 महीने से अधिक के आयात और जून 2024 के अंत में बकाया बाह्य ऋण के 99 प्रतिशत से अधिक को कवर करता है (चार्ट IV.26ए)। भारत ने वर्ष 2024 के दौरान अब तक (8 नवंबर तक) अपने भंडार में 53.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े हैं, जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे अधिक है (चार्ट IV.26बी)। 2024 में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार पर एशिया का दबदबा है, दुनिया की शीर्ष दस भंडार रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से सात इस क्षेत्र में स्थित हैं।

भुगतान प्रणाली

त्यौहारी मौसम के दौरान भुगतान के सभी माध्यमों में डिजिटल लेन-देन में तेज़ी देखी गई (सारणी IV.3)। तत्काल

चार्ट IV.24: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024)

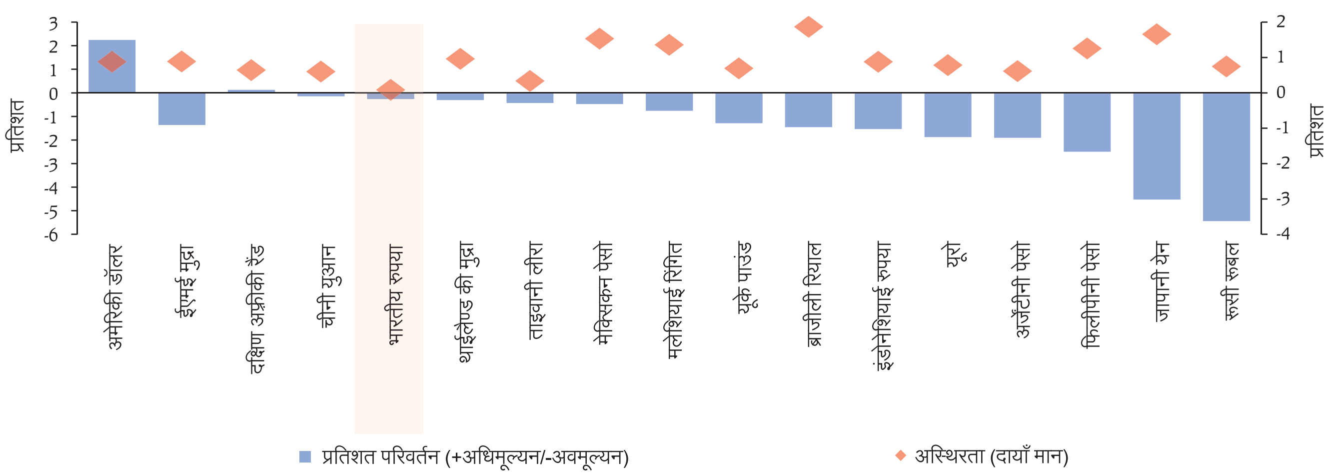

टिप्पणी: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना,स्विस फ्रैंक) की बास्केट की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव को मापता है।
स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.25: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

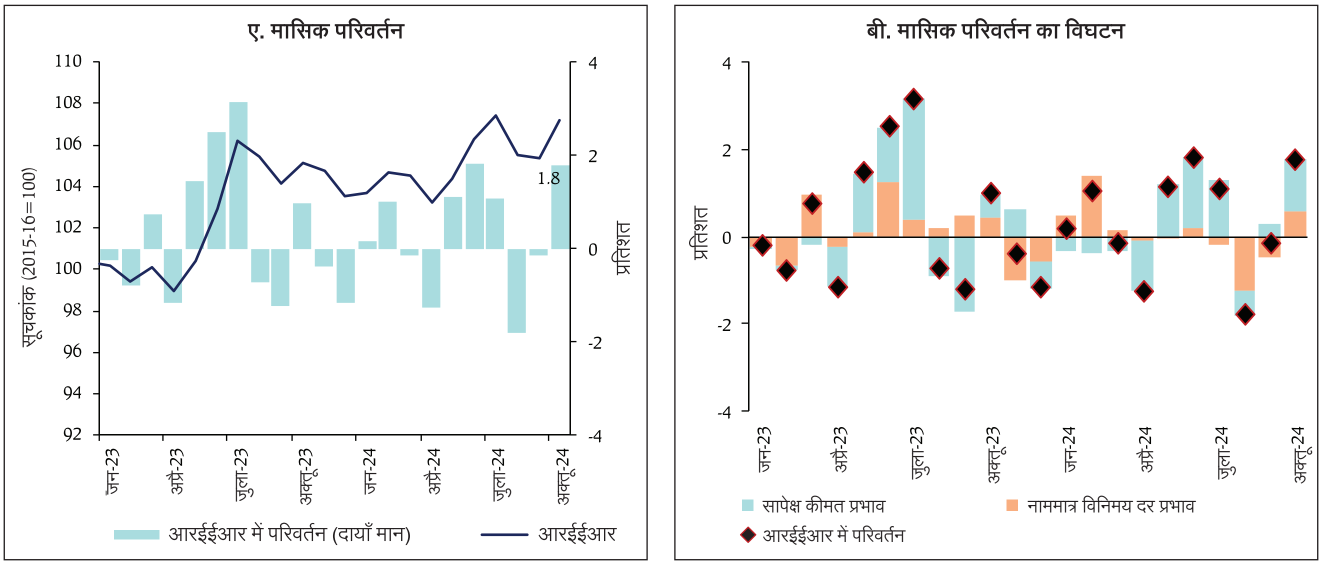

स्रोत: आरबीआई।

सकल निपटान (आरटीजीएस) में वृद्धि देखी जा रही है, अक्टूबर 2024 तक लेन-देन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 19 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से खुदरा भुगतान अक्टूबर 2024 में 16.6 बिलियन लेन-देन की रिकॉर्ड मात्रा तक पहुँच गया। यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की संख्या एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई, सितंबर 2024 तक लगभग 61 करोड़ सक्रिय यूपीआई क्यूआर हैं। पैमाने में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ, सिस्टम की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है, जो सितंबर 2023 में 77 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत तक सफल तत्काल डेबिट रिवर्सल में वृद्धि से प्रदर्शित होता है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने वर्ष 2024-25 में अब तक तिहरे अंकों की वृद्धि हासिल की है, जो कि अप्रैल 2024 से गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स को प्रणाली में अनुमति देने वाले

चार्ट IV.26: विदेशी मुद्रा भंडार

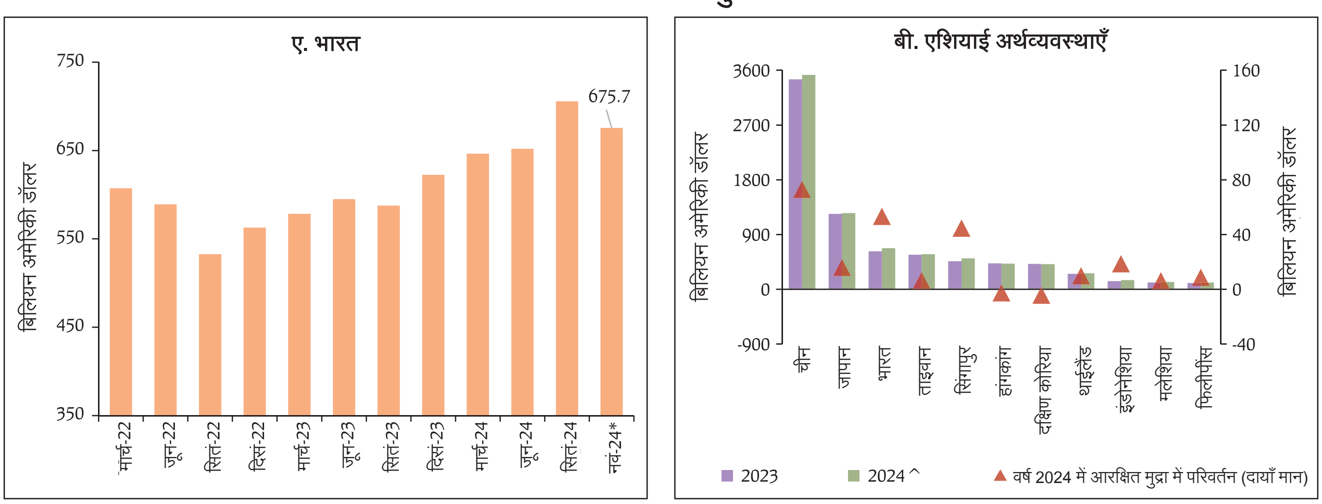

टिप्पणियाँ: 1. *: 8 नवंबर 2024 का डेटा।

2. ^: देशों को वर्ष 2024 में आरक्षित मुद्राओं में परिवर्तन के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। भारत के लिए नवीनतम डेटा 8 नवंबर 2024, हांगकांग और मलेशिया के लिए सितंबर के अंत और अन्य देशों के लिए अक्टूबर के अंत तक है।

स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

सारणी IV.3: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-द-व प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन की मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	सितं-23	सितं-24	अक्टू-23	अक्टू-24	सितं-23	सितं-24	अक्टू-23	अक्टू-24
आरटीजीएस	7.9	9.1	18.0	19.3	5.5	22.3	16.6	26.8
एनईएफ़टी	29.2	41.3	38.2	45.4	7.0	15.1	19.6	27.3
यूपीआई	55.7	42.5	56.2	45.4	41.4	30.7	41.6	37.0
आईएमपीएस	2.3	-9.1	2.2	-5.3	11.7	11.4	15.5	16.9
एनएसीएच	20.1	20.2	-1.5	64.5	14.0	27.1	11.9	43.5
एनईटीसी	15.4	6.5	13.0	7.9	19.9	10.4	24.4	10.4
बीबीपीएस	20.2	106.6	26.6	101.0	43.8	268.5	59.2	299.2

टिप्पणी: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, **एनईएफ़टी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस, **आईएमपीएस:** त्वरित भुगतान सेवा,
एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, **एनईटीसी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, **बीबीपीएस:** भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से प्रभावित है।[32] बिल भुगतानों को केंद्रीकृत करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बीबीपीएस सभी क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतानों को संसाधित करता है, जिसमें प्रमुख जारीकर्ता तीसरे पक्ष के लेनदेन का समर्थन करते हैं।[33] इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) भारत बिलपे लिमिटेड और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बीच साझेदारी ने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भुगतान को जोड़ा, जिससे बीबीपीएस को अपनाने में और तेजी आई।[34]

दिसंबर 2023 से, प्रति 1 लाख डिजिटल लेनदेन पर धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है, जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षा में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है (चार्ट IV.27)। आरबीआई इनोवेशन हब (आरबीआई) ने अगस्त 2024 में म्यूलहंटर नामक एक एडवांस एआई टूल विकसित किया, ताकि म्यूल खातों का पता लगाया जा सके।[35] इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की, जिसमें इंटरनेट पर सेंध लगाना और ओटीपी घोटाले जैसे जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।[36] इसके अलावा, एनपीसीआई ने उपयोगकर्ताओं में यूपीआई की सुरक्षा और मजबूती को सक्रिय रूप से सुदृढ़ करने के लिए यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है।[37]

28 अक्टूबर 2024 को, रिज़र्व बैंक ने भारत में समाशोधन और निपटान के लिए अधिकृत केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो जून 2019 के दिशा-

चार्ट IV.27: प्रति 1 लाख डिजिटल लेनदेन पर धोखाधड़ी की संख्या

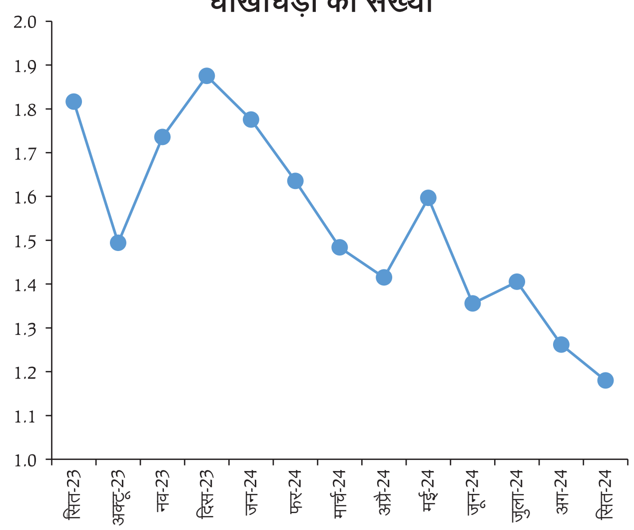

टिप्पणी: डेटा में धोखाधड़ी करने का प्रयास शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई।

32 आरबीआई मास्टर निर्देश, 29 फरवरी 2024

33 भारत कनेक्ट प्रेस रिलीज़, 9 जुलाई 2024

34 एनपीएस प्रेस प्रकाशनी, 28 अगस्त 2024

35 https://rbihub.in/mule-hunter-ai/

36 एनपीसीआई परिपत्र, 17 अक्टूबर 2024

37 एनपीसीआई परिपत्र, 6 नवंबर 2024

38 आरबीआई प्रेस प्रकाशनी, 28 अक्टूबर 2024

निर्देशों को बदल देते हैं।[38] इन नए नियमों का उद्देश्य सीसीपी की परिचालन सुरक्षा, वित्तीय आघात-सहनीयता बढ़ाना और वैश्विक मानकों के साथ संरेखण को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्यों में सीसीपी अभिशासन, वित्तीय सुदृढ़ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना, अंततः भारत की वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता और समाशोधन और निपटान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना शामिल है।

निष्कर्ष

वैश्विक वृद्धि की निकट भविष्य में अपनी गति बनाए रखने की उम्मीद है क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में घटती मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थितियों में सहजता उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देती है। नौकरी रिक्तियों की दरों में गिरावट और कम बेरोजगारी दरों के साथ श्रम बाजार की स्थिति सहायक बनी हुई है। वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण सकारात्मक है, हालांकि संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की आशंकाएँ नवजात सुदृढ़ता पर हावी हैं। मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता विश्वास अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जो आगे चलकर बाधा बन सकता है। हालाँकि लक्षित बुनियादी ढाँचा निवेश और सामाजिक व्यय कार्यक्रमों सहित विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीतियों से वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन उच्च ऋण स्तरों पर चिंताएँ महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, जिसने हाल के महीनों में प्रतिफल को बढ़ाया है। मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सहजता के लिए जगह बनने के बावजूद, ईएमई केंद्रीय बैंकों को बाहरी प्रतिकूलताओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नीतिगत प्रतिक्रियाओं में अंतर हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था त्योहारों से जुड़ी खपत और कृषि क्षेत्र में सुधार के कारण आघात-सहनीयता दिखा रही है। खरीफ खाद्यान्नों के लिए रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान और रबी फसल की आशाजनक संभावनाएं कृषि आय और ग्रामीण मांग के लिए भविष्य में अच्छी हैं। संस्थागत बुनियादी अवसंरचना के संदर्भ में, सटीक उत्पादन अनुमान के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षणों को अपनाना और ड्रोन की शुरूआत वास्तविक समय के आधार पर उत्पादन स्थितियों का आकलन करने और संभवतः सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन को सक्षम करके इस क्षेत्र में दीर्घकालिक दक्षता और उत्पादकता लाभ लाने के लिए तैयार है।

औद्योगिक मोर्चे पर, विनिर्माण और निर्माण में गतिशीलता बनी रहने की उम्मीद है। ईवी अपनाने, अनुकूल नीतियों, सब्सिडी और बढ़ते बुनियादी ढांचे ने भारत को टिकाऊ परिवहन में अग्रणी बना दिया है और उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि की गति, मजबूत रोजगार सृजन और उच्च उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को बनाए रखने की उम्मीद है।

वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में उतार-चढ़ाव के कारण बॉण्ड और इक्विटी बाजारों में दबाव के बावजूद, वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी रहने की संभावना है, जैसा कि कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने और एफडीआई प्रवाह में परिलक्षित होता है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भी अपनी विकास गति को बनाए रखने की उम्मीद है।

भारत के लिए संतुलन विनिमय दरों के अनुमान हेतु एक उपागम समूह

*माइकल देवब्रत पात्र, हरेंद्र बेहरा, धीरेंद्र गजभिए, सुजाता कुंडू और राजस सरॉय द्वारा^*

विभिन्न उपागम (एप्रोच), अर्थात् बीईईआर, पीईईआर और एफईईआर के माध्यम से भारत की संतुलन विनिमय दर की व्यापक पड़ताल, भारतीय रुपये के संतुलन मूल्य को निर्धारित करने में सापेक्ष उत्पादकता अंतर, व्यापार की निवल शर्तें, निवल विदेशी आस्ति की स्थिति और राजकोषीय संतुलन की भूमिका पर प्रकाश डालती है। मॉडल की सीमाओं और देश-विशिष्ट परि-स्थितियों के बारे में जानकारी के साथ मॉडलों का यह समूह नीति निर्माताओं को विनिमय दर की गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा प्रदान करता है।

भूमिका

नॉमिनल विनिमय दर का उचित स्तर क्या है, यह एक केंद्रीय नीतिगत प्रश्न है, चाहे विनिमय दर व्यवस्था का प्रकार कुछ भी हो। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब तक विदेशी बाजार लगातार समाशोधन कर रहा है, तब तक यह वास्तविक बाजार दर है। फिर भी, नीति निर्माता इस तथ्य के प्रति बेहद संवेदनशील हैं कि कई तरह के कारक बाजार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और अक्सर अजीबोगरीब परिणाम लाते हैं। वास्तविक समय में समाचारों के बाजार के मूल्य निर्धारण में निहित उच्च शोर-से-संकेत अनुपातों के अलावा, अन्य कारक जो अस्थिर बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं, वास्तविक आघात हैं, जैसे कि : वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव, पूंजी प्रवाह में बदलाव और मौद्रिक नीति में बदलाव जैसे आघात (क्रुगमैन, 1990)। नतीजतन, विदेशी मुद्रा बाजार शुरू में अति-प्रतिक्रिया कर सकता है, और इस अति-प्रतिक्रिया के विस्तार में लंबा समय लग सकता है। इसे मौलिक ओवरशूटिंग परिकल्पना (डॉर्नबुश, 1976) कहा जाता है। तदनुसार, यदि नीति निर्माताओं को "संतुलन" का कुछ बोध है, तो वे नॉमिनल दरों को उस दिशा में बढ़ने की अनुमति देकर या प्रेरित करके समायोजन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल दरों को दरकिनार करना वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रभावों के संदर्भ में महंगा पड़ सकता है, जैसे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की हानि, संसाधनों का गलत आबंटन या यहां तक कि आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव, और उछाल, अचानक जड़ता और पूंजी की निकासी।

संतुलन विनिमय दर एक ऐसी अवधारणा है जिसने सैद्धांतिक और शोधजन्य शोध का प्रसार किया है। इसकी जड़ें मौलिक कार्य में हैं जो इसे विनिमय दर के रूप में परिभाषित करती है, जो आंतरिक और बाह्य संतुलन की एक साथ उपलब्धि के अनुरूप है (आर्टस, 1977; विलियमसन, 1985)। आंतरिक संतुलन आर्थिक गतिविधि का वह स्तर है जो मुद्रास्फीति को कम और स्थिर या लक्ष्य पर रखता है। बाह्य संतुलन चालू खाता शेष के एक संधारणीय[1] स्तर से संबंधित है जो बचत और निवेश के वांछित स्तर को दर्शाता है। दोनों में मानक विकल्प शामिल हैं और इसलिए पद्धतिगत और माप संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। इसलिए, अवसर का लाभ लेने वाले नीति निर्माता के लिए, संतुलन विनिमय दर एक शोधजन्य मुद्दा है और इसका अनुमान इन अंतर्निहित बुनियादी बातों के बारे में साहसिक मान्यताओं के तहत लगाया जाना चाहिए।

साहित्य के सर्वेक्षण से, संतुलन विनिमय दर के मॉडलिंग के लिए कई उपागम सामने आए हैं (ड्राइवर और वेस्टवे, 2004; आईएमएफ 2007; बुसीयर और अन्य, 2010)। संतुलन विनिमय दर का अनुमान लगाने के लिए सही उपागम पर किसी भी आम सहमति के अभाव को देखते हुए, व्यावहारिक उपागम उपलब्ध मॉडलों के एक समूह का अनुमान लगाना रहा है जो विनिमय दर के स्तर का स्पष्ट आकलन करने के लिए संकेतकों और अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखते हैं (आईएमएफ, 2005)।

इस आलेख में, हम व्यावहारिक उपागम अपनाते हैं और भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर के उचित स्तरों का आकलन करने के लिए भारत के लिए संतुलन विनिमय दर मॉडल का शोधजन्य रूप से अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं जो

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] किसी देश की अंतर-कालिक बजट बाध्यता के अनुरूप।

आंतरिक और बाह्य संतुलन[2] की प्राप्ति के अनुरूप हैं। इस श्रेणी में मौलिक संतुलन विनिमय दर (एफईईआर) मॉडल (विलियमसन, 1994) और वांछित संतुलन विनिमय दर (डीईईआर) मॉडल (बायौमी, और अन्य, 1994) शामिल हैं। हम भारतीय डेटा पर कारकों के एक बहिर्जात सेट को लागू करके संतुलन विनिमय दर मॉडल का भी अनुमान लगाते हैं, जिन्हें पहचाना जाता है जो आंतरिक और बाह्य संतुलन के प्रतिनिधित्व के लिए नीति वरीयता को ग्रहण करते हैं। फिर एक छोटा रूप बनाया जाता है जो विनिमय दर को इन मौलिक कारकों से जोड़ता है (एडवर्ड्स, 1994)। इस प्रकार, यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चालू खाता शेष का संधारणीय स्तर क्या होना चाहिए क्योंकि यह प्रणाली के लिए अंतर्जात हो जाता है (फेयज़ियोग्लू, 1997)। इस श्रेणी के मॉडल में व्यवहारिक संतुलन विनिमय दर (बीईईआर) मॉडल (मैकडोनाल्ड और क्लार्क, 1998), स्थायी संतुलन विनिमय दर (पीईईआर) मॉडल (मेसो-फर्नांडीस, और अन्य, 2001) और प्राकृतिक वास्तविक संतुलन विनिमय दर (एनएटीआरईएक्स) मॉडल (एलन, 1995) शामिल हैं। इस उपागम के पीछे यह उपागम है कि प्रत्येक मॉडल एक विशेष नीति प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है और उन सभी को एक साथ लेने पर भारत के लिए संतुलन विनिमय दर का आकलन करने के लिए एक सीमा प्राप्त होती है।

इस आलेख में, हम क्रय शक्ति समता (पीपीपी) का आकलन करके इस खोज की शुरुआत करते हैं, जो प्रत्येक देश की मुद्रा में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की एक सामान्य टोकरी के संदर्भ में संतुलन विनिमय दरों के अंतर्निहित सबसे बुनियादी सिद्धांत के रूप में है; मौलिक संतुलन विनिमय दर (एफईईआर), जो समष्टि आर्थिक संतुलन के साथ संगति को दर्शाता है; व्यवहारिक संतुलन विनिमय दर (बीईईआर), जो दीर्घकालिक समष्टि-बुनियादी बातों और अल्पकालिक चक्रीय प्रभावों पर विचार करती है; और स्थायी संतुलन विनिमय दर (पीईईआर) जो केवल दीर्घकालिक बुनियादी बातों पर विचार करती है और बीईईआर का विस्तार है।

अगले भाग में, हम उन अंतर्निहित कारकों का वर्णन करते हैं जो चरों के चयन के लिए तर्क निकालने के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर के व्यवहार पर असर डालते हैं। भाग III प्रत्येक मॉडल और उनकी कमियों के लिए विशिष्ट विशेषताओं को बताता है। भाग IV उनके परिणाम और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। भाग V कुछ नीतिगत उपागमों के साथ आलेख का समापन करता है।

[2] भारतीय संदर्भ में उपलब्ध कुछ अध्ययनों ने मुख्य रूप से पीपीपी या बीईईआर दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है (अनुलग्नक सारणी ए3)।

II. स्थापित तथ्य

भारत की विनिमय दर 130 वर्षों से अधिक समय तक कई व्यवस्थाओं में विकसित हुई है। ये व्यवस्थाएँ, यानी उद्देश्यों और साधनों के साथ औपचारिक ढाँचे, स्वर्ण विनिमय मानक (1893-1946), ब्रेटन वुड्स सममूल्य प्रणाली (1947-1971), मुद्राओं की पेग्ड बास्केट व्यवस्था (1975-1990), एक संक्रमणकालीन दोहरी विनिमय दर व्यवस्था (1991-1992) और अंत में मार्च 1993 से बाजार संचालित विनिमय दर प्रणाली को कवर करती हैं।

2000 के दशक की शुरुआत से, भारत की 40-मुद्रा व्यापार-भारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में सालाना आधार पर औसतन 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में प्रति वर्ष लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो भारत और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर को दर्शाती है। चूंकि आरईईआर की गणना मुद्राओं की एक विस्तृत टोकरी के साथ की जाती है और मूल्य स्तरों के लिए समायोजित की जाती है, इसलिए यह द्विपक्षीय नॉमिनल विनिमय दरों की तुलना में एक स्थिर प्रवृत्ति दिखाती है। वास्तविक और नॉमिनल दोनों आघात आरईईआर के विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसके दीर्घकालिक रुझान अर्थव्यवस्था के भीतर गहरे, संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाते हुए चक्रीय बलों के लिए समायोजित किए जाते हैं।

आरईईआर की प्रवृत्ति में बदलाव तकनीकी परिवर्तनों, व्यापार की संरचना में बदलाव, उत्पादकता गतिशीलता, निवल विदेशी संपत्ति की स्थिति और दीर्घकालिक ब्याज दर अंतर, व्यापार की शर्तों में बदलाव और चालू खाता शेष से जीडीपी अनुपात के कारण हो सकता है। भारत में, व्यापार योग्य वस्तुओं के क्षेत्र में बढ़ती उत्पादकता ने आरईईआर की सराहना की एक निरंतर प्रवृत्ति में योगदान दिया है, जो बालासा-सैमुअलसन प्रभाव[3] (चार्ट 1) के अनुरूप है।

[3] बालसा-सैमुएलसन प्रभाव बताता है कि कैसे गैर-व्यापार योग्य क्षेत्र की तुलना में व्यापार योग्य क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वृद्धि, दोनों क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि की ओर ले जाती है, जिससे व्यापार से इतर योग्य वस्तुओं की सापेक्ष कीमत बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ते व्यापार योग्य क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि होती है (बालसा,1964; सैमुएलसन,1964)।

चार्ट 1: सापेक्ष श्रम उत्पादकता और आरईईआर में बदलाव

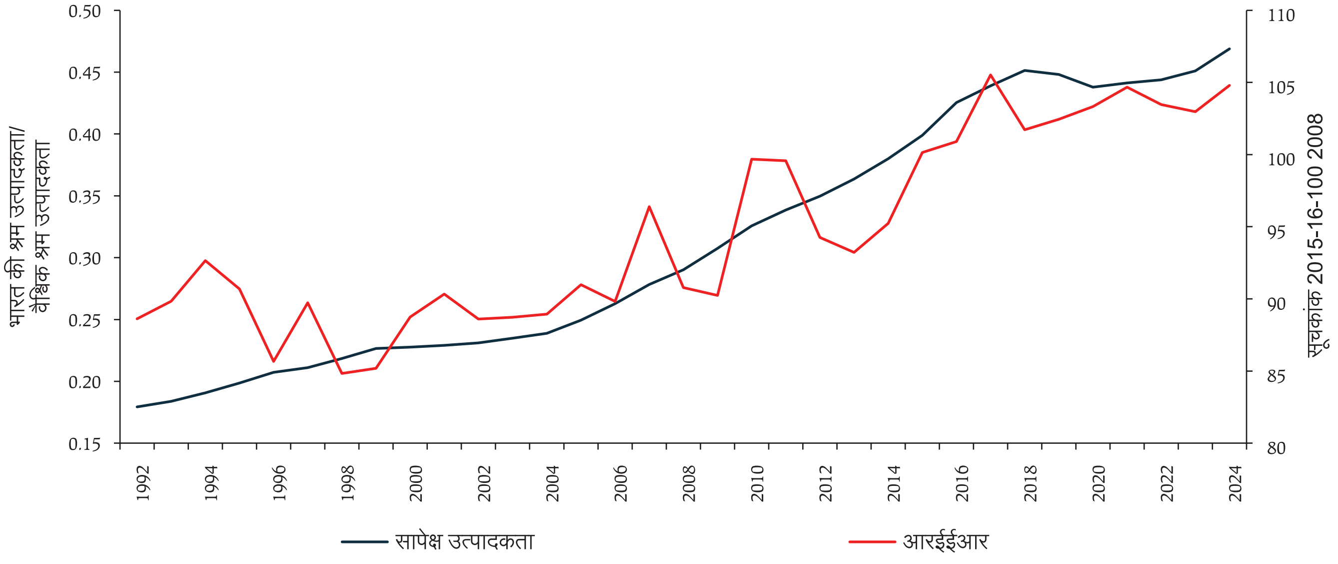

स्रोत: कॉन्फ्रेंस बोर्ड, और लेखकों की गणना।

अल्पावधि में, आरईईआर कमोडिटी मूल्य आघातों से प्रभावित हो सकता है - उदाहरण के लिए, भारत के मामले में कच्चे तेल की कीमतें - व्यापार की शर्तों में बदलाव लाती हैं। भारतीय अनुभव में, निवल व्यापार शर्तों (टीओटी) में सुधार आम तौर पर एक तिमाही के अंतराल के साथ आरईईआर की सराहना के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया जाता है (चार्ट 2)।

चालू खाता घाटा बढ़ने से भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है, जबकि भारत की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि से आरईईआर में वृद्धि होती है (चार्ट 3)[4]

वास्तविक ब्याज दर अंतर, अप्रकाशित ब्याज दर समता (यूआईपी) स्थिति के माध्यम से आरईईआर का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है- जब भारत की दीर्घकालिक ब्याज दर उसके

चार्ट 2: आरईईआर और व्यापार की शर्तें

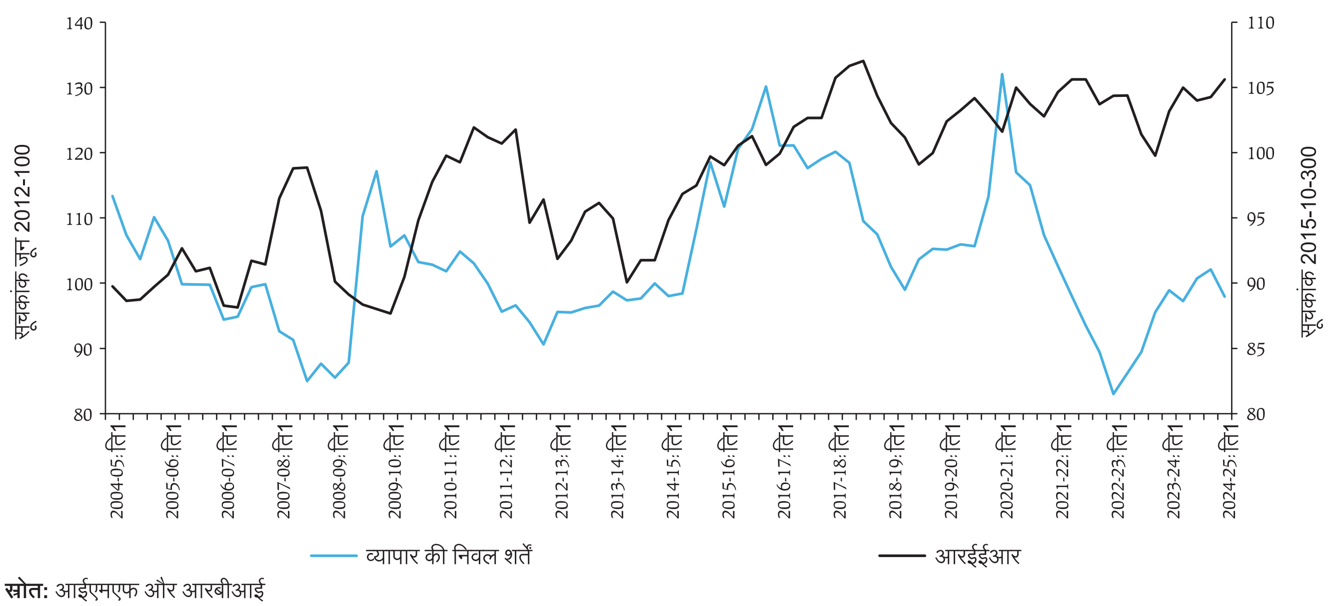

स्रोत: आईएमएफ और आरबीआई

4 हमारे विश्लेषण में जिन अन्य वैकल्पिक चरों पर विचार किया गया, वे हैं सकल घरेलू उत्पाद में निवल पूंजी प्रवाह अनुपात तथा सकल घरेलू उत्पाद में चालू खाता शेष (सीएबी) अनुपात।

चार्ट 3: आरईईआर में परिवर्तन, चालू खाता शेष और निवल विदेशी आस्तियाँ

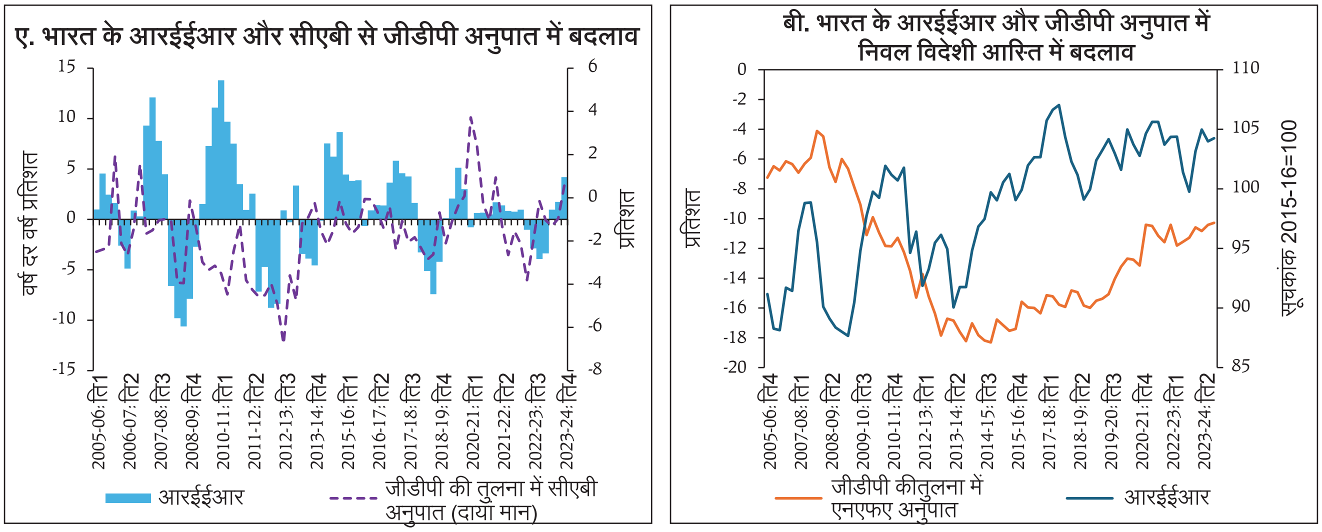

स्रोत: आरबीआई और लेखकों के आकलन।

व्यापारिक भागीदारों की तुलना में अधिक होती है, तो यह विदेशी पूंजी को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय मुद्रा की मांग बढ़ती है और आरईईआर में वृद्धि होती है (चार्ट 4ए)। यह संबंध अल्पकालिक और मध्यम अवधि की विनिमय दर गतिशीलता के बीच एक सेतु का काम करता है। वास्तविक अनुभव इस सैद्धांतिक प्रस्ताव को नकारता है कि ब्याज दर अंतर को लंबे समय में देशों में अभिसरित होना चाहिए।

व्यापार में खुलापन व्यापार की कुल मात्रा में वृद्धि की ओर ले जाता है। यदि परिणामस्वरूप चालू खाता खराब हो जाता है, तो आरईईआर आम तौर पर संतुलन बहाल करने के लिए मूल्यह्रास करता है। इसके विपरीत, यदि चालू खाता बेहतर होता है, तो प्रतिक्रिया में आरईईआर बढ़ता है (चार्ट 4बी)।

चार्ट 4: आरईईआर में बदलाव, दीर्घावधि ब्याज दर अवकलन और कुल व्यापार

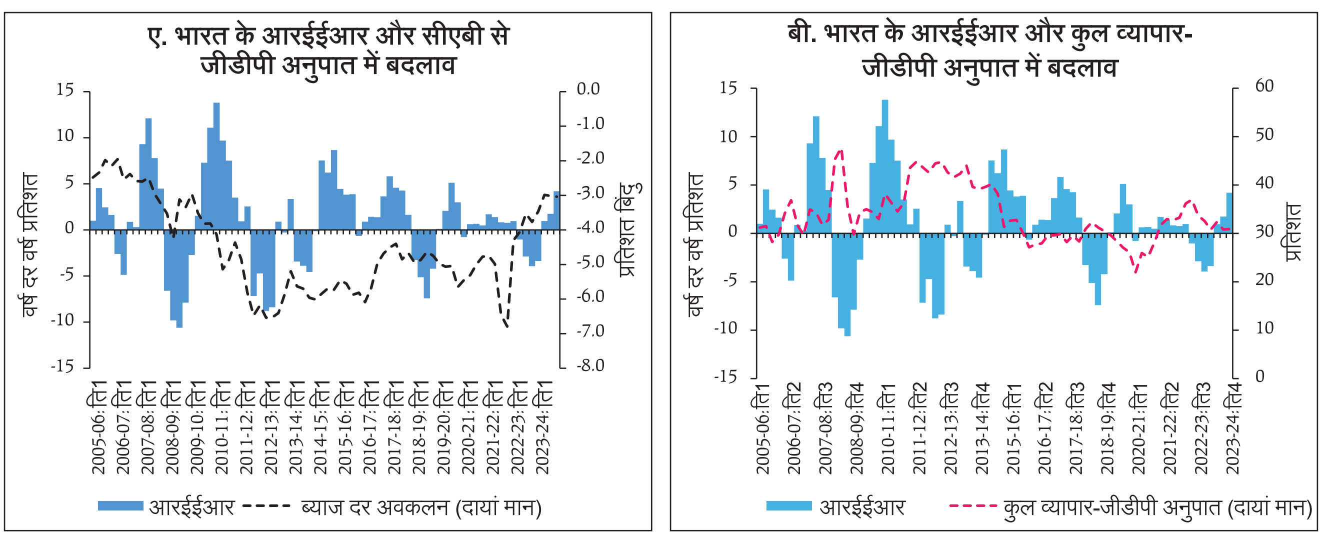

टिप्पणी: दीर्घावधि ब्याज दर अंतर यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड माइनस इंडिया 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड है; कुल व्यापार से जीडीपी अनुपात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक निर्यात और आयात का प्रतिनिधित्व करता है।
स्रोत: आरबीआई; आईएमएफ; रॉयटर्स; एफआरईडी; और लेखकों की गणना।

III. मॉडल विवरण

पीपीपी फ्रेमवर्क (रोगॉफ, 1996; डी ब्रोक और स्लोक, 2001) में व्यापारिक भागीदारों के पीपीपी-समायोजित प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात पर सापेक्ष मूल्य स्तरों का क्रॉस-सेक्शनल प्रतिगमन शामिल है- सापेक्ष उत्पादकता अंतर के लिए एक प्रॉक्सी। प्रतिगमन रेखा का ढलान संयुक्त राज्य अमेरिका के सापेक्ष प्रति व्यक्ति जीडीपी में 1 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी अपेक्षित वास्तविक विनिमय दर प्रशंसा को इंगित करता है (चार्ट 5)।

The regression results obtained are as follows:

$$\log\left(\frac{P}{P^{US}}\right) = 0.50 \log\left(\frac{GDP}{GDP^{US}}\right) + 2.0$$

जहाँ P घरेलू मूल्य स्तर को दर्शाता है, पीयूएस अमेरिकी कीमतों द्वारा दर्शाए गए विदेशी मूल्य स्तर को दर्शाता है, और जीडीपी तथा जीडीपीयूएस क्रमशः विभिन्न देशों और अमेरिका के पीपीपी आधार पर प्रति व्यक्ति जीडीपी हैं[5]।

इस सरलीकृत ढाँचे में, प्रतिगमन से अनुमानित मूल्य एक संदर्भ विनिमय दर के रूप में कार्य करते हैं जो बालासा-सैमुअलसन प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रतिगमन रेखा से ऊपर स्थित देशों जैसे भारत में उनके जीवन स्तर के सापेक्ष उच्च मूल्य स्तर हैं, जो दर्शाता है कि विनिमय दरें संतुलन स्तरों से अधिक हैं। इसके विपरीत, रेखा से नीचे स्थित देश अपेक्षाकृत कम मूल्य स्तर प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि विनिमय दर का कम मूल्यांकन किया गया है।

चार्ट 5: पीपीपी आधारित विनिमय दर का गलत संरेखण (2023 के लिए अनुमानित)

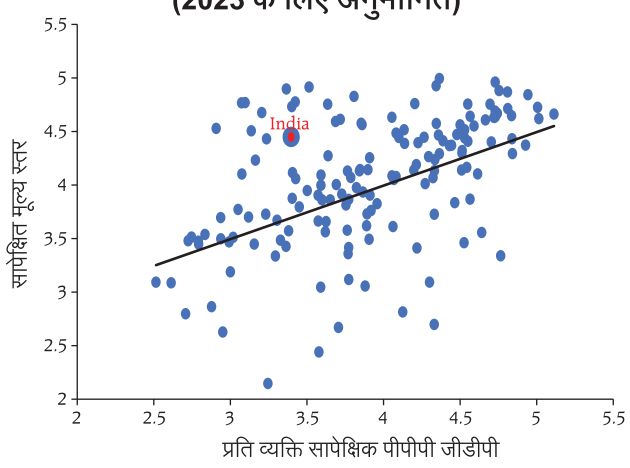

टिप्पणी: विभिन्न देशों के सापेक्ष मूल्य स्तरों की गणना अमेरिकी डॉलर में जीडीपी को पीपीपी शर्तों में जीडीपी से विभाजित करके और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल्य स्तर से की जाती है। इस प्रकार इन सापेक्ष मूल्य स्तरों की व्याख्या पीपीपी विनिमय दरों से विचलन के रूप में की जा सकती है।
स्रोत: आईएमएफ; और लेखकों की गणना।

बीईईआर उपागम वास्तविक यूआईपी का विस्तार है और इसे ऐतिहासिक डेटा (मैकडोनाल्ड, 1997; 1999) के माध्यम से पहचाना जा सकता है। सह-एकीकरण विधियों का उपयोग करते हुए, बीईईआर वास्तविक विनिमय दर में अल्पकालिक विचलन को सट्टा दबावों, अस्थायी आघातों या नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण होने वाले मिसअलाइनमेंट के रूप में मानता है। यह उपागम संतुलन विनिमय दर को वर्तमान आर्थिक बुनियादी बातों के साथ संरेखित करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। बीईईआर की विश्वसनीयता, हालांकि, स्थिर डेटा और स्थिर अवस्था के करीब पहुंचने वाले चर पर निर्भर करती है, जिससे यह परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त हो जाती है।

पीईईआर उस विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करता है जो तब प्रबल होगी जब सभी आर्थिक चर अपने स्थिर अवस्था मूल्यों पर होंगे, अस्थायी आघातों या चक्रीय उतार-चढ़ाव से अप्रभावित। पीईईआर उपागम का उद्देश्य सट्टा गतिविधि और नीति-संचालित प्रभावों (गोंजालो और ग्रेंजर, 1995; क्लार्क और मैकडोनाल्ड, 2000) जैसे अल्पकालिक कारकों को फ़िल्टर करके वास्तविक विनिमय दर के अंतर्निहित स्थिर घटक को अलग करना है। पीईईआर की गणना बीईईआर मॉडल (एगर्ट, 2003) में बुनियादी बातों के वास्तविक स्तरों को उनके अनुमानित रुझान स्तरों से प्रतिस्थापित करके की जा सकती है। बीईईआर मॉडल का यह विस्तार एफईईआर के करीब संतुलन आरईईआर का अनुमान प्रदान करता है।

एफईईआर उपागम एक विनिमय दर स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो अर्थव्यवस्था के चालू खाते को पूर्ण रोजगार या उत्पादन के संतुलन स्तर के अनुरूप एक स्थायी संतुलन में लाएगा। यह मानक है क्योंकि इसके लिए मध्यम अवधि में भुगतान संतुलन के लक्षित परिणाम के अनुरूप विनिमय दर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है (अक्सर चालू खाते में संरचनात्मक समायोजन को दर्शाता है)। यह उपागम एक संतुलन आरईईआर प्रदान करता है जो अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक संतुलन (विलियमसन, 1994) के अनुरूप है, जैसा कि पहले व्याख्या की गई है। इस उपागम से संतुलन आरईईआर का अनुमान लगाने के लिए संधारणीय चालू खाता संतुलन के बारे में मान्यताओं की आवश्यकता होती है, जो इसे बीईईआर की तुलना

[5] दोनों गुणांक 1 प्रतिशत के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं; आर2=0.16; प्रेक्षणों की संख्या (देश) = 161।

में कम डेटा-संचालित और अधिक सैद्धांतिक बनाता है। जबकि बीईईआर अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में अनुमानित संतुलन आरईईआर प्रदान करेगा, पीईईआर और एफईईआर संतुलन आरईईआर प्रदान करेगा जो मध्यम से दीर्घावधि में प्रबल होना चाहिए।

पीपीपी, एफईईआर और बीईईआर को एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है क्योंकि वे अवलोकनीय आर्थिक बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि अल्पकालिक से मध्यम अवधि के विनिमय दर आकलन के लिए व्यावहारिक उपयोगिता है। ये मॉडल मूल्य स्तर (पीपीपी), भुगतान संतुलन स्थिरता (एफईईआर) और यूपीआई स्थिति (बीईईआर) जैसी सीधी मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। डीईईआर, पीईआर और नैट्रेक्स जैसे मॉडल की तुलना में, जो लंबी अवधि के संतुलन या नीति-संचालित लक्ष्यों पर जोर देते हैं, पीपीपी, एफईईआर और बीईईआर को संचालित करना आसान है। यह समूह विनिमय दर की गतिशीलता को समझने के लिए एक सुसंगत रूपरेखा प्रदान करता है, जो वैकल्पिक मॉडलों के रणनीतिक, दीर्घकालिक उपागमों का पूरक है।

IV. शोधजन्य पद्धति और परिणाम

बीईईआर उपागम के माध्यम से संतुलन आरईईआर का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया जाता है:

$$REER = f(RELGDPPC, TOT, NFA_GDP) \quad \ldots(1)$$

जबकि एनएफए से जीडीपी अनुपात (एनएफए_जीडीपी) प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, सापेक्ष प्रति व्यक्ति जीडीपी (आरईएलजीडीपीपीसी)[6] और निवल टीओटी (टीओटी)[7] को विचलन को स्थिर करने के लिए उनके लघुगणक रूपों में बदल दिया जाता है (अनुबंध सारणी ए1)। मानक एक्स-13 एआरआईएमए प्रक्रिया का उपयोग करके सभी चरों को डी-सीजनलाइज़ किया जाता है।

समीकरण (1) के आधार पर, संतुलन आरईईआर का अनुमान (2) में लगाया जा सकता है, जिसमें टोपी (कैप) का प्रतीक फिट की गई श्रृंखला को दर्शाता है:

$$BEER_t = \beta_0 + \beta_1 \widehat{RELGDPPC_t} + \beta_2 \widehat{TOT_t} + \beta_3 \widehat{NFA_GDP_t} \quad \ldots(2)$$

फिर बीईईआर के मूलभूत निर्धारकों को एचपी फ़िल्टर तकनीक (होड्रिक और प्रेस्कॉट, 1997) का उपयोग करके स्थायी और क्षणिक घटकों में विघटित किया जाता है ताकि पीईईआर प्राप्त किया जा सके। सुपरस्क्रिप्ट p श्रृंखला के स्थायी या दीर्घकालिक रुझानों को इंगित करता है।

$$PEER_t = \beta_0 + \beta_1 RELGDPPC_t^p + \beta_2 TOT_t^p + \beta_3 NFA_GDP_t^p + \mu_t \quad \ldots(3)$$

एफईईआर उपागम के लिए, एक लक्ष्य चालू खाता शेष/जीडीपी अनुपात (सीएबी) माना जाता है। यह लक्ष्य उस स्तर के अनुरूप होना चाहिए जिसे भारत लंबे समय तक बनाए रख सकता है, जिससे अत्यधिक बाहरी असंतुलन या अत्यधिक विदेशी ऋण संचय से बचा जा सके। सीएबी को आरईईआर और प्रमुख बुनियादी बातों के एक कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$CAB_t = \beta REER_t + \gamma_1 RGDPPC_t + \gamma_2 TOT_t + \gamma_3 NFA_GDP_t + \gamma_4 FISC_t + \epsilon_t \quad \ldots(4)$$

जहाँ β आरईईआर (लॉग फॉर्म में) में परिवर्तनों के लिए चालू खाते की संवेदनशीलता को दर्शाता है, γ_i चालू खाते और अन्य आर्थिक बुनियादी बातों (उत्पादकता अंतर; व्यापार की शर्तें; निवल विदेशी संपत्ति; राजकोषीय संतुलन ($FISC_t$) और ϵ_t एक त्रुटि टर्म है) के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुणांक हैं।

एफईईआर उपागम के तहत संतुलन आरईईआर का अनुमान लगाने के लिए, आरईईआर को लक्ष्य (CAB*) के बराबर चालू खाता स्तर प्राप्त करना चाहिए।

इससे निम्नलिखित संतुलन स्थिति प्राप्त होती है:

$$FEER_t = \frac{CAB* - \gamma_1 RGDPPC_t - \gamma_2 TOT_t - \gamma_3 NFA_GDP_t - \gamma_4 FISC_t}{\beta} \quad \ldots(5)$$

2004-05:क्यू1 से 2023-24:क्यू4 तक तिमाही डेटा पर सह-एकीकृत प्रतिगमन का एक सेट उपयोग किया जाता है (अनुबंध सारणी A1 उन चर/संकेतकों का विवरण प्रदान करती है जिनका शोधजन्य विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है)। चरों के समय श्रृंखला गुणों की जाँच करने के लिए, मानक इकाई मूल परीक्षण किए जाते हैं। जबकि आरईईआर को क्रम 1 का एकीकृत पाया गया है, व्यापार की निवल शर्तें स्थिर हैं (अनुबंध सारणी

---

[6] 22 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (स्थिरांक मूल्य) का भारित योग, जिसका भार आरबीआई द्वारा प्रकाशित 40 देशों के आरईईआर की गणना में प्रयुक्त व्यापार भार के समान है।

[7] निवल निर्यात द्वारा भारित।

ए2)। इसलिए, बीईईआर उपागम के तहत संतुलन आरईईआर का अनुमान लगाने के लिए एक ऑटोरिग्रैसिव वितरित लैग मॉडल (एआरडीएल) का उपयोग किया जाता है। परिणामों की मजबूती की जाँच करने के लिए पूरी तरह से संशोधित साधारण न्यूनतम वर्ग (एफएमओएलएस) और गतिशील साधारण न्यूनतम वर्ग (डीओएलएस) पद्धतियों का भी उपयोग किया जाता है।

आरईईआर के मूलभूत निर्धारकों के अनुरूप प्रतिगमन गुणांक अपेक्षित संकेतों (सारणी 1) के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण साबित होते हैं। परिणाम संकेत देते हैं कि दीर्घावधि में, प्रति व्यक्ति सापेक्ष जीडीपी द्वारा प्रदर्शित उत्पादकता संतुलन आरईईआर का एक प्रमुख निर्धारण कारक है, इसके बाद व्यापार की निवल शर्तें और जीडीपी अनुपात में निवल विदेशी संपत्ति आती है। सीमा परीक्षण चर के बीच दीर्घकालिक संबंध के अस्तित्व की पुष्टि करता है। इसलिए प्राप्त दीर्घावधि गुणांक का उपयोग संतुलन आरईईआर का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

सारणी 1: बीईईआर दृष्टिकोण के लिए एआरडीएल मॉडल के परिणाम

व्याख्यात्मक चर	दीर्घावधि गुणांक
स्थिरांक$_t$	4.71*** [16.81]
एलएन (प्रति व्यक्ति सापेक्ष जीडीपी)$_{t-1}$	0.21*** [5.88]
निवल विदेशी आस्तियाँ जीडीपी अनुपात$_{t-1}$	0.01*** [3.96]
एलएन (व्यापार की निवल शर्तें)$_{t-1}$	0.12** [2.01]
ईसीएम$_t$	-0.40*** [-6.81]
अनुमान परिणाम पोस्ट करें	
एडीजे आर-स्क्वेर	0.91
एफ-आंकड़ा	53.88
डीडब्ल्यू सांख्यिकी	2.01
ब्रुश-गॉडफ्रे सीरियल सहसंबंध एलएम टेस्ट[8]	संभावना एफ(2.55) = 0.99
ब्रुश-पैगन-गॉडफ्रे हेटेरोस्केडैस्टिसिटी टेस्ट[9]	संभावना एफ(13.57) = 0.77
बाउंड्स टेस्ट परिणाम	
एफ-सांख्यिकी = 8.66; 5 प्रतिशत निचली सीमा = 2.8; ऊपरी सीमा = 3.7.	

टिप्पणी: ** *;* *;*: 1 प्रतिशत से कम, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-सांख्यिकी हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

सारणी 2: बीईईआर दृष्टिकोण के लिए वैकल्पिक मॉडल विनिर्देशों से परिणाम

व्याख्यात्मक चर	एफएमओएलएस	डीओएलएस
एलएन (प्रति व्यक्ति सापेक्ष जीडीपी)$_t$	0.23*** [5.70]	0.23*** [12.22]
एलएन (व्यापार की निवल शर्तें)$_t$	-0.11 [-1.05]	-0.11* [-1.75]
एलएन (व्यापार की निवल शर्तें)$_{t-1}$	0.16 [1.50]	0.16*** [2.55]
विदेशी आस्तियां जीडीपी अनुपात $_t$	0.01** [2.40]	0.01*** [3.85]
स्थिरांक$_t$	5.05*** (17.60)	5.05*** (30.26)
एडीजे आर-स्क्वेर्ड	0.60	0.60

टिप्पणी: ** *;* *;*: 1 प्रतिशत से कम, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े t-सांख्यिकी हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

हालांकि, अल्पावधि में, आरईईआर का अपना अंतराल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।[10] त्रुटि सुधार गुणांक (ईसीएम) भी (-)0.4 के परिमाण के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है। मॉडल अनुमान-पश्चात निदान और स्थिरता परीक्षणों को संतुष्ट करता है। एआरडीएल मॉडल से प्राप्त दीर्घावधि गुणांक वैकल्पिक एफएमओएलएस और डीओएलएस मॉडल (सारणी 2) से प्राप्त परिणामों के अनुरूप हैं। मॉडल से प्राप्त आरईईआर के फिट किए गए मूल्य बीईईआर उपागम के आधार पर अल्पावधि संतुलन आरईईआर प्रदान करते हैं, जबकि अनुमानित दीर्घावधि गुणांक का उपयोग इस उपागम के तहत दीर्घावधि संतुलन आरईईआर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, बीईईआर मॉडल से दीर्घावधि गुणांक को अंतर्निहित चरों से प्राप्त रुझानों के साथ मिलाकर पीईईआर उपागम के तहत संतुलन आरईईआर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एफईईआर उपागम का उपयोग करके संतुलन आरईईआर की गणना करने के लिए, एआरडीएल मॉडल का उपयोग करके समीकरण (4) का अनुमान लगाया जाता है। परिणाम दर्शाते हैं कि व्यापार की निवल शर्तों में सुधार, आरईईआर के मूल्यह्रास और राजकोषीय घाटे में कमी के साथ चालू खाता घाटा कम हो जाता है। हालांकि, उत्पादकता अंतर में वृद्धि से चालू खाता घाटा बढ़ सकता है क्योंकि उत्पादकता-आधारित आय में वृद्धि से आयात की मांग बढ़ सकती है (सारणी 3)। अनुमानित मॉडल मापदंडों के

8 शून्य परिकल्पना: 2 पश्चों तक कोई क्रमिक सहसंबंध नहीं।

9 शून्य परिकल्पना: होमोस्केडैस्टिसिटी।

10 संक्षिप्तता के लिए, मॉडल के अल्पकालिक प्रतिनिधित्व के परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

सारणी 3: एफईईआर मॉडल के लिए पैरामीटर अनुमान

व्याख्यात्मक चर	दीर्घावधि गुणांक
एलएन(आरईईआर)$_t$	-13.62** [-7.40]
एलएन (प्रति व्यक्ति सापेक्ष जीडीपी)$_t$	-6.48** [-3.49]
विदेशी आस्तियां जीडीपी अनुपात$_t$	-0.01 [-0.15]
एलएन(व्यापार की निवल शर्तें)$_t$	6.80** [2.28]
राजकोषीय घाटा$_t$	-0.17*** [-2.64]
रुझान	0.11*** [-6.81]
एडीजे. आर-स्क्वेर्ड	0.49

टिप्पणी: ** *;* *;*: 1 प्रतिशत से कम और 5 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े t-सांख्यिकी हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

आधार पर, हम समीकरण (5) में निर्दिष्ट एफईईआर की गणना करते हैं।

जैसा कि अपेक्षित था, अल्पावधि बीईईआर वास्तविक आरईईआर के साथ निकटता से चलता है। बीईईआर की तुलना में पीईईआर कम अस्थिर है। एफईईआर संतुलन आरईईआर का सबसे अस्थिर अनुमान पाया गया है। बीईईआर और पीईईआर दोनों उपागम बताते हैं कि आरईईआर दीर्घावधि बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप स्तर से थोड़ा नीचे है। दूसरी ओर, वास्तविक

सारणी 4: विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर आरईईआर मिसअलाइनमेंट की डिग्री

वित्तीय वर्ष: 2023-24	बीईईआर: लघु अवधि	बीईईआर: लंबी दौड़	समकक्ष	फीयर
प्रश्न1	-0.9	3.9	3.8	9.2
प्रश्न2	-1.8	2.0	1.1	7.2
प्रश्न3	0.7	2.3	1.9	10.5
प्रश्न4	0.01	1.6	0.6	10.3

टिप्पणी: आरईईआर मिसअलाइनमेंट = संतुलन आरईईआर - वास्तविक आरईईआर।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

आरईईआर और एफईईआर के बीच का अंतर अधिक है (चार्ट 6)।

कुल मिलाकर, परिणाम संकेत देते हैं कि 2023-24 में, भारत का आरईईआर अपने दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांतों (सारणी 4) के अनुरूप स्तर से कुछ नीचे था। यह पीपीपी उपागम के तहत अल्पकालिक उपागमों के संदर्भ में मूल्यांकन के विपरीत है - जिसे बालासा-सैमुएलसन प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है - जो बताता है कि उसी अवधि के दौरान आरईईआर अपने संतुलन स्तर से ऊपर था, जो बड़े पैमाने पर व्यापार की निवल शर्तों में सुधार को दर्शाता है। यह विनिमय दर के स्तर के अल्पकालिक आकलन को एक ऐसे मूल्यांकन के साथ योग्य

चार्ट 6: बीईईआर, पीईईआर और एफईईआर दृष्टिकोणों से अनुमानित वास्तविक बनाम संतुलन आरईईआर

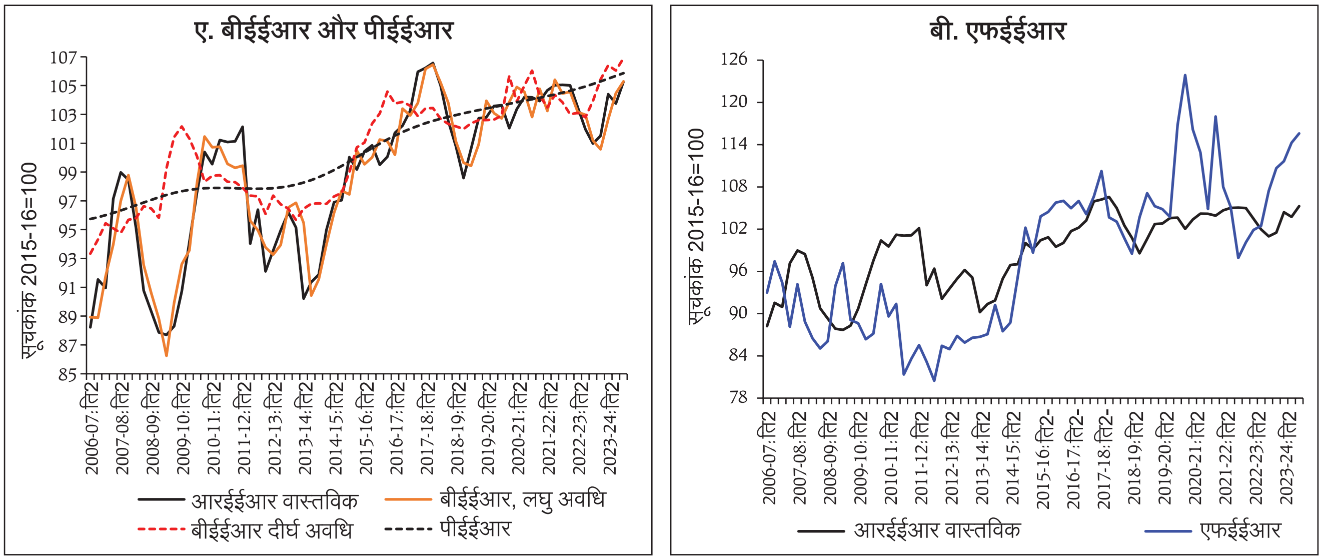

स्रोत: लेखकों के अनुमान और आरबीआई।

बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप हो।

V. समापन टिप्पणी

इस अध्ययन के निष्कर्ष संतुलन विनिमय दर के अनुमानों की एक श्रृंखला की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं, जो अवलोकनीय नहीं है। यहाँ अनुमानित वैकल्पिक उपागम आरईईआर या अन्य जैसे स्थिर संकेतकों के लिए बेहतर हैं जो सरल पीपीपी ढांचे की शैली से संबंधित हैं। संतुलन विनिमय दर को अंतर्निहित बुनियादी बातों में परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देकर, वे नीति निर्माताओं को विशिष्ट नीति उद्देश्यों के संबंध में मिसलिग्न्मेंट या अन्यथा के संदर्भ में विनिमय दर के स्तर का आकलन करने की अनुमति देते हैं। यह इस भावना में है कि इस आलेख की अगली कड़ी आईएनआर की संतुलन विनिमय दर का मूल्यांकन करने के लिए उपागमों के एक पूरे सूट को पूरा करने के लिए सीएचईईआर, डीईईआर और एनएटीआरईएक्स का अनुमान लगाने का प्रयास करेगी।

नीति उद्देश्यों के लिए इन अनुमानों का उपयोग करते समय, उनकी सीमाओं से अवगत होना उपयोगी है। एफईईआर यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि विनिमय दर संतुलन में कैसे जाएगी या हिस्टैरिसिस से कैसे निपटें जो आमतौर पर विनिमय दर व्यवहार को प्रभावित करता है। बीईईआर मानता है कि ऐतिहासिक डेटा से स्थिर दीर्घकालिक संबंधों का अनुमान लगाया जा सकता है, जो संरचनात्मक परिवर्तनों से विकृत हो सकता है।

तदनुसार, व्यावहारिक उपागम यह है कि अनेक तरीकों का उपयोग किया जाए तथा अंतर्निहित मान्यताओं और देश-विशिष्ट परिस्थितियों में उनकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तरीके की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जाए।

संदर्भ:

Allen, P. R. (1995). The economic and policy implications of the NATREX Approach. In *Fundamental Determinants of Exchange rates.* Oxford University Press.

Artus, J. R. (1977). Methods of Assessing the Long-Run Equilibrium Value of an Exchange Rate. *Journal of International Economics* 8(2). 277-299.

Banerjee, K., and Goyal, A. (2021). Behavioural Equilibrium Real Exchange Rates and Misalignments: Evidence from Large Emerging Markets. *Economic Analysis and Policy*, *70*, 414-436.

Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of Political Economy 72(6), 584–596.

Bayoumi, T., and Symansky, S. (1994). Robustness of equilibrium exchange rate calculations to alternative assumptions and methodologies. *IMF Working Paper* No. 94/17.

Bussière, M., Ca'Zorzi, M., Chudík, A., & Dieppe, A. (2010). Methodological advances in the assessment of equilibrium exchange rates. *European Central Bank Working Paper* No. 1151.

Clark, P. B., and MacDonald, R. (2000). Filtering the BEER: A Permanent and Transitory Decomposition. IMF Working Paper WP/00/144.

De Broeck, M., and Sløk, T. (2001). Interpreting Real Exchange Rate Movements in Transition Countries. *IMF Working Paper* WP/01/56.

Dornbusch, R. (1976). Expectations and Exchange Rate Dynamics. *Journal of Political Economy* 84 (6). 1161–1176.

Driver, R. L., and Westaway, P. F. (2004). Concepts of equilibrium exchange rates. In *Exchange rates, capital flows and policy* (pp. 98-148). Routledge.

Edwards, S. (1994). Exchange Rate Misalignment in Developing Countries. In *Approaches to Exchange Rate Policy.* International Monetary Fund.

Egert, B. (2003). Assessing Equilibrium Exchange Rates in CEE Acceding countries: Can we have DEER with BEER without FEER? A Critical Survey of the Literature. Oesterreichische Nationalbank, Focus on Transition Vol. 2/2003. 38-106.

Feyzioglu, M. T. (1997). *Estimating the equilibrium real exchange rate: an application to Finland.* International Monetary Fund.

Gonzalo, J., and Granger, C. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business and Economic Statistics*, *13*(1), 27-35.

Hodrick, R. J., and Prescott, E. C. (1997). Postwar US business cycles: an empirical investigation. *Journal of Money, credit, and Banking*, 1-16.

IMF (2005). Surveillance Guidance. Policy Development and Review Department. International Monetary Fund.

IMF (2007). The Equilibrium Exchange Rate: Alternative Concepts and Their Applications in IMF Surveillance.

Joshi, H. (2006). The Fundamental Equilibrium Real Exchange Rate in India: An Approach to Estimation and Measurement of Misalignment. *Reserve Bank of India Occasional Papers* 27 (3):1-24.

Krugman, P. (1990). Equilibrium Exchange Rates. In *International Policy Coordination and Exchange Rate Fluctuations*, William H. Branson, Jacob A. Frenkel, and Morris Goldstein (eds). University of Chicago Press.

Kumar, S. (2010). Determinants of real exchange rate in India: An ARDL approach. *Reserve Bank of India Occasional Papers* 31(1)1.

MacDonald, R. (1997). *What determines real exchange rates? The long and short of it.* International Monetary Fund.

MacDonald, R. and Clark, P. B. (1998). Exchange Rates and Economic Fundamentals: A Methodological Comparison of BEERs and FEERs. *IMF Working Paper* No. 1998/067.

MacDonald, R. (1999). Exchange rate behaviour: Are fundamentals important?. *The Economic Journal*, *109*(459).

Maeso-Fernandez, F., Osbat, C. and Schnatz, B. (2001). Determinants of the Euro Real Effective Exchange Rate: A BEER/PEER Approach". European Central Bank Working Paper No. 85.

Pattanaik, S. (1999). REER: The leading indicator. *Reserve Bank of India Occasional Papers* 20(2).

Raut, D. K. (2022). Behavioural Equilibrium Exchange Rates in Emerging Market Economies. *Reserve Bank of India Occasional Papers* 42(2).

Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. *Journal of Economic literature*, *34*(2), 647-668.

Samuelson, P. A. (1964). Theoretical Notes on Trade Problems. Review of Economics and Statistics 46(2), 145–154.

Williamson, J. (1985). The Exchange Rate System. In *Policy Analyses in International Economics* Volume 5. Institute of International Economics.

Williamson, J. (1994). *Estimating equilibrium exchange rates.* Peterson Institute.

अनुबंध

अनुबंध सारणी ए 1: चर विवरण और डेटा स्रोत

क्रम सं.	चर	सूचक	विवरण	विवरण
1.	आरईईआर	40 मुद्रा व्यापार आधारित आरईईआर	40-मुद्रा व्यापार-भारित आरईईआर	भारतीय रिज़र्व बैंक
2.	प्रति व्यक्ति सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद	प्रति व्यक्ति सापेक्ष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	घरेलू से विश्व वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, जहां विश्व सकल घरेलू उत्पाद को 22 प्रमुख व्यापार भागीदारों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (स्थिरांक मूल्य) के भारित योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका भार 40 देशों के आरईईआर की गणना में प्रयुक्त व्यापार भार के समान होता है।	ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2024, और लेखकों की गणना
3.	व्यापार की निवल शर्तें	व्यापार की निवल शर्तें	व्यापार की शर्तें वास्तविक वस्तु कीमतों के योग के रूप में परिभाषित की जाती हैं, जो कुल निवल निर्यात में प्रत्येक वस्तु के निवल निर्यात के हिस्से से भारित होती हैं। वास्तविक कीमतों का निर्माण यू.एस. डॉलर में वस्तु मूल्य को विनिर्मित निर्यात के लिए आई.एम.एफ. के इकाई मूल्य सूचकांक से विभाजित करके किया जाता है।	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
4.	सकल घरेलू उत्पाद में निवल विदेशी आस्ति अनुपात	सकल घरेलू उत्पाद में निवल विदेशी परिसंपत्ति अनुपात	निवल विदेशी आस्तियों (विदेशी आस्तियां - विदेशी देनदारियां) का नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात।	आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और लेखकों की गणना।
5.	राजकोषीय घाटा	केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और जीडीपी का अनुपात	सरकारी व्यय और राजस्व से नॉमिनल जीडीपी अनुपात के बीच अंतर।	महालेखा नियंत्रक, एनएसओ और लेखकों की गणना

स्रोत: लेखकों का संकलन।

अनुबंध सारणी ए 2: इकाई मूल परीक्षण के परिणाम

चर	एडीएफ परीक्षण सांख्यिकी		फिलिप्स-पेरोन यूनिट-रूट टेस्ट सांख्यिकी जेड (आरएचओ)	
	एक्स	Δएक्स	एक्स	Δएक्स
एलएन(आरईईआर)$_t$	-1.475	-6.557***	-1.963	-7.865***
एलएन (प्रति व्यक्ति सापेक्ष जीडीपी)$_t$	-2.854*	-10.227***	-2.963**	-10.256***
एलएन(व्यापार की निवल शर्तें)$_t$	-3.259**	-6.886***	-2.715**	-6.711***
उत्पाद में निवल विदेशी संपत्ति अनुपात$_t$	-1.101	-3.595***	-1.224	-7.082***

टिप्पणी: ***, **, और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत: लेखकों का अनुमान।

अनुबंध सारणी ए 3: साहित्य से परिणाम

लेखक	प्रविधि	संतुलन विनिमय दर का प्रकार	अवधि	परिणाम
पटनायक, एस. (1999)	यूनिट रूट परीक्षण, एंगल-ग्रेंजर और जोहान्सन सह-एकीकरण तकनीक	पीपीपी	1970-1999	एडीएफ परीक्षणों के अनुसार भारत के लिए पीपीपी मान्य नहीं है, लेकिन एंगल-ग्रेंजर और जोहानसन तकनीकों के आधार पर इसकी पुष्टि की जाती है। भारत में आरईईआर मिसअलाइनमेंट नॉमिनल विनिमय दर समायोजन और घरेलू मूल्य आंदोलनों के माध्यम से क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत प्रति तिमाही तक ठीक हो जाता है।
जोशी, एच. (2006)	संरचनात्मक वीएआर की व्याख्या तीन मौलिक संरचनात्मक झटकों के साथ की जाती है - वास्तविक मांग, सापेक्ष आपूर्ति और सापेक्ष नॉमिनल आघात	एफईईआर	1996-2005	भारत में वास्तविक विनिमय दर में परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से स्थायी वास्तविक मांग झटकों (पूर्वानुमान त्रुटि भिन्नता का 63.12 प्रतिशत हिस्सा) द्वारा स्पष्ट की जाती है, उसके बाद नॉमिनल (30.57 प्रतिशत) और आपूर्ति (7.29 प्रतिशत) झटकों द्वारा। चूंकि समग्र नॉमिनल आघात वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के पूर्वानुमान त्रुटि भिन्नता का लगभग 30 प्रतिशत ही स्पष्ट करते हैं, इसलिए यह उचित है कि कम या अधिक मूल्यांकन का निर्णय केवल सापेक्ष पीपीपी स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
कुमार (2010)	एआरडीएल	बालसा-सैमुअलसन परिकल्पना	1997-2009	उत्पादकता अंतर, व्यापार की शर्तों और निवल विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि से आरईईआर की सराहना होती है, जबकि उच्च बाहरी खुलेपन से मूल्यह्रास होता है। उत्पादकता अंतर वास्तविक विनिमय दर पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है।
बनर्जी और गोयल (2021)	8 ईएमई पर पैनल डेटा के साथ डीओएलएस और एफएमओएलएस	बीईईआर	1995-2017	संतुलन आरईईआर को प्रभावित करने वाले कारकों में, बालसा उत्पादकता प्रभाव प्रमुख है। चीन, भारत और मैक्सिको में जीएफसी से पहले की अवधि में संतुलन विनिमय दर जीएफसी के बाद की अवधि की तुलना में अधिक थी। वास्तविक विनिमय दर विसंगतियों को एशियाई या वैश्विक वित्तीय संकट जैसी वैश्विक घटनाओं से निकटता से जुड़े एक चक्रीय पैटर्न का पालन करते देखा जाता है।
राउत (2022)	10 ईएमई पर पैनल डेटा के साथ डीओएलएस और एफएमओएलएस	बीईईआर	1994-2020	ईएमई में आरईईआर इसके मूलभूत निर्धारकों जैसे कि बालसा-सैमुअलसन प्रभाव द्वारा संचालित होता है। सापेक्ष प्रति व्यक्ति जीडीपी में सुधार, व्यापार की शर्तें, निवल विदेशी संपत्ति की स्थिति और अमेरिका के मुकाबले ब्याज दर अंतर में वृद्धि आरईईआर को बढ़ाती है, जबकि सरकारी ऋण में वृद्धि इसे कम करती है।

स्रोत: लेखकों द्वारा संकलन।

भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार के बदलते परिदृश्य

*श्वेता कुमारी और संध्या कुरुगंती^*

संचार, औचक तत्वों को कम करने और आर्थिक कारकों की अपेक्षाओं को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। यह आलेख भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार के गतिशील परिदृश्य की पड़ताल करता है, जिसमें हाल ही में हुई दो संकटपूर्ण घटनाएँ- कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में भू-राजनीतिक संघर्ष शामिल हैं। मौद्रिक नीति बैठकों में विशिष्ट विषयों पर सापेक्षिक जोर बदलती आर्थिक स्थितियों के जवाब में भिन्न होता है। एक अनुकूलित शब्दकोश का उपयोग कर प्राप्त मुद्रास्फीति पर संचार का लहजा, बाजार की अपेक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण पाया गया है। यह प्रभाव विशेष रूप से मध्यम अवधि के एकदिवसीय सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों के लिए स्पष्ट है। संचार का प्रभाव भी सख्ती की अवधि के दौरान अधिक देखा गया है।.

भूमिका

मौद्रिक नीति ढांचे में गतिशील बदलावों के इस युग में, केंद्रीय बैंकों के संचार परिदृश्य ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव देखा है। नीतिगत निर्णयों के पूरक में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, इसे अब आधुनिक समय की नीति निर्माण का एक मूलभूत स्तंभ माना जाता है, जो समग्र नीतिगत प्रभाव को बढ़ाता है। जैसा कि ब्लाइंडर (2018) ने सटीक रूप से कहा है, "संचार मौद्रिक नीति के एक सूत्रधार से अपने आप में एक नए नीति साधन में बदल गया है"। यह बदलाव एक अधिक पारदर्शी और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पहले के समय में नीति निर्माण की विशेषता वाले अस्पष्टता से अलग है।

केंद्रीय बैंक संचार तीन प्राथमिक उद्देश्यों अर्थात, सूचित करना, समझाना और प्रभावित करना (बेंचिमोल और अन्य, 2021) द्वारा निर्देशित होता है। निकट और मध्यम अवधि के दृष्टिकोण के साथ-साथ निर्णयों के पीछे नीति उद्देश्यों और तर्क को स्पष्ट रूप से बताकर, केंद्रीय बैंक पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। स्पष्ट संचार नीति निर्माताओं को बदलती परिस्थितियों, चुनौतियों और जोखिमों और नीतिगत इरादों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संदेशों के माध्यम से, केंद्रीय बैंकों का उद्देश्य अनिश्चितता और औचक तत्वों को कम करना, बाजारों को संसूचित रखना और उनकी अपेक्षाओं को स्थिर रखना है। ऐसे उपायों की प्रभावशीलता केंद्रीय बैंकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जो समय के साथ विवेकपूर्ण कार्यों और सूक्ष्म संचार के माध्यम से अर्जित की जाती है। आधुनिक समय के नीति निर्माण में, यह महत्वपूर्ण है कि निर्णयों के साथ-साथ, निर्णय लेने का संदर्भ (अंतर्निहित स्थितियों और अनिश्चितता सहित) भी व्यापक दर्शकों के साथ उनकी समझ के लिए साझा किया जाए (राव 2024; और लेगार्ड 2023)।

आज की गतिशील दुनिया में दर्शकों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को ठीक करने के लिए संचार के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो बदलती परिस्थितियों को अनुकूलित और प्रतिबिंबित कर सके। संकट की स्थिति के दौरान इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, जब पारंपरिक नीति का दायरा सीमित हो सकता है और अपरंपरागत उपाय किए जाते हैं। ऐसे अनिश्चित समय के दौरान नीति उपायों को प्रभावी ढंग से समझाने और सही अपेक्षाएँ निर्धारित करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श, सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

नीति निर्माताओं द्वारा संचार उभरती हुई आर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर संकेत प्रदान करता है और अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक, आर्थिक एजेंटों, वित्तीय बाजारों और व्यापक आर्थिक समुच्चयों को प्रभावित कर सकती है (गोयल और परब 2021; हैनसेन और अन्य, 2019; और ब्लाइंडर और अन्य, 2008)।

संचार को रिज़र्व बैंक के नीति ढांचे में अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है और यह एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करता है।[1] पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अलावा, यह मार्गदर्शन, सीखने और सुनने के तत्वों पर भी जोर देता है (सुब्बाराव 2011)।

^ लेखक, भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग से हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] आरबीआई दो-तरफ़ा संचार का पालन करता है, (i) आरबीआई से जनता, बाज़ारों और मीडिया तक, और (ii) विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, बैंकरों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि के साथ नियमित परामर्श।

भारत में मौद्रिक नीति ढांचा देश के आर्थिक और वित्तीय संवृद्धि की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाने और 2016 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन ने मौद्रिक नीति निर्माण की एक नई व्यवस्था को चिह्नित किया है। इसके साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने और अपेक्षाओं को अनुकूल बनाने के लिए संचार पर जोर और भी बढ़ गया है (दास 2022ए)।

आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीतिगत संचार में विभिन्न प्रकार के उपकरण और संचार चैनल शामिल हैं, जैसे एमपीसी संकल्प और कार्यवृत्त, गवर्नर के बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, भाषण और मीडिया संवाद। ये प्रयास संचार को मजबूत करने में समर्पित प्रयासों का संकेत देते हैं, ताकि परिवारों और वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं का मार्गदर्शन और संचालन किया जा सके और उन्हें व्यापक नीति उद्देश्यों के साथ जोड़ा जा सके। हाल की अवधि में, कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व आघात दिए। 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप घरेलू मुद्रास्फीति में वैश्विक मूल्य दबावों के संचरण के कारण ये और भी बढ़ गए। बढ़ी हुई अनिश्चितताओं और अशांति के ऐसे दौर में जनता और बाजारों को विश्वास दिलाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया, जिससे संचार के एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई। जैसा कि आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बताया, *"मौद्रिक नीति केवल एक विज्ञान नहीं है, जहाँ हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी साधन में बदलाव करते हैं। यह नए साधन बनाने और प्रत्याशित और उभरती चुनौतियों के जवाब में नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें पूर्वज्ञान और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करने की कला भी है, खासकर संकट के समय में। निर्णायकता, समय और संचार प्रभावी मौद्रिक नीति की कुंजी हैं"* (दास 2022ए)।

जैसे-जैसे संचार रणनीति विकसित होती जा रही है, इसकी प्रभावशीलता का आकलन बहुत वांछनीय और अत्यधिक मूल्यवान होता जा रहा है। नीतिगत संचार जटिल है और इसका मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके बावजूद, हाल के समय में इसने गति पकड़ी है, जैसा कि इस क्षेत्र में बढ़ते विश्लेषणात्मक साहित्य से संकेत मिलता है। जबकि अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर शोध भी बढ़ रहा है (अहोकपोसी और अन्य, 2020; और लुआंगराम और वोंगवाचारा 2017)। संचार के कई आयामों की पड़ताल की जा रही है, जिसमें भाषाई जटिलता, प्रत्याशा विश्लेषण और बाजारों और आर्थिक एजेंटों पर इसका प्रभाव शामिल है। यह अध्ययन इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में योगदान देता है, जो भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार पर केंद्रित है, जहां आज तक कुछ विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। अक्टूबर 2016 में एमपीसी की पहली बैठक से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति निर्माण (एफआईटी) की नई व्यवस्था से शुरू होने वाली अवधि पर अध्ययन में विचार किया गया है। समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, दो प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। पहला पहलू इस बात से संबंधित है कि संचार की रूपरेखा कैसे बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ बदल गई है। यह एमपीसी बैठकों में चर्चा किए गए विषयों और समय के साथ उनके प्रचलन के संदर्भ में किया जाता है। दूसरा पहलू एमपीसी प्रस्तावों में व्यक्त प्रत्याशा या स्वर पर केंद्रित है, इसके संवृद्धि पर नज़र रखता है, और वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों की चाल पर इसके प्रभाव का आकलन करता है।

आलेख का बाकी हिस्सा इस प्रकार संरचित है। खंड II प्रासंगिक साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करता है, जो भारतीय संदर्भ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। खंड III में, विषय मॉडलिंग और विश्लेषणात्मक परिणामों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में संचार टोन के परिमाणीकरण की पद्धति और वित्तीय बाजारों पर संचार प्रभाव के विश्लेषण के लिए मॉडलिंग ढांचे के साथ-साथ विश्लेषणात्मक परिणामों पर चर्चा की गई है। खंड V में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. साहित्य की समीक्षा

केंद्रीय बैंक संचार और इसकी विश्लेषणात्मक पड़ताल ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जिसके लिए संभवतः दो प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं, अर्थात, संचार की अपनी क्षमता में एक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में बढ़ती मान्यता और पाठ्य विश्लेषणात्मक विधियों की बढ़ती पहुंच। यह अध्ययन भारतीय संदर्भ में बढ़ते साहित्य में योगदान देता है और दो पहलुओं की पड़ताल करता है, (i) एमपीसी विचार-विमर्श का कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और उनका संवृद्धि, और (ii) बाजार

व्यवहार को प्रभावित करने में संचार की भूमिका। इन पहलुओं से संबंधित मौजूदा अध्ययनों की संक्षिप्त समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई है।

पहले पहलू की कम्प्यूटेशनल भाषाई विधियों का उपयोग करके विस्तार से पड़ताल की गई है, विशेष रूप से विषय मॉडलिंग के माध्यम से। अध्ययनों से पता चलता है कि मौद्रिक नीति विचार-विमर्श मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, आर्थिक संवृद्धि, नीतिगत निर्णय, बाजार की गतिशीलता और वैश्विक संवृद्धि जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित हैं। इन विषयों पर सापेक्ष जोर अलग-अलग होता है और उभरती स्थितियों के जवाब में विकसित होता है (बेंचिमोल और अन्य, 2021; लुआंगाराम और वोंगवाचारा 2017; और हैनसेन और मैकमोहन 2016)।

दूसरा पहलू, जो वित्तीय बाजारों की प्रमुख ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव पर संचार के प्रभाव की पड़ताल करता है, का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। प्रारंभ में, प्राथमिक पाठ्य संचार को संसाधित किया जाता है और मात्रात्मक शब्दों में बदल दिया जाता है, जिसे फिर बाजारों पर प्रभाव की पड़ताल करने के लिए मॉडलिंग ढांचे में एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। शोध निष्कर्ष बताते हैं कि कथात्मक संचार की प्रत्याशा या स्वर बाजारों को निर्देशित करने और उनकी अपेक्षाओं को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (बोसकासे और अन्य, 2023; हैनसेन और अन्य, 2019; ह्यूबर्ट और लैबोंडेंस 2019; और ब्लाइंडर और अन्य, 2008)।

भारतीय संदर्भ में केंद्रीय बैंक संचार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन हाल के समय में जोर पकड़ रहे हैं। माथुर और सेनगुप्ता (2019) ने पाया कि भले ही मौद्रिक नीतिगत संचार भाषाई रूप से जटिल है, लेकिन नीति वक्तव्यों की लंबाई कम हो गई है और समय के साथ पठनीयता में सुधार हुआ है। सामंता और कुमारी (2021) भारत में मौद्रिक नीति पारदर्शिता की डिग्री को मापते हैं और पाते हैं कि पारदर्शिता कई पहलुओं में उत्तरोत्तर बढ़ी है। एफआईटी को अपनाने के बाद इसमें काफी वृद्धि हुई, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में मदद मिली। पात्र. और अन्य (2023) फॉरवर्ड गाइडेंस की भूमिका की पड़ताल करते हैं और पाते हैं कि इसका दीर्घकालिक ब्याज दर अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, हालांकि सख्ती की अवधि के दौरान इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

अहमद और अन्य (2022) ने मौद्रिक नीति पर बाजार की प्रतिक्रिया की विस्तार से जांच की है और पाया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचार, विशेष रूप से अग्रिम मार्गदर्शन तत्व महामारी के दौरान अनिश्चितता को कम करने और वित्तीय बाजारों का मार्गदर्शन करने में सहायक रहा है। जॉन और अन्य (2023) ने यह भी पाया है कि हाल की अवधि में मौद्रिक नीति में आश्चर्य दुर्लभ रहा है और बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर करने में संचार प्रभावी रहा है।

उपर्युक्त अध्ययन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वित्तीय बाजारों पर संचार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं; हालाँकि, वे मात्रात्मक नीति दर निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्तमान अध्ययन में दृष्टिकोण द्वि-मासिक एमपीसी प्रस्तावों में कथात्मक संचार के स्वर को निर्धारित करके और बाद में दर निर्णयों के प्रभाव की पड़ताल करने के अलावा बाजार व्यवहार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करके थोड़ा भिन्न है।

दो अध्ययन जो वर्तमान शोध से निकटता से संबंधित हैं, वे हैं गोयल और परब (2021) और महाम्ब्रे और पाठक (2021)। गोयल और परब (2021) पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर मात्रात्मक और गुणात्मक संचार के प्रभाव की पड़ताल करते हैं। एक प्रत्याशा शब्दकोश का उपयोग करते हुए, वे गुणात्मक संचार को निर्धारित करते हैं और देखते हैं कि एफआईटी को अपनाने और एमपीसी के गठन के बाद अक्टूबर 2016 से इसका प्रभाव बढ़ गया है। महाम्ब्रे और पाठक (2021) ने एमपीसी बैठकों के मिनटों का विश्लेषण किया और मुद्रास्फीति और संवृद्धि विषयों और प्रत्याशाओं पर उनके जोर के संदर्भ में आंतरिक और बाहरी सदस्यों के बीच संचार में अंतर की पहचान की। मिश्रा और आस्था (2023) ने पठनीयता और ध्रुवीयता के संदर्भ में आरबीआई द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) का विश्लेषण किया।

पात्रा (2022 और 2023) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौद्रिक नीतिगत संचार का आरबीआई के भीतर आंतरिक रूप से मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, जिसमें मौद्रिक नीति वक्तव्यों की

लंबाई और पठनीयता, व्यक्तिगत एमपीसी सदस्यों के बयानों का प्रत्याशा विश्लेषण और उनका समग्र तालमेल, और कई अवसरों पर दिए गए भाषणों की मीडिया में प्रतिक्रिया शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय और भारत-विशिष्ट अध्ययनों से प्रेरणा लेते हुए, यह पत्र रिज़र्व बैंक के एमपीसी प्रस्तावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह मौद्रिक नीतिगत संचार परिदृश्य में बदलावों की पड़ताल करता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण संकट घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि कोविड महामारी और यूक्रेन में भू-राजनीतिक संघर्ष। विषय मॉडलिंग और संचार टोन निष्कर्षण करने के लिए उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसका विवरण बाद के खंडों में प्रस्तुत किया गया है।

III. विषय की मॉडलिंग और विषय का उद्भव

भारत में मौद्रिक नीति के क्षेत्र में, एमपीसी बैठकों में विचार-विमर्श मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, आर्थिक गतिविधि, नीतिगत निर्णयों सहित प्रमुख विषयों पर केंद्रित होता है। यह पड़तालना दिलचस्प होगा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन विषयों पर ध्यान कैसे बदला है, और क्या आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के विकसित होने और नए जोखिम कारकों के सामने आने के साथ कोई नया विषय उभरा है। विश्लेषण के लिए द्वि-मासिक एमपीसी प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

अध्ययन अवधि के दौरान विषयों और उनके संबंधित अनुपातों की पहचान करने के लिए टॉपिक मॉडलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। चूँकि पाठ कच्चा और असंरचित है, इसलिए इसे टॉपिक मॉडलिंग से पहले उपयुक्त रूप से पूर्व-संसाधित किया जाना चाहिए। लेटेंट डिरिचलेट आवंटन (एलडीए) एक अप्रशिक्षित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और विश्लेषणात्मक अध्ययनों में टॉपिक मॉडलिंग के लिए अच्छी तरह से स्थापित विधि है (बेंचिमोल और अन्य, 2021; और हैनसेन और मैकमोहन 2016)।

एलडीए की अंतर्निहित अवधारणा सहज है, अर्थात, प्रत्येक दस्तावेज़ विभिन्न विषयों का मिश्रण है और प्रत्येक विषय विभिन्न शब्दों/शब्दों का मिश्रण है। इस पद्धति का लाभ यह है कि मॉडल आउटपुट पूरी तरह से पाठ्य सामग्री और दस्तावेज़ों में शब्द आवृत्ति और सह-घटना पर आधारित है। यह शब्दों के समूह बनाता है, जिन्हें फिर बार-बार आने वाले शब्दों द्वारा दर्शाए गए प्राथमिक विषय के आधार पर एक विशेष विषय के रूप में लेबल किया जाता है।

इसके बाद, विषय की व्यापकता को कई चरणों में इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। यह इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है कि एक ही समय अवधि के दौरान और विभिन्न समय अवधियों में अन्य विषयों की तुलना में किसी विषय पर ध्यान कैसे बदलता है। एमपीसी संकल्पों के अलग-अलग पैराग्राफ को विषय मॉडलिंग के लिए एक दस्तावेज के रूप में माना जाता है।

$$\text{Share of topic i in paragraph j of period t} = TS_{i,j|t} \quad \ldots (1)$$

जिस विषय का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, उसे नीचे दिए गए अनुसार विशिष्ट पैराग्राफ़ के लिए अंतिम विषय के रूप में असाइन किया जाता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक विषय को प्रत्येक दस्तावेज़ में संभावना का एक गैर-शून्य मान मिलता है।

$$FT_{j|t} = i, \text{ for which } TS_{i,j|t} = \max_i (TS_{i,j|t}) \quad \ldots (2)$$

एक ही अंतिम विषय वाले सभी पैराग्राफों की गणना की जाती है तथा एक विशेष अवधि के दौरान उनका अनुपात निम्नानुसार निकाला जाता है:

$$TP_{i|t} = \frac{\sum_{j=1}^{n} FT_{j|t}}{n} * 100 \quad \ldots (3)$$

यह अध्ययन अवधि को तीन उप-अवधियों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक उप-अवधि के लिए अलग-अलग विषय मॉडलिंग की गई थी ताकि विस्तृत विषयों को शामिल किया जा सके, जिनमें से कुछ खो सकते हैं यदि संपूर्ण अध्ययन अवधि का एक साथ उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2020 को कोविड-पूर्व अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि मार्च 2020 से फरवरी 2022 को कोविड और युद्ध-पूर्व अवधि और मार्च 2022 से अगस्त 2024 को युद्ध-पश्चात अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

कई प्रमुख विषय उभरकर सामने आए, जिन्हें समय अवधि के दौरान तुलना की सुविधा के लिए सात मुख्य विषयों में बांटा गया, जैसे मुद्रास्फीति, संवृद्धि, मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार, बाहरी क्षेत्र, चलनिधि और कोविड। शब्द बादलों के संदर्भ में विषयों का एक चित्रण अनुलग्नक I में दिया गया है। एक ही विषय के लिए शब्दों का परस्पर संबंध दिखाता है कि विभिन्न आयामों पर कैसे चर्चा की गई।

विषय मॉडलिंग के परिणाम दर्शाते हैं कि संचार का जोर अलग-अलग था और मौजूदा स्थितियों के अनुसार विकसित

चार्ट 1: विषय का उद्भव

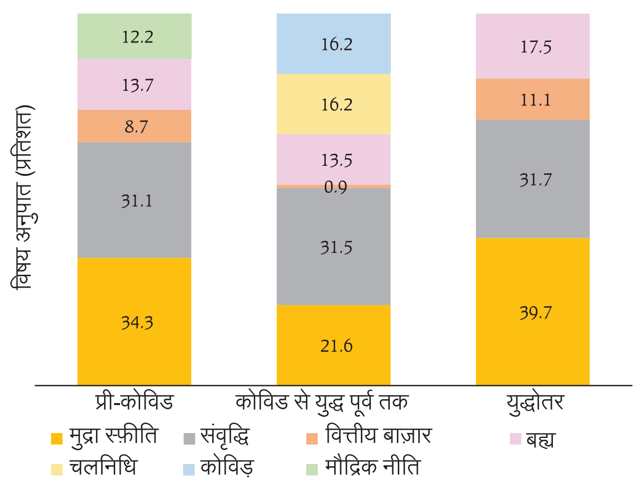

टिप्पणी: कोविड से लेकर युद्ध-पूर्व अवधि के लिए, मौद्रिक नीति और विकास विषयों को एक साथ रखा गया है, क्योंकि उन पर एक साथ चर्चा की गई थी। युद्धोतर अवधि के लिए, मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति विषयों को एक साथ रखा गया है।
स्रोत: आरबीआई: और लेखकों का अनुमान।

हुआ, जैसा कि प्रत्येक अवधि के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष हिस्से में परिलक्षित होता है (जैसा कि समीकरण 1 से 3 में पहले बताई गई कार्यप्रणाली के अनुसार है)। कोविड-पूर्व अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति चर्चा का मुख्य विषय बनी रही, उसके बाद वृद्धि (चार्ट 1) रही।

2020 और 2021 के दौरान कोविड के दौर ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और एमपीसी की चर्चा मुद्रास्फीति की तुलना में वृद्धि पर केंद्रित रही, जैसा कि उच्च विषय अनुपात में परिलक्षित होता है। इस अवधि के दौरान, कोविड से संबंधित चिंताओं और चलनिधि विषयों पर भी ध्यान दिया गया। इस अवधि के दौरान आरबीआई द्वारा पारंपरिक और अपरंपरागत सहित कई चलनिधि बढ़ाने वाले उपाय किए गए, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। हालाँकि, अधिकांश उपायों को ओपन एंडेड होने के बजाय परिभाषित टर्मिनल तिथियों के साथ शुरू किया गया था। इस तरह के विवेकपूर्ण और कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण ने बाजार की उम्मीदों को स्थिर करने और विश्वास बहाल करने में मदद की (दास 2022बी)।

जैसे-जैसे महामारी धीरे-धीरे कम होने लगी और अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ने दुनिया के लिए एक और बड़ी चुनौती पेश की। खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों से उत्पन्न वैश्विक आघात, आपूर्ति व्यवधानों से बढ़ गए, घरेलू अर्थव्यवस्था में संचारित हुए और भारत में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने लगा। स्थानीय कारकों जैसे मौसम के आघात और घरेलू मांग में सुधार ने और दबाव डाला और मुद्रास्फीति बढ़ गई (दास 2023ए)। परिणामी मूल्य दबावों ने बाद की एमपीसी बैठकों में विचार-विमर्श को आकार दिया और मुद्रास्फीति मुख्य विषय के रूप में वापस आ गई। इस अवधि के दौरान बाहरी संबंधों पर ध्यान भी काफी अधिक था। मई 2022 में रेपो दर में स्ख्ती शुरू हुई। नीतिगत रुख भी समायोजन[2] से समायोजन वापस लेने की ओर बदल गया।

हाल के दिनों में, घरेलू मांग और खपत के कारण आर्थिक संवृद्धि में लचीलापन देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई है; हालाँकि, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता के कारण जोखिम अभी भी बना हुआ है। ऐसे परिदृश्य में, मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देना और इसे टिकाऊ आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाना मौद्रिक नीति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे बयान हितधारकों को एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं।

IV. कथात्मक संचार और वित्तीय बाज़ारों पर इसका प्रभाव

वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संचार टोन के परिमाणीकरण और मॉडलिंग ढांचे के दृष्टिकोण का वर्णन नीचे किया गया है, जिसके बाद विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

IV.1 संचार टोन का परिमाणीकरण

मौद्रिक नीति की विशिष्ट प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, संचार प्रत्याशा या स्वर को निकालना एक विशिष्ट कार्य है। पाठ्य नीति दस्तावेजों से संचार स्वर का परिमाणीकरण आम तौर पर एक अनुकूलित शब्दकोश पर आधारित होता है, जिसमें शब्द अर्थगत अभिविन्यास या ध्रुवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शब्दकोश नीतिगत संचार की सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए।

मौद्रिक नीति संदर्भ में प्रासंगिक साहित्य अध्ययनों से प्रेरणा लेते हुए, विशेष रूप से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने

2 अक्टूबर 2024 में रुख न्यूट्रल हो जाएगा।

वाले एपेल और ब्लिक्स ग्रिमाल्डी (2012) ने भारतीय संदर्भ के लिए उपयुक्त एक अनुकूलित शब्दकोश विकसित किया है। चूंकि विभिन्न केंद्रीय बैंकों के लिए संचार शैली और शब्दों का चयन अलग-अलग हो सकता है, इसलिए भारत के लिए एक विशेष शब्दकोश का उपयोग संचार की बारीकियों और गतिशीलता को समझने में उपयोगी हो सकता है। शब्दों का यह शब्दकोश अध्ययन अवधि के लिए एकत्र किए गए एमपीसी संकल्प दस्तावेजों के संग्रह और केंद्रीय बैंक में काम करने की डोमेन समझ पर आधारित है।

गहराई से जाने पर, मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर संचार का स्वर अलग-अलग निकाला जाता है, जो आमतौर पर कुछ हालिया अध्ययनों (बोसकासे और अन्य, 2023; और गार्डनर और अन्य, 2022) को छोड़कर मौजूदा साहित्य में नहीं देखा जाता है। प्रत्याशा को अलग करना महत्वपूर्ण है और यह इस बात की समझ में सुधार कर सकता है कि बाजार मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर संचार को कैसे समझते हैं और अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। अनुकूलित शब्दकोष में मुद्रास्फीति के लिए हॉकिश और डोविश शब्द और संवृद्धि के लिए विस्तारवादी और संकुचनकारी शब्द शामिल हैं।[3] हालांकि, बाद के पैराग्राफ में चर्चा आशावादी/सकारात्मक और निराशावादी/नकारात्मक स्वर के संदर्भ में है। तदनुसार, प्रत्येक एमपीसी संकल्प के लिए, संचार स्वर इस तरह से प्राप्त किया जाता है कि यह मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर शुद्ध आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है

$$\mathrm{MPC_INF_t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{D_{it} - H_{it}}{D_{it} + H_{it}}\right) \quad \ldots (4)$$

$$\mathrm{MPC_GR_t} = \frac{1}{K}\sum_{j=1}^{K}\left(\frac{E_{jt} - C_{jt}}{E_{jt} + C_{jt}}\right) \quad \ldots (5)$$

जहाँ,

D यह i वें वाक्य में डोविस शब्दों की संख्या है अवधि

H यह i वें वाक्य में हॉकिश शब्दों की संख्या है अवधि

E_{jt} वें वाक्य में j वें वाक्य में विस्तारवादी शब्दों की संख्या है अवधि

C jt, t वें वाक्य में j वें वाक्य में संकुचनकारी शब्दों की संख्या है अवधि

i / j को क्रमशः मुद्रास्फीति / संवृद्धि से संबंधित वाक्य के रूप में पहचाना जाता है।

मुद्रास्फीति पर संचार स्वर (MPC_INF_t) शुद्ध आशावाद को इंगित करता है और जब मुद्रास्फीति कम और/या लक्ष्य के भीतर मानी जाती है तो सकारात्मक हो सकती है, और उच्च मुद्रास्फीति परिदृश्य के दौरान नकारात्मक हो सकती है। इसके विपरीत, संवृद्धि पर संचार स्वर (MPC_GR_t) तब सकारात्मक हो सकता है जब आर्थिक संवृद्धि मजबूत माना जाता है, और अन्यथा नकारात्मक हो सकता है। मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर स्वर के औसत का उपयोग करके एक समग्र स्वर ($MPC_OVERALL_t$) भी प्राप्त किया जाता है।

IV.2 प्रविधि – वित्तीय बाज़ारों पर संचार का प्रभाव

बाजार ब्याज दरों में बदलाव नीतिगत रेपो दर में बदलाव, रुख में बदलाव और नीति निर्माताओं द्वारा अन्य संचार के कारण हो सकता है। वित्तीय बाजारों में प्रचलित विभिन्न ब्याज दरों में से, ओआईएस दरों का उपयोग बाजार सहभागियों की नीति अपेक्षाओं को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक साहित्य में व्यापक रूप से किया जाता है। भारतीय संदर्भ में, ओआईएस दर और मौद्रिक नीति के साथ इसके संबंधों पर विस्तृत चर्चा पात्रा और अन्य, 2023 और जॉन और अन्य, 2023 में पाई जा सकती है। तदनुसार, वर्तमान अध्ययन में विभिन्न अवधियों पर माईबोर-आधारित ओआईएस दरों की पड़ताल की गई है।

चूंकि इसका उद्देश्य मौद्रिक नीतिगत संचार और नीति दर निर्णयों की भूमिका का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है, इसलिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि पर संचार स्वर और समग्र स्वर को व्याख्यात्मक चर के रूप में लिया जाता है। मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य, भारित औसत माँग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) भी विश्लेषण में शामिल है क्योंकि यह बाजार दरों को प्रभावित करता है।

घटना अध्ययन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, जहां प्रत्येक मौद्रिक नीति घोषणा दिवस को एक घटना के रूप में माना जाता है, पूर्व और पश्चात नीति के लिए डब्ल्यूएसीआर और ओआईएस दरों का औसत गणना की गई है और विश्लेषण के लिए उनके अंतर

[3] शब्दकोश में मूल रूप में लगभग 600 शब्द हैं (बिना स्टेमिंग के) और टोन को संदर्भगत तरीके से परिभाषित किया गया है। कुछ शब्द जो संवृद्धि के संदर्भ में आशावादी हो सकते हैं, मुद्रास्फीति के मामले में ऋणात्मक हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, विनिर्माण गतिविधि में वृद्धि को विस्तारवादी / सकारात्मक / आशावादी माना जाता है, जबकि मुद्रास्फीति में वृद्धि को आक्रामक / नकारात्मक / निराशावादी प्रत्याशा माना जाता है।

का उपयोग किया गया है। ओआईएस दरों पर नीतिगत संचार के प्रभाव को पर्याप्त रूप से कैप्चर करने के लिए नीति से पहले और बाद के पांच दिनों की अवधि पर विचार किया जाता है।[4] इस तरह के घटना अध्ययन आधारित दृष्टिकोण मौद्रिक नीति के प्रभाव को अन्य घटनाओं से अलग करने के लिए आवश्यक है जो बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं (जॉन और अन्य, 2023; अहमद और अन्य, 2022; और ह्यूबर्ट और लैबोंडेंस, 2019)।

वैकल्पिक विनिर्देशों का उपयोग करते हुए मॉडलिंग ढांचे का वर्णन नीचे किया गया है। छोटे से मध्यम क्षितिज पर डब्ल्यूएसीआर और संचार टोन में परिवर्तन के विभेदक प्रभाव की पड़ताल करने के लिए, विभिन्न अवधियों पर ओआईएस दर का विश्लेषण किया जाता है।

$$\Delta OIS_f_t = \alpha + \beta\, \Delta WACR_t + \varepsilon_t \qquad \ldots (6)$$

$$\Delta OIS_f_t = \alpha + \beta\, \Delta WACR_t + \gamma\, MPC_OVERALL_t + \varepsilon_t \qquad \ldots (7)$$

$$\Delta OIS_f_t = \alpha + \beta\, \Delta WACR_t + \gamma\, MPC_INF_t + \varepsilon_t \qquad \ldots (8)$$

$$\Delta OIS_f_t = \alpha + \beta\, \Delta WACR_t + \lambda\, MPC_GR_t + \varepsilon_t \qquad \ldots (9)$$

$$\Delta OIS_f_t = \alpha + \beta\, \Delta WACR_t + \gamma\, MPC_INF_t + \lambda\, MPC_GR_t + \varepsilon_t \qquad \ldots (10)$$

जहां, Δओआईएस_f_t अवधि t में नीति के पूर्व और पश्चात ओआईएस दर में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें f ओआईएस दर की अवधि (एक माह से एक वर्ष) को दर्शाता है, Δडब्ल्यूएसीआर t डब्ल्यूएसीआर और MPC_INF_t में परिवर्तन को दर्शाता है तथा MPC_GR_t और $MPC_OVERALL_t$ क्रमशः मुद्रास्फीति, संवृद्धि और समग्र स्वर पर संचार स्वर को दर्शाते हैं।

IV.3 विश्लेषणात्मक परिणाम

मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीतिगत संचार स्वर (MPC_INF) समय के साथ विकसित हुआ और अप्रैल 2018 से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान नीति चक्र के साथ अच्छी तरह से प्रतिध्वनित हुआ। यह स्वर आम तौर पर सख्त अवधि के दौरान नकारात्मक था, और सहजता अवधि के दौरान सकारात्मक था। अप्रैल-जून 2022 के दौरान यह तेजी से नकारात्मक हो गया, क्योंकि यूक्रेन संकट सामने आने लगा और मूल्य दबाव तेज हो गया (चार्ट 2)।

संवृद्धि पर संचार स्वर (MPC_GR) मौजूदा और उभरती आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल में चला। 2019 की दूसरी छमाही के दौरान, जब संवृद्धि में मंदी देखी गई, तो संवृद्धि पर दृष्टिकोण नकारात्मक हो गया। इसके अलावा, जब कोविड महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, तो स्वर निराशावादी हो गया। हालांकि, सुधार के साथ स्वर सकारात्मक हो गया और मामूली उतार-चढ़ाव के साथ सकारात्मक क्षेत्र में रहा।

चार्ट 2: संचार और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव

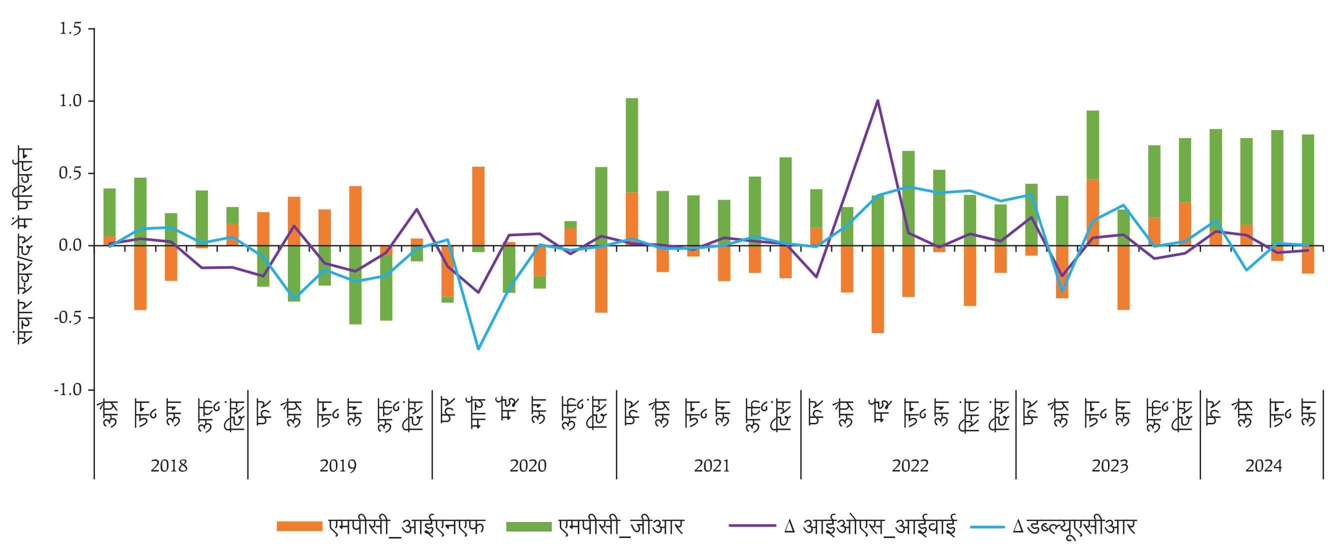

स्रोत: आरबीएल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआई) और लेखकों का अनुमान।

[4] जबकि रेपो दर में मात्रात्मक परिवर्तन बाजार दरों को तत्काल या अगले दिन प्रभावित कर सकता है, आरबीआई द्वारा विवरणात्मक संचार पर लंबी अवधि तक चर्चा की जाती है और इसलिए पांच दिनों का समय लेना उचित माना जाता है।

सारणी 1: सहसंबंध

	∆ओआईएस_1M	∆ओआईएस_2M	∆ओआईएस_3M	∆ओआईएस_6M	∆ओआईएस_9M	∆ओआईएस_1Y
∆डब्ल्यूएसीआर	0.74***	0.66***	0.61***	0.50***	0.49***	0.48***
एमपीसी_आईएनएफ	-0.50***	-0.49***	-0.50***	-0.47***	-0.46***	-0.46***
एमपीसी_जीआर	0.27	0.20	0.19	0.16	0.15	0.16
एमपीसी_समग्र	-0.13	-0.19	-0.20	-0.21	-0.21	-0.20

टिप्पणी: *** 1 प्रतिशत स्तर पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई; एफबीआईएल; तथा लेखकों का अनुमान।

उच्च मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से चिह्नित अवधि के दौरान, रेपो दर में वृद्धि की संभावना के परिणामस्वरूप ओआईएस दरों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे समय के दौरान, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ मुद्रास्फीति पर संचार में नकारात्मक स्वर में परिलक्षित होंगी। इस तरह के आधार पर ओआईएस और मुद्रास्फीति पर संचार स्वर के बीच एक समग्र व्युत्क्रम संबंध हो सकता है।

यह देखा गया है कि ओआईएस दरें रेपो दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुसरण करती हैं। हालांकि, अगर बाजार ने पहले से ही नीति दर में वृद्धि या कमी का अनुमान लगा लिया है, तो ओआईएस दरों में बहुत अधिक बदलाव नहीं हो सकता है, जो अपेक्षाओं के संरेखण को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन उन स्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब रेपो दर में परिवर्तन तेज हो और ढील या सख्ती के दौर की शुरुआत का संकेत हो।[5]

सहसंबंध विश्लेषण उपर्युक्त सैद्धांतिक आधारों की पुष्टि करता है। यह देखा गया है कि डब्ल्यूएसीआर और अल्पकालिक ओआईएस दरें एक उच्च सकारात्मक सहसंबंध साझा करती हैं, जबकि ओआईएस दरों की लंबी अवधि के लिए सहसंबंध कम हो जाता है। ओआईएस दरें मुद्रास्फीति पर संचार टोन के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबंधित हैं, जो पूरे समय सुसंगत है। इसके विपरीत, ओआईएस दर संवृद्धि पर संचार टोन से कमजोर रूप से संबंधित पाई गई है, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है। इसके अलावा, संयुक्त टोन भी किसी भी अवधि में ओआईएस दर में बदलाव के साथ कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं दिखाता है। इससे यह विचार भी मजबूत होता है कि बाजार मुद्रास्फीति और विकास पर संचार पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, और संयुक्त स्वर वास्तविक प्रभाव को प्रकट नहीं कर सकता है (सारणी 1)।

इसके बाद, पहले वर्णित मॉडलिंग ढांचे का उपयोग करके ओआईएस और डब्ल्यूएसीआर तथा संचार स्वर के बीच संबंध का अनुमान लगाया जाता है। चूंकि संवृद्धि स्वर और समग्र स्वर ओआईएस दरों में परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण रूप से सहसंबद्ध नहीं थे, इसलिए प्रतिगमन मॉडल ने भी कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दिया (संक्षिप्तता के लिए मॉडल परिणाम नहीं दिखाए गए हैं)।

मॉडल के विश्लेषणात्मक परिणाम जो मुद्रास्फीति पर डब्ल्यूएसीआर और संचार टोन में परिवर्तन का उपयोग करते हैं (समीकरण 8) सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं । यह देखा गया है कि डब्ल्यूएसीआर में परिवर्तन लघु अवधि ओआईएस दर (1-3

सारणी 2: ओआईएस दरों पर संचार का प्रभाव

	∆ओआईएस_1M	∆ओआईएस_2M	∆ओआईएस_3M	∆ओआईएस_6M	∆ओआईएस_9M	∆ओआईएस_1Y
∆डब्ल्यूएसीआर	0.483***	0.372***	0.328***	0.287**	0.300**	0.302*
एमपीसी_आईएनएफ	-0.091	-0.103	-0.129	-0.178*	-0.194*	-0.211*
स्थिर	-0.026	-0.012	-0.008	-0.002	0.001	0.005
टिप्पणियों	40	40	40	40	40	40
समायोजित आर^2	0.54	0.44	0.39	0.27	0.26	0.25

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व दर्शाते हैं। सामान्य निदान परीक्षणों के अनुसार ओएलएस रिग्रेशन मॉडल के अवशेषों में सीरियल सहसंबंध और हेटेरोसेडैस्टिसिटी नहीं देखी गई (परिणाम संक्षिप्तता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं)। अस्थिरता क्लस्टरिंग आम तौर पर दैनिक वित्तीय बाजार डेटा में देखी जाती है; हालाँकि, वर्तमान अध्ययन में ऐसा कोई क्लस्टरिंग नहीं पाया गया (डेटा को इवेंट स्टडी डिज़ाइन के अनुसार रूपांतरित किया गया है)।
स्रोत: आरबीआई; एफबीआईएल; और लेखकों का अनुमान।

5 उदाहरण के लिए, लंबे विराम के बाद मई 2022 में रेपो दर में 40 बीपीएस की वृद्धि ने ओआईएस दरों में कठोरता ला दी (1-वर्षीय ओआईएस दर में 100 बीपीएस की वृद्धि), जबकि मुद्रास्फीति का रुख काफी हद तक ऋणात्मक हो गया।

सारणी 3: ओआईएस दरों पर संचार का प्रभाव – विभिन्न नीति चक्र

	Δओआईएस_1M	Δओआईएस_2M	Δओआईएस_3M	Δओआईएस_6M	Δओआईएस_9M	Δओआईएस_1Y
Δडब्ल्यूएसीआर	0.384***	0.252**	0.201	0.127	0.154	0.139
MPC_INF_आसान	-0.235	-0.253	-0.246	-0.207	-0.187	-0.225
MPC_INF_कसना	-0.230	-0.301**	-0.385**	-0.625***	-0.639***	-0.684***
एमपीसी_आईएनएफ_न्यूट्रल	-0.026	-0.020	-0.038	-0.054	-0.077	-0.083
स्थिर	-0.024	-0.012	-0.012	-0.020	-0.019	-0.015
टिप्पणियों	40	40	40	40	40	40
समायोजित आर^2	0.54	0.45	0.42	0.36	0.33	0.32

टिप्पणी: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई; एफबीआईएल; और लेखकों का अनुमान।

महीने) में परिवर्तन के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा, जिसका महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ा, हालांकि लंबी अवधि ओआईएस दरों के लिए प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया।[6]

जैसा कि अपेक्षित था, मुद्रास्फीति पर संचार टोन का गुणांक नकारात्मक है। दिलचस्प बात यह है कि संचार प्रभाव लंबी अवधि की दरों के लिए मायने रखता है, जैसा कि सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक मूल्यों में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, उच्च अवधि (6 महीने या उससे अधिक) के लिए उत्तरोत्तर उच्च प्रभाव देखा जाता है। यह दर्शाता है कि नीतिगत संचार मध्यम अवधि की ओआईएस दरों के लिए अधिक मायने रखता है, जो बाजार अपेक्षा आयाम से महत्वपूर्ण हैं।

नीति प्रतिमान में, संचार प्रभाव सममित नहीं हो सकता है, इस अर्थ में कि संचार की बदलती गतिशीलता के आधार पर, विभिन्न नीति चक्रों के दौरान बाजार की अपेक्षाएँ अलग-अलग हो सकती हैं। अप्रैल 2018 से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान मौद्रिक नीतिगत संचार के विभेदक प्रभाव की जाँच करने के लिए उपरोक्त मॉडल का पुनः अनुमान लगाया गया है। मुद्रास्फीति टोन डमी नीति व्यवस्थाओं जैसे कि ढील, सख्ती और यथास्थिति के आधार पर बनाई जाती हैं।

विभिन्न व्यावहारिक परिणाम सामने आए। सबसे पहले, जब मुद्रास्फीति टोन डमी पेश की जाती है, तो डब्ल्यूएसीआर का प्रभाव सारणी 2 में दिखाए गए मॉडल की तुलना में काफी कम हो जाता है । दूसरा, मुद्रास्फीति पर नीतिगत संचार का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है और अन्य चरणों की तुलना में नीति सख्त करने के चरण के दौरान काफी अधिक है। इसके अलावा, सख्त करने के चरण के दौरान संचार 1 महीने (सारणी 3) को छोड़कर ओआईएस के सभी अवधियों के लिए मायने रखता है।

V. निष्कर्ष

2016 में एफआईटी ढांचे को अपनाने और एमपीसी के गठन ने भारत में मौद्रिक नीति निर्माण की एक नई व्यवस्था को चिह्नित किया है। इसके साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने और अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिए संचार पर जोर और भी बढ़ गया है। स्पष्ट संचार नीति निर्माताओं को बदलती परिस्थितियों, जोखिमों और नीतिगत इरादों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। अनिश्चित अवधि के दौरान जनता और बाजारों को विश्वास प्रदान करना चुनौतियों का सामना करता है, जिसके लिए संचार के संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नीति लक्ष्यों का समर्थन करने में संचार प्रभावशीलता का मूल्यांकन एक प्रमुख शोध विषय के रूप में उभरा है, जिसे उभरती हुई एनएलपी तकनीकों द्वारा समर्थित किया गया है।

यह लेख भारत में मौद्रिक नीतिगत संचार पर केंद्रित तेजी से बढ़ते डोमेन में योगदान देता है और दो प्रमुख पहलुओं की पड़ताल करता है- पहला, कैसे संचार की रूपरेखा विकसित आर्थिक स्थितियों के जवाब में बदल गई है और दूसरा, एमपीसी संकल्प दस्तावेजों में व्यक्त प्रत्याशा या स्वर का विकास और वित्तीय बाजारों पर इसका प्रभाव। संचार स्वर एक अनुकूलित शब्दकोश पर आधारित है जो भारत में नीतिगत संचार की बारीकियों को पकड़ सकता है।

[6] केवल डब्ल्यूएसीआर (समीकरण 6) के साथ बेंचमार्क मॉडल के परिणामों ने संकेत दिया कि डब्ल्यूएसीआर का गुणांक समान उत्तरोत्तर घटते पैटर्न का अनुसरण करता है, हालांकि, समायोजित आर-स्क्वायर सारणी 2 में प्रस्तुत संयुक्त मॉडल से कम था (परिणाम संक्षिप्तता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं)।

विश्लेषण से पता चलता है कि एमपीसी विचार-विमर्श में विषयों पर सामग्री और जोर अलग-अलग था, जो अभूतपूर्व संकट प्रकरणों के कारण उभरती स्थितियों और अनिश्चितताओं पर निर्भर करता था। महामारी से पहले की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति चर्चा का मुख्य विषय रही, उसके बाद संवृद्धि रहा। महामारी प्रकरणों के दौरान यह क्रम उलट गया, और चलनिधि और कोविड विषयों पर भी ध्यान दिया गया। 2022 में भू-राजनीतिक संकट और परिणामी मुद्रास्फीति दबावों ने बाद की एमपीसी चर्चाओं को आकार दिया, जिसमें मुद्रास्फीति मुख्य विषय के रूप में लौट आई, जबकि बाहरी संबंधों पर भी ध्यान बढ़ा। मुद्रास्फीति पर संचार स्वर बाजार की अपेक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता पाया गया है, खासकर मध्यम-क्षितिज ओआईएस दरों के लिए। सख्त चरण के दौरान संचार का प्रभाव अधिक देखा गया है।

संदर्भ:

Ahmed, F., Binici, M., and Turunen, J. (2022). Monetary Policy Communication and Financial Markets in India. *IMF Working Paper 209.*

Ahokpossi, C., Isnawangsih, A., Naoaj, M. S. and Yan, T. (2020). The Impact of Monetary Policy Communication in an Emerging Economy: The Case of Indonesia. *IMF Working Paper 109.*

Apel, M., and Blix Grimaldi, M. (2012). The Information Content of Central Bank Minutes. *Sveriges Riksbank Working Paper Series, No. 261.*

Benchimol, J., Kazinnik, S., and Saadon, Y. (2021). Federal Reserve Communication and the COVID-19 Pandemic. *Covid Economics, 79, 218-256.*

Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., and Jansen, D. J. (2008). Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature, 46(4), 910-945.*

Blinder, A. S. (2018). Through a Crystal Ball Darkly: The Future of Monetary Policy Communication. *In AEA Papers and Proceedings (Vol. 108, pp. 567-571).*

Bouscasse, J., Kapp, D., Kedan, D., McGregor, T. and Schumacher, J. (2023). How Words Guide Markets: Measuring Monetary Policy Communication. *The ECB Blog.*

Das, S. (2022a). Monetary Policy and Central Bank Communication. Address by Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India (RBI), Delivered at the National Defence College, Ministry of Defence, Government of India, New Delhi, March 4, 2022.

Das, S. (2022b). Globalisation of Inflation and Conduct of Monetary Policy. Speech by Shri Shaktikanta Das, Governor, RBI, Delivered at the Kautilya Economic Conclave, organised by Institute of Economic Growth in New Delhi, July 9, 2022.

Das, S. (2023a). Central Banking in Uncertain Times: The Indian Experience. Opening Plenary Address by Shri Shaktikanta Das, Governor, RBI, Delivered at the Summer Meetings organised by Central Banking, London, UK, June 13, 2023.

Das, S. (2023b). Art of Monetary Policy Making: The Indian Context. Speech by Shri Shaktikanta Das, Governor, RBI at Delhi School of Economics Diamond Jubilee Distinguished Lecture, September 5, 2023.

Gardner, B., Scotti, C., and Vega, C. (2022). Words Speak as Loudly as Actions: Central Bank Communication and the Response of Equity Prices to Macroeconomic Announcements. *Journal of Econometrics, 231(2), 387-409.*

Goyal, A., and Parab, P. (2021). Central Bank Communications and Professional Forecasts: Evidence from India. *Journal of Emerging Market Finance, 20(3), 308-336.*

Hansen, S., and McMahon, M. (2016). Shocking Language: Understanding the Macroeconomic Effects of Central Bank Communication. *Journal of International Economics, 99, S114-S133.*

Hansen, S., McMahon, M., and Tong, M. (2019). The Long-run Information Effect of Central Bank Communication. *Journal of Monetary Economics, 108, 185-202.*

Hubert, P., and Labondance, F. (2019). Central Bank Tone and the Dispersion of Views within M onetary Policy Committees. *Hal-03403256.*

John, J., Talwar, B.A., Sachdeva, P. and Bhattacharyya, I. (2023). Reading the Market's Mind: Decoding Monetary Policy Expectations from Financial Data. *RBI Bulletin, November 2023.*

Lagarde, C. (2023). Communication and Monetary Policy. Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the Distinguished Speakers Seminar organised by the European Economics and Financial Centre, London, 4 September 2023.

Luangaram, P., and Wongwachara, W. (2017). More Than Words: A Textual Analysis of Monetary Policy Communication. *PIER Discussion Papers, 54, 1-42.*

Mahambare, V., and Pathak, J. (2021). Differential Impact of Diversity in Policy Communication. *Economics Letters, 209, 110142.*

Mathur, A. and Sengupta, R. (2019). Analysing Monetary Policy Statements of the Reserve Bank of India. *Graduate Institute of International and Development Studies Geneva, Working Paper No. 08.*

Misra, S. and Aastha (2023). Monetary Policy Report as a Communication Tool: Evidence from Textual Analysis. *RBI Bulletin, December 2023.*

Patra, M. D. (2022). The Lighter Side of Making Monetary Policy. Speech Delivered by Michael Debabrata Patra, Deputy Governor, RBI in the 9th SBI Banking and Economics Conclave, November 24, 2022.

Patra, M. D. (2023). Statistics Shape the Setting of Monetary Policy. Speech delivered by Michael Debabrata Patra, Deputy Governor, RBI at the Statistics Day Conference, June 30, 2023.

Patra, M. D., Bhattacharyya, I., and John, J. (2023). When Circumspection is the Better Part of Communication. *RBI Bulletin, July 2023.*

Rao, M. R. (2024). Credible Communication - Perspective and Thoughts. Padma Bhushan Professor Emeritus Dr. M.V. Pylee Memorial Lecture delivered by Shri M. Rajeshwar Rao, Deputy Governor, RBI, February 26, 2024.

Report on Currency and Finance (2020-21). Reviewing the Monetary Policy Framework. Reserve Bank of India.

Samanta, G. P., and Kumari, S. (2021). Monetary Policy Transparency and Anchoring of Inflation Expectations in India. *Reserve Bank of India Working Paper No. 3.*

Subbarao, D. (2011). Dilemmas in Central Bank Communication: Some Reflections Based on Recent Experience. Second Business Standard Annual Lecture delivered by Dr. Duvvuri Subbarao, Governor, RBI, at New Delhi on January 7, 2011.

अनुबंध I : युद्धोत्तर काल के दौरान प्रमुख विषय[7]

मुद्रास्फीति: तीन विषय

मुद्रास्फीति: तीन विषय

वित्तीय बाज़ार: एक विषय

बाह्य क्षेत्र: एक विषय

7 वर्ड क्लाउड मूल शब्दों पर आधारित होते हैं, जो किसी शब्द का मूल रूप प्रस्तुत करते हैं।

भारतीय कृषि में कृषि-तकनीक स्टार्टअप और नवोन्मेष

डी. सुगंथी, जोबिन सेबेस्टियन और मोनिका सेठी

यह आलेख भारतीय कृषि-तकनीक परिदृश्य के विकास की पड़ताल करता है, जिसमें तकनीकी अंतर को पाटने के लिए संस्थागत नवोन्मेष के रूप में उभरने की महत्वपूर्ण विकास क्षमता है। उन्नत तकनीकें, एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर तक पहुंच, संस्थापकों की शिक्षा और पिछले अनुभव , फंडिंग की स्थिति और घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों तक पहुंच, किसी स्टार्टअप के लिए अभिनव ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की संभावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एग्री-टेक स्टार्टअप्स के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उन्हें सरकार के फंडिंग समर्थन, अनुसंधान और विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में राज्य के समर्थन से लाभ होता है, जबकि पर्याप्त फंडिंग की कमी, खंडित भूमि जोत और राजस्व मैट्रिक्स में लंबा समय उनके विकास की संभावनाओं में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक हैं।

परिचय

कृषि क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित (जूवीए) में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है और भारत में कुल कार्यबल का 46 प्रतिशत हिस्सा इसमें लगा हुआ है। प्रौद्योगिकी अपनाने से इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं जैसे, कम उत्पादकता, बढ़ती इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरे, मूल्य अस्थिरता, मूल्य श्रृंखला की अक्षमता, खंडित भूमि जोत और संसाधनों की कमी को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है। हाल के वर्षों में, भारत में कृषि-तकनीक स्टार्टअप तकनीकी अंतर को पाटने और कृषि आय बढ़ाने के लिए एक संस्थागत नवोन्मेष के रूप में विकसित हुए हैं। अपने शुरुआती चरण में होने के बावजूद, कृषि-तकनीक स्टार्टअप परितंत्र तंत्र तेजी से बढ़ रहा है और निजी कॉर्पोरेट फंडों को आकर्षित कर रहा है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी उभरती हुई तकनीकों का इस्तेमाल कई स्टार्टअप द्वारा किया जा रहा है (अग्रवाल और अन्य, 2022)। 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया', स्टार्टअप फंड और एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर[1] सहायता पहलों के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किया गया नीतिगत समर्थन, महामारी के दौरान उत्पन्न अवसरों द्वारा और भी अधिक बढ़ गया, कृषि-तकनीक स्टार्टअप के विकास के लिए आवश्यक सुविधाकर्ता रहे हैं।

भारतीय कृषि-तकनीकों का प्रारंभिक ध्यान कृषि क्षेत्र में खंडित आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थता के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल विकसित करने पर था। अब, वे इनपुट और सलाहकार प्लेटफ़ॉर्म, इन-फ़ार्म ट्रेसेबिलिटी समाधान और फ़ार्म प्रबंधन समाधान प्रदाताओं जैसे कई क्षेत्रों में हैं, ताकि बीज से कांटे तक ट्रेसेबिलिटी को सक्षम किया जा सके (अग्रवाल और अन्य, 2022; आध्या और साहू, 2022)। कई स्टार्टअप वर्तमान में 'फ़िजिटल' मॉडल को अपना रहे हैं, जो किसानों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल और भौतिक रणनीति को मिलाता है।

भारत में कृषि-तकनीक पर मौजूदा साहित्य आम तौर पर इस क्षेत्र का अवलोकन, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों की प्रकृति, स्टार्टअप परितंत्र तंत्र में विविधता, स्टार्टअप के विकास के चरणों और राज्य और केंद्र सरकारों (नथालपति और नथालपति, 2021; आध्या और साहू, 2022) द्वारा प्रदान की गई नीतिगत पहलों तक ही सीमित है। हालाँकि, कृषि-तकनीक के अभिनव ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों के विकास और धन उगाहने को प्रेरित करने वाले कारकों पर सीमित ध्यान दिया गया है। साहित्य में इस अंतर को पाटने के लिए, वर्तमान अध्ययन भारत में मौजूदा स्टार्टअप वातावरण का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से इसके चालकों, विविधता, बाधाओं और नीति विकल्पों के संदर्भ में। आलेख में भारत में कृषि-तकनीक स्टार्टअप पर एक प्राथमिक सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करके धन उगाहने, विकास और स्केलेबिलिटी बाधाओं पर कृषि-तकनीक स्टार्टअप के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई है।[2]

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से हैं। लेखक श्री राजीब दास, श्रीमती रेखा मिश्र और संपादकीय समिति के प्रति उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए आभारी हैं। लेखक ऑनलाइन एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के प्रति आभारी हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] इनक्यूबेटर एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत ही प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को स्थापित करने में मदद करने के लिए मेंटरशिप, निवेशकों और अन्य प्रकार की सहायता तक पहुँच प्रदान करता है। एक्सेलेरेटर एक ऐसी पहल है जो विकासशील स्टार्टअप को मेंटरशिप, निवेश पूंजी और अतिरिक्त संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर स्थिर फर्मों के रूप में खुद को स्थापित करने में सहायता मिल सके।

[2] भारत में कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की प्रकृति के संबंध में उनके दृष्टिकोण जानने के लिए एक पूर्व-संरचित प्रश्नावली का उपयोग करते हुए एक ऑनलाइन प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया।

इस आलेख में विश्लेषण से पता चलता है कि उन्नत तकनीकों (एआई या ब्लॉकचेन) का उपयोग, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर तक पहुँच, कृषि के क्षेत्र में संस्थापकों का पिछला अनुभव, संस्थापक की शिक्षा, फंडिंग की स्थिति और घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों तक पहुँच, किसी स्टार्टअप के लिए अभिनव ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की संभावना को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा, फर्म की आयु, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर द्वारा प्रदान किया गया समर्थन, प्रमुख संस्थानों के साथ संस्थापकों का जुड़ाव और उनका अनुभव फंडिंग की संभावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और इसलिए एग्री-टेक स्टार्टअप फंडिंग के चालक के रूप में कार्य करते हैं।

इस आलेख का शेष भाग पाँच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत करता है; खंड III कृषि-तकनीक स्टार्टअप परितंत्र तंत्र का अवलोकन प्रदान करता है; खंड IV ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य अन्वेषण करता है; खंड V में स्टार्टअप के विकास और मापनीयता में बाधाओं पर एक प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से उनके दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है, तथा खंड VI में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. साहित्य की समीक्षा

नवोन्मेष संगठनों की सफलता को सक्षम बनाता है, चाहे उनका आकार और क्षेत्र कुछ भी हो। जोसेफ शम्पेटर[3] द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक विनाश, नवोन्मेष को बाजार अर्थव्यवस्थाओं की प्रेरक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ओपन इनोवेशन थ्योरी (चेसब्रो, 2003) के अनुसार, नई डिजिटल तकनीकों के प्रसार, वैश्वीकरण और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी नवोन्मेष की उन्नति (टैम्बे और अन्य, 2012; रोपर और अन्य, 2017; नोबेन और बकर, 2019) द्वारा अंतर-फर्म सहयोग और ज्ञान प्रसार को सुगम बनाया जाता है।

भारत में कृषि-तकनीक के बीच खुले नवोन्मेष का विचार लोकप्रिय हो रहा है, खासकर खाद्य मूल्य श्रृंखला क्षेत्र में (नथालापति और नथालापति, 2021; नथालापति और अन्य, 2020)। खुले नवोन्मेष ने स्टार्टअप्स और इनपुट कंपनियों, प्रोसेसर, ई-कॉमर्स कंपनियों, शोध संगठनों, विश्वविद्यालयों, इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और राज्य और केंद्र सरकारों के साथ उनकी व्यावसायिक साझेदारी के बीच परस्पर निर्भरता का एक जटिल जाल तैयार किया है। इन तेजी से बढ़ते ज्ञान हस्तांतरण ने कृषि क्षेत्र में कई अत्याधुनिक नवाचारों को जन्म दिया है। बढ़ती नवोन्मेष लागत और संसाधनों की कमी भी स्टार्टअप्स को संयुक्त रूप से ज्ञान का उत्पादन करने के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए बाहर देखने के लिए मजबूर करती है (कोरेक, 2019)।

III. भारत में स्टार्टअप - एक अवलोकन

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, किसी भारतीय स्टार्टअप को कंपनी की आयु, प्रकार, वार्षिक कारोबार, मूल इकाई नवोन्मेष और मापनीयता[4] जैसे मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। डीपीआईआईटी द्वारा लगभग 1.3 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है; उसमें से, कृषि क्षेत्र में लगभग 4.7 प्रतिशत स्टार्टअप शामिल हैं (27 मई, 2024 तक) [चार्ट 1]। कृषि क्षेत्र के भीतर, तकनीकी स्टार्टअप में मुख्य रूप से फसल-तकनीक, उसके बाद पशुधन-तकनीक और अन्य शामिल हैं (चार्ट 2)।

चार्ट 1: व्याख्यानों का प्रमुख उद्योग-वार सूचकांक (प्रतिशत)

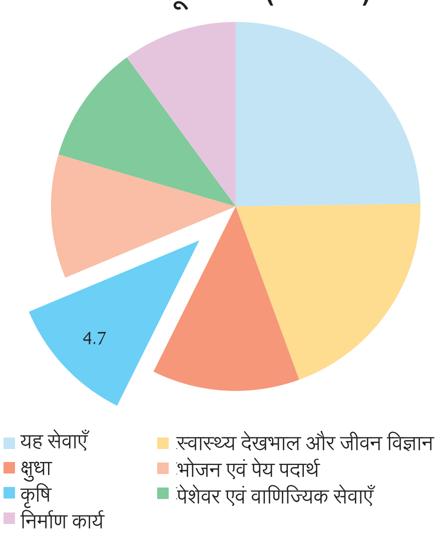

स्रोत: डी.आई.एस.आई.टी.

[3] शुम्पीटर, जे.ए. (1942). पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, हार्पर एंड ब्रदर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका।

[4] https://www.startupindia.gov.in/, भारत का राजपत्र संख्या 111, 19 फरवरी, 2019।

चार्ट 2: कृषि-तकनीकी मूर्तिकला का चित्र (चित्र)

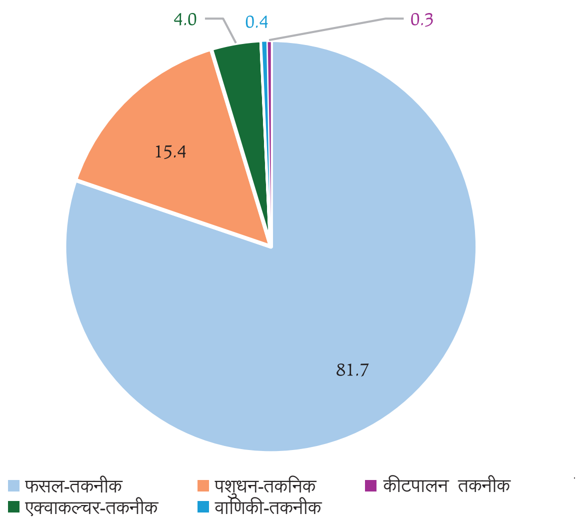

स्रोत: ट्रैक्सन।

2020 में स्थापित एग्री-टेक की संख्या चरम पर थी (चार्ट 3)। स्थान के हिसाब से, छह प्रमुख शहरों में एग्री-टेक स्टार्टअप्स का आधा हिस्सा है (चार्ट 4)।

क. स्टार्टअप जीवनचक्र और वित्तपोषण

स्टार्टअप के जीवनचक्र में पाँच चरण शामिल हैं - विचार, सत्यापन, प्रारंभिक कर्षण, स्केलिंग और निकास विकल्प। विचार चरण वह प्रारंभिक बिंदु है जहाँ विचारों को व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित किया जाता है। सत्यापन चरण कंपनी को व्यापक ग्राहकों के लिए उन्मुख करने पर केंद्रित है। प्रारंभिक कर्षण चरण में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद तैयार करना और कर्षण प्राप्त करने के लिए उसी को परिष्कृत करना शामिल है। बाद के विकास चरण स्केलिंग और निकास चरण हैं जिनमें बड़े बाजार में स्केलिंग, दीर्घकालिक लाभप्रदता उत्पन्न करना और अन्य बाजार खंडों में विस्तार करना शामिल है। निकास चरण के विकल्पों में अधिग्रहित होना या सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियाँ बनना शामिल है।

इसी तरह, स्टार्टअप के फंडिंग चरणों में पाँच चरण शामिल हैं - प्री-सीड/बूटस्ट्रैपिंग, सीड, प्रारंभिक चरण, लेट स्टेज और आरंभिक सार्वजनिक ऑफ़र (आईपीओ) के माध्यम से धन उगाहना [सलामज़ादेह और केसिम, 2015]। बूटस्ट्रैपिंग चरण की विशेषता स्व-वित्तपोषण या परिवार और दोस्तों या एंजेल निवेशकों के माध्यम से होती है। सीड स्टेज में, परिवार और दोस्तों, इनक्यूबेटर, एंजेल निवेशकों और क्राउडफंडिंग से फंडिंग मिलती है। इसके बाद शुरुआती चरण आता है, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट, संस्थागत निवेशक और एक्सेलेरेटर से फंडिंग शामिल होती है। लेट स्टेज में, निजी इक्विटी फर्मों और संस्थागत निवेशकों से फंडिंग प्राप्त की जाती है।

चार्ट 3: स्थापित कृषि-तकनीकी मूर्तियों की संख्या

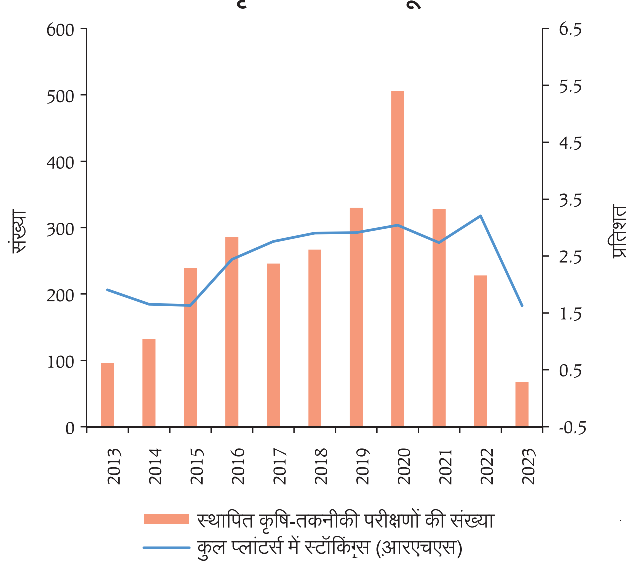

स्रोत: ट्रैक्सन (27 मई 2024 तक का डेटा)।

चार्ट 4: भारत में कृषि-तकनीक स्टार्टअप का शहर-वार वितरण

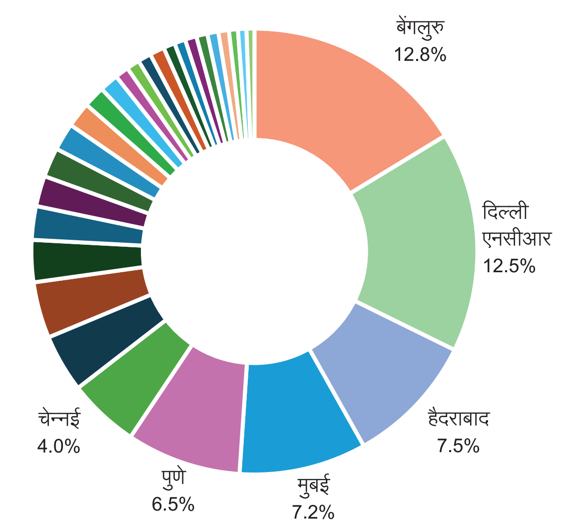

स्रोत: ट्रैकॉन (27 मई, 2024 तक डेटा)।

ख. कृषि-तकनीकों को वैश्विक वित्तपोषण

कृषि-तकनीक के लिए वैश्विक वित्तपोषण 2021 और 2022 में 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंच गया, उसके बाद 2023 में यह तेजी से घटकर 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 5)। वैश्विक कृषि-तकनीक क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी (टिकाऊ इनपुट), नवीन कृषि प्रणाली और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रमुख क्षेत्र हैं (चार्ट 6)। नवीन कृषि समाधानों और टिकाऊ इनपुट में निवेश ने फसल उत्पादकता में वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु आघातों झटकों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है (गोह, 2022)।

इसी तरह, इन-फार्म श्रेणी में, प्रौद्योगिकी उन्नति (रोबोटिक्स, एआई, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स) ने खेतों के स्वचालन, सटीक कृषि, रिमोट सेंसिंग, सलाहकार सेवाओं और खेत प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है। दुनिया भर में कृषि-तकनीक क्षेत्र में ट्रेसेबिलिटी और एग्री-कार्बन उभरते क्षेत्र हैं (गोह, 2022)। फंडिंग के हिसाब से एग्री-टेक कंपनियों की हिस्सेदारी के मामले में, अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा (43.2 प्रतिशत) है, उसके बाद चीन (14.4 प्रतिशत), कनाडा (12 प्रतिशत) और भारत (8.5 प्रतिशत) हैं [चार्ट 7]। इस प्रकार भारतीय कृषि-तकनीक परितंत्र तंत्र ने वैश्विक फंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल किया है।

ग. भारत के कृषि-तकनीक परितंत्र तंत्र का विकास और कृषि-तकनीक को सरकार का समर्थन

भारत के कृषि-तकनीक परितंत्र तंत्र में निवेशकों की रुचि में भारी उछाल देखा गया। 2019 में 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश के साथ; इसके बाद निवेशकों की रुचि कम हुई, जो वैश्विक रुझानों को दर्शाता है (चार्ट 8)। हालाँकि भारतीय कृषि-तकनीक परिदृश्य में केवल एक ही यूनिकॉर्न की पहचान की गई है, लेकिन कृषि-तकनीक सूनिकॉर्न[5] और मिनीकॉर्न[6] की कुल संख्या क्रमशः 19 और 40 होने का अनुमान है।

चार्ट 5: फार्म-टेक के बीच वैश्विक निवेश की प्रवृत्ति

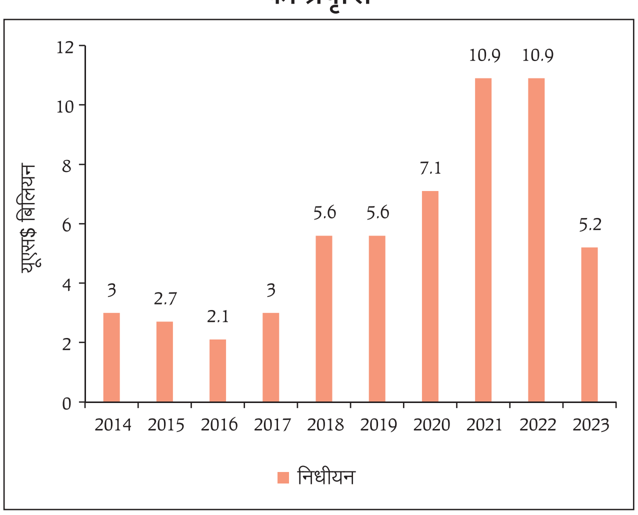

चार्ट 6: प्रमुख कृषि-तकनीक क्षेत्रों में वैश्विक निवेश

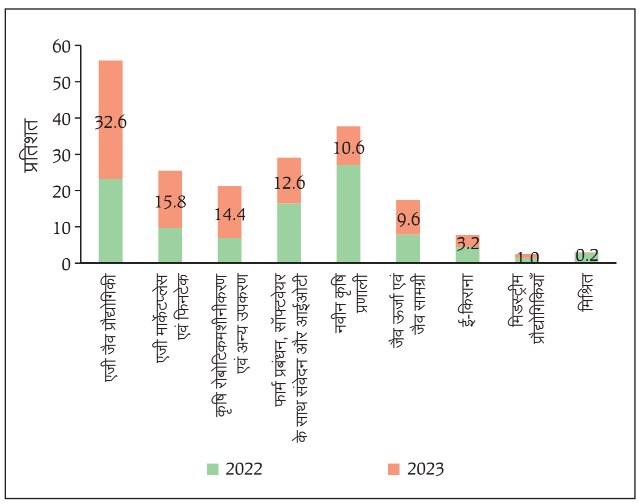

टिप्पणी:
1. एजी का तात्पर्य कृषि से है।
2. कृषि जैव प्रौद्योगिकी फसल और पशु कृषि के लिए ऑन-फार्म इनपुट, जिसमें आनुवंशिकी, माइक्रोबायोम, प्रजनन और पशु स्वास्थ्य शामिल हैं।
3. एजी मार्केटप्लेस और फिनटेक कमोडिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, किसान फिनटेक, ऑनलाइन इनपुट खरीद, उपकरण पट्टे पर देना
4. कृषि रोबोटिक्स, मशीनीकरण और उपकरण: कृषि मशीनरी, स्वचालन, ड्रोन निर्माता, कृषि उपकरण।
5. फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर, सेंसिंग और आईओटी एजी डेटा कैप्चरिंग डिवाइस, निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर, बिग डेटा एनालिटिक्स।
6. नवीन कृषि प्रणालियाँ इनडोर फार्म, जलीय कृषि, कीट और शैवाल उत्पादन
7. जैव ऊर्जा और जैव सामग्री: गैर-खाद्य निष्कर्षण और प्रसंस्करण, फीडस्टॉक प्रौद्योगिकी, कैनबिस फार्मास्यूटिकल्स।
8. खेत से उपभोक्ता तक ई-किराना: किसानों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे वे अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें।
9. मिडस्ट्रीम प्रौद्योगिकियाँ: खाद्य सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी तकनीक, लॉजिस्टिक्स और परिवहन, प्रसंस्करण तकनीक।
10. विविध: अन्य सभी कृषि-खाद्य-संबंधी तकनीक।

स्रोत: एगफंडर.

[5] ऐसे स्टार्टअप जिसमें विकास की संभावना हो तथा यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने की संभावना हो, उसे सूनिकॉर्न कहा जाता है।

[6] मिनीकॉर्न स्टार्टअप ऐसी कंपनियां हैं जिनका मूल्यांकन 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, और वे अभी भी यूनिकॉर्न व्यवसाय बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

चार्ट 7: फंडिंग के आधार पर दुनिया भर में कृषि-तकनीकों का वितरण (प्रतिशत में)

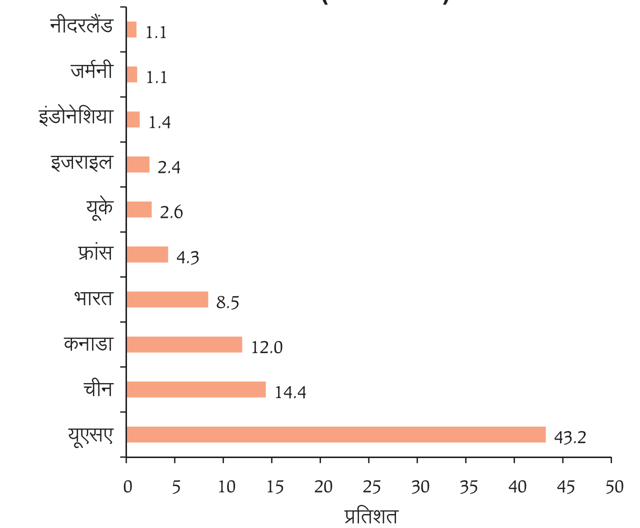

स्रोत: ट्रैकएन (27 मई, 2024 तक का डेटा)।

चार्ट 8: भारतीय कृषि-तकनीक में निवेश के रुझान (27 मई 2024 तक)

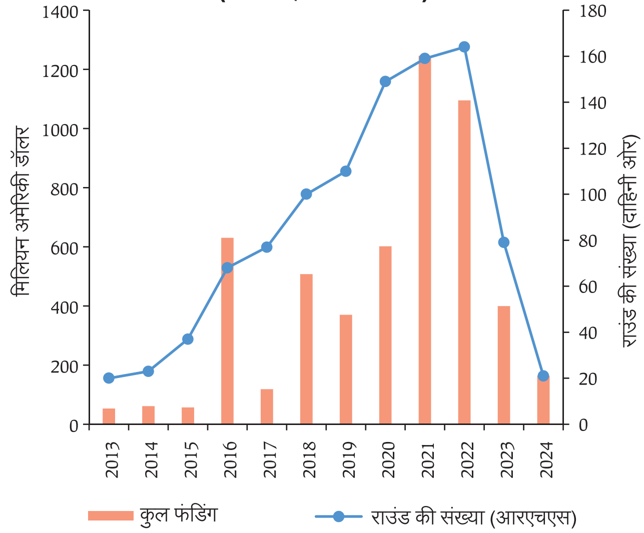

स्रोत: ट्रैकएम

अभिनव कृषि-तकनीक उत्पादों का विकास और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण और किसानों द्वारा अपनाने की गति सरकार के समर्थन से लाभान्वित होती है (न्यूवेल और अन्य, 2021; सरॉय और अन्य, 2023)। केंद्र सरकार विनियामक बाधाओं को कम करने, नवोन्मेष-संचालित बुनियादी ढाँचा सुविधाओं को विकसित करने और उद्यमियों के बीच सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से कृषि-उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देती है (आनंद और राज, 2019)। यह कृषि-स्टैक विकसित करके नवोन्मेष को बढ़ावा देने और कृषि-तकनीक को मुख्यधारा में लाने की सुविधा के लिए एक मजबूत परितंत्र तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[7]

एआई पर राष्ट्रीय रणनीति कृषि को एआई-संचालित समाधानों को लागू करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता देती है (महिंद्रू, 2019)। एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर (एबीआई)[8] की स्थापना, निवेशक नेटवर्क, एक्सेलरेटर और एग्री इंडिया हैकाथॉन9 की स्थापना कृषि-तकनीक परितंत्र तंत्र के विकास का समर्थन करती है। इसके अलावा, कृषि-तकनीक के लिए एक विशेष कोष, कृषि गतिविधियों के लिए ड्रोन के उपयोग में बाधाओं को कम करना और कई राज्य सरकार की पहल (जैसे तेलंगाना का एग्री-हब सैंडबॉक्स, कर्नाटक का ई-सहमती और महाराष्ट्र का महा-एग्री-टेक प्रोजेक्ट) कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

घ. विभिन्न क्षेत्रों में वित्तपोषित कृषि-तकनीक स्टार्टअप

वेंचर कैपिटल फर्म सभी चरणों में स्टार्टअप के लिए उपलब्ध फंडिंग का प्राथमिक स्रोत हैं, साथ ही निजी इक्विटी फर्म और व्यक्तिगत निवेशक जिन्हें एंजल्स के रूप में जाना जाता है (सरोय और अन्य, 2023)।[10] एग्री-टेक के बीच, स्थापित और वित्तपोषित ई-कॉमर्स स्टार्टअप की हिस्सेदारी दूसरों की तुलना में काफी अधिक है (चार्ट 9ए और 9बी)। फिर भी, जिन स्टार्टअप ने फंड नहीं जुटाए हैं उनकी हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है (चार्ट 9सी)। पर्याप्त फंड जुटाने में असमर्थता स्टार्टअप की विफलता के पीछे प्रमुख कारण पाई जाती है (आनंद और राज, 2019)। साथ ही, सभी स्टार्टअप स्केलिंग-अप चरण तक नहीं पहुंचते हैं; जबकि कुछ का अधिग्रहण हो जाता है, अन्य डेडपूल (18 प्रतिशत) में समाप्त हो जाते हैं।

[7] एग्री-स्टैक एक ऐसा परितंत्र तंत्र स्थापित करने की सरकार की पहल है जो डिजिटल कृषि सेवाओं के प्रावधान को सुव्यवस्थित करता है, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट और जिम्मेदार सलाह तक पहुँच। यह डेटाबेस, रजिस्ट्री, डेटा मानकों, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और नीतियों का एक संग्रह भी है।

[8] https://www.manage.gov.in/managecia/ViewAgriResources.aspx

[9] एग्री इंडिया हैकाथॉन एक प्रमुख वर्चुअल कार्यक्रम है जो संवाद को बढ़ावा देने और कृषि नवोन्मेष में तेजी लाने के लिए समर्पित है।

[10] सरोय और अन्य (2023) उन तंत्रों की विस्तृत चर्चा प्रदान करता है जिनके माध्यम से उद्यम पूंजीपति स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और फर्मों के साथ उनके सहयोग के लाभ बताते हैं।

चार्ट 9: कृषि-तकनीक स्टार्टअप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र: स्थापित और वित्तपोषित

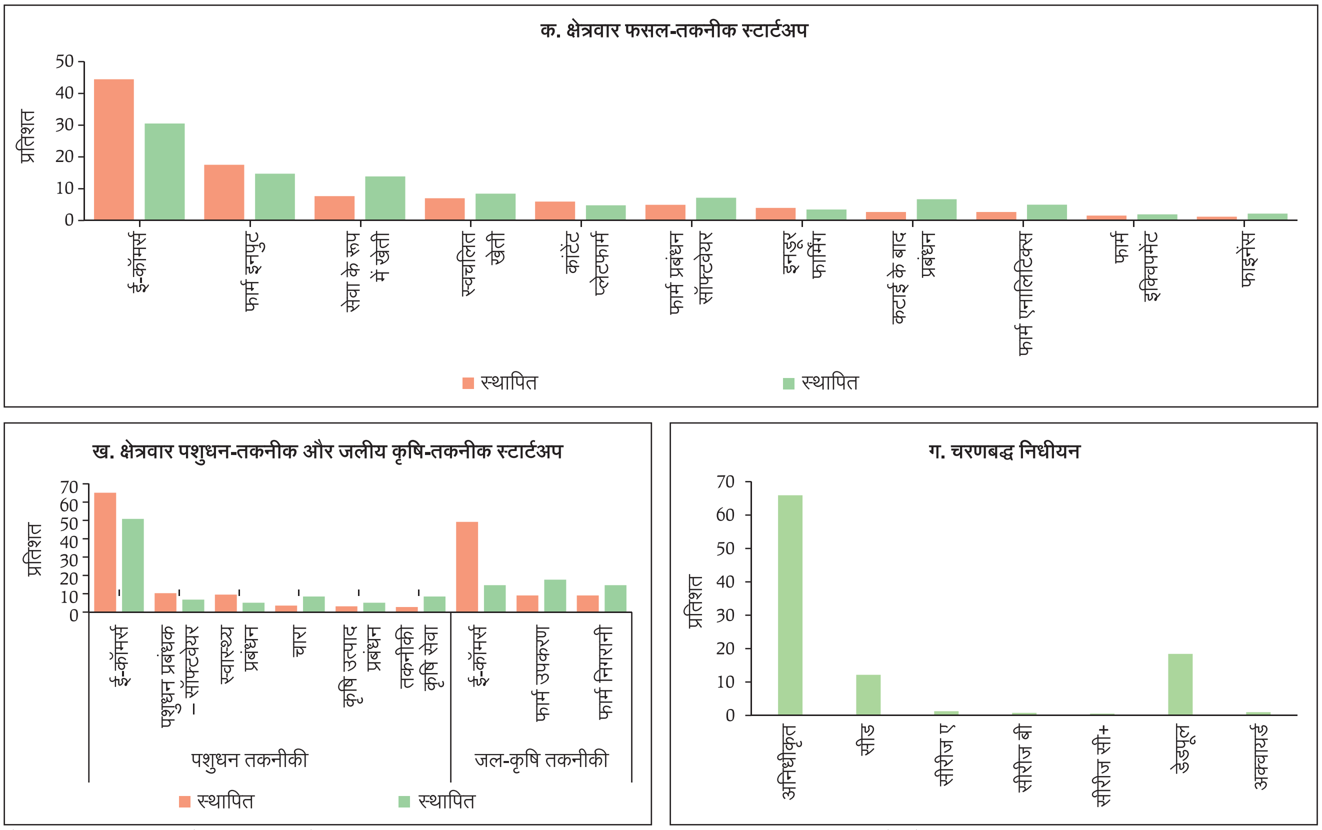

नोट: सीड, सीरीज ए, बी और सी+ क्रमिक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके माध्यम से एग्रीटेक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और अन्य व्यवसाय से निधि जुटाते हैं। डेडपूल निष्क्रिय कृषि-तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: ट्रैक्सन और लेखकों की गणना।

IV. तकनीकों द्वारा खेत पर उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित करने वाले कारक

इस खंड में 780 फर्मों के क्रॉस-सेक्शनल डेटा का उपयोग करके अभिनव उत्पादकता बढ़ाने वाली ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों के विकास के चालकों की पड़ताल की गई है।[11] ऑन-फार्म प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को प्रेरित करने वाले अंतर्निहित कारक ई-कॉमर्स स्टार्टअप को प्रेरित करने वाले कारकों से बहुत अलग हैं। इनमें से कुछ ऐसे अप्राप्य कारक हैं (उद्यमी क्षमताएँ या संस्थापकों के नेटवर्क प्रभाव) जो ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले स्टार्टअप के गैर-यादृच्छिक चयन की ओर ले जाते हैं। इन अप्राप्य कारकों को अन्य अवलोकनीय विशेषताओं, जैसे जुटाए गए फंड या एआई या ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को नियोजित करने के साथ भी सहसंबद्ध किया जा सकता है।

इसलिए, एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग या वित्त पोषण के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हो और इन चरों के माध्यम से फर्मों के ऑन-फार्म प्रौद्योगिकी विकसित करने के निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करे। चर (वेरियेबल), जैसे कि वर्तमान स्टार्टअप के समान क्षेत्र में संस्थापक का पिछला अनुभव और उनका कृषि अनुभव, संभावित उपकरण हैं। हालाँकि, संस्थापक का अनुभव दोनों फर्मों की धन उगाहने की क्षमताओं के साथ-साथ उनके निवेश निर्णयों को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए, ऑन-फार्म प्रौद्योगिकी और धन उगाहने की क्षमताओं को विकसित करने के निर्णय पर अनुभव के प्रभाव को अलग करना आसान नहीं है। अनुमान लॉजिस्टिक प्रतिगमन पर आधारित है और इसलिए फर्मों के ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के निर्णय

[11] डेटा को 26 जून, 2023 को ट्रैक्सन डेटाबेस से एक्सेस किया गया था। हालाँकि शोध में 3,111 कंपनियों को शामिल किया गया है, लेकिन डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक उप-नमूना चुना गया था। परिणामी नमूने में, प्रारंभिक (बीज चरण), मध्य (श्रृंखला ए और बी) और देर से चरण (श्रृंखला सी+) स्टार्टअप की हिस्सेदारी क्रमशः 29 प्रतिशत, 10.4 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थी। कृषि-तकनीक स्टार्टअप के भीतर विभिन्न क्षेत्रों से बिना वित्तपोषित स्टार्टअप की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत थी। यह काफी प्रतिनिधि नमूना है।

के निर्धारकों के परिणामों की व्याख्या कार्य-कारण के बजाय सहसंबंध के रूप में की जानी चाहिए।

फार्म पर प्रौद्योगिकियों के चालकों की पहचान करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करके निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी प्रतिगमन समीकरण का अनुमान लगाया गया:

$$I_i = \begin{cases} 1 \; if \; I_i^* > 0, \\ 0 \; if \; I_i^* \leq 0, \end{cases}$$

$$I_i^* = \alpha + \beta_1 \boldsymbol{X_i} + \beta_2 \boldsymbol{Z_i} + \varepsilon_i$$

जहां *i* फर्म का प्रतिनिधित्व करता है।

जहाँ I_i फर्म i की निवेश की स्थिति के लिए द्विभाजक सूचक को दर्शाता है और I_i^* स्थिति निर्धारित करने के लिए एक सतत अव्यक्त चर है। आश्रित चर बाइनरी है, यदि स्टार्टअप अभिनव उत्पादकता बढ़ाने वाली ऑन-फार्म तकनीकों (गैर-ई-कॉमर्स) में काम करता है तो इसका मान 1 होता है और यदि फर्म आउटपुट और/या इनपुट के लिए एक विशेष ऑनलाइन मार्केटप्लेस है तो इसका मान 0 होता है। $\boldsymbol{X_i}$ संस्थापक-विशिष्ट विशेषताओं जैसे कि उनकी मानव पूंजी (संस्थापकों की पीएचडी डिग्री सहित), प्रमुख संस्थानों (IIT और IIM या विदेश में अध्ययन) के साथ उनका जुड़ाव, और वर्तमान स्टार्टअप संचालन के समान पिछले कार्य अनुभव के एक वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है - कम से कम एक संस्थापक ने वर्तमान स्टार्टअप (ई-कॉमर्स या गैर-ई-कॉमर्स) की प्रकृति के समान फर्म में काम किया है या उसकी स्थापना की है और कृषि क्षेत्र में उनका अनुभव है। ये चर होंजो और अन्य (2022) द्वारा किए गए पिछले अनुभवजन्य कार्य के अनुरूप हैं। $\boldsymbol{Z_i}$ फर्म i की विशेषताओं के एक वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें फर्म की आयु, स्थान और फंडिंग स्थिति के कई संकेतक शामिल हैं। इनमें यह शामिल है कि क्या फर्म को फंड मिला है या नहीं, फंडिंग का चरण और संस्थागत निवेशकों का प्रकार (घरेलू या विदेशी)। फंडिंग चरण श्रेणियां हैं: प्रारंभिक (बीज), मध्य (श्रृंखला ए और बी), और देर से (श्रृंखला सी और ऊपर) कंपनियां। फर्मों द्वारा उन्नत तकनीकों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, एक डमी वैरिएबल बनाया गया था। यदि कंपनियाँ एआई, ब्लॉकचेन, जीनोमिक्स, प्रिसिजन तकनीक, ड्रोन, सेंसर और मौसम पूर्वानुमान के संचालन के लिए सॉफ़्टवेयर जैसी तकनीकों का उपयोग करती हैं, तो इसका मान 1 होता है और अन्यथा 0 होता है। केंद्र या राज्य सरकार के नीति समर्थन का आकलन करने के लिए, एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर तक पहुँच को कैप्चर करने वाले एक अन्य डमी वैरिएबल का उपयोग किया गया और ε_i एक त्रुटि शब्द है।

परिणाम दर्शाते हैं कि उन्नत तकनीकों को अपनाने वाली फर्म की आयु और एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर तक पहुँच, नवीन उत्पादकता बढ़ाने वाली ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की संभावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है (सारणी 1)। संस्थापकों का अनुभव ऑन-फार्म तकनीक में निवेश की संभावना को बढ़ाता है; हालाँकि, कृषि में अनुभव का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। प्रबंधन और इंजीनियरिंग दोनों डिग्री वाले संस्थापक ई-कॉमर्स में निवेश के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जबकि पीएचडी वाले संस्थापक ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की संभावना के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों दोनों से फंडिंग और पहुँच होना ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की संभावना के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही, फंडिंग के शुरुआती चरण में स्टार्टअप या नए स्टार्टअप ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जो विकास की गति को दर्शाता है।

इस तथ्य को देखते हुए कि केवल 34 प्रतिशत एग्री-टेक को ही वित्त पोषित किया जाता है, उन फर्मों और संस्थापकों की विशेषताओं को समझना जो वित्त पोषण को आकर्षित करते हैं, सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि फर्म की आयु, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर द्वारा प्रदान किया गया समर्थन, प्रमुख संस्थानों के साथ संस्थापकों का जुड़ाव और उनका अनुभव वित्त पोषण की संभावना के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है (सारणी A1)।

V. चुनौतियों की पहचान: कृषि-तकनीक स्टार्टअप सर्वेक्षण का परिप्रेक्ष्य

अब तक की प्रगति के बावजूद, भारत में कृषि-तकनीक को अपने परिचालन को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि-तकनीक की स्थिरता सीधे किसानों द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के समानुपाती है। उनके परिचालन को बढ़ाने में आने वाली बाधाओं में विखंडन, मानक डेटा

सारणी 1: कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स द्वारा उत्पादकता बढ़ाने वाली नवीन तकनीकों का विकास करने के चालक

	मॉडल 1		मॉडल 2		मॉडल 3	
	तकनीक आधारित#	सीमांत प्रभाव	तकनीक आधारित	सीमांत प्रभाव	तकनीक आधारित	सीमांत प्रभाव
फर्म की आयु	0.141*** (0.02)	0.028*** (0.004)	0.154*** (0.03)	0.028*** (0.005)	0.135*** (0.02)	0.027*** (0.004)
एआई और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	2.316*** (0.44)	0.364*** (0.039)	2.961*** (0.65)	0.379*** (0.035)	2.213*** (0.45)	0.351*** (0.042)
इनक्यूबेटर/एक्सेलेरेटर तक पहुंच	0.378 (0.29)	0.074 (0.056)	0.714* (0.43)	0.127* (0.072)	0.319 (0.27)	0.062 (0.060)
संस्थापक की शिक्षा: इंजीनियरिंग (बेस)						
एमबीए	-0.406 (0.27)	-0.082* (0.042)	-0.107 (0.33)	-0.020 (0.047)	-0.369 (0.21)	-0.074* (0.055)
एमबीए और इंजीनियरिंग	-0.652*** (0.24)	-0.133*** (0.049)	-0.451 (0.29)	-0.085 (0.054)	-0.658*** (0.25)	-0.134*** (0.049)
विज्ञान	-0.389* (0.20)	-0.079* (0.054)	-0.411 (0.26)	-0.078 (0.048)	-0.346 (0.21)	-0.069 (0.042)
पीएच.डी.	1.500*** (0.57)	0.240*** (0.067)	1.201** (0.60)	0.189** (0.078)	1.466** (0.57)	0.236** (0.069)
संस्थापकों का पिछला अनुभव	0.381** (0.18)	0.076** (0.037)	0.550** (0.22)	0.104** (0.042)	0.341* (0.19)	0.067* (0.038)
संस्थापकों का कृषि अनुभव	0.255 (0.21)	0.041 (0.041)	0.224 (0.26)	0.041 (0.048)	0.326 (0.22)	0.064 (0.042)
वित्त पोषित	0.494** (0.21)	0.098** (0.041)				
वित्तपोषण चरण: वित्तपोषित नहीं (आधार)						
बीज-चरण			0.612** (0.27)	0.112** (0.047)		
मध्य चरण			-0.003 (0.37)	-0.001 (0.071)		
अंतिम चरण			0.057 (0.49)	0.010 (0.092)		
संस्थागत निवेशक का प्रकार						
घरेलू					0.512* (0.29)	0.102* (0.057)
विदेश					0.696*** (0.24)	0.137*** (0.047)
कोविड-19 के दौरान स्थापित	0.401 (0.30)	0.077 (0.057)	0.338 (0.33)	0.061 (0.058)	0.459 (0.310)	0.088 (0.058)
जगह	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
स्थिर	-1.268* (0.73)		-1.244 (0.78)		-1.245* (0.72)	
प्रेक्षणों की संख्या	778		551		751	
आर स्कवेयर	0.159		0.188		0.159	

टिप्पणीयाँ: 1. # तकनीक आधारित कृषि-तकनीक स्टार्टअप में गैर-ई-कॉमर्स फर्म (सेवा के रूप में खेती, खेत प्रबंधन, स्वायत्त खेती, खेत विश्लेषण, कटाई के बाद प्रबंधन, कृषि उपकरण, पशुधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर, पशुधन फार्म इंटेलिजेंस, एंड-टू-एंड पशुधन फार्म स्वचालन, वित्त और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन) शामिल हैं। ई-कॉमर्स स्टार्टअप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आउटपुट और इनपुट की मार्केटिंग करते हैं।

2. ***, **, * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोष्ठक में बताई गई मानक त्रुटियाँ मजबूत मानक त्रुटियाँ हैं।

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

आर्किटेक्चर और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी की कमी के साथ-साथ कम राजस्व, वित्तपोषण संबंधी मुद्दे, विनियामक और कराधान जटिलताएँ, कुशल कार्यबल और ग्राहक जागरूकता की कमी शामिल है (पेरम और कोटेश्वरी, 2018; डेविड और अन्य, 2020; फियोको और अन्य, 2023)। किसान तेजी से नवोन्मेष के लिए अधिक खुले हो रहे हैं, हालांकि उनके बीच अपनाने की गति धीमी है (फियोको और अन्य, 2023)। जबकि पिछले कुछ वर्षों में कृषि-तकनीक को उच्च निजी इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है

(भारत सरकार, 2023), तकनीकी स्टार्टअप के लिए फंडिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

इन पहलुओं को और अधिक जानने के लिए, भारत में कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के दृष्टिकोण जानने के लिए एक ऑनलाइन प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। कृषि-तकनीकों के सामने आने वाली चुनौतियों, किसानों के साथ काम करने में आने वाली कठिनाइयों और मौजूदा तथा आवश्यक नीतिगत समर्थन पर दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाली प्रश्नावली लगभग 300 कृषि-तकनीकों को ऑनलाइन भेजी गई।[12] 40 कृषि-तकनीकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सारांश नीचे दिया गया है।

उत्तरदाताओं का संक्षिप्त अवलोकन

लगभग 75 प्रतिशत उत्तरदाता फसल-तकनीक में काम कर रहे थे, उसके बाद पशुधन-तकनीक, मत्स्य पालन और अन्य जल-तकनीक (चार्ट 10 ए) थे। इसके अलावा, उनमें से लगभग 80 प्रतिशत सीधे किसानों के साथ काम कर रहे थे और अन्य 10 प्रतिशत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से काम कर रहे थे (चार्ट 10 बी)। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार के संबंध में, लगभग 32 प्रतिशत सटीक कृषि सेवाएँ प्रदान कर रहे थे, उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, कृषि सलाह और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (चार्ट 10 सी) थे। क्लाउड शब्द इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह क्षेत्र आशाजनक और गतिशील है, हालाँकि अभी भी नवजात है और इसे समर्थन की आवश्यकता है (चार्ट 10 डी)।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सर्वेक्षण के अनुसार, किसानों के साथ काम करते समय भारतीय कृषि-तकनीकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में किसानों की छोटी जोत और उनके साथ विश्वास बनाने में कठिनाइयाँ शामिल हैं (चार्ट 11)। खंडित भूमि जोत, तकनीक के

चार्ट 10: कृषि-तकनीक उत्तरदाता स्टार्टअप

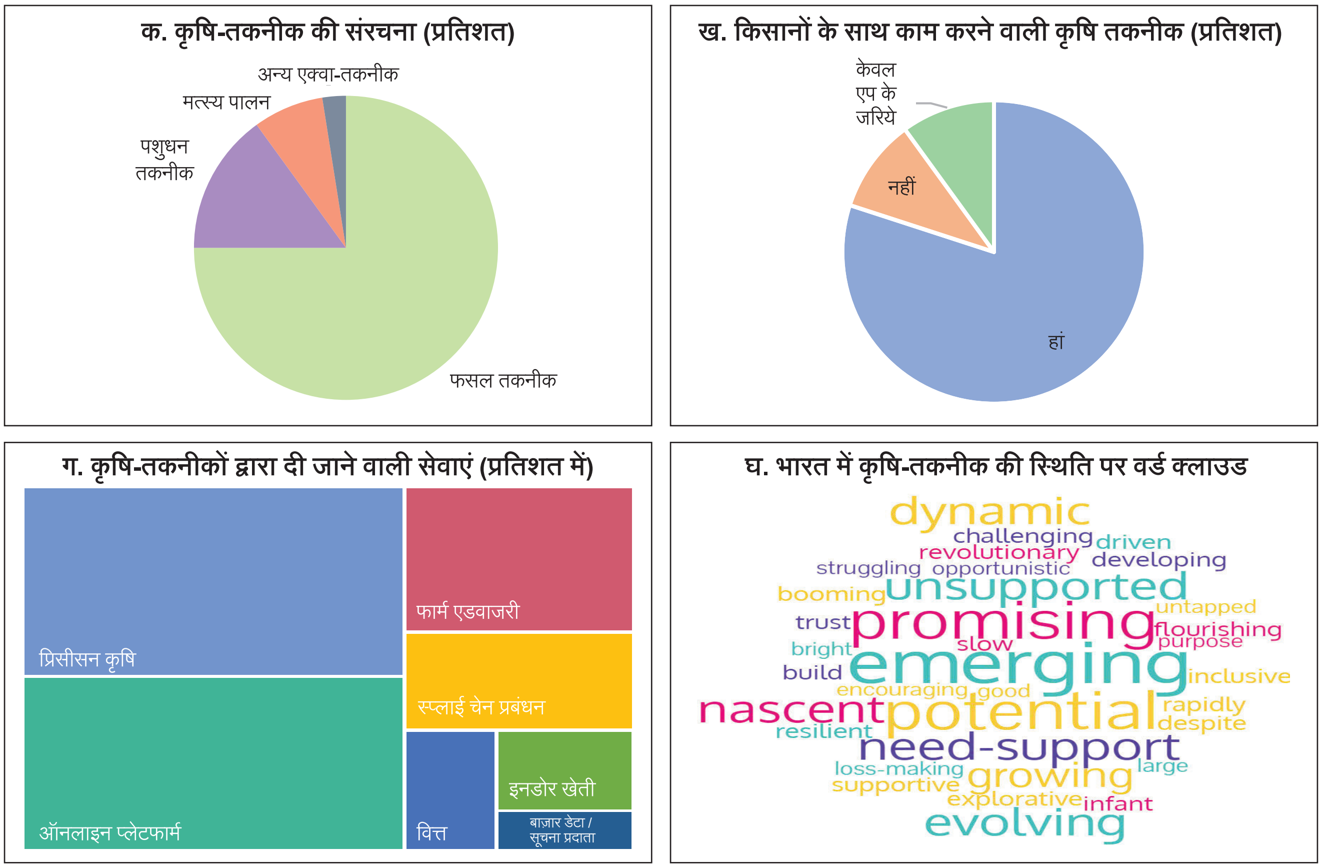

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण और लेखकों की गणना।

[12] ट्रैक्सन डेटा का उपयोग करके, जुटाए गए फंड की रैंकिंग के आधार पर कंपनियों का चयन किया गया और संस्थापकों या सामान्य ईमेल आईडी पर उनके साथ एक प्रश्नावली साझा की गई। क्षेत्र द्वारा जुटाए गए कुल फंड के आधार पर, सैंपल एग्री-टेक स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है, इसलिए, सैंपल प्रतिनिधि है।

चार्ट 11: किसानों के साथ काम करते समय कृषि-तकनीकों के लिए चुनौतियाँ

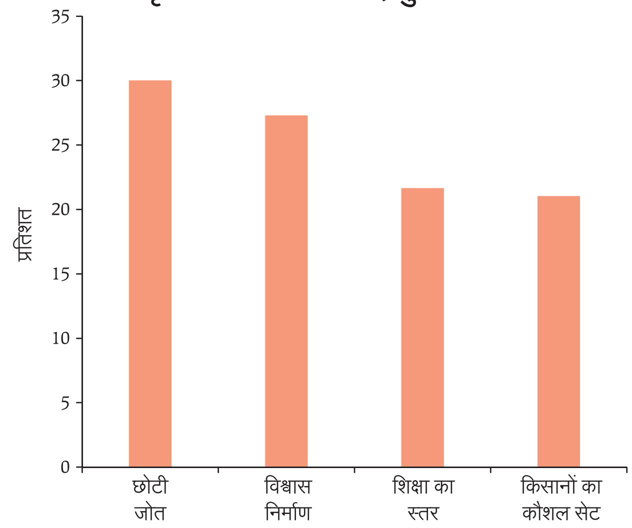

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण: और लेखकों की गणना।

बारे में जागरूकता की कमी और तकनीक की लागत को भारत में किसानों द्वारा तकनीक अपनाने में प्रमुख बाधाओं के रूप में देखा गया (चार्ट 12)। यह फियोको एट अल। (2023) के निष्कर्षों के अनुरूप है कि विकसित देशों में भी, केवल बड़े खेतों के बीच ही प्रौद्योगिकी को अपनाना अधिक था। इसके अलावा, आलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मौसम और जलवायु अनिश्चितताओं के कारण तकनीक की उच्च एकमुश्त लागत और वापसी की अनिश्चित दर तकनीक को अपनाने को हतोत्साहित करती है। उसी को ठीक करने के लिए, कृषि-तकनीकें एकमुश्त खरीद के बजाय फ्लैट-शुल्क वार्षिक नवीनीकरण और पट्टे या किराए पर देने को प्रोत्साहित कर रही हैं।

लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि किसान नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हैं। सस्ते स्मार्टफोन, मजबूत सार्वजनिक कृषि विस्तार प्रणाली और सस्ती कीमतों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करती है (चार्ट 13)।[13] कृषि-तकनीकें समय पर सूचना तक पहुँच को आसान बनाने, स्थानीय ज्ञान के साथ मिश्रित नवीन तकनीकों के प्रावधान और किसानों के लिए अनुरूप अनुशंसाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक कृषि विस्तार प्रणाली का लाभ उठा सकती हैं (फियोको और अन्य, 2023)।

सर्वेक्षण के अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने परिचालन को बढ़ाने में प्रमुख चुनौतियों के रूप में फंड/निवेश तक पहुंच, खंडित कृषि प्रणाली और राजस्व मैट्रिक्स के लिए लंबा समय बताया

चार्ट 12: किसानों के लिए तकनीक अपनाने में बाधाएं

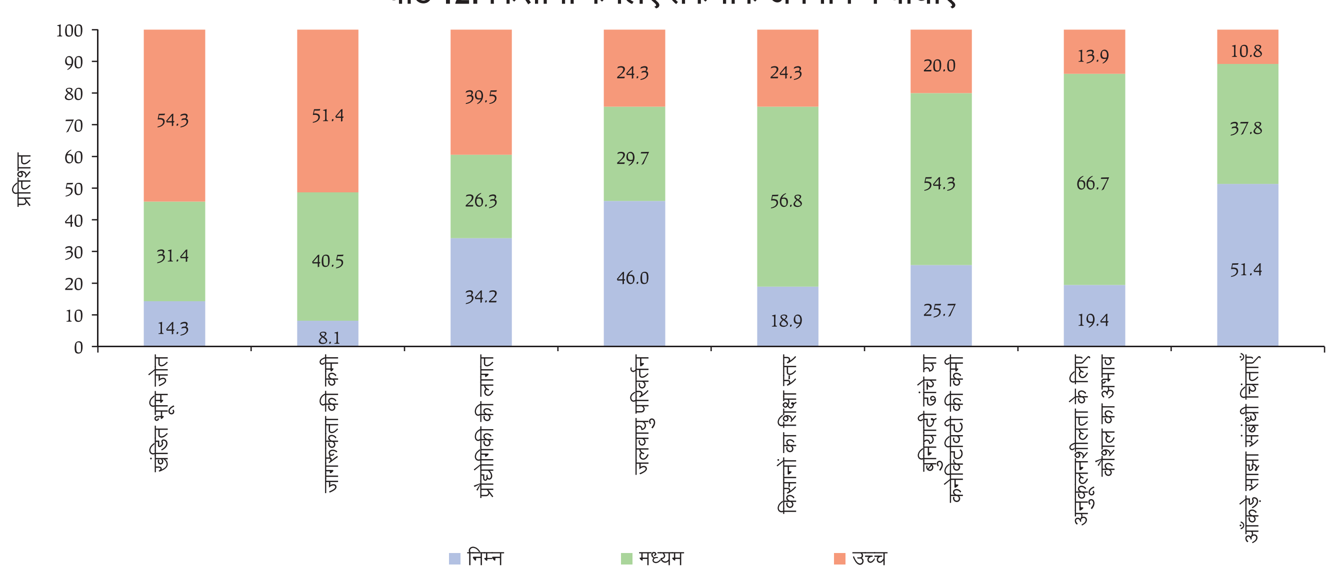

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण और लेखकों की गणना।

[13] यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत में डेटा शुल्क सबसे कम है।

चार्ट 13: किसानों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारक

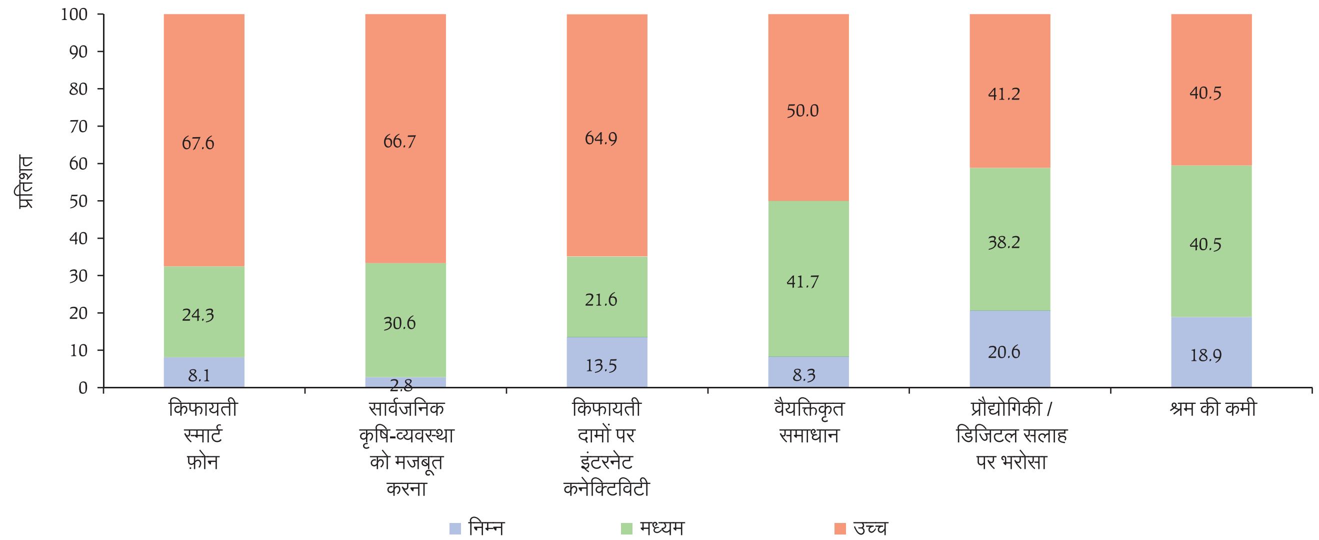

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण: और लेखकों की गणना।

(चार्ट 14)। कुछ उत्तरदाताओं के अनुसार, मूल्यांकन (निवेशकों और निदेशकों द्वारा सहमत) और निवेशकों से धन उगाहने के बीच अनुपालन के लिए एक महीने की प्रतीक्षा अवधि भी एक चुनौती थी।

मौजूदा नीति संरचना से समर्थन के संदर्भ में, लगभग तीन-पांचवें उत्तरदाताओं ने इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेटर योजना को अत्यधिक या मध्यम रूप से सहायक के रूप में पहचाना, उसके बाद स्टार्टअप फंडिंग योजनाएं (चार्ट 15)। इसके अलावा, उन्होंने शुरुआती और स्केलिंग-अप चरण में वित्तीय सहायता, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और कर प्रोत्साहन और रियायतों के रूप में राज्य समर्थन को अपने संचालन को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक नीति समर्थन के रूप में माना (चार्ट 16)। निष्कर्ष पहले के साक्ष्य के अनुरूप हैं कि स्टार्टअप के शुरुआती चरणों के दौरान सरकारी समर्थन उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता

चार्ट 14: कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के लिए परिचालन बढ़ाने में चुनौतियां

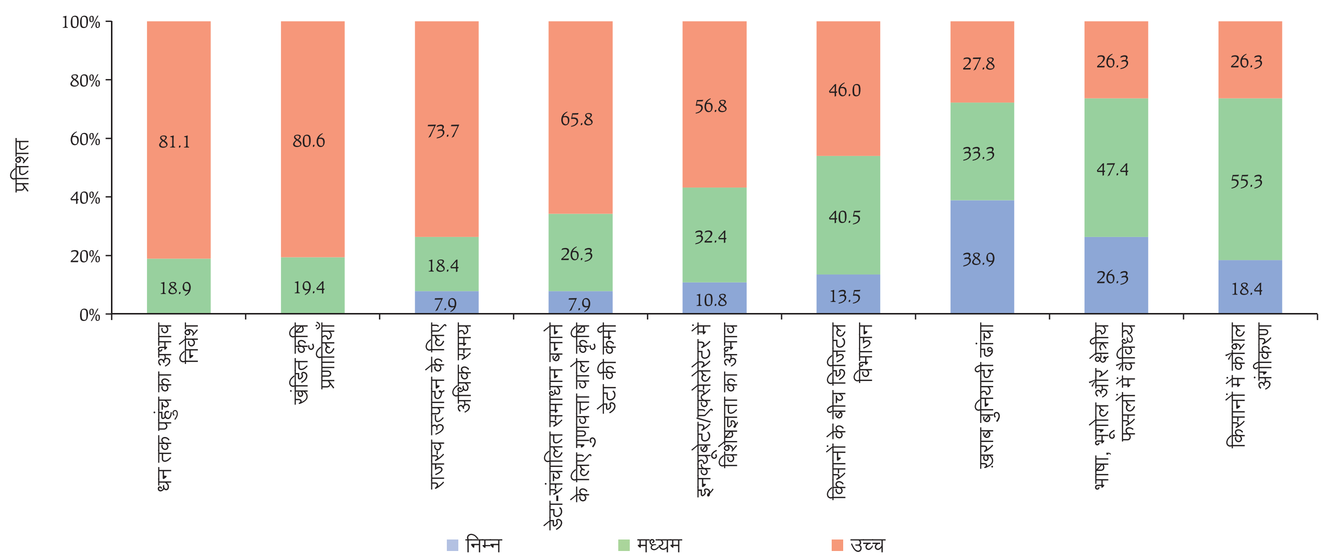

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण और लेखकों की गणना।

चार्ट 15: कृषि-स्टार्टअप के लिए मौजूदा नीति समर्थन की प्रासंगिकता

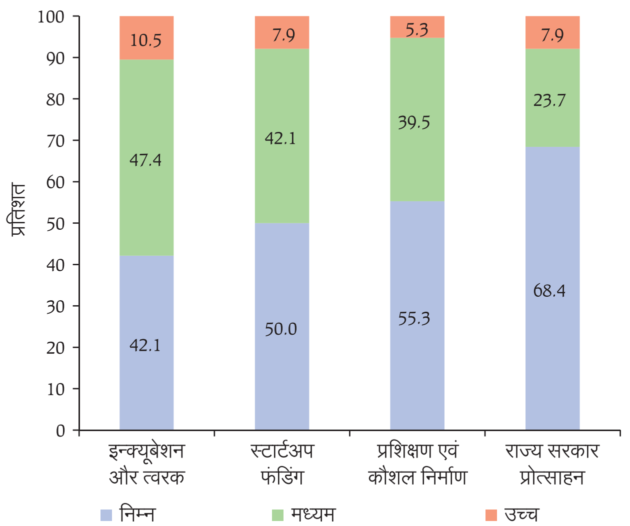

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण: और लेखकों की गणना।

चार्ट 16: कृषि-स्टार्टअप के लिए वांछित नीतिगत समर्थन

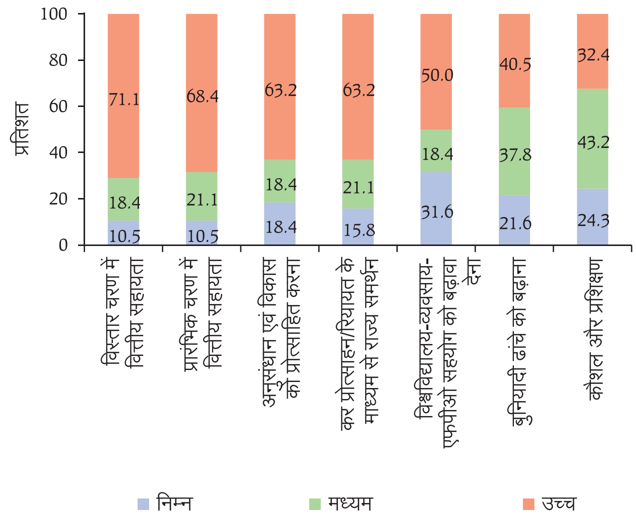

स्रोत: एग्री-टेक स्टार्टअप सर्वेक्षण; और लेखकों की गणना।

को बढ़ाने, उन्हें विस्तार के लिए तैयार करने और भविष्य में निवेशक पूंजी को लुभाने के लिए महत्वपूर्ण है (भूषण और कुमार, 2020)।

VI. निष्कर्ष

भारत में कृषि-तकनीक परितंत्र तंत्र अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह पारंपरिक कृषि बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण गतिशीलता और क्षमता दिखाता है। कोविड-19 अवधि के दौरान भारतीय कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स ने फंडिंग में तेज़ी देखी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई। ज़्यादातर कृषि-तकनीकें बिना फ़ंड के हैं, और फंड जुटाने वाले मध्यम से लेकर अंतिम चरण के स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी शुरुआती चरण की तुलना में कम है, जो उनके विस्तार और स्केलिंग को रोकती है। साथ ही, कृषि-तकनीक का फ़ोकस इनोवेटिव डिसइंटरमीडिएशन बिज़नेस मॉडल से उत्पादकता में सुधार करने वाले बिज़नेस मॉडल जैसे ट्रेसेबिलिटी, एग्री-कार्बन हार्वेस्टिंग और वैज्ञानिक भंडारण समाधानों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव है, जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता है। किसानों से सीधे जुड़ने वाले कृषि-तकनीक की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आँकड़ा विश्लेषण से पता चलता है कि उन्नत तकनीकों (एआई या ब्लॉकचेन) को अपनाना, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर तक पहुँच, संस्थापकों का पिछला अनुभव और शिक्षा, फंडिंग की स्थिति और घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों तक पहुँच, स्टार्टअप के लिए अभिनव ऑन-फार्म तकनीक विकसित करने की अधिक संभावना से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, फर्म की उम्र, एक्सेलरेटर और इनक्यूबेटर द्वारा दिए गए समर्थन, प्रमुख संस्थानों के साथ संस्थापकों के जुड़ाव और उनके अनुभव के साथ धन उगाहने की संभावना बढ़ जाती है।

एग्री-टेक स्टार्टअप्स के सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एग्री-टेक को सरकार के वित्त पोषण समर्थन, अनुसंधान और विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में राज्य के समर्थन से लाभ होता है, जबकि फंड/निवेश तक पहुंच की कमी, खंडित कृषि प्रणाली और लाभ प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि की अवधि को बाधाओं के रूप में देखा जाता है। सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों के आधार पर वास्तविक समय के अनुरूप समाधान प्रदान करने और प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए विशिष्ट और कम लाभ वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एग्री-टेक को प्रोत्साहित करना एक अधिक टिकाऊ और उत्पादक कृषि क्षेत्र की नींव रख सकता है।

संदर्भ:

Adhya, P. S., and Sahoo, S. K. (2022). The Evolving Scenario of Climate Finance in India–A Scoping Study. *Gradiva Review Journal*, *8*(12), 634-646.

Agarwal, R., Gupta, H., and Kholi, A. (2022). What's Next for Indian Agri-Tech? Emerging Opportunities and The Way Forward for India's Agricultural Technology Sector, FSG, Reimagining Social Change.

Anand, A., and Raj, S. (2019). Agritech Startup: The Ray of Hope in Indian Agriculture. *Discussion Paper 10*, MANAGE Centre for Agricultural Extension Innovation, Reforms and Agripreneurship, MANAGE, Hyderabad, India.

Bhooshan, N., and Kumar, A. (2020). How did Agri-Start-Ups Fare during the COVID-19 Pandemic? Challenges and the Way Forward. *Economic and Political Weekly*, Vol. *55*(50), 13-17.

Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business Press.

David, D., Gopalan, S., and Ramachandran, S. (2020). The Startup Environment and Funding Activity in India. *ADBI Working Paper 1145*, Asian Development Bank Institute.

Fiocco, D., Ganesan, V., Lozano, M., and Sharifi, H. (2023). Agtech: Breaking Down the Farmer Adoption Dilemma. Mckinsey And Company.

Honjo, Y., Kwak, C., and Uchida, H. (2022). Initial Funding and Founders' Human Capital: An Empirical Analysis Using Multiple Surveys for Start-Up Firms. *Japan And the World Economy*, *63* (2022) 101145.

Goh, L. (2022). How Agritech Is Transforming Traditional Agriculture in Emerging Markets. In H. Kharas, J.W. Aurther and I. Ohno (Eds.), Breakthrough: The Promise of Frontier Technologies for Sustainable Development. Brookings, Washington D.C.

Korreck, S. (2019). The Indian Startup Ecosystem: Drivers, Challenges and Pillars of Support. *ORF Occasional Paper, 210.*

Knoben, J., and Bakker, R. M. (2019). The Guppy and The Whale: Relational Pluralism and Start-Ups' Expropriation Dilemma in Partnership Formation. *Journal Of Business Venturing*, *34*(1), 103-121.

Mahindru, T. (2019). Role Of Digital and AI Technologies In Indian Agriculture: Potential and Way Forward. *Niti Aayog, Government of India.*

GoI. (2023). *Economic Survey 2022-23.* Chapter 12: Physical and Digital Infrastructure: Lifting Potential Growth.

Newell, R., Newman, L., and Mendly-Zambo, Z. (2021). The Role of Incubators and Accelerators In The Fourth Agricultural Revolution: A Case Study Of Canada. *Agriculture*, *11*(11), 1066.

Nuthalapati, C. S., and Nuthalapati, C. (2021). Has Open Innovation Taken Root in India? Evidence From Startups Working in Food Value Chains. *Circular Economy and Sustainability*, *1*(4), 1207-1230.

Nuthalapati, C. S., Srinivas, K., Pandey, N., and Sharma, R. (2020). Startups With Open Innovation: Accelerating Technological Change and Food Value Chain Flows in India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, *75*(4), 415-437.

Peram, P., and Koteswari, B. (2018). A Study on Challenges Faced by Start-Ups In India. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 3, Issue 7, July – 2018.

Roper, S., Love, J. H., and Bonner, K. (2017). Firms' Knowledge Search and Local Knowledge Externalities in Innovation Performance. *Research Policy*, *46*(1), 43-56.

Salamzadeh, A., and Kawamorita Kesim, H. (2015). Startup Companies: Life Cycle and Challenges. In *4th International Conference on Employment, Education and Entrepreneurship (EEE), Belgrade, Serbia.*

Saroy, R., Khobragade, A., Misra, R., Awasthy, S., and Dhal, S. (2023). What Drives Startup Fundraising in India? *RBI Bulletin.*

Tambe, P., Hitt, L. M., and Brynjolfsson, E. (2012). The Extroverted Firm: How External Information Practices Affect Innovation and Productivity. *Management Science*, *58*(5), 843-859.

अनुबंध

सारणी ए1: कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के बीच फंडिंग के चालक

	मॉडल 1	सीमांत प्रभाव	मॉडल 2	सीमांत प्रभाव
फर्म की आयु	0.033*** (0.015)	0.005** (0.002)	0.031* (0.016)	0.005* (0.002)
कोविड-19 के दौरान स्थापित	1.349*** (0.330)	0.237*** (0.057)	1.323*** (0.351)	0.223*** (0.059)
इनक्यूबेटर/एक्सेलेरेटर तक पहुंच	4.747*** (0.602)	0.645*** (0.025)	4.878*** (0.588)	0.639*** (0.025)
प्रमुख संस्थान के संस्थापक	1.026*** (0.196)	0.174*** (0.033)	1.001*** (0.204)	0.163*** (0.033)
संस्थापक का पिछला अनुभव	0.578*** (0.231)	0.090*** (0.035)	0.513** (0.239)	0.077** (0.035)
संस्थापक का कृषि अनुभव	-0.356 (0.237)	-0.055 0.036	-0.339 (0.254)	-0.051 (0.037)
जगह	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
कृषि-तकनीक स्टार्टअप के प्रकार			हाँ	हाँ
स्थिर	-2.499*** (0.910)		-2.265*** (0.915)	
आर स्कवेयर	0.300		0.325	
अवलोकनों की संख्या	690	690	690	690

नोट: ***, **, * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं। कोष्ठकों में बताई गई मानक त्रुटियाँ मजबूत मानक त्रुटियाँ हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीता

शिवांगी मिश्रा, अनिरबन सान्याल और संजय सिंह द्वारा^

यह आलेख भारत में प्रमुख आर्थिक संकेतकों के मौसमी कारकों की जांच करता है, जिसमें 25 तिमाही संकेतकों के साथ छह क्षेत्रों- मौद्रिक और बैंकिंग, भुगतान प्रणाली, मूल्य, औद्योगिक उत्पादन, माल व्यापार और सेवाओं के 78 मासिक संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। कई संकेतकों में स्पष्ट मौसमी भिन्नताएं होती हैं, जिनमें आरबीआई के पास नकद शेष, मांग जमा, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और व्यापारिक निर्यात शामिल हैं। तिमाही डेटा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में मौसमी भिन्नताओं को उजागर करते हैं, विशेष रूप से सरकारी व्यय, जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण मौसमी प्रभाव दिखाती है। जनवरी-मार्च तिमाही में विनिर्माण में क्षमता उपयोग चरम पर है, जो सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ मेल खाती है।

प्रस्तावना

समष्टि आर्थिक संकेतकों में मौसमीता एक वर्ष के भीतर होने वाले आवर्ती और पूर्वानुमानित पैटर्न को संदर्भित करती है। यह प्रवृत्ति, चक्रीय भिन्नता और यादृच्छिक उतार-चढ़ाव के साथ-साथ समय श्रृंखला विश्लेषण के एक प्रमुख घटक का प्रतिनिधित्व करती है। मौसमी परिवर्तन मौसम की स्थिति, उत्पादन चक्र, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, अवकाश के दिन और अवकाश के दिनों की प्रवृत्ति जैसे कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। मौसमी समायोजन समय श्रृंखला डेटा से इन मौसमी और कैलेंडर प्रभावों को समाप्त करने की प्रक्रिया है ताकि अंतर्निहित दीर्घकालिक रुझानों, चक्रों के साथ-साथ अल्पकालिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके, जिससे आर्थिक स्थितियों का स्पष्ट आकलन हो सके। 1980 से, रिज़र्व बैंक प्रमुख समष्टि आर्थिक चर के लिए मासिक मौसमी कारक प्रकाशित करता रहा है।[1]

यह आलेख भारत में प्रमुख आर्थिक संकेतकों के मौसमी पैटर्न का अनुमान करता है। कोविड़-19 महामारी से व्यवधानों के कारण 2020 में आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धीरे-धीरे सामान्यीकरण हुआ, जो प्रमुख समष्टि आर्थिक चर में भी परिलक्षित हुआ। अत्यधिक अस्थिरता की इस अवधि को देखते हुए, मौसमी कारक विश्लेषण इन आर्थिक श्रृंखलाओं के अस्थायी गुणों में संभावित परिवर्तनों पर विचार करता है। इसके अतिरिक्त, मौसमी कारकों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मौसमी पैटर्न की स्थिरता का महामारी-पूर्व डेटा के साथ सत्यापन किया जाता है।[2]

आलेख का शेष हिस्सा इस प्रकार व्यवस्थित है: खंड II डेटा और कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। खंड III मौसमी कारक अनुमानों को दर्शाता है और चयनित आर्थिक श्रृंखला में मौसमी भिन्नताओं पर चर्चा करता है। आलेख खंड IV में निष्कर्षों को सारांशित करके समाप्त होता है।

II. डेटा और कार्यप्रणाली

ऐतिहासिक रूप से, इस आलेख के पिछले संस्करणों ने विशेष रूप से मासिक आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस संस्करण में, इसका कवरेज पहली बार तिमाही प्रकाशित होने वाले प्रमुख आर्थिक संकेतकों तक बढ़ाया गया है।

मासिक चर में मौद्रिक और बैंकिंग सांख्यिकी, मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सांख्यिकी, सेवा क्षेत्र संकेतक, माल व्यापार और भुगतान प्रणाली संकेतक जैसे छह प्रमुख विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया हैं। इन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत शामिल 78 संकेतकों की पूरी सूची सारणी ए1-एम1 (अनुलग्नक I) में दी गई है। मौसमी कारकों का अनुमान अमेरिकी जनगणना ब्यूरो[3] के

^ लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ हैं। लेखक इस आलेख को तैयार करने में उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए डॉ. ए. आर. जोशी के आभारी हैं। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं जो जरूरी नहीं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साझा किए गए हों।

1 इस श्रृंखला का पहला लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिसंबर 1956 अंक में प्रकाशित हुआ था और जनवरी 1980 से वार्षिक आलेख प्रकाशित किए गए थे। इस श्रृंखला का पिछला लेख आरबीआई बुलेटिन के मार्च 2024 अंक में प्रकाशित हुआ था।

2 मौसमी कारकों का पूर्वानुमान श्रृंखला पर उपयुक्त RegARIMA मॉडल का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के बाद डेटा जनरेटिंग प्रक्रिया में संभावित परिवर्तन, मॉडल की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार, मौसमी कारकों के पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकते हैं।

X13-ARIMA-SEATS सॉफ़्टवेयर के साथ एक गुणात्मक समय श्रृंखला मॉडल का उपयोग करके लगाया जाता है, जिसे दिवाली और भारतीय व्यापारिक दिन के प्रभावों के लिए समायोजन सहित भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है।

त्रैमासिक श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखे, क्षमता उपयोग और ऑर्डर बुक से नए ऑर्डर, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस), व्यापार मूल्यांकन और प्रत्याशा सूचकांक, औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) से घटक श्रृंखला और भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़ों से सेवाओं में बाह्य व्यापार को शामिल किया गया है[4]। मौसमी विश्लेषण के लिए चयनित 25 त्रैमासिक श्रृंखलाओं की पूरी सूची सारणी ए2-ति1 (अनुबंध II) में दी गई है।

आर्थिक श्रृंखला में महामारी से प्रभावित अस्थिरता को तीन प्रकार के आउटलेयर अर्थात् एडिटिव आउटलेयर (एओ), अस्थायी परिवर्तन (टीसी) और लेवल शिफ्ट (एलएस) के माध्यम से एक स्वचालित आउटलेयर डिटेक्शन तंत्र का उपयोग करके समायोजित किया जाता है, जिनकी आर्थिक व्याख्या को सही ठहराने के लिए जाँच की जाती है। यह मानते हुए कि महामारी के बाद की अवधि के लिए दीर्घावधि श्रृंखला डेटा की कमी आउटलेयर डिटेक्शन को प्रभावित कर सकती है और इस तरह मौसमी कारक अनुमानों को प्रभावित कर सकती है, कोविड-पूर्व नमूनों (तकनीकी अनुलग्नक) के मौसमी कारक अनुमानों की तुलना करके दृढ़ता की जाँच की जाती है।

III. भारत में प्रमुख आर्थिक चर में मौसमीता

III.ए. मासिक श्रृंखला में मौसमीता

अध्ययन में विश्लेषण किए गए अधिकांश आर्थिक चरों ने मौसमी पैटर्न प्रदर्शित किए हैं (सारणी ए1-एम2 और ए1-एम3, अनुलग्नक I)। चयनित 14 मौद्रिक और बैंकिंग संकेतकों में से 10 संकेतक मार्च या अप्रैल में उच्च मौसमी स्तर प्रदर्शित करते हैं, जबकि 14 में से पांच संकेतकों में अगस्त के दौरान मौसमी गर्त होते हैं। आरक्षित मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा के लिए मौसमीता मार्च में उच्चतम स्तर पर होती हैं, जबकि व्यापक मुद्रा अप्रैल के दौरान मौसमी उच्चतम स्तर प्रदर्शित करती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमाराशियाँ अप्रैल के दौरान मौसमी उच्चतम स्तर का अनुभव करती हैं, जबकि बैंक ऋण मार्च के दौरान बढ़ता है। कुल जमाराशियों और बैंक ऋण में मौसमी गर्त क्रमशः फरवरी और अगस्त के दौरान दर्ज किए जाते हैं। कुल जमाराशियों के भीतर, मांग जमाराशियाँ मार्च के दौरान मौसमी वृद्धि दर्ज करती हैं, जबकि सावधि जमाराशियाँ अप्रैल के दौरान उच्च मौसमी स्तर पर होती हैं। एससीबी के ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट मार्च में उच्च मौसमी स्तर को छूती हैं और अगस्त में सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाते हैं। गैर-खाद्य ऋण में भी इसी तरह का मौसमी पैटर्न देखा जाता है। एससीबी का निवेश अगस्त में उच्च रहता है और मार्च में धीमा हो जाता है। मई के दौरान प्रचलन में मुद्रा बढ़ जाती है तथा मौसमी परिवर्तनों के कारण सितम्बर में इसमें कमी आ जाती है।

मौद्रिक और बैंकिंग संकेतकों में, माँग जमाराशियों, एससीबी के पास की नकदी और आरबीआई के पास की शेष राशि और संकीर्ण मुद्रा में मौसमी विविधताएँ अधिक हैं। 2023-24 में माँग जमाओं में मौसमी विविधताओं की सीमा 7.5 प्रतिशत अंकों पर है, जो इसके पिछले दस वर्षों के औसत से कम है। दूसरी ओर, एससीबी के पास की नकदी और आरबीआई के पास की शेष राशि में मौसमी विविधताओं की सीमा समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ी और यह 2023-24 के दौरान 7.7 प्रतिशत अंकों पर रही। 2023-24 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल जमा, सावधि जमा और बैंक ऋण में मौसमी विविधताओं में कमी आई (सारणी ए1-एम3, अनुलग्नक-I)।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में मौसमी पैटर्न यह दर्शाता है कि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के मौसमी पैटर्न से प्रेरित सीपीआई अक्टूबर में अपने मौसमी शिखर पर पहुँच जाता है और मार्च में कम हो जाता है। सीपीआई खाद्य पदार्थों में सब्जियों के कारण उच्च मौसमी विविधताएँ देखी जाती हैं, जो एक वर्ष के दौरान सबसे अधिक मौसमी मूल्य विविधताओं का अनुभव करती हैं। टीओपी (टमाटर, आलू और प्याज) की कीमतों में मौसमी विविधताएँ अधिक स्पष्ट हैं। आलू और प्याज की कीमतें नवंबर में बढ़ जाती हैं और मौसमी दबाव क्रमशः फरवरी और मई में कम हो जाता है। टमाटर की कीमतें जुलाई के दौरान बढ़ जाती हैं और मार्च तक कम हो जाती हैं (चार्ट 1 और सारणी ए1-एम2)। दूसरी ओर, अन्य प्रमुख समूह (जैसे, कपड़े और जूते, आवास और विविध) कम मौसमी उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं (सारणी ए1-एम3)।

[3] https://www.census.gov/data/software/x13as.html

[4] तिमाही आवृत्ति के तहत, श्रृंखला अर्थात, सेवाओं का आयात, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में आयात, ओबीआईसीयूएस से नए आदेश, रोजगार मूल्यांकन और प्रत्याशा और बाह्य वित्त मूल्यांकन और प्रत्याशा की लागत को स्थिर मौसमीता की कमी के कारण वर्तमान आलेख में छोड़ दिया गया था।

चार्ट 1: सीपीआई के औसत[5] मासिक मौसमी कारक (संयुक्त)

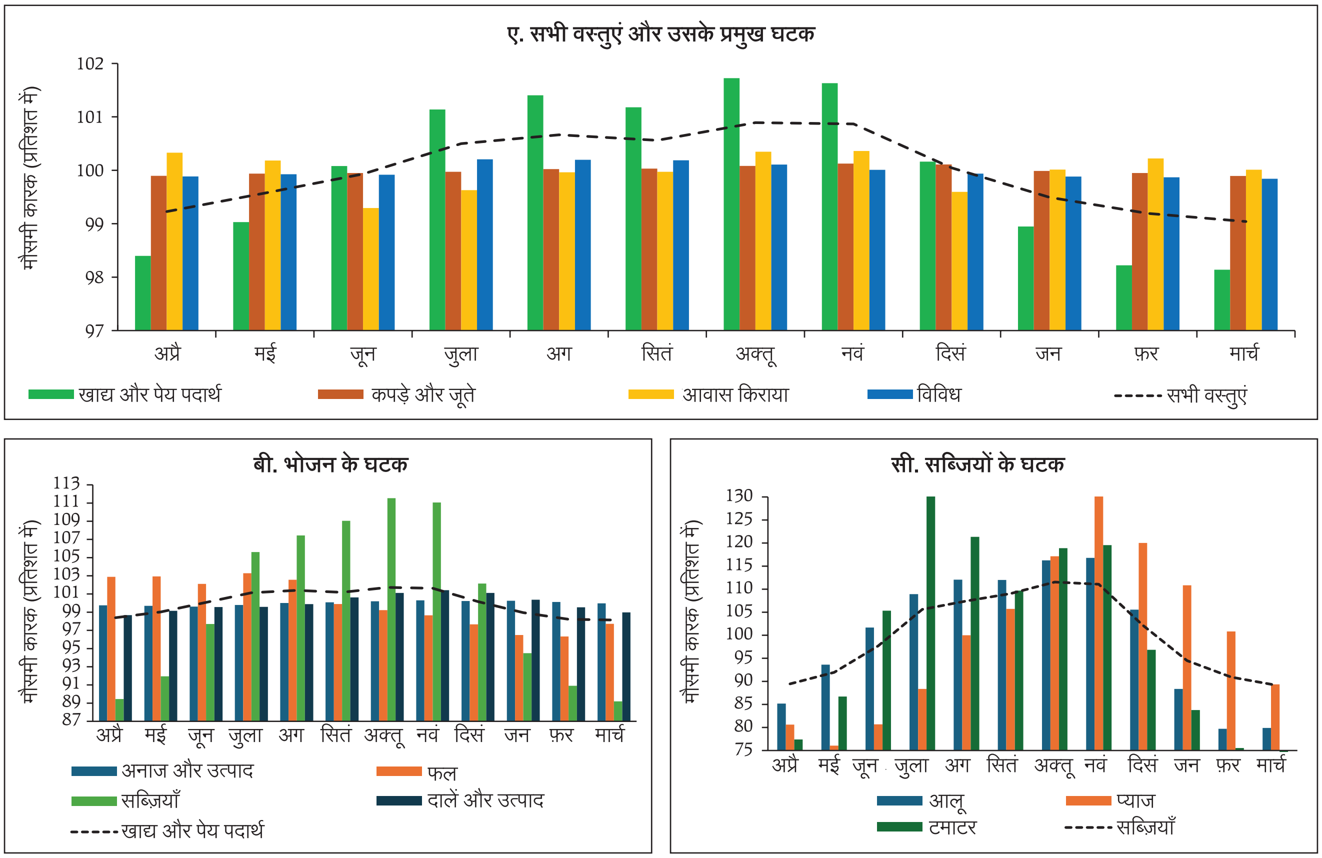

स्रोत: एमओएसपीआई; तथा लेखकों की गणना।

अन्य प्रमुख मूल्य सूचकांकों में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) अक्टूबर में मौसमी शिखर पर पहुंच जाता है, जो कृषि मजदूरों (एएल) और ग्रामीण मजदूरों (आरएल) के उपभोक्ता मूल्यों के विपरीत है, जो नवंबर में चरम पर होते हैं। मार्च में सभी तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मौसमी मॉडरेशन का अनुभव करते हैं। सीपीआई-आईडब्ल्यू, एएल और आरएल में मौसमी बदलाव 2023-24 के दौरान सीपीआई हेडलाइन इंडेक्स के लगभग समान स्तर पर थे (चार्ट 2 और सारणी ए1-एम2, ए1-एम3)।

थोक मूल्य, सामान्य रूप से, नवंबर में मौसमी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं और जनवरी और फरवरी में कम हो जाते हैं (चार्ट 3)। प्राथमिक वस्तुओं के लिए डब्ल्यूपीआई में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत अंकों का मौसमी परिवर्तन देखा गया जिसमें मुख्य रूप से डब्ल्यूपीआई खाद्य वस्तुओं (एसएफ रेंज 5.4 प्रतिशत अंक) अग्रणी थी और उसके बाद ईंधन और बिजली 1.6 प्रतिशत अंक थी (सारणी ए1-एम3)।

[5] पिछले 10 वर्षों के मौसमी कारकों का औसत।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में परिलक्षित औद्योगिक उत्पादन मौसमीता, मार्च के दौरान तीव्र होती है और अप्रैल में कम हो जाती है, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के मौसमी पैटर्न को दर्शाती है। खनन गतिविधियाँ मार्च के दौरान चरम पर होती हैं, लेकिन मौसमी गर्त सितंबर में होता है। बिजली उत्पादन मई में मौसमी शिखर को छूता है और फरवरी में कम हो जाता है। विनिर्माण के भीतर, विभिन्न क्षेत्रों के मौसमी शिखर और गर्त अलग-अलग महीनों के दौरान होते हैं। दिसंबर के दौरान खाद्य उत्पादों का विनिर्माण तेज हो जाता है, जबकि पेय पदार्थ का उत्पादन मई के दौरान मौसमी उच्चतर स्तर को छूता है। खाद्य और पेय पदार्थों के उत्पादन में मौसमी गर्त क्रमशः जून और अगस्त के दौरान होता है।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण में, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन अक्टूबर के दौरान भारत में प्रमुख त्योहारों के कारण मौसमी शिखर पर पहुँच जाता है, जबकि गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन दिसंबर के दौरान चरम पर होता है। अन्य सभी

चार्ट 2: सीपीआई-आईडब्ल्यू, एएल और आरएल के औसत मासिक मौसमी कारक

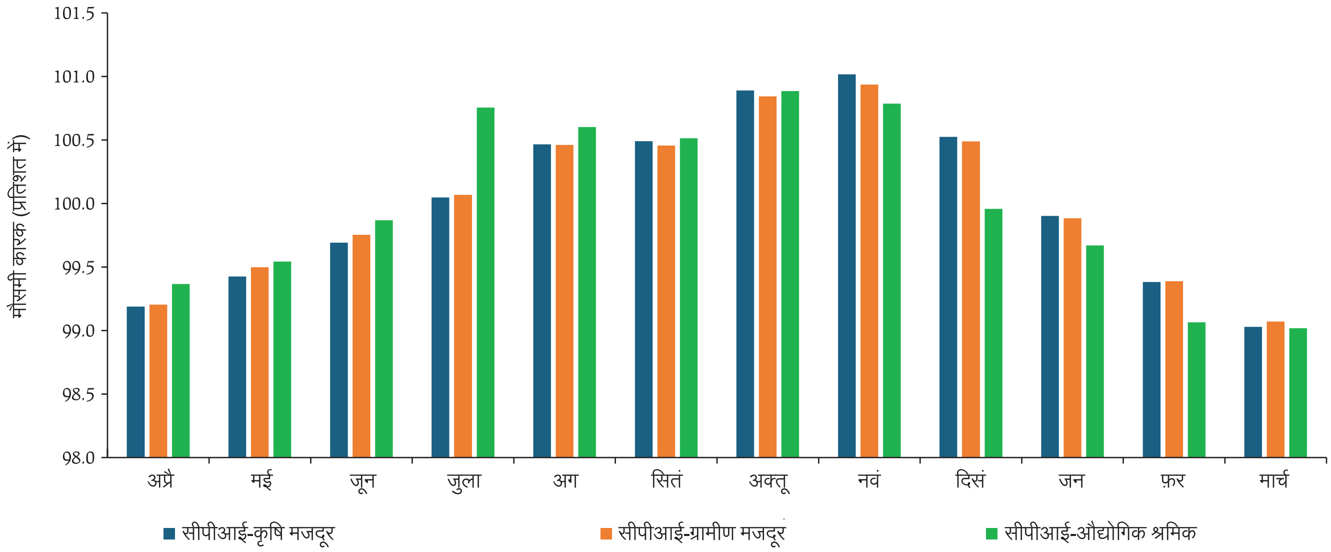

स्रोत: श्रम ब्यूरो; तथा लेखकों की गणना।

प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्पादन गतिविधि मार्च के दौरान चरम पर होती है। पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में मौसमी गर्त अप्रैल के दौरान होता है। अच्छे प्राथमिक और मध्यवर्ती स्तर के उत्पादन में क्रमशः सितंबर और फरवरी के दौरान मौसमी संतुलन का सामना करना पड़ता है। संरचनागत वस्तुओं का उत्पादन नवंबर में कम होता है। उर्वरक और प्राकृतिक गैस को छोड़कर, आठ प्रमुख उद्योगों में से अधिकांश मार्च के दौरान मौसमी शिखर दर्ज करते हैं। उर्वरक और प्राकृतिक गैस का उत्पादन अक्टूबर के दौरान मौसमी शिखर को छूता है (चार्ट 4 और सारणी ए1-एम2)।

मौसमी कारकों की सीमा द्वारा मापा गया मौसमी उतार-चढ़ाव, आईआईपी और इसके घटक श्रृंखला में उच्च स्तर पर रहें। आईआईपी के प्रमुख क्षेत्रों में, खनन क्षेत्र ने सबसे अधिक

चार्ट 3: डब्ल्यूपीआई के औसत मासिक मौसमी कारक

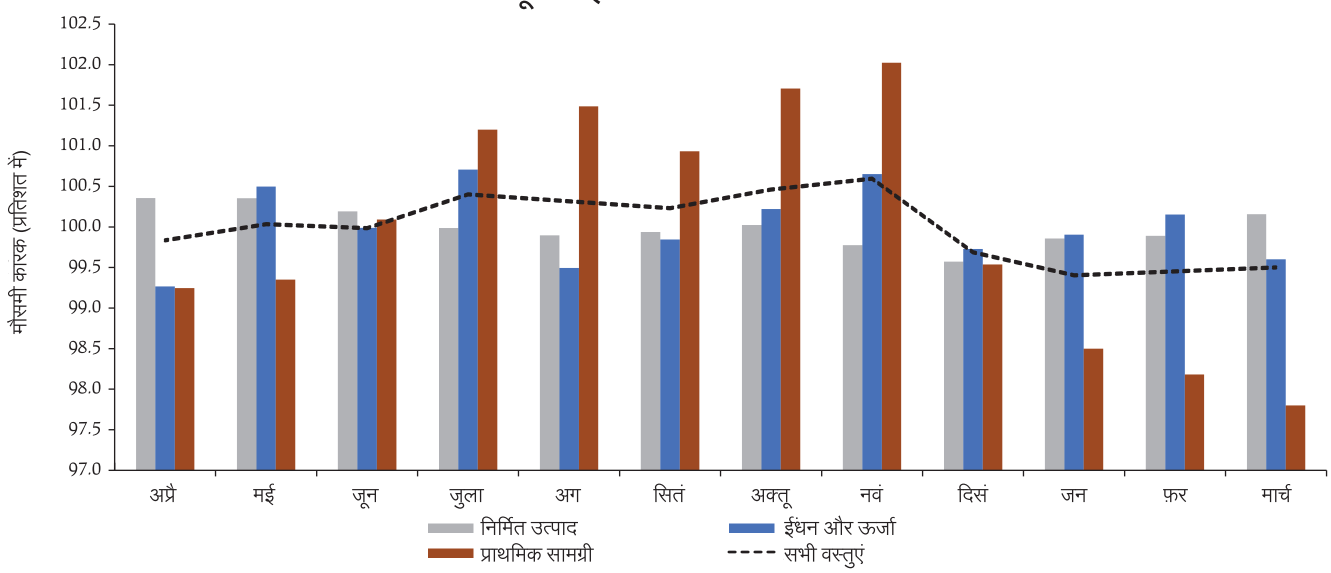

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा लेखकों की गणना।

चार्ट 4: आईआईपी और आठ प्रमुख उद्योगों के लिए मौसमी कारक

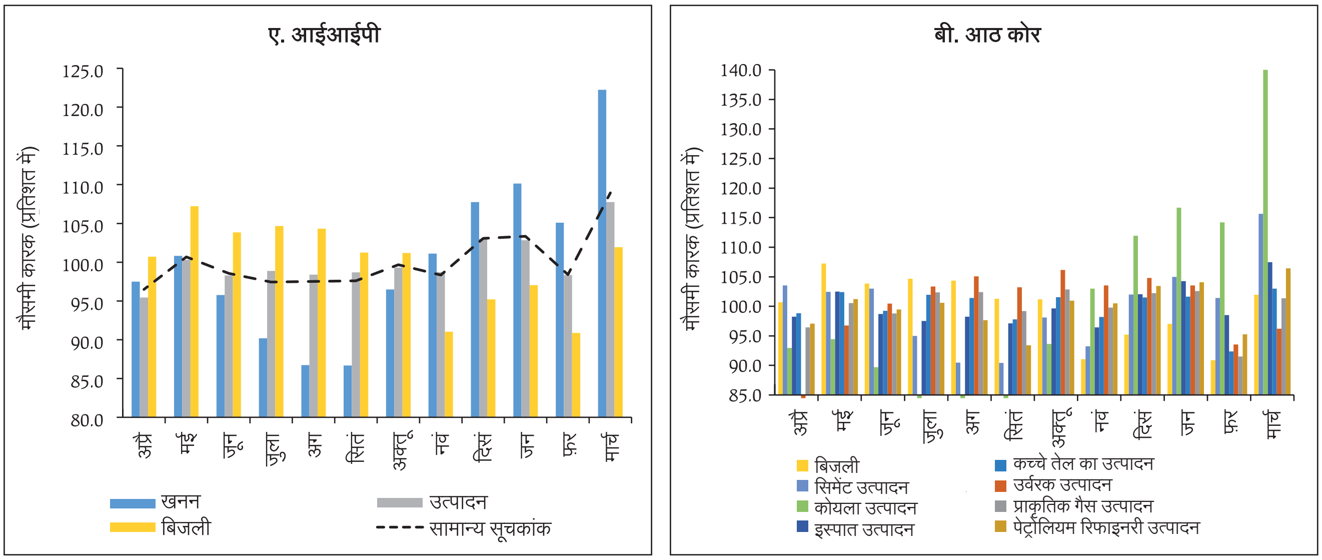

स्रोत: एमओएसपीआई; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा लेखकों की गणना।

विविधताएँ प्रदर्शित कीं और उसके बाद बिजली क्षेत्र का स्थान रहा। आईआईपी पूंजीगत वस्तुओं ने उपयोग-आधारित वर्गीकरण के बीच बहुत अधिक मौसमी विविधताएँ प्रदर्शित कीं, उसके बाद प्राथमिक वस्तुओं का स्थान रहा। आठ मुख्य उद्योगों के घटकों में, मौसमी कारकों की सीमा कोयला उत्पादन में सबसे अधिक है, जबकि कच्चे तेल में मौसमी विविधता सबसे कम है (सारणी ए1-एम3)।

उच्च आवृत्ति सेवा क्षेत्र के संकेतकों के संबंध में, यात्री वाहनों की बिक्री में मौसमी शिखर अक्टूबर के दौरान होता है, जो मुख्य रूप से त्योहार के मौसम के दौरान उच्च मांग दर्शाता है। मार्च के दौरान कार्गो और रेलवे यातायात में मौसमी वृद्धि होती है। मई के दौरान घरेलू हवाई यात्री यातायात बढ़ता है और जनवरी में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में उच्च मौसमी मात्रा दर्ज की जाती है (चार्ट 5ए और सारणी ए1-एम2)। यात्री वाहन बिक्री

चार्ट 5: सेवा क्षेत्र और व्यापारिक व्यापार के लिए मौसमी कारक

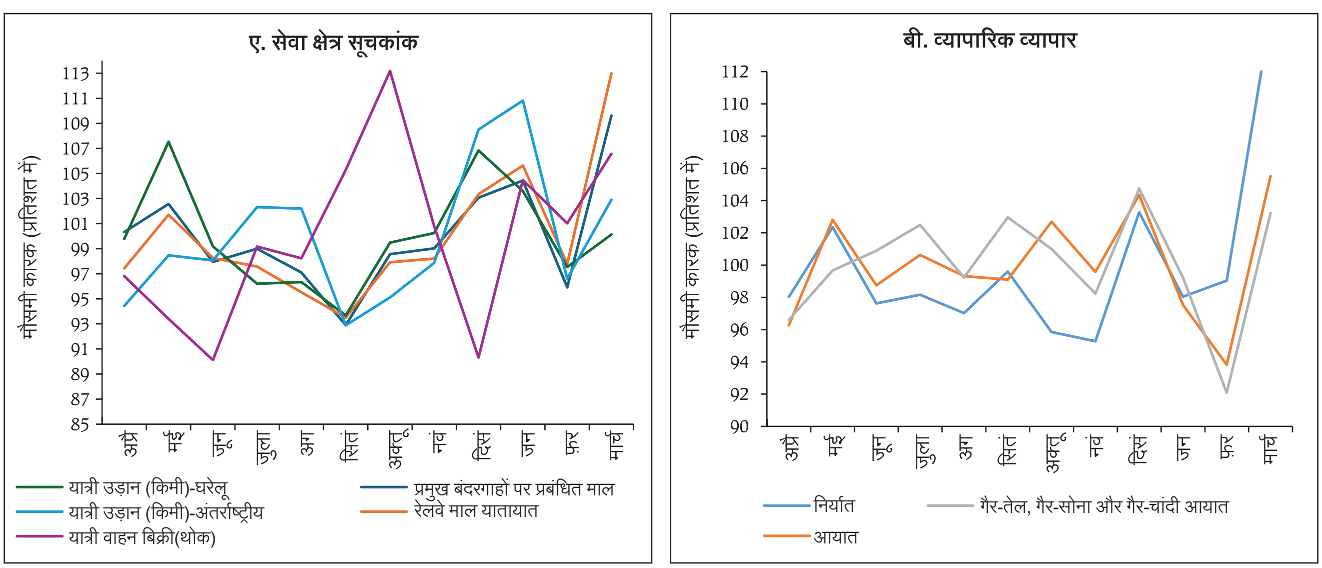

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; डीजीसीए; रेल मंत्रालय; भारतीय बंदरगाह संघ; सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); और लेखकों की गणना।

चार्ट 6: भुगतान प्रणाली संकेतकों के लिए मौसमी कारक

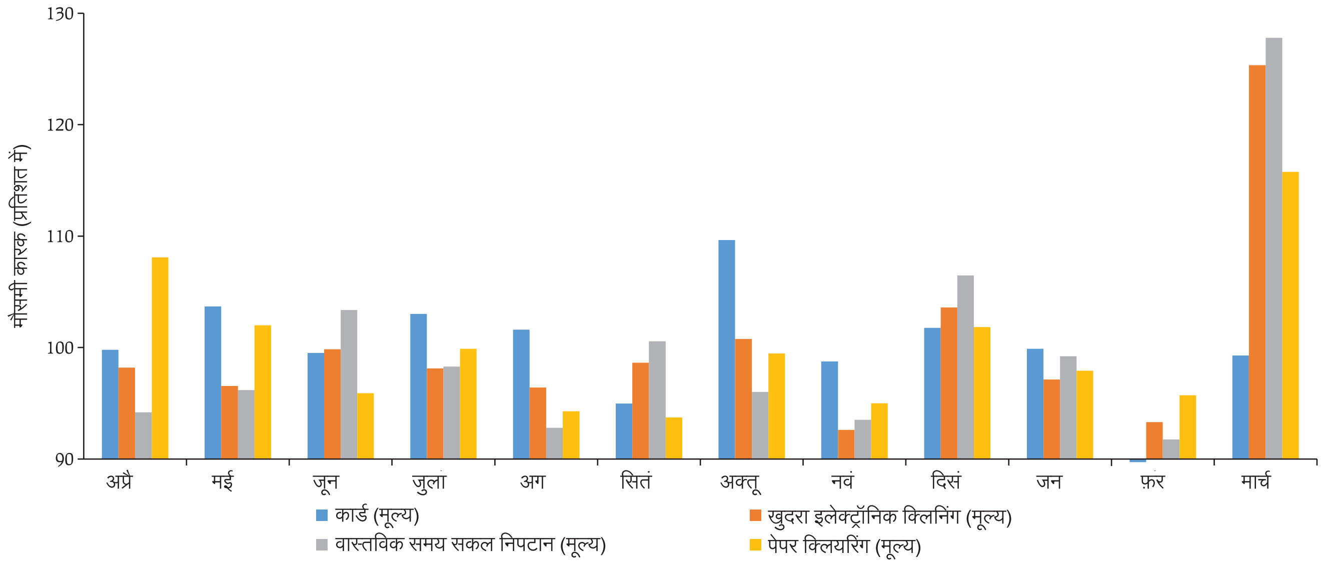

स्रोत: आरबीआई: और लेखकों की गणना।

(थोक) जिसमें जून के दौरान मौसमी गर्त होता है, को छोड़कर प्रमुख उच्च आवृत्ति सेवा क्षेत्र के संकेतक सितंबर के दौरान मौसमी गर्त का अनुभव करते हैं। मौसमी विविधताओं के संबंध में, मौसमी कारक यात्री वाहन बिक्री में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जिनकी सीमा 2023-24 में 25.8 प्रतिशत अंकों की होती है। रेलवे और कार्गो यातायात ने भी हवाई यात्रियों की तुलना में अधिक मौसमी विविधताएँ प्रदर्शित कीं (सारणी ए1-एम3)।

मार्च के दौरान व्यापारिक व्यापार चरम पर होता है और निर्यात एवं आयात दोनों ही मौसमी वृद्धि दर्ज करते हैं। नवंबर के दौरान निर्यात में गिरावट होती है जबकि फरवरी में आयात मौसमी रूप से कम होता है। दिसंबर के दौरान गैर-तेल, गैर-स्वर्ण और गैर-चांदी के आयात में मौसमी चरम और फरवरी के दौरान गिरावट दर्ज होती हैं (चार्ट 5बी और सारणी ए1-एम2)। आयात की तुलना में माल निर्यात में मौसमी उतार-चढ़ाव अधिक हैं। 2023-24 के दौरान समग्र आयात की तुलना में गैर-तेल, गैर-सोना और गैर-चांदी के आयात में अपेक्षाकृत अधिक मौसमी परिवर्तन दिखाई दिए (सारणी ए1-एम3)।

मार्च के दौरान कार्ड भुगतान को छोड़कर भुगतान प्रणाली संकेतकों में मौसमी शिखर होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) भुगतान फरवरी में मौसमी गिरावट दर्ज करता है जबकि पेपर क्लियरिंग सितंबर में मौसमी बोटमिंग आउट दर्ज करता है। नवंबर के दौरान खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में कमी आती है, जबकि कार्ड भुगतान फरवरी के दौरान मौसमी मॉडरेशन का अनुसरण करते हैं (चार्ट 6 और सारणी ए 1-एम 2)। भुगतान संकेतकों में, आरटीजीएस लेनदेन और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान 2023-24 में क्रमशः 30.8 प्रतिशत अंक और 28.5 प्रतिशत अंक की सीमा में मौसमी कारकों के साथ उच्चतम मौसमी बदलाव प्रदर्शित करते हैं (सारणी ए1-एम3)।

III.बी. त्रैमासिक श्रृंखला में मौसमीता[6]

त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) अनुमान चौथी तिमाही के दौरान मौसमी उच्चता दिखाते हैं, जबकि मौसमी गर्त क्रमशः पहली और दूसरी तिमाही में देखे जाते हैं। जीडीपी के घटकों में, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) पहली तिमाही के दौरान मौसमी रूप से बढ़ता है, लेकिन तीसरी तिमाही के दौरान कम हो जाता है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) चौथी तिमाही के दौरान मौसमी शिखर पर होता है, जबकि दूसरी तिमाही में गर्त देखे जाते हैं, जो मानसून का मौसम है। दूसरी तिमाही के दौरान मौसमी नरमी के बाद, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) तिसरी तिमाही अर्थात प्रमुख त्योहार के मौसम के दौरान ऊंचा रहता है। आपूर्ति

[6] इस लेख में, तिमाहियाँ वित्तीय वर्षों के अनुरूप हैं। अर्थात, पहली तिमाही अप्रैल से जून के अनुरूप है, दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक है, तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक और चौथी तिमाही जनवरी से मार्च है।

चार्ट 7: राष्ट्रीय खातों के मौसमी कारक

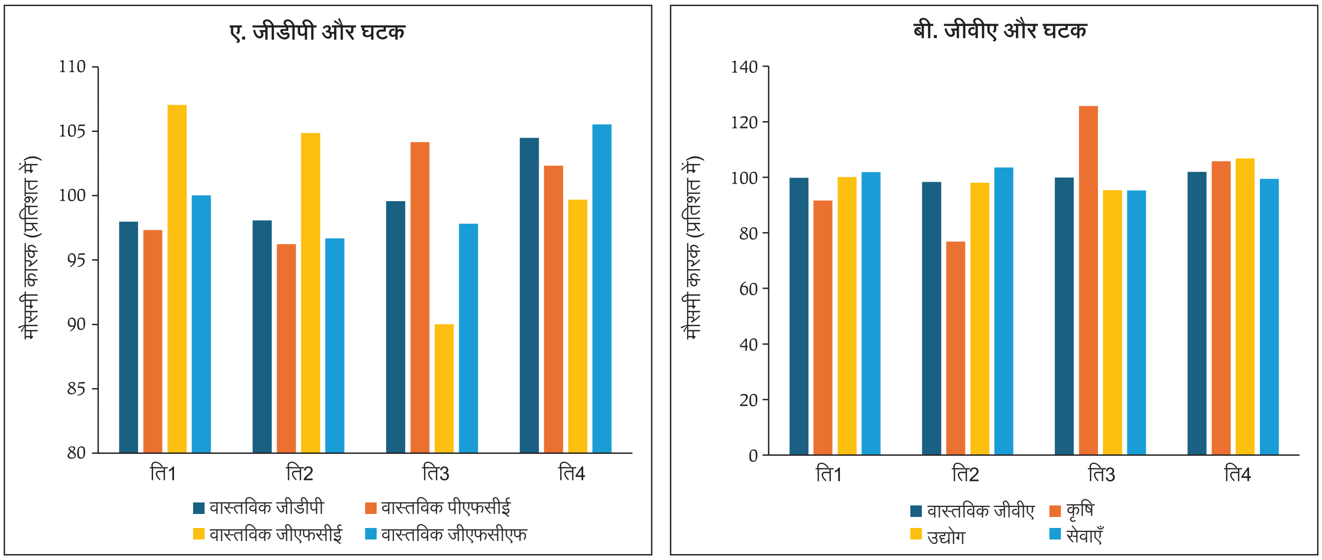

स्रोत: एमओएसपीआई; और लेखकों की गणना।

पक्ष पर, कृषि में उत्पादन (मूल्य वर्धित) दूसरी तिमाही के दौरान मौसमी गिरावट दर्ज करता है जो प्रमुख खरीफ बुवाई अवधि है, जबकि यह खरीफ फसलों की कटाई के साथ तीसरी तिमाही के दौरान एक मौसमी उच्च स्तर दर्ज करता है। औद्योगिक उत्पादन में मौसमी शिखर और निम्नतम स्तर क्रमशः चौथी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान होता है, जबकि सेवा गतिविधियां दूसरी तिमाही के दौरान तेज़ होती हैं, लेकिन तीसरी तिमाही में मध्यम हो जाती हैं (चार्ट 7 और सारणी ए2-ति2)।

मौसमी कारकों की सीमा द्वारा मापा जाने वाला मौसमी उतार-चढ़ाव, जीवीए की तुलना में जीडीपी में अधिक है, संभवतः यह निवल करों में भिन्नता के कारण होता है जो बाजार की कीमतों को प्रभावित करते हैं। जीवीए में मौसमी उतार-चढ़ाव पिछले 10 वर्षों के औसत की तुलना में 2023-24 में अधिक है। जीएफसीई सकल घरेलू उत्पाद के व्यय-पक्ष के घटकों में उच्चतम मौसमी बदलाव प्रदर्शित करता है। जीएफसीएफ और पीएफसीई के मौसमी उतार-चढ़ाव लगभग एकसमान हैं (सारणी ए2- ति3)।

ऑर्डर बुक में मापे गए विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग (सीयू), इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) चौथी तिमाही के दौरान उच्च स्तर पर और पहली तिमाही के दौरान गर्त में रहा। इसके अलावा, क्षमता उपयोग में मौसमी बदलाव पिछले 10 वर्षों में 3.7 प्रतिशत की औसत सीमा के भीतर है। आरबीआई के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) इनपुट से प्राप्त कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशा सूचकांक, क्रमशः चौथी और तीसरी तिमाही के दौरान चरम पर था। इन दोनों श्रृंखलाओं में मौसमी गिरावट क्रमशः दूसरी तिमाही और पहली तिमाही के दौरान होती है। ऑर्डर बुक मूल्यांकन और प्रत्याशा चौथी तिमाही के दौरान मौसमी शिखर को छूती है। हालांकि, ऑर्डर बुक मूल्यांकन दूसरी तिमाही के दौरान कम होता है, जबकि ऑर्डर बुक प्रत्याशा पहली तिमाही के दौरान कम होती है। सीयू के बारे में उत्पादकों का मूल्यांकन चौथी तिमाही में चरम पर होता है और सीयू की प्रत्याशा तीसरी तिमाही में चरम पर होती है। मूल्य निर्धारण के दृष्टिकोण पर, विक्रय मूल्य के बारे में उत्पादकों का मूल्यांकन पहली तिमाही के दौरान अधिक होता है, और दूसरी तिमाही के दौरान यह कम हो जाता है। विक्रय मूल्यों पर प्रत्याशा पहली तिमाही के दौरान बढ़ जाती है, लेकिन चौथी तिमाही में कम हो जाती है। उत्पादक चौथी तिमाही में अपनी लाभप्रदता का उच्चतर आकलन करते हैं, लेकिन भविष्य की लाभप्रदता के बारे में उनकी प्रत्याशाएं दूसरी तिमाही में चरम पर होती हैं (चार्ट 8 और सारणी ए2-ति2)।

कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशा सूचकांक अपेक्षाकृत कम मौसमी उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं जिसमें मौसमी कारक 1.7 - 2.1 प्रतिशत अंकों की औसत सीमा के भीतर मँडराते हैं। हालांकि, उत्पादन और क्षमता उपयोग का मूल्यांकन और प्रत्याशाएं सर्वाधिक मौसमी परिवर्तन दर्शाती हैं (सारणी ए2-ति3)।

चार्ट 8: औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण और ओबीआईसीयूएस के मौसमी कारक

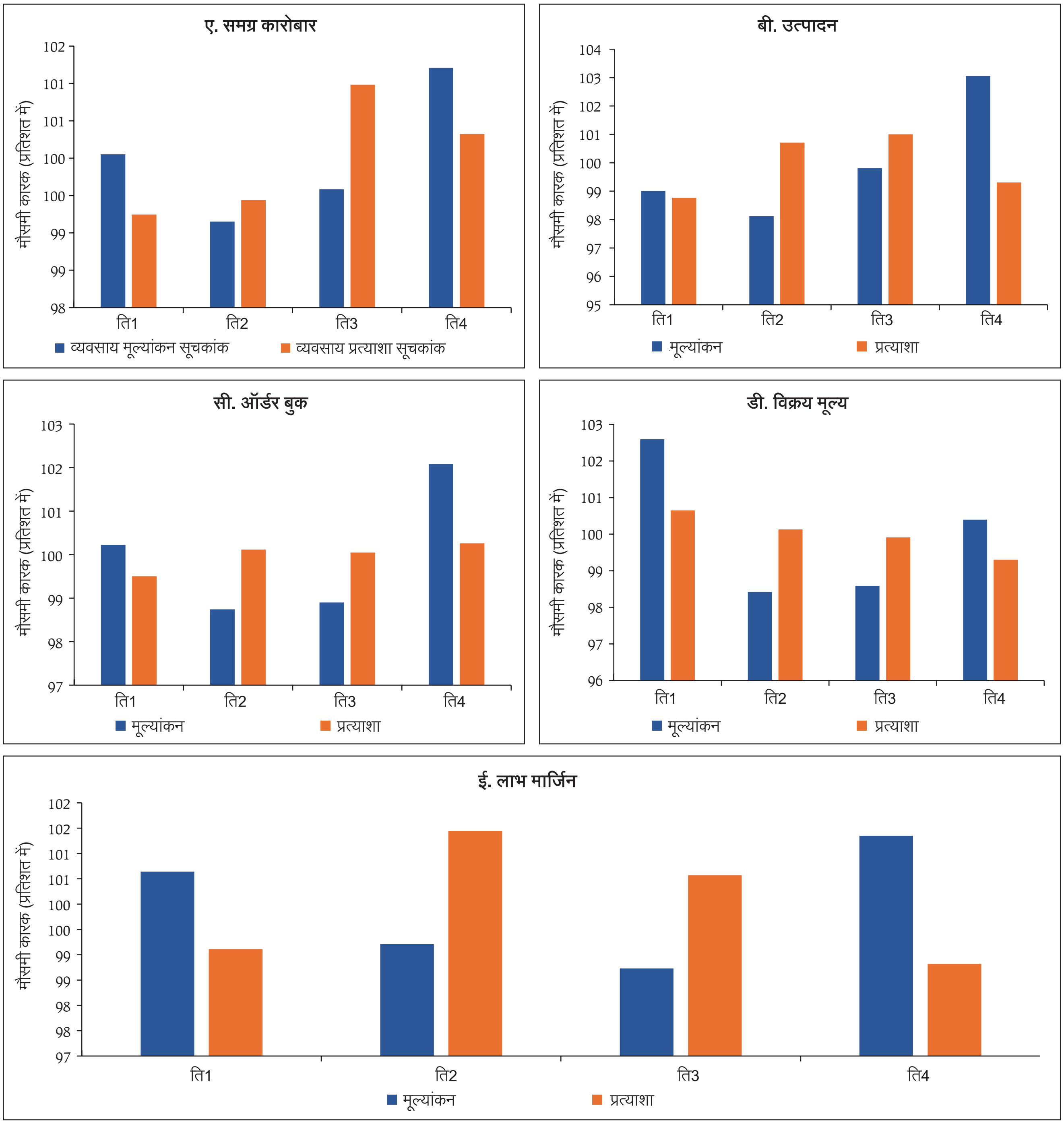

स्रोत: आरबीआई; तथा लेखकों की गणना।

कुल मिलाकर सेवा निर्यात चौथी तिमाही में चरम पर और पहली तिमाही में सबसे कम रहा। हालांकि, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का निर्यात तीसरी तिमाही के दौरान मौसमी रूप से उच्च रहा, और यात्रा सेवाओं का निर्यात चौथी तिमाही में सर्वाधिक रहा। यात्रा सेवाओं का आयात पहली तिमाही के दौरान चरम पर रहा (चार्ट 9 और सारणी ए2-ति2)। तुलनात्मक आधार पर, सेवा निर्यात में 6.3 प्रतिशत अंकों की दस साल की औसत सीमा के साथ उच्च मौसमी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। यात्रा निर्यात और आयात सेवा व्यापार के भीतर उच्च मौसमी उतार-चढ़ाव दिखाते हैं (सारणी ए2-ति3)।

चार्ट 9: सेवाओं में व्यापार का मौसमी कारक

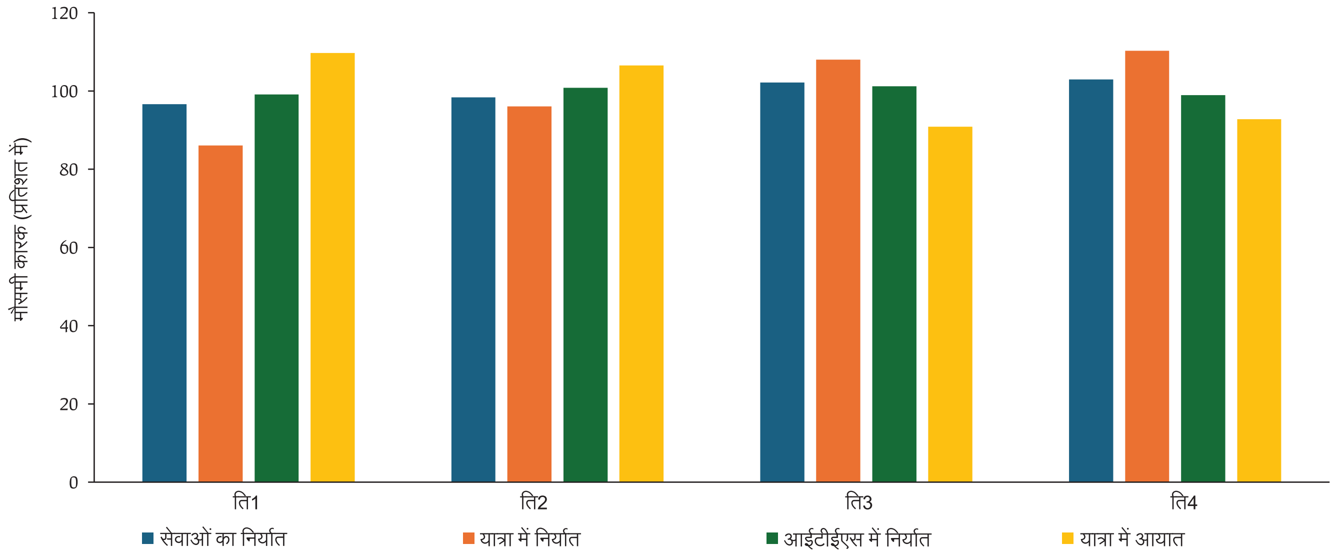

स्रोत: एमओएसपीआई; तथा लेखकों की गणना।

III.सी. मौसमी स्थिरता

मौसमी विविधताओं की स्थिरता को पैरामीट्रिक और गैर-पैरामीट्रिक परीक्षणों का उपयोग करके जांचा जाता है। मौसमी कारक विश्लेषण के साधन सारणी ए1-एम4 और सारणी ए2-ति4 में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, मौसमी कारक अनुमानों की स्थिरता की जाँच वित्त वर्ष: 2023-24 के लिए अनुमानित मौसमी कारकों की सीमा की तुलना मासिक और त्रैमासिक श्रृंखलाओं के लिए पूर्व-कोविड अवधि से 5-वर्षीय औसत मौसमी कारक के साथ करके की जाती है। मौसमी कारक विविधताओं के स्कैटर प्लॉट से पता चलता है कि वित्त वर्ष: 2023-24 में मौसमी विविधताएँ सभी मासिक श्रृंखलाओं में पूर्व-महामारी अवधि से औसत मौसमी विविधताओं के लगभग समान हैं। जीएफसीई और यात्रा निर्यात को छोड़कर तिमाही श्रृंखलाओं में एक समान पैटर्न देखा जाता है, जहाँ मौसमी विविधताओं की सीमा हाल ही में बढ़ी है (चार्ट 10 और सारणी ए1-एम5 और ए2-ति5)।

चार्ट 10: मासिक और त्रैमासिक श्रृंखला में मौसमी परिवर्तनों की सीमा

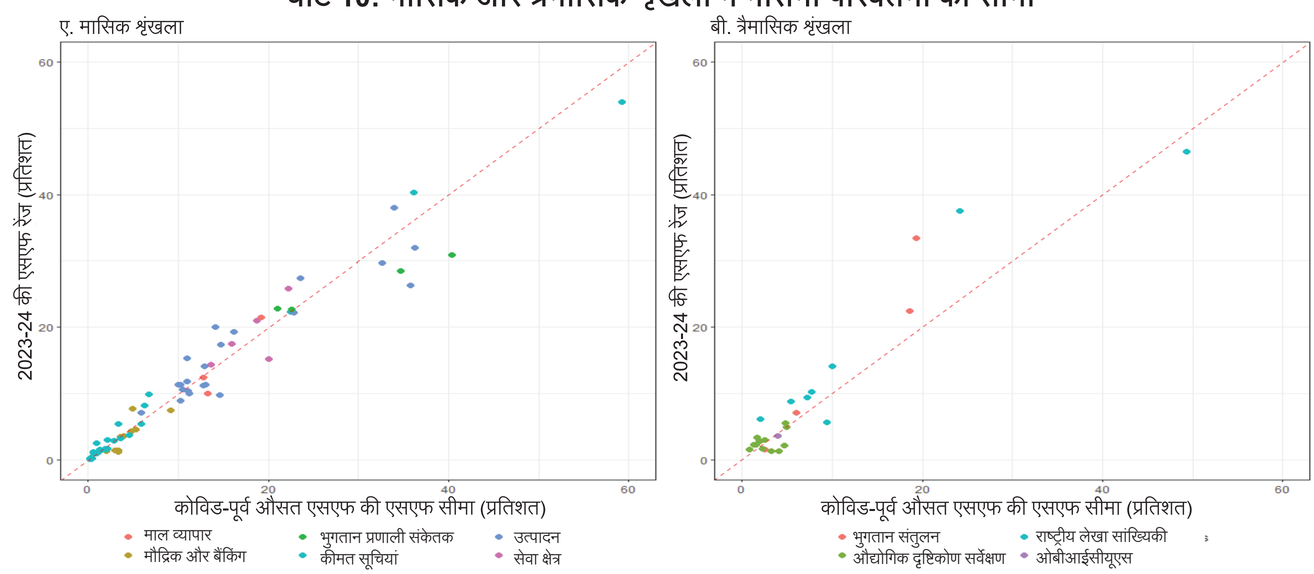

स्रोत: लेखकों की गणना।

IV. निष्कर्ष

यह आलेख भारत के लिए प्रमुख आर्थिक समय श्रृंखला डेटा के लिए मौसमी कारकों के अद्यतन अनुमान प्रदान करता है। कुल मिलाकर, मौसमी पैटर्न चरों में ज्यादातर स्थिर रहता है, हालांकि मौसमी विविधताएं कई संकेतकों जैसे कि हाथ में नकदी और आरबीआई के पास शेष राशि, मांग जमा, प्रमुख सब्जियों की कीमतें, औद्योगिक उत्पादन, यात्री वाहन बिक्री और व्यापार निर्यात में अधिक स्पष्ट हो गई हैं। कुछ सूचकांकों और बैंकिंग और मौद्रिक समुच्चय ने भी अपने चरम और गर्त महीनों में बदलाव देखा।

बैंक ऋण, गैर-खाद्य ऋण और मांग जमा जैसे बैंकिंग संकेतक आमतौर पर मार्च में साल के अंत के अपने उच्च स्तर को दर्ज करते हैं। जुलाई से नवंबर तक सीपीआई को मौसमी दबाव का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से मानसून के मौसम के दौरान सब्जियों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित होता है, जबकि फलों की कीमतें गर्मियों के महीनों में चरम पर होती हैं। औद्योगिक उत्पादन में, अधिकांश वस्तुएं मार्च में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती हैं, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं अक्टूबर में त्योहारों के मौसम के साथ मेल खाते हुए चरम पर पहुंचती हैं। निर्यात और आयात दोनों भी मार्च में चरम पर होते हैं, जिसमें आयात की तुलना में निर्यात में अधिक स्पष्ट मौसमी उतार-चढ़ाव दिखाई देता है।

तिमाही श्रृंखलाओं में, वास्तविक जीडीपी और जीवीए ने चौथी तिमाही के दौरान अपने मौसमी शिखर को दर्ज करना जारी रखा है। तकनीकी अनुलग्नक में इंगित महामारी से प्रेरित अस्थिरताओं को समायोजित करने के बाद भी, महामारी की शुरुआत के बाद से राष्ट्रीय खातों के समुच्चय में मौसमी विविधताएँ बढ़ी हैं। जीडीपी का मौसमी गर्त पहली तिमाही में होता है, जबकि जीवीए दूसरी तिमाही के दौरान गिरता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में, जीएफसीई, जीवीए उद्योग और सेवाओं को छोड़कर अधिकांश संकेतकों ने दूसरी तिमाही में गर्त देखा। औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के अधिकांश संकेतकों में, उत्पादक बिक्री मूल्य मूल्यांकन और प्रत्याशाओं को छोड़कर तिसरी और चौथी तिमाही में उच्च मौसमीता और पहली एवं दूसरी तिमाही में कम मौसमीता का आकलन करते हैं। चौथी तिमाही के दौरान सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई। तिसरी तिमाही के दौरान दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का निर्यात अधिक था।

महामारी ने आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किए, जिससे असामान्य डेटा पैटर्न सामने आए। महामारी के बाद के डेटा की अवधि सीमित रहती है, जो मौसमी एआरआईएमए मॉडल के माध्यम से स्टोकेस्टिक मौसमी अनुमानों को प्रभावित कर सकती है। डेटा की सीमित उपलब्धता के साथ डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया में परिवर्तनों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस आलेख में बताए गए मौसमी कारक अनुमान उचित सावधानियों और मजबूती की जाँच करके निकाले गए हैं। हालाँकि, महामारी के बाद की अवधि से अधिक डेटा उपलब्ध होनेपर, मौसमी कारक आगे भी बदलावों के अधीन हो सकते हैं।

संदर्भ:

Shiskin, J., Young, A. H., and Musgrave, J. C. (1967). The X-11 variant of the census method II seasonal adjustment program. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.

Gómez, Victor and Maravall, Agustin (1996). Programs TRAMO and SEATS, Instruction for User (Beta Version: September 1996). Working Papers, Banco de España.

तकनीकी अनुबंध

आर्थिक डेटा में मौसमी पैटर्न वर्ष के विशिष्ट समय पर होने वाले नियमित उतार-चढ़ाव को संदर्भित करते हैं, जो मौसम, अवकाश और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। X13-ARIMA-SEATS मौसमी समायोजन और समय श्रृंखला डेटा में प्रवृत्ति निष्कर्षण के लिए यू.एस. जनगणना ब्यूरो द्वारा विकसित एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सांख्यिकीय कार्यक्रम है। यह दो दृष्टिकोणों को जोड़ता है: RegARIMA मॉडलिंग और SEATS (ARIMA समय श्रृंखला में सिग्नल निष्कर्षण)। RegARIMA घटक समय श्रृंखला का पूर्वानुमान और मॉडल बनाता है, जबकि SEATS मौसमी, प्रवृत्ति और अनियमित घटकों में श्रृंखला के अपघटन का ध्यान रखता है। बार-बार केंद्रित मूविंग एवरेज फ़िल्टर लागू करके और प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ घटकों के पृथक्करण को परिष्कृत करके अपघटन को प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में, श्रृंखला से समय श्रृंखला घटकों को निकालने के लिए विभिन्न फ़िल्टर और मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है।

अब योजना में दो मौसमी समायोजन मॉड्यूल शामिल हैं। एक शिस्किन, यंग और मुसग्रेव (1967) में वर्णित X-11 मौसमी समायोजन विधि का उपयोग करता है। कार्यक्रम में X-11 और X-11-ARIMA योजना की सभी मौसमी समायोजन क्षमताएँ हैं। वही मौसमी और ट्रेड मूविंग एवरेज उपलब्ध हैं, और योजना अभी भी X-11 कैलेंडर और हॉलिडे एडजस्टमेंट रूटीन प्रदान करती है। दूसरा मौसमी समायोजन मॉड्यूल में बैंक ऑफ़ स्पेन में विक्टर गोमेज़ और अगस्टिन मारवाल द्वारा विकसित SEATS मौसमी समायोजन योजना से ARIMA मॉडल आधारित मौसमी समायोजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। X-13 ARIMA-SEATS के इस संस्करण में SEATS की सभी क्षमताएँ शामिल हैं, जो X-11 मौसमी समायोजन के समान ही SEATS मौसमी समायोजन के लिए स्थिरता और स्पेक्ट्रल डाईग्नोस्टिक्स उत्पन्न कर सकती हैं। इस आलेख में, मौसमी कारकों को निकालने के लिए पहले मौसमी समायोजन मॉड्यूल का उपयोग किया गया था।

X-13 ARIMA-SEATS एक अस्थायी या स्थायी प्रकृति की श्रृंखला के स्तर में अचानक परिवर्तनों से निपटने के लिए चार अन्य प्रकार के प्रतिगमन चर अर्थात योजक आउटलेयर (एओ), स्तर परिवर्तन (एलएस), अस्थायी परिवर्तन (टीसी) और रैंप प्रदान करता है । एओ पूरी श्रृंखला में केवल एक अवलोकन को प्रभावित करते हैं और इसलिए यह प्रभाव एक डमी चर द्वारा हटा दिया जाता है, जो विराम पर '0' और अन्य अवधि के लिए '1' लेता है। एलएस एक निश्चित समय बिंदु से आगे सभी अवलोकनों को कुछ स्थिर राशि से बढ़ाता या घटाता है, यह एलएस प्रभाव एक डमी चर को पेश करके हटा दिया जाता है जो विराम बिंदु तक सभी समय बिंदु के लिए '-1' मान लेता है और उसके बाद सभी समय बिंदुओं के लिए '0' लेता है। टीसी श्रृंखला के स्तर में अचानक वृद्धि या कमी की अनुमति देते हैं। जो तेजी से अपने पिछले स्तर पर लौटता है, यह प्रभाव एक चर द्वारा कैप्चर किया जाता है जो परिवर्तन बिंदु से पहले सभी अवलोकन के लिए मूल्य '0' लेता है और उसके बाद, $\alpha t\ (0<\alpha\ 0 - t_1)$ । रैम्प को एक चर के द्वारा सुचारू किया जाता है,, जो समय $t < t_0$ के लिए '-1', $t_0 < t < t_1$ के लिए $(t-t_0)/((t_1- t_0)-1)$ और समय बिंदु $t > t\ 1.</ t</t$ और समय बिंदु $t > t_1$ के बाद '0' ये तीन मान लेता है।

X-13 ARIMA आर्थिक श्रृंखला में मौसमी पैटर्न निर्धारित करने के लिए एसएआरआईएमए मॉडल का उपयोग करता है। एसएआरआईएमए मॉडल का क्रम विभिन्न मॉडलों के फिट होने की इन-सैंपल सौजन्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उपयुक्त सूचना मानदंडों का उपयोग करके सर्वोत्तम मॉडल का चयन किया जाता है। इसलिए, चयनित मॉडल औसत पैरामीटर अनुमानों के माध्यम से अंतर्निहित डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। कोविड़-19 महामारी की घटना ने इस प्रक्रिया में एक चुनौती पेश की।

कोविड़-19 महामारी ने कई क्षेत्रों में आर्थिक डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल दिया हो सकता है। आर्थिक डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया अब अधिक अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती है, जिसके विश्लेषण के लिए अधिक अनुकूल और लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

कोविड़-19 अवधि के दौरान लाए गए परिवर्तनों और उसके बाद कोविड़ के सामान्यीकरण ने मौसमी पैटर्न को प्रभावित किया हो सकता है। हालांकि, पिछले 2-3 वर्षों का सीमित डेटा एसएआरआईएमए मॉडल के माध्यम से इन बदलावों को पूरी तरह

से पकड़ने के लिए अपर्याप्त हैं। कोविड के बाद से मौसमी पैटर्न में संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए, मौसमी समायोजन की स्थिरता आउटलेयर समायोजन, कोविड-पूर्व अनुमानों से तुलना और सबसे हालिया अवधि के लिए मौसमी कारकों के वार्षिक अपडेट के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

एक्स-13 एआरआईएमए मॉडल में आउटलेयर समायोजन, विशेष रूप से कोविड अवधि के लिए, तीन प्रकार के आउटलेयर- एओ, टीसी और एलएस का उपयोग करके किया जाता है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन आउटलेयर का स्वचालित रूप से पता लगाया जाता है और भारत में आर्थिक घटनाओं के साथ उन्हें संरेखित करके उनकी प्रासंगिकता की पुष्टि की जाती है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व-महामारी अवधि से मौसमी कारकों की औसत सीमा के साथ नवीनतम अवधि से मौसमी कारकों की सीमा की तुलना करके मौसमी पैटर्न की जांच की जाती है।

अनुबंध – I

सारणी ए1-एम1: मासिक मौसमी कारकों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त समय अवधि

सेक्टर/चर का नाम	समय सीमा
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखला)	
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3) ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1) ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) ए.1.3.1 प्रचलन में मुद्रा ए.2.1 समग्र जमाराशियां (एससीबी) ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी) ए.2.1.2 सावधि जमाराशियां (एससीबी) ए.3.1 हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष (एससीबी) ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी) ए.3.2.1 ऋण, नकद, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (एससीबी) ए.3.2.2 गैर-खाद्य ऋण (एससीबी) ए.3.3 निवेश (एससीबी)	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
मूल्य सूचकांक [सीपीआई : 21 श्रृंखला और डब्ल्यू पीआई: 8 श्रृंखला]	
बी. सीपीआई (आधार: 2012 = 100) सभी वस्तुएं बी.1 सीपीआई - खाद्य और पेय पदार्थ बी.1.1 सीपीआई - अनाज और उत्पाद बी.1.2 सीपीआई - मांस और मछली बी.1.3 सीपीआई – अंडा बी.1.4 सीपीआई - दूध और उत्पाद बी.1.5 सीपीआई – फल बी.1.6 सीपीआई – सब्जियां बी.1.6.1 सीपीआई – आलू बी.1.6.2 सीपीआई – प्याज बी.1.6.3 सीपीआई – टमाटर बी.1.7 सीपीआई - दालें और उत्पाद बी.1.8 सीपीआई – मसाले बी.1.9 सीपीआई - गैर-मादक पेय बी.1.10 सीपीआई - तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। बी.2 सीपीआई - वस्त्र और जूते बी.3 सीपीआई –आवास बी.4 सीपीआई - विविध	जनवरी 2011 से मार्च 2024
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2001 = 100) सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100) सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100)	जनवरी 2000 से मार्च 2024
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार: 2011-12=100) सभी वस्तुएं डी. 1 डब्ल्यूपीआई - प्राथमिक वस्तुएं डी. 1.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य वस्तुएं डी.2 डब्ल्यूपीआई - ईंधन और ऊर्जा डी.3 डब्ल्यूपीआई - निर्मित उत्पाद डी.3.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण डी.3.3 डब्ल्यूपीआई - मूल धातुओं का विनिर्माण	अप्रैल 2012 से मार्च 2024

सेक्टर/चर का नाम	समय सीमा
औद्योगिक उत्पादन (23 श्रृंखला)	
ई. आईआईपी (आधार 2011-12 = 100) सामान्य सूचकांक	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
ई.1.1 आईआईपी - प्राथमिक वस्तुएँ ई.1.2 आईआईपी - पूंजीगत वस्तुएँ ई.1.3 आईआईपी - मध्यवर्ती वस्तुएँ ई.1.4 आईआईपी – अवसंरचना/ निर्माण वस्तुएँ ई.1.5 आईआईपी - उपभोक्ता वस्तुएँ ई.1.5.1 आईआईपी - उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ ई.1.5.2 आईआईपी - उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	अप्रैल 2012 से मार्च 2024
ई.2.1 आईआईपी -खनन ई. 2.2 आईआईपी - विनिर्माण	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
ई. 2.2.1 आईआईपी - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण ई. 2.2.2 आईआईपी - पेय पदार्थों का विनिर्माण ई. 2.2.3 आईआईपी - वस्त्रों का विनिर्माण ई. 2.2.4 आईआईपी - रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण ई. 2.2.5 आईआईपी - मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	अप्रैल 2012 से मार्च 2024
ई.2.3 आईआईपी - बिजली	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
ई.3 सीमेंट उत्पादन ई.4 इस्पात उत्पादन ई.5 कोयला उत्पादन ई.6 कच्चे तेल का उत्पादन ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन ई.8 उर्वरक उत्पादन ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	अप्रैल 2004 से मार्च 2024
सेवा क्षेत्र संकेतक (5 श्रृंखला)	
एफ.1 प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रित कार्गो एफ.2 रेलवे माल यातायात एफ.3 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) – घरेलू एफ.4 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) अंतरराष्ट्रीय	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
एफ.5 यात्री वाहन बिक्री (थोक)	अप्रैल 2004 से मार्च 2024
व्यापारिक लेन-देन (3 श्रृंखला)	
जी.1 निर्यात जी.2 आयात जी.3 गैर-तेल गैर-सोना और गैर-चांदी आयात	अप्रैल 1994 से मार्च 2024
भुगतान प्रणाली संकेतक (4 श्रृंखला)	
एच.1 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट	अप्रैल 2004 से मार्च 2024
एच.2 पेपर क्लियरिंग	अप्रैल 2005 से मार्च 2024
एच.3 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (आरईसी) एच.4 कार्ड	अप्रैल 2004 से मार्च 2024

सारणी ए1-एम2: औसत* चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के मासिक मौसमी कारक (प्रतिशत)

श्रृंखला का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फ़रवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखला)												
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	**101.0**	100.6	100.1	100.3	99.9	99.7	99.7	**99.3**	99.5	99.6	99.7	100.6
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	101.1	100.8	100.5	**101.6**	101.3	99.9	99.6	99.9	**97.9**	98.9	99.3	99.3
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	100.6	100.0	99.9	99.7	**99.2**	99.5	99.7	99.3	100.1	100.0	100.1	**101.9**
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	101.8	101.3	100.9	99.7	99.0	99.0	98.6	**98.3**	98.9	99.0	100.2	**103.4**
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा(आरएम)	101.4	101.9	101.5	100.3	99.1	98.5	**98.3**	98.8	99.2	99.1	99.0	**102.8**
ए.1.3.1 प्रचलन में मुद्रा	102.5	**102.7**	102.0	100.3	99.2	**98.1**	98.3	98.6	98.7	99.2	99.9	100.5
ए.2.1 सकल जमाराशियां (एससीबी)	**100.7**	100.1	99.9	100.2	99.8	100.3	99.9	99.6	99.8	99.6	**99.5**	100.5
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	100.7	98.5	99.4	98.3	**97.8**	103.2	98.8	98.7	100.6	98.5	98.8	**106.8**
ए.2.1.2 सावधि जमाराशियां (एससीबी)	**100.6**	100.2	100.0	100.3	100.0	100.1	100.1	99.8	99.7	99.7	**99.6**	99.8
ए.3.1 हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष (एससीबी)	100.6	100.2	101.8	99.6	101.0	100.9	99.8	100.7	**102.3**	98.5	97.3	**97.1**
ए.3.2 बैंक क्रेडिट (एससीबी)	100.6	100.0	99.9	99.4	**99.0**	100.0	99.6	99.5	100.3	100.1	100.1	**101.6**
ए.3.2.1 ऋण, नकद, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	100.5	100.0	99.9	99.4	**99.0**	100.1	99.6	99.6	100.3	100.1	100.1	**101.4**
ए.3.2.2 गैर-खाद्य ऋण (एससीबी)	100.7	99.9	99.9	99.5	**99.1**	100.0	99.7	99.4	100.2	99.9	100.1	**101.6**
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	99.5	100.1	100.4	101.3	**101.4**	101.2	100.9	100.1	99.0	98.9	99.1	**98.2**
मूल्य सूचकांक [सीपीआई: 21 श्रृंखला और थोक मूल्य सूचकांक: 8 श्रृंखला]												
बी. सीपीआई (आधार: 2012 = 100) सभी वस्तुएं	99.2	99.6	99.9	100.5	100.7	100.6	**100.9**	100.9	100.0	99.5	99.2	**99.0**
बी.1 सीपीआई - खाद्य और पेय पदार्थ	98.4	99.0	100.1	101.1	101.4	101.2	**101.7**	101.6	100.2	98.9	98.2	**98.1**
बी.1 .1 सीपीआई - अनाज और उत्पाद	99.8	99.7	**99.6**	99.8	100.0	100.1	100.2	**100.3**	100.2	100.3	100.1	100.0
बी.1 .2 सीपीआई - मांस और मछली	99.4	100.8	**102.7**	102.2	100.4	100.1	99.8	99.2	**98.7**	99.0	98.8	98.8
बी.1 .3 सीपीआई - अंडा	**96.6**	96.7	99.0	100.5	98.8	98.5	99.1	101.6	103.9	**104.3**	102.2	98.9
बी.1 .4 - सीपीआई - दूध और उत्पाद	99.8	100.0	100.1	100.1	**100.2**	100.1	100.1	100.1	99.9	99.9	99.9	**99.8**
बी.1 .5 सीपीआई - फल	102.9	102.9	102.1	**103.3**	102.6	99.9	99.2	98.7	97.7	96.5	**96.3**	97.7
बी.1 .6 सीपीआई - सब्जियां	89.5	91.9	97.7	105.6	107.4	109.1	**111.5**	111.1	102.1	94.5	90.9	**89.2**
बी.1 .6.1 सीपीआई - आलू	85.2	93.6	101.7	108.9	112.1	112.0	116.3	**116.8**	105.6	88.4	**79.7**	79.9
बी.1 .6.2 सीपीआई - प्याज	80.6	**76.1**	80.7	88.4	100.0	105.7	117.1	**132.2**	120.0	110.8	100.8	89.4
बी.1 .6.3 सीपीआई - टमाटर	77.4	86.7	105.3	**131.6**	121.4	109.7	118.9	119.6	96.9	83.8	75.5	**74.5**
बी.1 .7 सीपीआई - दलहन और उत्पाद	**98.7**	99.1	99.6	99.6	99.9	100.6	101.1	**101.4**	101.1	100.4	99.5	99.0
बी.1 .8 सीपीआई - मसाले	**99.5**	99.6	99.5	99.9	100.1	100.3	100.4	**100.5**	100.5	100.3	99.9	99.5
बी.1 .9 सीपीआई - गैर-मादक पेय	**99.9**	99.9	99.9	100.0	100.0	100.1	100.0	100.1	**100.1**	100.1	100.0	99.9
बी.1 .10 सीपीआई - तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि।	99.9	**99.9**	99.9	100.0	100.1	100.0	100.0	**100.1**	100.1	100.0	100.0	100.0
बी.2 सीपीआई - कपड़े और जूते	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.1	**100.1**	100.1	100.0	99.9	**99.9**
बी.3 सीपीआई - आवास	100.3	100.2	**99.3**	99.6	100.0	100.0	100.3	**100.4**	99.6	100.0	100.2	100.0
बी.4 सीपीआई - विविध	99.9	99.9	99.9	**100.2**	100.2	100.2	100.1	100.0	99.9	99.9	99.9	**99.8**
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2001 = 100)	99.4	99.5	99.9	100.8	100.6	100.5	**100.9**	100.8	100.0	99.7	99.1	**99.0**
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	99.2	99.4	99.7	100.0	100.5	100.5	100.9	**101.0**	100.5	99.9	99.4	**99.0**
सी.3 ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100)	99.2	99.5	99.8	100.1	100.5	100.5	100.8	**100.9**	100.5	99.9	99.4	**99.1**
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी वस्तुएं	99.8	100.0	100.0	100.4	100.3	100.2	100.5	**100.6**	99.7	**99.4**	99.4	99.5
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	99.2	99.4	100.1	101.2	101.5	100.9	101.7	**102.0**	99.5	98.5	98.2	**97.8**
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य पदार्थ	98.7	98.9	100.3	101.2	101.6	101.5	102.8	**102.8**	99.5	98.4	97.4	**97.0**
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और ऊर्जा	**99.3**	100.5	100.0	**100.7**	99.5	99.8	100.2	100.7	99.7	99.9	100.2	99.6
डी.3 डब्ल्यूपीआई – निर्मित उत्पाद	**100.4**	100.4	100.2	100.0	99.9	99.9	100.0	99.8	**99.6**	99.9	99.9	100.2
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	100.2	100.1	100.2	100.1	100.5	**100.5**	100.2	100.0	99.7	99.5	**99.4**	99.5

सारणी ए1-एम2: औसत* चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के मासिक मौसमी कारक (प्रतिशत) *(जारी)*

श्रृंखला का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फ़रवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	100.3	**100.6**	100.3	100.2	100.0	99.8	99.9	99.8	99.6	**99.5**	99.8	100.1
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई - डब्ल्यूपीआई - मूल धातुओं का विनिर्माण	100.9	**101.4**	100.7	99.5	99.2	99.8	99.7	99.2	**98.9**	100.0	100.1	100.7
औद्योगिक उत्पादन (23 श्रृंखला)												
ई. आईआईपी (आधार 2011-12 =ए51: ए72 100) सामान्य सूचकांक	**96.5**	100.7	98.6	97.4	97.4	97.6	99.7	98.3	103.1	103.3	98.4	**108.9**
ई.1.1 आईआईपी - प्राथमिक वस्तुएं	97.8	103.1	100.2	98.8	97.0	**94.3**	98.2	97.5	102.3	103.8	96.8	**110.2**
ई.1.2 आईआईपी - पूंजीगत वस्तुएं	**89.4**	97.3	99.7	95.4	96.7	102.4	98.1	97.2	100.9	100.3	101.5	**120.6**
ई.1.3 आईआईपी - मध्यवर्ती माल	97.6	100.3	98.3	101.3	99.8	98.6	99.0	97.8	102.0	101.9	**96.7**	**106.6**
ई.1.4 आईआईपी - बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान	98.7	102.2	100.1	97.9	97.5	96.1	99.5	**94.7**	101.9	104.0	99.6	**108.4**
ई.1.5 आईआईपी- उपभोक्ता वस्तुएं	**95.3**	97.9	95.7	98.5	97.9	101.5	99.7	101.8	**104.7**	103.2	99.1	104.6
ई.1.5.1 आईआईपी - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	**95.8**	99.4	97.8	100.8	99.5	105.9	**106.7**	98.6	96.8	98.2	96.1	104.0
ई.1.5.2 आईआईपी - उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	**95.0**	97.7	95.3	96.9	95.8	96.7	95.9	103.0	**109.9**	106.5	101.5	105.6
ई.2.1 आईआईपी - खनन	97.5	100.8	95.8	90.2	86.7	**86.7**	96.5	101.1	107.7	110.1	105.1	**122.2**
ई.2.2 आईआईपी - विनिर्माण	**95.5**	100.3	98.3	98.9	98.4	98.7	99.3	98.7	103.0	102.8	98.4	**107.7**
ई.2.2.1 आईआईपी - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	96.0	89.0	**86.3**	90.8	89.5	89.2	93.6	105.8	**121.2**	118.3	110.7	108.7
ई.2.2.2 आईआईपी - पेय पदार्थों का विनिर्माण	112.2	**121.6**	106.8	92.5	**88.7**	91.2	90.2	88.8	93.1	97.8	100.9	117.6
ई.2.2.3 आईआईपी - वस्त्रों का विनिर्माण	97.7	98.9	98.3	100.5	101.2	100.9	100.9	99.9	**102.7**	101.2	**96.4**	101.7
ई.2.2.4 आईआईपी - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	95.0	101.0	100.0	**104.0**	101.7	101.0	100.3	97.7	101.0	101.1	**93.5**	103.4
ई.2.2.5 आईआईपी - मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	98.3	100.5	97.1	100.8	98.7	100.4	102.3	99.6	**94.2**	100.7	100.3	**107.3**
ई.2.3 आईआईपी - बिजली	100.7	**107.2**	103.9	104.7	104.3	101.3	101.2	91.0	95.2	97.0	**90.9**	101.9
ई.3 सीमेंट उत्पादन	103.5	102.5	103.0	95.0	90.5	**90.4**	98.1	93.2	102.0	105.0	101.4	**115.6**
ई.4 इस्पात उत्पादन	98.2	102.5	98.7	97.5	98.3	97.1	99.6	**96.4**	102.0	104.2	98.5	**107.5**
ई.5 कोयला उत्पादन	93.0	94.4	89.7	82.2	**80.1**	80.2	93.6	103.0	111.9	116.7	114.2	**140.9**
ई.6 कच्चे तेल का उत्पादन	98.9	102.4	99.2	102.0	101.4	97.8	101.5	98.2	101.5	101.6	**92.4**	**103.0**
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	97.1	101.2	99.5	100.6	97.7	**93.4**	100.9	100.5	103.4	104.1	95.3	**106.4**
ई.8 उर्वरक उत्पादन	**83.0**	96.7	100.5	103.4	105.1	103.2	**106.2**	103.5	104.8	103.5	93.6	96.2
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	96.4	100.5	98.8	102.4	102.4	99.2	**102.9**	99.8	102.2	102.6	**91.5**	101.4
सेवा क्षेत्र संकेतक (5 श्रृंखला)												
एफ.1 प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रित कार्गो	100.3	102.6	97.9	99.0	97.1	**92.9**	98.6	99.0	103.1	104.4	95.9	**109.6**
एफ.2 रेलवे माल यातायात	97.4	101.7	98.3	97.6	95.5	**93.5**	97.9	98.2	103.3	105.6	97.8	**113.0**
एफ.3 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) - घरेलू	99.8	**107.5**	99.2	96.2	96.3	**93.7**	99.5	100.3	106.8	103.6	97.5	100.1
एफ.4 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) - अंतर्राष्ट्रीय	94.4	98.5	98.1	102.3	102.2	**92.9**	95.1	97.9	108.5	**110.8**	96.6	102.9
एफ.5 यात्री वाहन बिक्री (थोक)	96.8	93.4	**90.1**	99.2	98.2	105.3	**113.2**	100.8	90.3	104.5	101.0	106.6
व्यापारिक लेन-देन (3 श्रृंखला)												
जी.1 निर्यात	98.0	102.3	97.6	98.2	97.0	99.6	95.8	**95.3**	103.3	98.0	99.0	**115.9**
जी.2 आयात	96.3	102.8	98.7	100.6	99.3	99.1	102.7	99.6	104.3	97.5	**93.8**	**105.5**
जी.3 गैर-तेल गैर-सोना और गैर-चांदी आयात	96.6	99.7	100.9	102.5	99.2	103.0	101.0	98.2	**104.7**	99.2	**92.1**	103.2
भुगतान प्रणाली संकेतक (4 श्रृंखला)												
एच.1 आरटीजीएस	94.2	96.2	103.4	98.3	92.8	100.6	96.0	93.5	106.5	99.2	**91.8**	**127.8**
एच.2 पेपर क्लियरिंग	108.1	102.0	95.9	99.9	94.3	**93.7**	99.5	95.0	101.8	97.9	95.7	**115.8**
एच.3 आरईसी	98.2	96.6	99.9	98.1	96.4	98.6	100.8	**92.6**	103.6	97.1	93.3	**125.3**
एच.4 कार्ड	99.8	103.7	99.5	103.0	101.6	95.0	**109.7**	98.8	101.8	99.9	**87.9**	99.3

*: सामान्यत पिछले दस वर्षों के मासिक मौसमी कारकों का औसत। यहां, औसत मासिक मौसमी कारकों की गणना पिछले 10 वर्षों (यानी, अप्रैल 2014 से मार्च 2024) के आधार पर की गई है। 'मोटे अक्षरों' में चिह्नित संख्याएँ संबंधित श्रृंखला की उच्चतम और निम्नतम संख्या हैं।

सारणी ए1-एम3: मासिक मौसमी कारकों की सीमा (उच्चतम और निम्नतम के बीच का अंतर)

(प्रतिशत अंक)

श्रृंखला \ वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	औसत सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखला)											
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3.7	3.8	3.9	4.1	4.1	4.1	3.8	3.5	3.4	3.6	3.7
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	3.0	3.2	3.4	3.6	3.5	3.2	2.6	2.0	1.4	1.2	2.7
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	4.1	4.5	5.3	5.9	6.2	6.1	5.6	5.1	4.8	4.6	5.1
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.6
ए.1.3.1 प्रचलन में मुद्रा	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	4.4	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5
ए.2.1 सकल जमाराशियां (एससीबी)	1.3	1.1	1.4	1.7	1.7	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	5.6	7.4	9.5	11.5	12.2	11.6	10.1	8.8	7.8	7.5	9.1
ए.2.1.2 सावधि जमाराशियां (एससीबी)	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0
ए.3.1 हाथ में नकद और आरबीआई के पास शेष (एससीबी)	3.6	4.7	5.5	5.5	5.8	6.2	6.7	6.4	7.1	7.7	5.2
ए.3.2 बैंक क्रेडिट (एससीबी)	2.6	2.8	3.2	3.4	3.5	3.2	2.6	2.0	1.5	1.4	2.6
ए.3.2.1 ऋण, नकद, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.0	2.5	1.9	1.4	1.4	2.4
ए.3.2.2 गैर-खाद्य ऋण (एससीबी)	2.5	3.0	3.5	3.8	3.9	3.5	2.8	1.9	1.2	1.4	2.6
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.2
मूल्य सूचकांक [सीपीआई: 21 श्रृंखला और डब्लूपीआई: 8 श्रृंखला]											
बी. सीपीआई (आधार: 2012 = 100) सभी वस्तुएं	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.9
बी.1 सीपीआई - खाद्य और पेय पदार्थ	4.0	3.8	3.7	3.5	3.6	3.7	3.8	3.6	3.4	3.2	3.6
बी.1 .1 सीपीआई - अनाज और उत्पाद	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	0.7
बी.1 .2 सीपीआई - मांस और मछली	3.2	3.2	3.2	3.4	3.8	4.2	4.6	4.9	5.2	5.4	3.9
बी.1 .3 सीपीआई - अंडा	7.3	7.0	6.8	6.6	6.7	7.1	7.8	8.5	9.4	9.9	7.7
बी.1 .4 सीपीआई - दूध और उत्पाद	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
बी.1 .5 सीपीआई - फल	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.8	7.3	7.7	8.1	8.2	6.9
बी.1 .6 सीपीआई - सब्जियां	23.7	22.7	22.1	21.7	22.6	23.6	24.5	24.3	23.5	22.4	22.3
बी.1 .6.1 सीपीआई - आलू	37.0	36.6	35.5	34.8	35.7	37.6	38.5	39.9	40.3	40.2	37.1
बी.1 .6.2 सीपीआई - प्याज	43.9	42.4	43.9	48.6	55.8	62.4	66.8	67.9	66.3	63.7	56.2
बी.1 .6.3 सीपीआई - टमाटर	63.7	62.5	60.9	59.7	57.9	56.4	55.4	54.1	52.2	53.9	57.2
बी.1 .7 सीपीआई - दलहन और उत्पाद	3.2	3.4	3.3	3.1	2.7	2.2	2.0	2.3	2.7	2.9	2.7
बी.1 .8 सीपीआई - मसाले	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.9	1.4	2.0	2.5	1.1
बी.1 .9 सीपीआई - गैर-मादक पेय	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
बी.1 .10 सीपीआई - तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि।	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
बी.2 सीपीआई - कपड़े और जूते	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
बी.3 सीपीआई - आवास	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
बी.4 सीपीआई - विविध	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2001 = 100)	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0
सी.3 ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100)	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी वस्तुएं	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	4.9	5.0	4.8	4.6	4.8	4.7	4.5	4.1	3.9	3.7	4.2
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य पदार्थ	5.6	5.5	5.5	5.8	6.3	6.6	6.6	6.2	5.8	5.4	5.8
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और ऊर्जा	2.9	3.0	2.6	2.0	1.6	1.2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.4
डी.3 डब्ल्यूपीआई – निर्मित उत्पाद	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	0.8
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.2

सारणी ए1-एमउ: मासिक मौसमी कारकों की सीमा (उच्चतम और निम्नतम के बीच अंतर) *(जारी)*

(प्रतिशत अंक)

श्रृंखला \ वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	औसत सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.0
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई - मूल धातुओं का विनिर्माण	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	2.4
औद्योगिक उत्पादन (23 श्रृंखला)											
ई. आईआईपी (आधार 2011-12 = 100) सामान्य सूचकांक	12.7	12.8	13.0	13.2	13.2	12.9	12.4	11.9	11.4	11.3	12.5
ई.1.1 आईआईपी - प्राथमिक वस्तुएं	13.5	13.8	14.2	15.1	16.0	16.7	17.2	17.5	17.6	17.4	15.9
ई.1.2 आईआईपी - पूंजीगत वस्तुएं	35.9	34.4	32.3	31.1	30.1	29.7	29.5	29.5	29.7	29.7	31.2
ई.1.3 आईआईपी - मध्यवर्ती माल	10.4	10.5	10.4	10.3	10.4	10.2	9.9	9.5	9.2	8.9	9.9
ई.1.4 आईआईपी - बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान	12.3	12.6	13.2	13.8	14.2	14.2	14.3	14.3	14.3	14.1	13.7
ई.1.5 आईआईपी - उपभोक्ता वस्तुएं	10.8	10.3	9.8	9.5	9.5	9.4	10.1	10.7	11.2	11.3	9.5
ई.1.5.1 आईआईपी - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	13.5	12.9	11.8	11.0	11.0	10.7	10.3	9.9	9.9	10.1	10.8
ई.1.5.2 आईआईपी - उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	13.2	13.0	13.5	14.2	14.7	15.3	15.9	16.6	18.5	20.1	14.9
ई.2.1 आईआईपी - खनन	31.1	32.0	33.0	34.8	36.4	37.7	38.1	38.2	38.2	38.0	35.5
ई.2.2 आईआईपी - विनिर्माण	12.3	12.6	12.6	12.8	12.8	12.7	12.4	11.9	11.5	11.2	12.3
ई.2.2.1 आईआईपी - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	36.1	36.1	36.5	36.7	36.4	35.3	34.6	33.3	32.5	32.0	35.0
ई.2.2.2 आईआईपी - पेय पदार्थों का विनिर्माण	51.3	46.0	39.6	34.7	31.2	28.9	28.8	26.9	26.2	26.4	32.9
ई.2.2.3 आईआईपी - वस्त्रों का विनिर्माण	7.5	6.6	5.5	5.4	6.0	6.6	7.1	7.2	7.2	7.1	6.3
ई.2.2.4 आईआईपी - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	10.8	10.9	11.5	11.7	11.5	10.7	10.8	10.7	10.5	10.4	10.5
ई.2.2.5 आईआईपी - मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	14.0	14.8	15.2	15.3	14.7	13.7	12.1	11.1	10.2	9.7	13.1
ई.2.3 आईआईपी - बिजली	13.5	14.6	15.8	16.8	17.8	18.2	19.3	19.8	19.7	19.3	16.3
ई.3 सीमेंट उत्पादन	22.5	22.4	22.9	24.3	26.0	27.7	28.7	28.5	28.1	27.4	25.2
ई.4 इस्पात उत्पादन	9.8	9.7	10.2	11.0	11.9	12.5	12.4	12.0	11.6	11.3	11.1
ई.5 कोयला उत्पादन	55.1	56.4	58.8	61.9	64.1	64.9	64.1	62.8	61.4	60.1	60.7
ई.6 कच्चे तेल का उत्पादन	10.3	10.5	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	10.4	9.7	10.0	11.0	12.5	14.0	15.3	16.1	15.9	15.4	13.0
ई.8 उर्वरक उत्पादन	26.4	24.6	22.9	22.0	22.2	22.6	23.0	23.0	22.8	22.2	23.2
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	11.0	10.9	10.9	11.0	11.3	11.6	11.9	11.9	12.0	11.9	11.4
सेवा क्षेत्र संकेतक (5 श्रृंखला)											
एफ.1 प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रित कार्गो	14.9	15.4	15.9	16.3	16.9	17.4	17.6	17.6	17.7	17.5	16.7
एफ.2 रेलवे माल यातायात	18.2	18.0	18.2	18.9	19.4	19.8	20.1	20.5	20.7	21.0	19.5
एफ.3 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) - घरेलू	19.7	17.3	14.9	12.9	11.8	11.7	12.3	13.0	13.8	14.4	13.9
एफ.4 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) – अंतरराष्ट्रीय	19.4	20.0	20.2	20.6	20.2	19.4	18.4	17.5	16.2	15.2	17.9
एफ.5 यात्री वाहन बिक्री (थोक)	18.8	19.0	20.3	21.8	24.5	26.4	27.1	26.4	25.4	25.8	23.1
व्यापारिक लेन-देन (3 श्रृंखला)											
जी.1 निर्यात	19.1	18.4	18.5	20.1	21.5	22.4	22.3	22.2	21.6	21.5	20.6
जी.2 आयात	12.8	13.7	13.7	13.5	13.0	13.1	11.5	10.2	9.6	10.0	11.7
जी.3 गैर-तेल गैर-सोना और गैर-चांदी आयात	12.6	13.1	13.1	12.9	12.6	12.7	12.5	12.4	12.3	12.5	12.7
भुगतान प्रणाली संकेतक (4 श्रृंखला)											
एच.1 आरटीजीएस	43.3	42.7	40.6	38.8	37.1	35.3	33.2	32.7	31.8	30.8	36.0
एच.2 पेपर क्लियरिंग	24.3	23.1	22.3	22.3	22.2	21.9	22.2	22.7	22.7	22.7	22.0
एच.3 आरईसी	37.5	36.9	35.8	34.3	33.3	32.1	30.6	29.5	29.1	28.5	32.7
एच.4 कार्ड	19.6	20.1	20.5	21.2	21.7	22.5	22.9	23.1	23.0	22.9	21.7

टिप्पणियां: औसत मौसमी कारक सीमा पिछले दस वर्षों के लिए औसत मौसमी कारकों की सीमा है; सीमा की गणना मासिक मौसमी कारकों के अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर के रूप में की जाती है।

सारणी ए1-एम4: सभी मासिक संकेतकों के प्रमुख डायग्नोस्टिक्स

चर का नाम	मूल शृंखला में मौसम		अवशिष्ट मौसमी		गुणवत्ता निदान	
	एफ परीक्षण पी-मान	किलोवैट परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण 3 वर्ष पी-मान	एम7	प्रश्न
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम 3)	0.00	0.00	1.00	0.73	0.32	0.31
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	0.00	0.00	1.00	0.74	0.39	0.33
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	0.00	0.00	1.00	1.00	0.39	0.30
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	0.00	0.00	0.96	0.02	0.28	0.26
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	0.00	0.00	0.45	0.99	0.28	0.22
ए.1.3.1 प्रचलन में मुद्रा	0.00	0.00	0.58	0.46	0.20	0.16
ए.2.1 सकल जमाराशियां (एससीबी)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.55	0.37
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	0.00	0.00	0.76	0.36	0.48	0.57
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.57	0.33
ए.3.1 हाथ में नकदी और आरबीआई के पास शेष (एससीबी)	0.00	0.00	0.86	0.22	1.46	0.93
ए.3.2 बैंक क्रेडिट (एससीबी)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.44	0.30
ए.3.2.1 ऋण, नकद, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.43	0.31
ए.3.2.2 गैर-खाद्य ऋण (एससीबी)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.71	0.46
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	0.00	0.00	0.88	1.00	0.43	0.31
बी. सीपीसी (आधार: 2012 = 100) सभी वस्तुएं	0.00	0.00	1.00	0.88	0.31	0.33
बी.1 सीपीसी - खाद्य और पेय पदार्थ	0.00	0.00	1.00	0.96	0.26	0.35
बी.1.1 सीपीसी - अनाज और उत्पाद	0.00	0.00	1.00	0.96	0.87	0.50
बी.1.2 सीपीसी - मांस और मछली	0.00	0.00	0.97	0.74	0.46	0.48
बी.1.3 सीपीआई - अंडा	0.00	0.00	1.00	0.95	0.39	0.31
बी.1.4 सीपीआई - दूध और उत्पाद	0.00	0.00	0.95	1.00	1.34	0.59
बी.1.5 सीपीआई - फल	0.00	0.00	0.99	0.99	0.26	0.27
बी.1.6 सीपीआई - सब्जियां	0.00	0.00	0.99	0.87	0.26	0.32
बी.1.6.1 सीपीआई - आलू	0.00	0.00	1.00	0.85	0.23	0.33
बी.1.6.2 सीपीआई - प्याज	0.00	0.00	0.85	1.00	0.43	0.36
बी.1.6.3 सीपीआई - टमाटर	0.00	0.00	0.76	0.95	0.50	0.83
बी.1.7 सीपीआई - दलहन और उत्पाद	0.00	0.00	1.00	1.00	0.70	0.53
बी.1.8 सीपीआई - मसाले	0.00	0.00	0.99	0.96	1.16	0.71
बी.1.9 सीपीआई - गैर-मादक पेय	0.00	0.00	1.00	0.04	1.04	0.51
बी.1.10 सीपीआई - तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि।	0.00	0.00	0.95	0.93	1.57	0.73
बी.2 सीपीआई - कपड़े और जूते	0.00	0.00	0.97	1.00	1.39	0.75
बी.3 सीपीआई - आवास	0.00	0.00	0.92	0.98	0.40	0.38
बी.4 सीपीआई - विविध	0.00	0.00	1.00	0.84	1.02	0.49
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2001 = 100)	0.00	0.00	0.98	0.87	0.23	0.23
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	0.00	0.00	1.00	0.94	0.26	0.31
सी.3 ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100)	0.00	0.00	1.00	0.90	0.26	0.28
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार: 2011-12=100) सभी वस्तुएं	0.00	0.00	1.00	1.00	0.46	0.44
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	0.00	0.00	0.99	1.00	0.33	0.39
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य पदार्थ	0.00	0.00	0.77	0.95	0.30	0.34
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और ऊर्जा	0.00	0.00	1.00	1.00	1.49	0.74
डी.3 डब्ल्यूपीआई – निर्मित उत्पाद	0.00	0.00	1.00	0.96	0.69	0.52
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00	1.00	0.94	0.96	0.68
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00	1.00	1.00	1.16	0.70

सारणी ए1-एम4: सभी मासिक संकेतकों के प्रमुख डायग्नोस्टिक्स *(जारी)*

चर का नाम	मूल श्रृंखला में मौसम		अवशिष्ट मौसमी		गुणवत्ता निदान	
	एफ परीक्षण पी-मान	किलोवैट परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण 3 वर्ष पी-मान	एम7	प्रश्न
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई - मूल धातुओं का विनिर्माण	0.00	0.00	0.99	0.95	0.89	0.57
डी.3.4 डब्ल्यूपीआई - मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण	0.07	0.04	1.00	0.97	1.90	0.85
ई. आईआईपी (आधार 2011-12 = 100) सामान्य सूचकांक	0.00	0.00	0.22	0.90	0.16	0.24
ई.1.1 आईआईपी - प्राथमिक वस्तुएं	0.00	0.00	0.20	0.73	0.27	0.74
ई.1.2 आईआईपी - पूंजीगत वस्तुएं	0.00	0.00	0.33	0.66	0.31	0.51
ई.1.3 आईआईपी - मध्यवर्ती माल	0.00	0.00	0.37	0.50	0.37	0.43
ई.1.4 आईआईपी - बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान	0.00	0.00	0.34	0.61	0.47	0.49
ई.1.5 आईआईपी - उपभोक्ता वस्तुएं	0.00	0.00	0.43	0.75	0.50	0.59
ई.1.5.1 आईआईपी - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	0.00	0.00	0.14	0.44	0.41	0.44
ई.1.5.2 आईआईपी - उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	0.00	0.00	0.44	0.88	0.40	0.73
ई.2.1 आईआईपी - खनन	0.00	0.00	0.80	0.92	0.24	0.36
ई.2.2 आईआईपी - विनिर्माण	0.00	0.00	0.18	0.83	0.21	0.26
ई.2.2.1 आईआईपी - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00	1.00	0.32	0.18	0.44
ई.2.2.2 आईआईपी - पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.00	0.00	0.52	0.96	0.54	0.46
ई.2.2.3 आईआईपी - वस्त्रों का विनिर्माण	0.00	0.00	0.34	0.89	0.60	0.65
ई.2.2.4 आईआईपी - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00	0.49	1.00	0.52	0.75
ई.2.2.5 आईआईपी - मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	0.00	0.00	0.30	0.76	0.60	0.60
ई.2.3 आईआईपी - बिजली	0.00	0.00	0.46	0.64	0.52	0.56
ई.3 सीमेंट उत्पादन	0.00	0.00	0.42	0.34	0.23	0.34
ई.4 इस्पात उत्पादन	0.00	0.00	0.49	0.56	0.47	0.58
ई.5 कोयला उत्पादन	0.00	0.00	0.61	0.90	0.12	0.29
ई.6 कच्चे तेल का उत्पादन	0.00	0.00	0.88	1.00	0.17	0.28
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	0.00	0.00	0.94	0.80	0.46	0.73
ई.8 उर्वरक उत्पादन	0.00	0.00	0.47	0.74	0.29	0.61
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	0.00	0.00	0.92	0.88	0.26	0.39
एफ.1 कार्गो प्रमुख बंदरगाहों नियंत्रित करना	0.00	0.00	0.95	1.00	0.30	0.50
एफ.2 रेलवे माल यातायात	0.00	0.00	0.53	0.98	0.13	0.32
एफ.3 हवाई जहाज से यात्रा करनेवाले (किमी) - घरेलू	0.00	0.00	0.22	0.72	0.30	0.32
एफ.4 हवाई जहाज से यात्रा करनेवाले (किमी) - अंतर्राष्ट्रीय	0.00	0.00	0.64	0.88	0.36	0.53
एफ.5 यात्री वाहन बिक्री (थोक)	0.00	0.00	0.79	0.34	0.40	0.39
जी.1 निर्यात	0.00	0.00	0.64	0.67	0.37	0.52
जी.2 आयात	0.00	0.00	0.99	0.86	0.83	0.80
जी.3 गैर-तेल गैर-सोना और गैर-चांदी आयात	0.00	0.00	1.00	0.99	0.59	0.71
एच.1 आरटीजीएस	0.00	0.00	0.56	0.78	0.39	0.37
एच.2 पेपर क्लियरिंग	0.00	0.00	0.12	0.37	0.30	0.76
एच.3 आरईसी	0.00	0.00	0.79	0.31	0.41	0.34
एच.4 कार्ड	0.00	0.00	0.04	0.39	0.37	0.43

टिप्पणियां : 1. मूल श्रृंखला में मौसमीता के लिए परीक्षण: स्थिरता मानते हुए मौसमीता की उपस्थिति के लिए एफ-परीक्षण और स्थिर मौसमीता के लिए क्रुस्कल और वालिस परीक्षण (एक गैर-पैरामीट्रिक परीक्षण)।

2. मौसमी रूप से समायोजित श्रृंखला में मौसमीता के लिए परीक्षण: स्थिरता मानते हुए पूर्ण नमूने और नवीनतम 3 वर्षों के लिए मौसमी की उपस्थिति के लिए एफ परीक्षण।

3. ए7 स्थिर मौसमीता की मात्रा के सापेक्ष मौजूद अस्थिर मौसमीता की मात्रा से मेल खाता है (स्वीकार्य सीमा 0 और 1 के बीच है)। हालांकि, एम डायग्नोस्टिक्स को एकल गुणवत्ता नियंत्रण संकेतक - क्यू में एकत्रित किया जाता है, जो समायोजन का समग्र मूल्यांकन देता है (स्वीकार्य सीमा 0 और 1 के बीच है)।

सारणी ए1-एम5: 2023-24 के लिए चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के मासिक मौसमी कारक (प्रतिशत)

श्रृंखला का नाम	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू	नवं	दिसं	जन	फ़र	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखला)												
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	100.7	100.2	99.9	**100.7**	100.0	99.5	99.5	**99.4**	100.2	99.8	99.8	100.3
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	101.6	100.0	100.0	101.2	101.2	99.7	99.1	100.2	98.1	**98.0**	99.4	**101.6**
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	100.1	**99.6**	99.7	100.2	99.6	99.6	100.1	99.7	**100.7**	100.0	99.9	100.6
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	101.4	101.1	101.1	100.1	98.8	98.3	**98.0**	98.4	100.1	99.7	100.3	**102.6**
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	100.6	**102.5**	102.0	100.9	99.3	98.4	**98.1**	98.7	99.1	99.1	99.1	102.2
ए.1.3.1 प्रचलन में मुद्रा	102.4	**102.5**	102.2	100.4	99.5	98.4	**98.2**	98.4	98.4	99.3	99.8	100.7
ए.2.1 सकल जमाराशियां (एससीबी)	**100.6**	99.8	100.0	100.5	99.9	**100.6**	99.9	99.6	100.3	99.5	**99.5**	99.8
ए.2.1.1 मांग जमा (एससीबी)	100.9	98.4	98.1	99.2	**97.1**	103.3	99.6	98.4	101.7	99.1	99.3	**104.6**
ए.2.1.2 सावधि जमाराशियाँ (एससीबी)	100.6	99.9	100.1	**100.6**	100.2	100.4	100.0	99.7	100.1	99.5	**99.4**	99.5
ए.3.1 हाथ में नकदी और आरबीआई के पास शेष (एससीबी)	100.6	100.8	100.9	100.8	**103.1**	102.4	100.1	100.2	101.4	98.6	**95.4**	95.6
ए.3.2 बैंक क्रेडिट (एससीबी)	100.2	99.5	99.5	99.9	**99.3**	100.4	100.0	100.1	**100.7**	100.0	99.9	100.4
ए.3.2.1 ऋण, नकद, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	100.2	99.5	99.5	99.8	**99.3**	100.3	100.0	100.1	**100.7**	100.1	99.9	100.4
ए.3.2.2 गैर-खाद्य ऋण (एससीबी)	100.1	**99.2**	99.6	100.3	99.7	100.2	100.3	100.3	**100.6**	99.8	99.7	100.0
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	99.7	99.9	100.5	101.8	101.4	**101.8**	100.9	99.3	98.7	**98.3**	98.9	98.9
मूल्य सूचकांक [सीपीआई: 21 श्रृंखला और डब्ल्यूपीआई: 8 श्रृंखला]												
बी. सीपीआई (आधार: 2012 = 100) सभी वस्तुएं	99.3	99.8	100.1	100.5	100.5	100.4	**100.8**	100.8	100.0	99.5	99.3	**99.1**
बी.1 सीपीआई - खाद्य और पेय पदार्थ	98.6	99.2	100.2	100.9	101.2	100.7	101.6	**101.6**	100.2	99.0	98.5	**98.4**
बी.1 .1 सीपीआई - अनाज और उत्पाद	99.7	99.7	**99.4**	99.6	99.9	100.0	100.2	100.4	100.4	**100.4**	100.3	100.1
बी.1 .2 सीपीआई - मांस और मछली	99.2	101.3	**103.6**	102.3	99.8	100.5	100.6	99.2	**98.1**	98.2	98.3	98.7
बी.1 .3 सीपीआई - अंडा	**95.6**	96.0	100.1	100.8	97.8	97.8	98.9	101.8	104.6	**105.5**	103.0	98.5
बी.1 .4 सीपीआई - दूध और उत्पाद	100.0	**100.1**	100.0	100.0	100.1	100.0	100.0	100.0	99.9	**99.9**	100.0	100.0
बी.1 .5 सीपीआई - फल	103.6	103.2	101.8	**104.0**	103.0	100.1	99.5	98.5	97.4	95.8	**95.8**	97.4
बी.1 .6 सीपीआई - सब्जियां	**89.2**	91.9	98.6	104.1	106.2	107.9	111.5	**111.5**	102.3	94.4	91.4	90.2
बी.1 .6.1 सीपीआई - आलू	83.0	94.1	102.5	111.3	114.1	113.4	**117.3**	116.1	104.2	87.4	**77.0**	78.2
बी.1 .6.2 सीपीआई - प्याज	79.7	**74.9**	79.7	88.9	95.4	100.4	115.3	**138.7**	122.7	110.1	102.6	89.8
बी.1 .6.3 सीपीआई - टमाटर	**74.3**	82.2	103.3	126.2	120.7	110.9	**128.3**	119.4	98.7	84.2	77.3	74.9
बी.1 .7 सीपीआई - दलहन और उत्पाद	99.0	99.2	99.4	99.3	99.4	100.8	101.4	**101.7**	101.3	100.4	99.4	**98.8**
बी.1 .8 सीपीआई - मसाले	99.1	99.3	99.1	99.7	100.4	101.0	101.1	**101.2**	100.8	100.4	99.5	**98.6**
बी.1.9 सीपीआई - गैर-मादक पेय	**99.9**	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.1	**100.1**	100.1	100.0	99.9
बी.1.10 सीपीआई - तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि।	**99.9**	100.0	100.0	100.0	**100.1**	100.1	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
बी.2 सीपीआई - कपड़े और जूते	**100.0**	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	**100.1**	100.0	100.0	100.0	100.0
बी.3 सीपीआई - आवास	**100.5**	100.4	**99.4**	99.7	100.1	99.8	100.4	100.4	99.6	99.8	100.2	99.8
बी.4 सीपीआई - विविध	100.0	100.0	100.0	**100.2**	100.2	100.1	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	**99.9**
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2001 = 100)	99.5	99.5	100.0	**100.6**	100.5	100.4	100.8	100.7	100.0	99.6	99.2	**99.1**
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	99.3	99.5	99.7	**99.9**	100.2	100.2	100.7	101.0	100.6	100.1	99.6	**99.3**
सी.3 ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87 = 100)	99.3	99.6	99.7	**99.9**	100.2	100.2	100.7	100.9	100.6	100.0	99.6	**99.3**
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी वस्तुएं	100.3	100.0	100.3	**100.3**	100.2	99.9	100.4	100.6	99.6	99.3	99.3	**99.7**
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	100.0	99.6	100.2	**100.6**	101.0	100.0	101.5	102.0	99.4	98.7	98.2	**98.7**
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य पदार्थ	99.4	99.2	100.5	**100.5**	101.0	101.0	103.0	102.8	99.2	98.2	97.6	**97.6**
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और ऊर्जा	100.0	100.1	99.9	**100.3**	99.5	99.5	99.9	101.0	100.1	99.5	100.1	**100.2**

सारणी ए1-एम5: 2023-24 के लिए चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के मासिक मौसमी कारक (प्रतिशत) *(जारी)*

श्रृंखला का नाम	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू	नवं	दिसं	जन	फ़र	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डी.3 डब्ल्यूपीआई – निर्मित उत्पाद	100.7	100.6	100.2	**99.8**	99.9	99.8	99.8	99.7	99.5	99.8	99.9	**100.3**
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	100.7	100.5	100.5	**100.1**	100.5	100.3	99.8	99.9	99.4	99.4	99.2	**99.8**
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	100.5	100.6	100.2	**100.0**	99.8	99.7	100.0	99.8	99.7	99.6	99.9	**100.2**
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई - डब्ल्यूपीआई - मूल धातुओं का विनिर्माण	101.2	101.9	100.3	**99.1**	99.4	99.6	99.5	99.0	98.8	99.8	100.4	**101.0**
औद्योगिक उत्पादन (23 श्रृंखला)												
ई. आईआईपी (आधार 2011-12 =एर51: एर72 100) सामान्य सूचकांक	97.1	100.0	99.1	97.9	97.2	**96.9**	98.9	98.3	103.8	104.0	98.2	**108.2**
ई.1.1 आईआईपी - प्राथमिक वस्तुएं	98.4	103.9	100.5	99.1	96.7	**93.4**	96.9	96.1	102.0	104.0	98.2	**110.8**
ई.1.2 आईआईपी - पूंजीगत वस्तुएं	**89.1**	97.0	100.3	96.8	97.9	103.6	98.9	96.7	98.9	101.4	100.1	**118.9**
ई.1.3 आईआईपी - मध्यवर्ती माल	97.8	101.0	98.6	101.1	99.8	98.0	99.5	98.0	102.1	102.8	**96.0**	**105.0**
ई.1.4 आईआईपी - बुनियादी ढांचा/निर्माण सामान	98.2	100.2	97.7	97.1	98.5	97.5	100.4	**94.4**	102.7	105.1	99.5	**108.5**
ई.1.5 आईआईपी - उपभोक्ता वस्तुएं	96.0	97.1	**95.6**	100.2	98.2	101.0	97.3	103.0	**106.9**	103.4	97.7	103.7
ई.1.5.1 आईआईपी - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	**95.9**	99.0	99.1	102.2	99.9	**106.0**	105.3	98.2	96.0	97.8	96.3	104.4
ई.1.5.2 आईआईपी - उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	97.1	95.5	95.8	98.5	95.5	95.2	**93.9**	105.7	**114.0**	106.7	98.7	103.1
ई.2.1 आईआईपी - खनन	97.9	101.3	95.5	89.8	85.7	**84.9**	96.3	100.8	107.6	110.5	106.6	**122.9**
ई.2.2 आईआईपी - विनिर्माण	**95.7**	99.8	98.5	99.3	98.7	98.2	98.2	98.9	104.0	103.7	97.9	**107.0**
ई.2.2.1 आईआईपी - खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	99.5	90.2	**86.9**	90.6	90.7	87.2	91.9	107.5	**118.9**	117.2	110.5	109.0
ई.2.2.2 आईआईपी - पेय पदार्थों का विनिर्माण	105.2	**115.4**	109.4	98.1	91.4	91.6	**89.0**	90.1	92.9	99.5	102.3	114.6
ई.2.2.3 आईआईपी - वस्त्रों का विनिर्माण	98.0	98.6	98.4	100.1	99.7	99.9	101.0	100.0	**103.7**	102.0	**96.6**	102.1
ई.2.2.4 आईआईपी - रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	96.1	102.5	102.1	**104.1**	101.6	100.3	99.8	97.0	100.6	100.4	**93.7**	101.3
ई.2.2.5 आईआईपी - मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	96.7	99.8	97.8	102.1	98.6	100.5	102.8	99.8	**94.8**	102.1	100.2	**104.5**
ई.2.3 आईआईपी - बिजली	101.4	**107.2**	106.2	105.0	105.5	101.4	100.3	**87.9**	93.6	97.3	91.6	102.6
ई.3 सीमेंट उत्पादन	103.4	101.2	104.2	94.0	90.9	**89.3**	97.7	92.5	102.7	104.5	102.2	**116.7**
ई.4 इस्पात उत्पादन	98.4	100.0	96.9	96.4	98.7	98.0	100.2	**96.2**	103.1	106.0	98.7	**107.5**
ई.5 कोयला उत्पादन	94.2	94.8	90.8	83.7	80.5	**79.5**	92.6	101.2	110.9	117.4	114.0	**139.6**
ई.6 कच्चे तेल का उत्पादन	99.1	102.7	99.3	102.1	101.2	97.7	101.2	98.0	101.3	101.8	**92.5**	**103.1**
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	99.4	101.8	98.8	99.5	96.2	**92.3**	97.2	100.5	105.3	104.4	96.7	**107.7**
ई.8 उर्वरक उत्पादन	**83.6**	98.8	101.0	103.7	104.2	101.6	**105.8**	104.3	105.3	104.3	92.9	94.1
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	95.8	100.0	98.7	102.7	103.1	100.0	**103.2**	99.5	101.9	102.4	**91.4**	101.4
सेवा क्षेत्र संकेतक (5 श्रृंखला)												
एफ.1 कार्गो प्रमुख बंदरगाहों नियंत्रित	100.7	101.2	98.5	97.5	96.0	**91.8**	99.1	99.8	103.8	104.8	97.2	**109.4**
एफ.2 रेलवे माल यातायात	98.0	102.8	98.8	97.0	95.4	**92.8**	97.0	97.3	103.5	105.5	98.2	**113.7**
एफ.3 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) - घरेलू	100.4	107.1	98.2	93.8	95.9	**93.4**	99.0	100.4	**107.8**	103.1	98.9	102.2
एफ.4 हवाई जहाज में सवार यात्री (किमी) - अंतर्राष्ट्रीय	**91.8**	98.5	100.3	104.4	102.9	94.2	96.4	97.6	106.4	**106.9**	96.8	102.7
एफ.5 यात्री वाहन बिक्री (थोक)	95.0	93.6	90.8	101.0	100.2	106.0	**113.4**	99.9	**87.6**	106.4	102.3	102.9
व्यापारिक लेन-देन (3 श्रृंखला)												
जी.1 निर्यात	100.2	101.4	98.1	100.2	96.5	95.9	94.0	**93.9**	103.9	99.4	101.0	**115.4**
जी.2 आयात	**95.4**	102.0	96.8	100.9	100.6	99.1	**105.4**	97.9	103.7	95.8	97.1	104.8
जी.3 गैर-तेल गैर-सोना और गैर-चांदी आयात	96.2	99.6	99.5	102.5	99.0	101.7	103.4	98.3	**104.9**	98.5	**92.4**	103.7
भुगतान प्रणाली संकेतक (4 श्रृंखला)												
एच.1 आरटीजीएस	**91.2**	95.0	101.0	97.8	93.9	100.9	99.2	96.6	110.3	98.6	93.1	**122.0**
एच.2 पेपर क्लियरिंग	109.4	102.3	95.7	99.7	**93.3**	95.3	98.2	94.9	102.3	96.6	96.7	**115.9**
एच.3 आरईसी	95.0	97.6	97.7	99.9	96.0	96.7	101.4	**94.8**	103.1	98.4	96.3	**123.2**
एच.4 कार्ड	99.3	102.8	99.0	103.7	101.4	95.6	**111.6**	98.1	101.0	98.7	**88.7**	100.6

अनुबंध – II

सारणी ए2-ति1: त्रैमासिक मौसमी कारकों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त समय अवधि

<table>
<tr><th colspan="2">त्रैमासिक श्रृंखला</th><th colspan="2">औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (12 श्रृंखला)</th></tr>
<tr><th colspan="2">राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (8 श्रृंखला)</th><td rowspan="4">एल.1 उत्पादन मूल्यांकन
एल.2 उत्पादन प्रत्याशा
एल.3 ऑर्डर बुक मूल्यांकन
एल.4 ऑर्डर बुक प्रत्याशा
एल.5 क्षमता उपयोग आकलन
एल.6 क्षमता उपयोग प्रत्याशा
एल.7 बिक्री मूल्य मूल्यांकन
एल.8 बिक्री मूल्य प्रत्याशा
एल.9 लाभ मार्जिन मूल्यांकन
एल.10 लाभ मार्जिन प्रत्याशा
एल.11 व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक
एल.12 व्यवसाय प्रत्याशा सूचकांक</td><td rowspan="4">ति1:2000-01 से ति4:2023-2024</td></tr>
<tr><td>आई.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
आई.2 वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)
आई.3 वास्तविक पीएफसीई
आई.4 वास्तविक जीएफसीई
आई.5 वास्तविक जीएफसीएफ
आई.6 कृषि का जीवीए
आई.7 उद्योग का जीवीए
आई.8 सेवाओं का जीवीए</td><td>ति1:2011-12 से ति4:2023-2024</td></tr>
<tr><th colspan="2">भुगतान संतुलन (4 श्रृंखला)</th></tr>
<tr><td>जे.1 सेवाओं के निर्यात
जे.2 यात्रा में निर्यात
जे.3 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात
जे.4 यात्रा में आयात</td><td>ति1:2011-12 से ति4:2023-2024</td></tr>
<tr><th colspan="2">ओबीआईसीयूएस (1 श्रृंखला)</th><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>के.1 विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग</td><td>ति1:2008-09 से ति3:2023-2024</td></tr>
</table>

सारणी ए2-ति2: औसत* चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के त्रैमासिक मौसमी कारक

(प्रतिशत)

श्रृंखला का नाम	प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	प्रश्न 4
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (8 श्रृंखला)				
आई.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	**98.0**	98.1	99.6	**104.5**
आई.2 वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	99.8	**98.4**	100.0	**102.0**
आई.3 रियल पीएफसीई	97.3	**96.2**	**104.2**	102.3
आई.4 रियल जीएफसीई	**107.1**	104.9	**90.0**	99.7
आई.5 रियल जीएफसीएफ	100.0	**96.7**	97.8	**105.5**
आई.6 कृषि का जीवीए	91.7	**76.9**	**125.6**	105.8
आई.7 उद्योग का जीवीए	100.2	98.1	**95.3**	**106.8**
आई.8 सेवाओं का जीवीए	101.9	**103.6**	**95.3**	99.5
भुगतान संतुलन (4 श्रृंखला)				
जे.1 सेवाओं का निर्यात	**96.6**	98.4	102.2	**102.9**
जे.2 यात्रा में निर्यात	**86.1**	96.1	108.0	**110.3**
जे.3 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात	99.1	100.8	**101.2**	**98.9**
जे.4 यात्रा में आयात	**109.7**	106.5	**90.8**	92.8
ओबीआईसीयूएस (1 श्रृंखला)				
के.1 विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग	**98.5**	99.3	100.0	**102.2**
औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (12 श्रृंखला)				
एल.1 उत्पादन मूल्यांकन	99.0	**98.1**	99.8	**103.1**
एल.2 उत्पादन प्रत्याशा	**98.8**	100.7	**101.0**	99.3
एल.3 ऑर्डर बुक मूल्यांकन	100.2	**98.7**	98.9	**102.1**
एल.4 ऑर्डर बुक प्रत्याशा	**99.5**	100.1	100.0	**100.3**
एल.5 क्षमता उपयोग मूल्यांकन	99.3	**98.1**	99.4	**103.3**
एल.6 क्षमता उपयोग प्रत्याशा	**99.2**	99.6	**101.2**	100.0
एल.7 विक्रय मूल्य मूल्यांकन	**102.6**	**98.4**	98.6	100.4
एल.8 विक्रय मूल्य प्रत्याशा	**100.7**	100.1	99.9	**99.3**
एल.9 लाभ मार्जिन मूल्यांकन	100.6	99.2	**98.7**	**101.3**
एल.10 लाभ मार्जिन प्रत्याशा	99.1	**101.4**	100.6	**98.8**
एल.11 व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक	100.1	**99.2**	99.6	**101.2**
एल.12 व्यवसाय प्रत्याशा सूचकांक	**99.2**	99.4	**101.0**	100.3

टिप्पणी: * सामान्य रूप से पिछले दस वर्षों के तिमाही मौसमी कारकों का औसत। यहां, औसत तिमाही मौसमी कारकों की गणना पिछले 10 वर्षों (यानी, ति1: 2014-15 से ति4: 2023-24) के आधार पर की गई है। 'मोटे अक्षरों' में चिह्नित संख्याएँ संबंधित श्रृंखला की उच्चतम और निम्नतम संख्या हैं।

सारणी ए2-ति3: त्रैमासिक मौसमी कारकों की सीमा (उच्चतम और निम्नतम के बीच अंतर)

(प्रतिशत अंक)

शृंखला \ वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	औसत सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (8 शृंखला)											
आई.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	5.5	5.1	5.1	5.5	6.1	6.7	7.2	7.9	8.5	8.8	6.5
आई.2 वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	2.3	1.7	1.7	2.1	2.7	3.6	4.6	5.4	6.0	6.2	3.6
आई.3 वास्तविक पीएफसीई	7.9	7.2	6.8	6.8	7.3	7.9	8.4	8.8	9.1	9.4	7.9
आई.4 वास्तविक जीएफसीई	30.3	31.0	29.7	25.0	16.8	18.0	19.5	26.9	33.6	37.6	17.0
आई.5 वास्तविक जीएफसीएफ	6.6	6.5	6.8	7.7	8.9	10.0	10.7	10.9	10.6	10.2	8.8
आई.6 कृषि का जीवीए	54.8	52.2	50.2	48.8	48.0	47.3	46.9	46.5	46.4	46.4	48.8
आई.7 उद्योग का जीवीए	9.6	10.0	10.3	10.4	10.6	11.1	11.8	12.7	13.6	14.1	11.4
आई.8 सेवाओं का जीवीए	10.3	10.3	10.0	9.6	8.9	8.2	7.3	6.6	6.0	5.6	8.3
भुगतान संतुलन (4 शृंखला)											
जे.1 सेवाओं का निर्यात	5.4	5.5	5.7	5.8	6.1	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	6.3
जे.2 यात्रा में निर्यात	24.0	20.9	18.7	17.5	18.5	21.7	26.4	30.2	32.0	33.4	24.2
जे.3 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात	3.2	3.0	2.9	2.5	2.2	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	2.3
जे.4 यात्रा में आयात	17.2	19.2	19.5	19.4	19.9	19.6	19.3	19.8	21.0	22.4	18.8
ओबीआईसीयूएस (1 शृंखला)											
के.1 विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग	5.0	4.4	3.9	3.5	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7
औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (12 शृंखला)											
एल.1 उत्पादन मूल्यांकन	4.9	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.0	4.9	4.9
एल.2 उत्पादन प्रत्याशा	3.8	3.2	2.8	2.5	2.2	2.4	3.1	3.6	3.5	3.0	2.2
एल.3 ऑर्डर बुक मूल्यांकन	4.3	4.4	4.3	4.1	4.0	3.6	3.2	2.7	2.0	1.3	3.3
एल.4 ऑर्डर बुक प्रत्याशा	2.1	1.5	0.9	0.8	1.0	0.8	0.4	1.0	1.4	1.6	0.8
एल.5 क्षमता उपयोग मूल्यांकन	5.0	4.7	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.6	5.2
एल.6 क्षमता उपयोग प्रत्याशा	3.9	3.1	2.3	1.4	1.3	1.8	2.4	2.7	3.4	3.3	2.0
एल.7 विक्रय मूल्य मूल्यांकन	3.3	3.6	4.4	5.0	5.3	5.3	5.1	4.5	3.4	2.1	4.2
एल.8 विक्रय मूल्य प्रत्याशा	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	2.0	1.9	2.0	2.4	2.2	1.4
एल.9 लाभ मार्जिन मूल्यांकन	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	1.8	1.3	2.6
एल.10 लाभ मार्जिन प्रत्याशा	1.7	1.8	1.8	2.2	3.1	3.8	4.3	4.3	3.7	2.7	2.6
एल.11 व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक	2.9	2.5	2.4	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.7	2.1
एल.12 व्यवसाय प्रत्याशा सूचकांक	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	2.2	2.3	1.7

टिप्पणियां : औसत मौसमी कारक सीमा पिछले दस वर्षों के लिए औसत मौसमी कारकों की सीमा है; सीमा की गणना अधिकतम और न्यूनतम त्रैमासिक मौसमी कारकों के बीच अंतर के रूप में की जाती है।

सारणी ए2-ति4: सभी तिमाही संकेतकों के प्रमुख डायग्नॉस्टिक

चर का नाम	मूल श्रृंखला में मौसम		अवशिष्ट मौसमी		गुणवत्ता डायग्नॉस्टिक	
	एफ परीक्षण पी-मान	किलोवैट परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण पी-मान	एफ परीक्षण 3 वर्ष पी-मान	एम 7	प्रश्न
आई.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	0.00	0.00	0.06	0.17	0.24	0.29
आई.2 वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	0.00	0.00	0.04	0.09	0.56	0.57
आई.3 वास्तविक पीएफसीई	0.00	0.00	0.04	0.09	0.20	0.52
आई.4 वास्तविक जीएफसीई	0.00	0.00	0.47	0.11	0.76	1.07
आई.5 वास्तविक जीएफसीएफ	0.00	0.00	0.13	0.14	0.36	0.69
आई.6 कृषि का जीवीए	0.00	0.00	0.77	0.90	0.08	0.11
आई. 7 उद्योग का जीवीए	0.00	0.00	0.10	0.43	0.26	0.45
आई.8 सेवाओं का जीवीए	0.00	0.00	0.03	0.10	0.32	0.60
जे.1 सेवाओं का निर्यात	0.00	0.00	0.44	0.38	0.31	0.36
जे.2 यात्रा में निर्यात	0.00	0.00	0.94	0.58	0.44	0.46
जे.3 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात	0.00	0.00	0.06	0.42	0.56	0.45
जे.4 सेवाओं का आयात	0.03	0.00	0.98	0.93	1.12	0.85
जे.5 यात्रा में आयात	0.00	0.00	0.19	0.35	0.33	0.32
जे.6 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में आयात	0.01	0.04	0.55	0.42	1.14	1.39
के.1 विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग	0.00	0.00	0.16	0.28	0.34	0.44
एल.1 उत्पादन मूल्यांकन	0.00	0.00	0.17	0.30	0.32	0.46
एल.2 उत्पादन प्रत्याशा	0.00	0.00	0.95	0.90	0.58	0.64
एल.3 ऑर्डर बुक मूल्यांकन	0.00	0.00	0.16	0.27	0.59	0.66
एल.4 ऑर्डर बुक की प्रत्याशा	0.00	0.00	0.31	0.56	0.84	0.96
एल.5 रोजगार मूल्यांकन	0.40	0.07	0.31	0.40	2.38	1.13
एल.6 रोजगार प्रत्याशा	0.03	0.05	0.65	0.64	1.37	1.10
एल.7 क्षमता उपयोग मूल्यांकन	0.00	0.00	0.09	0.31	0.29	0.45
एल.8 क्षमता उपयोग प्रत्याशा	0.00	0.00	0.89	0.79	0.73	1.07
एल.9 विक्रय मूल्य मूल्यांकन	0.00	0.00	0.36	0.42	0.59	0.83
एल.10 विक्रय मूल्य प्रत्याशा	0.01	0.00	0.50	0.82	1.16	1.21
एल.11 बाह्य वित्त निर्धारण की लागत	0.35	0.42	0.24	0.45	2.02	1.00
एल.12 बाह्य वित्त प्रत्याशा की लागत	0.02	0.01	0.22	0.33	1.24	0.77
एल.13 लाभ मार्जिन मूल्यांकन	0.00	0.00	0.18	0.53	0.77	1.08
एल.14 लाभ मार्जिन प्रत्याशा	0.00	0.00	0.91	0.52	1.05	0.90
एल.15 व्यापार मूल्यांकन सूचकांक	0.00	0.00	0.30	0.38	0.53	0.78
एल.16 व्यापार प्रत्याशा सूचकांक	0.00	0.00	0.92	0.63	0.60	0.94

टिप्पणियां : कृपया सारणी ए1-एम4 की टिप्पणियाँ देखें।

सारणी ए2-ति5: 2023-24 के लिए चयनित आर्थिक समय श्रृंखला के त्रैमासिक मौसमी कारक

(प्रतिशत)

श्रृंखला का नाम	प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	प्रश्न 4
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (8 श्रृंखला)				
आई.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	97.0	97.4	99.9	105.8
आई.2 वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	98.5	97.7	100.0	103.9
आई.3 वास्तविक पीएफसीई	96.1	96.5	105.5	102.0
आई.4 वास्तविक जीएफसीई	103.0	92.5	83.8	121.4
आई.5 वास्तविक जीएफसीएफ	99.2	97.1	96.7	106.9
आई.6 कृषि का जीवीए	91.2	77.2	123.6	108.3
आई.7 उद्योग का जीवीए	98.1	98.1	94.9	109.0
आई.8 सेवाओं का जीवीए	100.4	102.0	96.3	101.4
भुगतान संतुलन (4 श्रृंखला)				
जे.1 सेवाओं का निर्यात	95.9	98.6	102.4	103.1
जे.2 यात्रा में निर्यात	81.1	91.2	114.6	113.3
जे.3 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात	99.3	100.4	100.9	99.5
जे.4 यात्रा में आयात	112.1	103.1	89.7	94.7
ओबीआईसीयूएस (1 श्रृंखला)				
के.1 विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग	98.5	99.6	99.9	102.1
औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (12 श्रृंखला)				
एल.1 उत्पादन मूल्यांकन	98.7	98.1	100.2	103.0
एल.2 उत्पादन प्रत्याशा	99.5	101.3	101.1	98.3
एल.3 ऑर्डर बुक मूल्यांकन	100.0	99.5	99.5	100.8
एल.4 ऑर्डर बुक की प्रत्याशा	99.1	100.6	100.7	99.6
एल.5 क्षमता उपयोग मूल्यांकन	98.6	97.9	99.9	103.5
एल.6 क्षमता उपयोग की प्रत्याशा	99.0	99.6	102.3	99.4
एल.7 विक्रय मूल्य मूल्यांकन	101.6	99.5	99.5	99.6
एल.8 विक्रय मूल्य की प्रत्याशा	99.8	101.3	100.0	99.0
एल.9 लाभ मार्जिन मूल्यांकन	100.3	100.3	99.0	100.4
एल.10 लाभ मार्जिन की प्रत्याशा	99.2	101.8	100.1	99.1
एल.11 व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक	99.7	99.5	99.7	101.2
एल.12 व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक	99.0	99.7	101.3	100.0

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	149
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	150
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	151
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	152
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलयन अमेरिकी डॉलर)	153
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	153
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	154
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	155
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	156
9	कुल चलनिधि राशियाँ	157
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	158
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	158
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	159
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	159
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	160
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	161
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	162
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	163
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	164
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	164
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	164
21	थोक मूल्य सूचकांक	165
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	169
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	169
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	170
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	170
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	171
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	172
28	वाणिज्यिक पत्र	172
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	172
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	173

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	174
32	विदेशी मुद्रा भंडार	174
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	174
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	175
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	175
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	176
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	177
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	178
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	179
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	180
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	181
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	182
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	183
	आवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	185
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	186
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	187
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	188
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	189
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	190
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	191
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	194

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम	आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2022-23	2023-24		2024-25
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	6.0	8.3	6.3	6.8
1.1.1 कृषि	1.4	7.6	3.7	0.6	2.0
1.1.2 उद्योग	9.3	1.7	5.0	8.3	7.4
1.1.3 सेवाएं	7.9	7.3	10.4	7.0	7.7
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	3.5	4.6	3.4	6.3
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	3.8	8.5	6.5	7.5
	2023-24	2023		2024	
		अग	सितं	अग	सितं
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	10.9	6.4	-0.1	3.1
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9	12.4	11.5	12.3	10.8
	(13.5)	(13.2)	(12.3)	(11.9)	(10.4)
2.1.2 ऋण#	16.3	14.9	13.0	14.4	13.7
	(20.2)	(19.7)	(17.6)	(13.1)	(12.3)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3	15.0	13.1	14.4	13.7
	(20.2)	(19.8)	(17.6)	(13.1)	(12.4)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1	14.2	16.7	7.2	7.7
	(12.8)	(16.5)	(18.9)	(6.3)	(6.8)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	9.8	6.4	4.8	6.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	10.8	10.9	10.2	10.8
	(11.6)	(11.5)	(11.5)	(9.8)	(10.4)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	5.8	5.4	5.1	5.1
	(5.0)	(5.7)	(5.4)	(5.1)	(5.1)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1	75.0	75.3	76.5	77.3
	(80.3)	(77.5)	(77.8)	(78.4)	(79.2)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8	60.9	69.7	50.4	64.6
	(113.4)	(103.8)	(99.5)	(47.7)	(61.6)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	30.3	30.3	29.1	29.4
	(29.8)	(30.7)	(30.6)	(29.3)	(29.6)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8	35.6	33.2	22.5	27.7
	(28.4)	(40.6)	(37.0)	(20.8)	(26.2)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.२ स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.85/10.10	8.85/10.10	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.40	7.95/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.75	6.75	6.59	6.61
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.82	6.86	6.63	6.65
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.02	7.08	6.72	6.72
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.03	7.08	6.72	6.70
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.14	7.22	6.90	6.78
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	82.65	83.06	83.87	83.67
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	89.17	87.94	92.91	93.46
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	1.00	1.31	1.88	1.12	1.65
3-माह (%)	1.11	1.38	1.69	1.34	1.74
6-माह (%)	1.31	1.40	1.75	1.64	2.11
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	6.8	5.0	3.7	5.5
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	6.9	4.7	2.4	4.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	-0.5	-0.1	1.2	1.8
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	6.7	4.4	2.5	6.6
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-6.3	-3.3	-0.5	-4.0
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-2.3	-1.3	1.0	1.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	0.7	-14.0	3.3	1.5
7.2 निर्यात	-3.1	3.4	-2.8	-9.6	0.5

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।
कोष्टकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2023-24	2023	2024				
		अक्तू	सितं 27	अक्तू 04	अक्तू 11	अक्तू 18	अक्तू 25
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3271881	3447381	3458701	3488363	3483562	3499601
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	22	28	15	17	15
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3482344**	**3271894**	**3447403**	**3458729**	**3488378**	**3483579**	**3499616**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	162996	143945	199209	198637	198139	202683	205953
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3127636	3247889	3259632	3289855	3280587	3293260
1.2.3 रुपया सिक्का	463	313	305	460	384	308	402
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1675645	1851979	1830991	1730127	1721272	1727119
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	100	101	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	906993	1020447	985504	983424	984541	1042981
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	8100	8254	8375	8072	8057	8265
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	4610	5134	5659	5413	5372	5434
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	47526	49498	49747	49663	49830	50532
2.1.1.8 अन्य	545400	566312	600409	616262	532980	530762	465711
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	141961	168095	165300	150432	142565	154053
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1499252	2008888	1984396	1931136	1937177	1925821
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3587080**	**3174897**	**3860867**	**3815387**	**3661263**	**3658447**	**3652940**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	22	28	15	17	15
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1225339	1944750	1919366	1806073	1783536	1736918
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	21871	24412	35809	9074	23398	24079
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	160738	33302	7076	4843	7756	30948
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्ज़िम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	3181	8496	6851	7218	7223	8699
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	141618	167968	165099	149232	141884	153006
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1371530	1316708	1314098	1315513	1314543	1313046
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	250608	365211	367061	369295	380092	386229
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	238344	351532	353523	353793	364349	370227

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सितं. 1, 2024	-	-	-	-	675	100765	-	-	-	-100090
सितं. 2, 2024	-	-	-	38965	1131	174326	-	220	-	-212380
सितं. 3, 2024	-	-	-	62365	1077	136411	-738	100	-	-198537
सितं. 4, 2024	-	-	-	57660	1352	93975	-686	100	-	-151069
सितं. 5, 2024	-	-	-	40530	10930	72703	-	235	-	-102538
सितं. 6, 2024	-	-	-	65478	2900	184700	-	40	-	-247318
सितं. 7, 2024	-	-	-	-	16343	71891	-	-	-	-55548
सितं. 8, 2024	-	-	-	-	11153	65348	-	-	-	-54195
सितं. 9, 2024	-	-	-	-	1217	81653	-968	385	-	-81789
सितं. 10, 2024	-	-	-	-	1289	104380	968	330	-	-102453
सितं. 11, 2024	-	-	-	25000	1282	124451	-	330	-	-148499
सितं. 12, 2024	-	-	-	72240	2740	96275	-	1345	-	-167120
सितं. 13, 2024	-	-	-	-	6427	136851	-	1535	-	-131959
सितं. 14, 2024	-	-	-	-	5718	110618	-	-	-	-104900
सितं. 15, 2024	-	-	-	-	4665	106705	-	-	-	-102040
सितं. 16, 2024	-	-	-	-	26324	43007	-	-	-	-16683
सितं. 17, 2024	-	-	82630	-	5024	77881	679	1195	-	9257
सितं. 18, 2024	-	-	-	-	10807	83407	-	-	-	-72600
सितं. 19, 2024	-	-	-	-	5304	108713	745	-	-	-102664
सितं. 20, 2024	-	-	25002	-	21731	85863	-	-	-	-39130
सितं. 21, 2024	-	-	-	-	40727	47414	-	-	-	-6687
सितं. 22, 2024	-	-	-	-	29237	43762	-	-	-	-14525
सितं. 23, 2024	-	-	50007	-	3320	57919	-	-	-	-4592
सितं. 24, 2024	-	-	50003	-	1424	62381	-703	-	-	-11657
सितं. 25, 2024	-	-	-	-	5549	83582	651	-	-	-77382
सितं. 26, 2024	-	-	-	-	1370	83095	-	-	-	-81725
सितं. 27, 2024	-	-	-	-	4410	117953	-	-	-	-113543
सितं. 28, 2024	-	-	-	-	3439	91467	-	-	-	-88028
सितं. 29, 2024	-	-	-	-	3285	93486	-	-	-	-90201
सितं. 30, 2024	-	-	-	1000	5761	188048	-	-	-	-183287

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	-1508	-6494	9639
1.1 क्रय (+)	194296	27757	16141	28930
1.2 विक्रय (-)	153025	29265	22635	19291
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	-12611	-54476	80549
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	17687	-1092	8547
(₹ करोड़)	339528	144667	-9604	70945
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	4642	-18980	-14580

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	1598	1993	2149
1.2 विक्रय (-)	7930	1598	1993	2149
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	-1725	-897	-200

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	30 सितंबर 2024 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	11400	-11400
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	3180	-3180
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	0	0
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**0**	**14580**	**-14580**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2023-24	2023	2024					
		अक्तू 20	मई 31	जून 28	जुला 26	अग 23	सितं 20	अक्तू 18
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	124191	14601	46848	2021	1818	21731	4216
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	4900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	3181	9311	9061	9062	8541	8547	7223
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	127372	23912	55909	11083	10359	30278	11439

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	**2023**	**2024**		
		सितं 22	**अग 23**	**सितं 6**	**सितं 20**
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3195976	3404741	3403962	3392284
1.1 संचलन में नोट	3477795	3270406	3477861	3470477	3455216
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	30657	33563	33851	33851
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	105887	108200	101721	98253
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2416872	2680305	2693592	2735069
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2344131	2588482	2599982	2640984
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72741	91822	93610	94085
3 एम1 (1+2)	**6091700**	**5612848**	**6085046**	**6097554**	**6127353**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	225927	211136	199017	199017	199017
5 एम2 (3+4)	**6317627**	**5823984**	**6284063**	**6296571**	**6326370**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	17749453	19619055	19836342	19751495
	(18848160)	(17891449)	(19698002)	(19913292)	(19826970)
7 एम3 (3+6)	24831618	23362301	25704100	25933896	25878848
	(24939860)	(23504298)	(25783048)	(26010846)	(25954324)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1298623	1225055	1361211	1361211	1361211
9 एम4 (7+8)	26130241	24587356	27065311	27295107	27240059
	(26238483)	(24729353)	(27144259)	(27372057)	(27315535)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		सितं 22	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**7512016**	**7179702**	**7629866**	**7790330**	**7562614**
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7292667)	(7694769)	(7854015)	(7626155)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	1010573	1025545	1165032	921112
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1406456	1343455	1350954	1340430
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1392976	1316653	1315528	1313984
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	13480	26802	35426	26447
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	395882	317910	185922	419318
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	395840	317868	185879	419275
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6169128	6604322	6625298	6641501
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6282093)	(6669224)	(6688983)	(6705043)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**16672145**	**15290027**	**17224460**	**17332342**	**17412955**
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(15882467)	(17709792)	(17810857)	(17889364)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5118	10307	8853	10589
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	15284909	17214153	17323489	17402366
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(15877350)	(17699485)	(17802004)	(17878775)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	14558874	16459977	16568087	16648643
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(15151314)	(16945309)	(17046602)	(17125052)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	708331	735395	736415	734471
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	17704	18781	18988	19252
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(17704)	(18781)	(18988)	(19252)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**5543700**	**5095734**	**5866203**	**5929626**	**5931859**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5240824	4735054	5563327	5626750	5628983
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4735313	5563586	5627018	5629252
3.1.2 विदेशी देयताएं	259	259	259	268	269
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	302876	360680	302876	302876	302876
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**33432**	**31400**	**34306**	**34594**	**34594**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**4929674**	**4234561**	**5050735**	**5152997**	**5063174**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5443674)	(4797970)	(5522022)	(5618246)	(5527649)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1789875	1507527	1892962	1941771	1957063
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3139799	2727034	3157772	3211226	3106111
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3653798)	(3290443)	(3629060)	(3676476)	(3570586)
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**24831618**	**23362301**	**25704100**	**25933896**	**25878848**
एम$_3$ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(23504298)	(25783048)	(26010846)	(25954324)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		सितं 22	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5612848	6085046	6097554	6127353
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1)	14424855	13517264	14798820	14906842	14895519
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(13581162)	(14834346)	(14941470)	(14929483)
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	24017844	26360365	26517421	26491792
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(24159840)	(26439312)	(26594372)	(26567267)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3195976	3404741	3403962	3392284
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	19909500	21952425	22176177	22125797
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(20051497)	(22031372)	(22253127)	(22201272)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2344131	2588482	2599982	2640984
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	17565368	19363943	19576195	19484812
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(17707365)	(19442890)	(19653145)	(19560288)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	7904416	8713774	8809288	8768166
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(7968314)	(8749300)	(8843915)	(8802130)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	280304	441388	450106	467853
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	9660953	10650168	10766907	10716647
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(9739051)	(10693589)	(10809230)	(10758158)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72741	91822	93610	94085
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	839627	911377	843672	879626
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25295986	23570334	26020508	26305923	26153058
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(24275739)	(26570742)	(26848124)	(26693009)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7179702	7629866	7790330	7562614
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7292667)	(7694769)	(7854015)	(7626155)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1010573	1025545	1165032	921112
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6169128	6604322	6625298	6641501
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6282093)	(6669224)	(6688983)	(6705043)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	16390632	18390642	18515593	18590445
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(16983073)	(18875973)	(18994108)	(19066853)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5118	10307	8853	10589
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	16385515	18380335	18506740	18579856
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(16977955)	(18865667)	(18985255)	(19056265)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1089184	1085195	1150445	1167091	1162164
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31400	34306	34594	34594
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5110820	4759109	5420007	5491823	5546300
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4735054	5563327	5626750	5628983
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-130004	24056	-143320	-134927	-82683
2.4 पूंजी खाता	3912897	3884768	4421744	4442024	4437226
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653576	1021640	1163999	1338145	1269410

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2023	2024		
		सितं	जुला	अग	सितं
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**25387764**	**24017844**	**26277956**	**26360365**	**26491792**
	(25496006)	(24159840)	(26361158)	(26439312)	(26567267)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	694535	720419	724264	724264
3 एल$_1$ (1 + 2)	**26117010**	**24712379**	**26998375**	**27084629**	**27216056**
	(26225252)	(24854375)	(27081577)	(27163576)	(27291531)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	65846	68324	68118	68824
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	1152	748	395	94
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	53260	54670	54670	55520
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	11435	12905	13054	13210
5 एल$_2$ (3 + 4)	**26202160**	**24778225**	**27066699**	**27152748**	**27284880**
	(26310403)	(24920222)	(27149901)	(27231695)	(27360355)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	96210	..	..	102994
7 एल$_3$ (5 + 6)	**26305155**	**24874435**	**..**	**..**	**27387874**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		सितं 22	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3301863	3512941	3505684	3490538
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	1021317	1023595	1052061	1018975
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	959345	960220	988846	956255
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	72741	91822	93610	94085
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4395920	4628359	4651355	4603598
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1136994	923688	931781	897083
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1010573	1025545	1165032	921112
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	997136	998785	1129648	894708
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1392638	1316259	1315048	1313609
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1363369	1392638	1316259	1315048	1313609
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	338	393	479	375
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	395840	317868	185879	419275
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	13437	26760	35384	26404
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	121303	-112164	-242104	-34618
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	121303	-112164	-242104	-34618
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5118	10307	8853	10589
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3054	8541	7123	8547
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31400	34306	34594	34594
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4735054	5563327	5626750	5628983
2.3.1 स्वर्ण	439319	367410	511818	520331	531633
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4801522	4367662	5051527	5106436	5097367
2.4 पूंजी खाता	1589134	1622166	1863913	1879492	1874081
2.5 अन्य मदें (निवल)	200741	-114638	29049	62278	82982

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2023-24	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2023	2024				
		सितं 29	अग 30	सितं 6	सितं 13	सितं 20	सितं 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4395307	4668483	4651355	4669723	4603598	4660892
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3289165	3493088	3505684	3509043	3490538	3482214
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	1032373	1082361	1052061	1068059	1018975	1083333
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	73769	93034	93610	92621	94085	95346
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	1023924	1085576	1165032	1101329	921112	957345
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	104528	-130881	-242104	-142968	-34618	-84648
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	5080	10604	8853	9138	10589	10556
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	4719356	5579046	5626750	5627573	5628983	5742984
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	31649	34594	34594	34594	34594	34833
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1789875	1489230	1910457	1941771	1959943	1957063	2000178

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		सितं 22	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188	18954584	20991067	21213218	21163509
	(20253430)	(19096581)	(21070014)	(21290169)	(21238985)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2204591	2446039	2457244	2498373
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334	16749993	18545028	18755975	18665136
	(17809577)	(16891990)	(18623975)	(18832925)	(18740611)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7537497	8345262	8440189	8399311
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	280304	441388	450106	467853
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	9212496	10199765	10315786	10265825
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	839627	911377	843672	879626
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	23019606	21519171	23918044	24062713	24156294
	(23641847)	(22224577)	(24468278)	(24604913)	(24696244)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054	5867696	6300226	6319540	6338211
	(6105610)	(5980661)	(6365128)	(6383225)	(6401753)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551	15651476	17617818	17743173	17818082
	(17536238)	(16243916)	(18103150)	(18221688)	(18294491)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477	14558874	16459977	16568087	16648643
	(16432164)	(15151314)	(16945309)	(17046602)	(17125052)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397	14540009	16435616	16546583	16628718
	(16409083)	(15132449)	(16920948)	(17025099)	(17105126)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	15674	16000	16422	15588
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	696	358	535	649
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1076232	1141482	1158129	1153202
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	24056	-143320	-134927	-82683
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	241661	321548	283039	291486	358411
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	184084	255112	260147	266682
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	149868	113408	171247	166266	174411
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	932184	1168575	1320973	1077119
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	959345	960220	988846	956255
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	94141	96191	90022	86246
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	121303	-112164	-242104	-34618
2.4 पूंजी खाता	2299592	2238432	2533660	2538361	2538975
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	442768	507195	653508	568620
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	763831	759393	886025	856786
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	175607	122730	134616	131836

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2023	2024		
		सितं 22	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6106558	5981357	6365487	6383760	6402402
	(6015003)	(5868392)	(6300584)	(6320075)	(6338860)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	180020	158539	158553	157582
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	57960	66632	65813	63049
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	8972	12953	13429	13615
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	83603	95920	96592	97368
4.3 अन्य	5624	5399	7347	7339	6834
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	91056	120612	122253	123351
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	287065	244395	246536	250152
5.3 अन्य	124690	108132	144139	149394	146237
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	70679	109634	115376	111561
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	183184	181702	182843	183453

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3) में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2023	2024		2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	211	208	208	137	137	135	135
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**554117**	**529155**	**541312**	**453177**	**549351**	**526671**	**536780**	**448404**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	255220	334046	298150	294471	252857	330012	293853
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	202599	128765	131578	182429	202552	128550	131408
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	71336	78501	23449	72452	71263	78218	23143
2 अन्य के प्रति देयताएं	**22664868**	**21883000**	**24097455**	**24067308**	**22190597**	**21423326**	**23629065**	**23597567**
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	20141430	22139250	22197886	20475226	19701045	21688112	21746608
	(20823825)	(20000678)	(22061445)	(22123057)	(20366984)	(19560294)	(21610308)	(21671779)
2.1.1 माँग	2492916	2455794	2715452	2630676	2443853	2408810	2666996	2582832
2.1.2 मीयादी	18439151	17685635	19423797	19567210	18031373	17292236	19021116	19163776
2.2 उधार	782260	795714	920015	905313	777942	791542	915858	900827
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	945857	1038191	964109	937428	930738	1025094	950132
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**222716**	**170292**	**6968**	**33302**	**222716**	**170292**	**6968**	**33302**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	170292	6968	33302	222716	170292	6968	33302
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	1043272	1087103	1134910	1132310	1020916	1064207	1112899	1110006
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	97221	95928	92085	89433	94972	93444	89559
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	989882	1038982	1040225	931483	969235	1019456	1020447
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**455057**	**437813**	**479881**	**400181**	**374474**	**375498**	**414893**	**333625**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	236386	284096	252863	198327	194010	233398	201534
5.1.1 चालू खाते में	12010	18115	28162	15175	8971	14642	25424	12452
5.1.2 अन्य खातों में	234373	218271	255934	237687	189357	179368	207974	189082
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	51640	23818	27376	12355	35254	13637	16083
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	51774	42175	45009	48368	51014	41391	44328
5.4 अन्य आस्तियां	117734	98013	129792	74933	115424	95220	126467	71681
6 निवेश	**6256962**	**6177145**	**6509652**	**6589114**	**6106558**	**6028859**	**6357943**	**6439289**
	(6165407)	(6066030)	(6445920)	(6525561)	(6015003)	(5917744)	(6294211)	(6375736)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	6170331	6501765	6580833	6105610	6028163	6357504	6438770
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6814	7887	8281	949	696	439	519
7 बैंक ऋण	**16866336**	**15717431**	**17448862**	**17661371**	**16432164**	**15323660**	**17010621**	**17215335**
	(16335650)	(15125862)	(16966951)	(17190229)	(15901477)	(14732090)	(16528710)	(16744193)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	59884	74656	69694	23081	18687	24036	19075
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	15444677	17133011	17344195	16134303	15053691	16697901	16901348
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	47381	68481	67187	60467	47367	67049	65697
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	183687	208532	211015	197358	181569	207367	209905
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	17124	16582	15988	16412	16896	16397	15793
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	24562	22256	22987	23624	24136	21906	22592

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		सितं 22	अग 23	सितं 20	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**16432164**	**15151314**	**16945162**	**17125371**	**4.2**	**13.0**
	(15901477)	(14558874)	(16459830)	(16648962)	(4.7)	(14.4)
II. खाद्यान्न ऋण	**23081**	**18865**	**24361**	**19926**	**-13.7**	**5.6**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**16409083**	**15132449**	**16920802**	**17105445**	**4.2**	**13.0**
	(15878397)	(14540009)	(16435470)	(16629037)	(4.7)	(14.4)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2071251**	**1862538**	**2160634**	**2167287**	**4.6**	**16.4**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3652804**	**3489700**	**3756194**	**3801604**	**4.1**	**8.9**
	(3635810)	(3471775)	(3740619)	(3786279)	(4.1)	(9.1)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	662065	743704	750825	3.4	13.4
2.2 मध्यम	303998	277614	324746	334412	10.0	20.5
2.3 बड़े	2622490	2550021	2687743	2716366	3.6	6.5
3. सेवाएं	**4592227**	**4166060**	**4643586**	**4736957**	**3.2**	**13.7**
	(4490467)	(4040721)	(4559593)	(4654649)	(3.7)	(15.2)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	209425	243486	245008	6.4	17.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	24160	27990	29760	14.8	23.2
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	77513	75767	80570	78753	1.6	3.9
3.4 शिपिंग	7067	6642	7257	7166	1.4	7.9
3.5 विमानन	43248	39218	44837	44458	2.8	13.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	152272	173738	177730	6.3	16.7
3.7 व्यापार	1025752	937960	1052621	1072493	4.6	14.3
3.7.1 थोक व्यापार[1]	538744	482405	553316	567242	5.3	17.6
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	455555	499305	505251	3.7	10.9
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	442202	494809	497333	6.0	12.5
	(400470)	(354751)	(437854)	(441714)	(10.3)	(24.5)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1548027	1396680	1522204	1529006	-1.2	9.5
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	325626	308711	322093	324354	-0.4	5.1
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	193196	196565	203257	-10.4	5.2
3.10 अन्य सेवाएं[3]	998281	881734	996074	1055250	5.7	19.7
	(978198)	(858200)	(977918)	(1037408)	(6.1)	(20.9)
4. व्यक्तिगत ऋण	**5331290**	**4934424**	**5555484**	**5596719**	**5.0**	**13.4**
	(4919468)	(4485276)	(5170917)	(5219246)	(6.1)	(16.4)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	21881	24396	23764	0.2	8.6
4.2 आवास	2718715	2527201	2833166	2845505	4.7	12.6
	(2331935)	(2105971)	(2471488)	(2490574)	(6.8)	(18.3)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	114851	121817	125694	0.4	9.4
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7764	9722	9546	12.4	22.9
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	230259	276576	271813	5.8	18.0
4.6 शिक्षा	119380	109772	126148	129116	8.2	17.6
4.7 वाहन ऋण	589251	544599	610792	617180	4.7	13.3
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	97426	140391	147081	43.4	51.0
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921	1280670	1412476	1427020	2.9	11.4
	(1362113)	(1253324)	(1389666)	(1404553)	(3.1)	(12.1)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	2081856	1881206	2152535	2164159	4.0	15.0
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1974191	1818843	2027278	2057867	4.2	13.1
(iii) मध्यम उद्यम[6]	490703	449895	529582	543388	10.7	20.8
(iv) आवास	755222	737700	749534	750223	-0.7	1.7
	(660572)	(637057)	(661835)	(663719)	(0.5)	(4.2)
(v) शिक्षा ऋण	62235	60715	61988	62389	0.2	2.8
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	4872	6844	6778	13.1	39.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2581	1072	1124	-57.0	-56.5
(viii) निर्यात ऋण	11774	12209	11530	11290	-4.1	-7.5
(ix) अन्य	61336	51048	60587	58561	-4.5	14.7
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1498137	1692726	1711473	3.9	14.2

टिप्पणियाँ:

(1) डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।

(2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियां" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		सितं 22	अग 23	सितं 20	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3652804	3489700	3756194	3801604	4.1	8.9
	(3635810)	(3471775)	(3740619)	(3786279)	(4.1)	(9.1)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	52551	52810	52560	-3.0	0.0
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	172398	199514	192363	-7.9	11.6
2.2.1 चीनी	26383	16137	20808	18789	-28.8	16.4
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	17241	18436	17113	-13.1	-0.7
2.2.3 चाय	5692	5870	6043	6157	8.2	4.9
2.2.4 अन्य	157089	133150	154227	150304	-4.3	12.9
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	26120	31077	31690	1.8	21.3
2.4 वस्त्र	256048	243634	255993	256793	0.3	5.4
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	93950	94108	93859	-5.4	-0.1
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	3904	4130	4155	-2.9	6.4
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	41800	46081	46812	3.8	12.0
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	103979	111675	111967	4.2	7.7
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	12109	12615	12788	1.6	5.6
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	22726	24731	25229	5.8	11.0
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	46426	44854	49051	49765	7.2	10.9
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक ईंधन	132356	135640	158505	169289	27.9	24.8
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	229276	257192	263369	5.6	14.9
2.9.1 उवर्रक	37569	30726	34119	32556	-13.3	6.0
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	76059	82683	86061	6.2	13.1
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	21612	29019	30677	32.5	41.9
2.9.4 अन्य	107584	100878	111370	114075	6.0	13.1
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	85476	91839	94633	4.7	10.7
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	10845	12515	12447	3.0	14.8
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59757	60244	60851	59806	0.1	-0.7
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	366324	413557	422794	10.0	15.4
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	250052	295207	300521	9.8	20.2
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	116272	118350	122273	10.5	5.2
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	188587	215640	218183	11.0	15.7
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	43175	43914	52395	50514	17.0	15.0
2.14.2 अन्य	153468	144673	163244	167669	9.3	15.9
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	113185	110725	112816	114310	1.0	3.2
2.16 रत्न और आभूषण	84860	92819	86229	91172	7.4	-1.8
2.17 निर्माण	133520	126918	141627	141905	6.3	11.8
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1273079	1306202	1299854	-0.3	2.1
2.18.1 बिजली	644042	620804	638639	641606	-0.4	3.4
2.18.2 दूरसंचार	138192	135113	132305	124047	-10.2	-8.2
2.18.3 सड़क	318072	317177	328001	325928	2.5	2.8
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7969	8261	8428	15.8	5.8
2.18.5 बंदरगाह	6681	7686	6340	6702	0.3	-12.8
2.18.6 रेलवे	13062	11988	11988	11940	-8.6	-0.4
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	172342	180669	181203	2.5	5.1
2.19 अन्य उद्योग	259016	235375	273430	292655	13.0	24.3

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2023	2024						
		अग 25	जून 14	जून 28	जुला 12	जुला 26	अग 09	अग 23	अग 30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	33	33	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**138788.9**	**139938.2**	**134828.9**	**133938.0**	**134144.6**	**134816.8**	**133835.2**	**133649.7**	**133771.9**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**30226.7**	**26773.3**	**28943.0**	**27801.7**	**27708.4**	**28112.2**	**27873.9**	**27398.4**	**27177.9**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	6615.2	7685.6	7904.7	8145.7	8204.5	7890.8	7972.0	7554.0
2.1.1.2 अन्य	15000.4	14594.4	15296.8	14567.8	13823.1	13980.0	14068.5	13618.3	13721.9
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0		179.9			179.9	299.8		
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	5563.7	5780.7	5329.2	5739.6	5747.8	5614.8	5808.1	5902.0
2.2 मीयादी देयताएं	**198141.8**	**182044.5**	**185975.8**	**185708.9**	**183696.0**	**183917.4**	**182003.8**	**181518.0**	**181698.8**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	53971.0	64573.2	64501.4	61491.5	61265.5	60102.2	58935.4	59084.4
2.2.1.2 अन्य	123788.5	125343.8	119532.1	119370.2	120321.5	120836.7	119766.7	120031.4	120050.0
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	1584.5	653.2	653.2	651.8	653.8	940.7	1263.8	1235.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1145.2	1217.2	1184.1	1231.2	1161.3	1194.2	1287.4	1329.4
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0								
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	68594.1	84574.6	85281.4	86852.7	86318.6	84421.5	82219.7	84199.0
4.1 मांग	27317.7	18516.2	23242.7	23887.4	24191.9	24467.9	25452.2	24027.2	23957.2
4.2 मीयादी	68596.8	50077.9	61331.9	61394.0	62660.8	61850.7	58969.3	58192.5	60241.8
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**16263.7**	**11838.9**	**11435.2**	**13323.7**	**12646.4**	**13611.0**	**13590.9**	**11787.9**	**11195.1**
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	664.1	770.9	759.4	797.8	687.9	780.2	679.8	699.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	11174.8	10664.3	12564.3	11848.6	12923.1	12810.7	11108.1	10496.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**2088.1**	**1475.4**	**1694.6**	**1631.9**	**2109.0**	**1700.0**	**1709.6**	**1586.6**	**1607.4**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77700.5**	**71649.5**	**76482.9**	**75500.4**	**76042.2**	**75409.2**	**75025.8**	**74867.2**	**75232.9**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**34355.3**	**21285.0**	**19092.4**	**20740.5**	**18751.9**	**18960.1**	**16731.3**	**14985.4**	**14673.7**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**135141.9**	**125245.6**	**137026.6**	**134324.1**	**137253.1**	**136993.2**	**136583.7**	**138287.3**	**136830.6**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**134936.8**	**125169.9**	**136811.1**	**134111.9**	**137025.2**	**136836.3**	**136416.6**	**138117.1**	**136641.1**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	142185.2	116627.8	136794.5	135046.8	135412.8	134692.9	135559.1	137049.5	137902.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	75.7	215.5	212.2	227.9	156.9	167.1	170.2	189.5

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अक्तू 23	सितं 24	अक्तू 24 (अ)	अक्तू 23	सितं 24	अक्तू 24 (अ)	अक्तू 23	सितं 24	अक्तू 24 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**185.9**	**192.7**	**188.4**	**188.5**	**202.1**	**206.7**	**194.9**	**209.5**	**214.0**	**190.9**	**204.8**	**209.4**
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	183.0	194.3	196.3	182.7	192.8	194.0	182.9	193.8	195.6
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	215.1	220.2	221.6	222.9	229.4	230.5	217.8	223.4	224.7
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	185.2	190.3	194.0	189.3	195.2	198.8	186.8	192.2	195.9
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	181.8	186.6	186.9	182.2	187.6	187.9	181.9	187.0	187.3
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	163.1	169.4	180.9	157.0	160.9	168.1	160.9	166.3	176.2
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	174.9	188.1	192.5	183.8	195.1	196.1	179.1	191.4	194.2
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	190.5	251.1	270.4	234.1	306.6	333.9	205.3	269.9	291.9
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	199.8	214.1	215.0	205.7	219.7	220.2	201.8	216.0	216.8
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	128.1	131.0	131.3	129.7	132.9	133.0	128.6	131.6	131.9
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	248.7	229.6	229.7	238.6	224.7	225.0	245.3	228.0	228.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	181.1	184.7	185.5	168.6	173.3	174.0	175.9	179.9	180.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	193.5	198.9	199.5	201.4	209.3	210.1	197.2	203.7	204.4
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**202.0**	**207.1**	**203.3**	**202.5**	**206.9**	**207.4**	**207.8**	**213.3**	**213.5**	**203.9**	**208.6**	**209.0**
3 कपड़ा और जूते	**192.9**	**181.5**	**188.4**	**193.2**	**197.6**	**198.3**	**182.1**	**186.5**	**187.1**	**188.8**	**193.2**	**193.9**
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	193.8	198.5	199.2	184.2	188.7	189.2	190.0	194.6	195.3
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	189.5	192.4	192.9	170.6	174.7	175.2	181.6	185.0	185.5
4 आवास	--	**176.7**	**176.7**	--	--	--	**177.7**	**181.0**	**182.7**	**177.7**	**181.0**	**182.7**
5 ईंधन और बिजली	**183.0**	**178.9**	**181.4**	**182.3**	**181.1**	**181.2**	**175.7**	**169.9**	**169.8**	**179.8**	**176.9**	**176.9**
6 विविध	**181.7**	**173.7**	**177.8**	**181.9**	**188.9**	**189.9**	**174.0**	**180.8**	**181.5**	**178.1**	**185.0**	**185.8**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	181.7	185.2	185.8	171.9	177.0	177.4	177.1	181.3	181.8
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	191.4	197.9	198.6	185.5	193.0	193.6	189.2	196.0	196.7
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	171.4	176.2	176.3	161.4	165.4	165.5	166.1	170.5	170.6
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	176.3	179.8	180.5	171.7	175.5	176.0	173.7	177.4	178.0
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	184.8	191.6	191.9	180.4	187.4	187.6	182.2	189.1	189.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	185.2	201.4	205.1	186.2	203.4	207.3	185.6	202.2	206.0
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**185.6**	**182.4**	**184.1**	**187.0**	**196.7**	**199.5**	**183.4**	**191.4**	**193.7**	**185.3**	**194.2**	**196.8**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2023	2024	
				सितं	अग	सितं
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	137.5	142.6	143.3
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1226	1297	1304
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1237	1309	1316

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	58743	70441	72878
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	71852	82751	86187

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अक्तू	अग	सितं (अ)	अक्तू (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**151.4**	**152.5**	**154.4**	**154.6**	**156.1**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**183.0**	**185.3**	**195.1**	**195.7**	**200.3**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**191.3**	**192.0**	**209.0**	**210.9**	**218.0**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	197.4	210.0	211.8	213.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	204.9	259.2	263.8	291.8
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	180.2	185.9	185.7	185.6
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	171.9	173.1	172.8	171.0
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	250.7	236.8	244.6	242.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	199.0	205.7	209.1	219.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**162.4**	**164.1**	**160.2**	**161.9**	**161.3**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	167.1	161.2	163.8	160.1
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	181.8	178.6	183.6	185.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	134.9	138.8	140.0	140.2	139.2
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	298.9	248.6	244.7	247.3
1.1.3 खनिज	**0.833**	**217.7**	**219.7**	**227.6**	**227.6**	**223.8**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	202.7	217.4	217.4	214.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	279.3	263.6	263.4	256.0
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**153.6**	**167.0**	**155.0**	**146.1**	**146.7**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**152.0**	**155.5**	**148.3**	**146.9**	**146.5**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**136.4**	**136.7**	**135.6**	**135.6**	**135.5**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	258.1	232.0	232.0	229.5
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**159.0**	**165.6**	**156.9**	**154.2**	**152.9**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**145.0**	**142.5**	**134.8**	**135.8**	**137.4**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**140.2**	**140.4**	**141.3**	**141.8**	**142.5**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**160.5**	**160.8**	**166.5**	**169.2**	**173.3**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	143.9	153.0	152.6	152.8
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	143.7	143.8	142.5	146.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	130.6	131.6	132.8	133.2
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	141.4	150.5	157.7	169.9
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	180.3	178.5	179.6	180.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	178.2	184.0	185.9	187.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	154.5	173.3	174.3	173.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	165.1	168.4	168.7	170.1
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	136.7	139.5	138.7	139.0
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	138.7	157.1	160.3	162.2
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	150.6	150.8	153.6	155.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	182.3	202.8	202.6	199.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	191.1	191.9	192.4	192.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	148.6	151.9	151.5	151.3
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	180.8	185.9	186.8	186.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	211.6	208.6	210.6	209.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**131.5**	**131.7**	**134.0**	**133.9**	**134.5**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	133.3	133.9	135.6	135.9	136.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	135.7	138.3	137.2	139.0
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	125.3	128.1	128.2	128.2
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**173.5**	**174.1**	**176.0**	**176.9**	**176.1**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	174.1	176.0	176.9	176.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अक्तू	अग	सितं (अ)	अक्तू (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**134.6**	**134.7**	**135.9**	**135.8**	**135.9**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	120.5	122.3	121.6	121.1
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	156.8	155.7	156.3	157.3
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	121.0	123.7	123.4	125.3
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	156.6	160.5	160.7	161.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	137.4	141.1	141.1	142.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	131.0	135.4	135.8	135.0
1.3.5 पहनने योग्य वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**150.8**	**152.0**	**152.9**	**153.5**	**153.9**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, पहनने योग्य वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	149.5	150.3	150.9	151.0
१.३.५.२ बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	158.6	159.8	160.5	161.6
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**124.1**	**124.0**	**124.9**	**125.1**	**125.2**
१.३.६.१ चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; फर की ड्रेसिंग और रंगाई	0.142	107.3	106.5	104.1	105.1	106.4
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	141.2	143.1	142.7	142.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	127.8	129.8	129.8	129.4
१.३.७ लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**146.6**	**147.1**	**149.5**	**148.8**	**148.9**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	137.8	140.3	141.9	142.1
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	147.4	149.1	147.6	147.8
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	206.4	201.7	216.4	216.4	216.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	139.1	141.1	140.9	140.3
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**140.3**	**138.5**	**139.8**	**139.4**	**139.9**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	145.3	145.5	144.8	144.2
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	141.4	146.1	145.8	148.0
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	124.8	124.0	124.0	124.6
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**182.3**	**183.9**	**187.0**	**185.2**	**185.4**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	183.9	187.0	185.2	185.4
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.9**	**136.6**	**136.7**	**136.4**	**136.3**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	139.8	137.9	138.0	137.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	142.2	143.2	142.7	143.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	131.5	134.1	133.4	134.2
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.8	133.0	129.8	129.4	130.3
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	144.1	140.7	141.1	139.7
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	140.0	139.0	139.1	138.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	133.9	136.2	136.2	136.6
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	103.2	106.9	104.7	102.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**142.9**	**142.9**	**144.8**	**144.8**	**143.5**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	142.9	144.8	144.8	143.5
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**127.5**	**127.2**	**129.1**	**129.0**	**129.2**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.2	114.8	115.1	116.6
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	106.8	113.6	113.9	113.6
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	137.1	138.2	137.8	137.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**134.7**	**135.6**	**129.8**	**130.4**	**130.1**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	163.4	163.5	164.1	162.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	120.0	119.6	119.7	118.8
1.3.13.3 मिट्टी से भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	130.1	121.6	123.9	126.0
1.3.13.4 अन्य चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	122.3	124.6	124.6	124.7
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	138.8	127.7	128.4	128.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अक्तू	अग	सितं (अ)	अक्तू (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	137.6	138.4	138.0	138.1
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	130.8	133.7	135.4	135.2
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	101.2	96.8	97.2	94.5
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**141.0**	**142.2**	**138.3**	**138.5**	**139.0**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	143.3	131.2	130.4	134.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	153.6	145.4	142.8	145.2
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	120.0	114.4	117.0	114.8
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	143.5	138.6	138.8	140.1
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	145.1	136.4	133.3	131.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	139.1	134.6	133.5	134.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	136.8	128.6	131.9	128.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	170.8	165.2	163.7	163.9
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	143.9	154.6	155.7	157.5
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	145.0	144.0	144.4	144.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	173.8	170.7	170.8	172.7
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**138.6**	**138.9**	**136.6**	**136.4**	**135.3**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	132.3	131.5	131.4	129.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	157.7	151.2	150.6	147.2
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	106.3	105.3	111.5	110.8	112.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	143.8	138.4	138.6	139.9
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	108.6	101.9	102.0	101.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	143.8	144.7	144.3	143.5
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**119.3**	**120.1**	**121.6**	**121.7**	**121.7**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	116.0	117.4	117.6	117.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.9	136.2	135.4	135.3
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	137.3	145.4	145.1	145.7
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	104.7	101.1	101.2	101.1
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	114.1	118.1	120.9	120.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	157.0	166.3	166.3	167.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	107.9	119.7	117.7	117.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	103.8	106.9	106.9	107.0
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**131.4**	**132.2**	**133.5**	**133.4**	**133.5**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	132.1	131.7	131.6	131.6
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	137.8	137.7	141.8	141.3	141.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	123.5	120.7	121.2	121.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	146.1	145.4	153.3	153.1	154.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	116.3	118.9	118.7	118.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	133.9	132.4	132.3	131.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	121.4	122.6	123.0	124.1
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**129.0**	**128.9**	**130.6**	**130.8**	**131.0**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	128.6	132.4	133.6	133.9
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	132.3	134.0	133.7	134.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	117.0	118.5	118.5	118.3
१.३.१८.४ बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	126.3	126.4	126.2	128.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	82.4	86.7	88.4	86.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	128.5	129.5	129.9	129.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2023	2024		
			अक्तू	अग	सितं (अ)	अक्तू (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	145.8	149.2	148.3	146.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	142.5	144.3	145.0	145.3
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.9	122.8	122.8	123.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	89.2	88.8	88.9	89.1
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.3	126.2	126.1	126.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	137.5	141.9	141.1	142.8
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	144.1	144.8	144.9	144.5
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	71.5	69.1	69.0	68.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**128.4**	**127.7**	**129.8**	**129.6**	**129.6**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	128.4	130.3	130.0	129.9
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	126.9	129.3	129.1	129.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**143.1**	**143.7**	**144.6**	**144.8**	**145.2**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	177.9	177.9	177.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	109.0	110.0	108.2	109.5
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	145.3	145.4	145.9	146.4
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	138.5	134.6	133.7	133.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	161.2	162.4	162.9	164.1
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**159.6**	**159.5**	**159.0**	**159.7**	**159.5**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	159.5	159.0	159.7	159.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**158.2**	**153.4**	**174.1**	**178.9**	**184.0**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	152.8	175.0	180.1	185.5
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	189.4	201.4	204.7	199.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	155.0	163.6	164.4	168.0
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	159.6	158.8	163.6	163.2	163.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	163.2	159.7	159.7	158.6
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**179.8**	**180.3**	**193.1**	**195.3**	**201.2**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रैल-सितंबर		सितंबर	
				2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	143.5	149.3	142.3	146.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	118.1	122.9	111.5	111.7
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	141.9	147.2	141.5	147.0
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	204.9	217.3	205.9	206.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	144.1	150.4	138.8	141.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	104.1	108.2	112.6	115.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	154.8	161.0	154.2	160.7
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	172.3	182.1	172.8	178.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	117.6	127.7	125.0	133.1
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	149.3	147.4	142.6	145.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-सितंबर			
	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3129200**	**1622373**	**1397112**	**51.8**	**53.1**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2583499	1265159	1160340	49.0	49.8
1.2 करेतर राजस्व	545701	357214	236772	65.5	78.5
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**78000**	**14601**	**20166**	**18.7**	**24.0**
2.1 ऋण की वसूली	28000	11434	13216	40.8	57.5
2.2 अन्य प्राप्तियां	50000	3167	6950	6.3	11.4
3 कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) (1+2)	**3207200**	**1636974**	**1417278**	**51.0**	**52.2**
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3709401	1696528	1628511	45.7	46.5
4.1 ब्याज भुगतान	1162940	515010	484329	44.3	44.8
5 पूंजी व्यय	1111111	414966	490628	37.3	49.0
6 कुल व्यय (4+5)	**4820512**	**2111494**	**2119139**	**43.8**	**47.1**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**580201**	**74155**	**231399**	**12.8**	**26.6**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1613312**	**474520**	**701861**	**29.4**	**39.3**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**450372**	**-40490**	**217532**	**-9.0**	**30.8**

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		सितं 29	अग 23	अग 30	सितं 6	सितं 13	सितं 20	सितं 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	19820	3715	2796	3042	4751	3475	5662
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	17017	7947	9371	6616	8334	8242	5698
1.3 राज्य सरकारें	5701	31677	61087	66587	68588	72388	71688	69688
1.4 अन्य	88670	106663	86638	90133	96643	97215	94083	90440
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	75415	55945	55481	54498	55542	51781	44787
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	108252	46735	44716	41837	42085	37767	30674
2.3 राज्य सरकारें	4070	25418	15947	16093	14793	14693	13909	13909
2.4 अन्य	102311	83033	106420	99903	95365	86073	79152	78239
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	87844	86463	82259	84818	86514	84627	84526
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	172707	120165	123440	120067	121511	117499	122233
3.3 राज्य सरकारें	41487	48023	38128	37845	37518	36791	31022	28145
3.4 अन्य	165095	149448	185373	186301	187114	183975	183873	173241
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	133789	182562	180908	120753	155935	175422	167512
4.4 अन्य	442	783	1298	1073	1528	248	811	449
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	925317	814562	814924	810899	809871	777119	747242

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024-25	**91-दिवसीय खज़ाना बिल**									
अग 28	8000	82	20488	7044	41	7956	7044	15000	98.37	6.6342
सितं 4	8000	100	25416	8561	44	7940	8561	16501	98.37	6.6301
सितं 11	8000	87	17251	8340	57	7960	8340	16300	98.37	6.6462
	182-दिवसीय खज़ाना बिल									
2024-25										
अग 28	6000	90	19914	168	38	5978	168	6145	96.76	6.7210
सितं 4	6000	89	15897	626	52	5974	626	6600	96.76	6.7261
सितं 11	6000	92	15990	1717	42	5983	1717	7700	96.76	6.7222
2024-25	**364-दिवसीय खज़ाना बिल**									
अग 28	6000	107	27850	1127	21	5985	1127	7112	93.72	6.7175
सितं 4	6000	96	24086	1368	27	5956	1368	7325	93.72	6.7153
सितं 11	6000	107	28815	1753	19	5981	1753	7734	93.73	6.7037

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

की स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
सितम्बर 02 ,2024	5.10-6.60	6.49
सितम्बर 03 ,2024	5.10-6.55	6.47
सितम्बर 04 ,2024	5.10-6.55	6.46
सितम्बर 05 ,2024	5.10-6.65	6.49
सितम्बर 06 ,2024	5.10-6.60	6.48
सितम्बर 09 ,2024	5.10-6.60	6.52
सितम्बर10 ,2024	5.10-6.60	6.50
सितम्बर 11 ,2024	5.10-6.65	6.54
सितम्बर 12 ,2024	5.10-6.60	6.52
सितम्बर 13 ,2024	5.10-6.75	6.62
सितम्बर 16 ,2024	5.50-6.25	6.03
सितम्बर 17 ,2024	5.10-6.95	6.64
सितम्बर 19 ,2024	5.10-6.80	6.64
सितम्बर 20 ,2024	5.10-6.80	6.65
सितम्बर 21 ,2024	5.75-6.70	6.29
सितम्बर 23 ,2024	5.10-6.80	6.68
सितम्बर 24 ,2024	5.10-6.80	6.69
सितम्बर 25 ,2024	5.10-7.00	6.67
सितम्बर 26 ,2024	5.10-6.70	6.54
सितम्बर 27 ,2024	5.10-6.65	6.53
सितम्बर 30 ,2024	5.10-6.90	6.68
अक्तूबर 01 ,2024	5.10-6.55	6.47
अक्तूबर 03 ,2024	5.10-6.55	6.44
अक्तूबर 04 ,2024	5.10-6.50	6.41
अक्तूबर 05 ,2024	5.50-6.50	6.09
अक्तूबर 07 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 08 ,2024	5.10-6.75	6.42
अक्तूबर 09 ,2024	5.10-6.60	6.43
अक्तूबर 10 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 11 ,2024	5.10-6.50	6.43
अक्तूबर 14 ,2024	5.10-6.50	6.42
अक्तूबर 15 ,2024	5.00-6.50	6.42

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2023	2024			
	सितं 22	अग 9	अग 23	सितं 6	सितं 20
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	291829.65	435778.32	446580.44	463005.01	474683.60
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	31959.30	26212.32	46185.89	55104.80	67552.42
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.88-7.70	6.96-7.56	7.03-7.68	7.02-7.56	7.11-7.83

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2023	2024			
	सितं 30	अग 15	अग 31	सितं 15	सितं 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (र करोड़)	412234.35	473153.85	471121.50	440945.45	397590.45
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	49675.85	63925.50	78270.05	78418.60	48447.90
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.89-11.36	6.97-11.69	6.90-13.77	7.09-12.88	7.07-14.72

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		सितं 29	अग 23	अग 30	सितं 6	सितं 13	सितं 20	सितं 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	13325	16106	17258	18166	21371	11343	18628
2 नोटिस मुद्रा	2550	4295	750	4045	333	254	5874	208
3 मीयादी मुद्रा	871	312	1024	958	1144	1077	281	805
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	559348	644906	791363	607781	734837	605817	678781
5 बाजार रेपो	574534	444818	503684	601046	510382	620109	486193	548987
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	152	4666	4270	3736	3931	2839	5566
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	106919	103856	127583	109685	120154	126154	140598
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	117087	125631	82172	74736	108595	168177	156651
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	8406	7229	2572	10025	5111	8231	11412
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	6645	4528	3373	3055	4209	900	2522
10.2 182-दिवसीय	6079	6311	5603	2703	4416	1978	2727	5341
10.3 364-दिवसीय	4307	2936	5403	2703	5272	3406	4404	4387
10.4 नकदी प्रबंधन बिल			0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	141385	148394	93522	97504	123299	184439	180314
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	560	1310	648	165	1062	788	586

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रैल-सितं)		2024-25 (अप्रैल-सितं) *		सितं 2023		सितं 2024 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**339**	**80942**	**147**	**31158**	**255**	**85980**	**35**	**9565**	**58**	**16883**
1ए प्रीमियम	328	76319	138	29063	242	65333	34	9121	55	15314
1.1 पब्लिक	272	65832	109	24900	186	74274	31	9285	47	16213
1.1.1 प्रीमियम	272	62791	109	23965	186	55007	31	9084	47	14967
1.2 राइट्स	67	15110	38	6258	69	11706	4	280	11	671
1.2.1 प्रीमियम	56	13527	29	5097	56	10326	3	38	8	347
2 अधिमान शेयर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**44**	**16342**	**20**	**7682**	**21**	**4856**	**6**	**2318**	**5**	**1695**
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	44	16342	20	7682	21	4856	6	2318	5	1695
3.1.1 पब्लिक	44	16342	20	7682	21	4856	6	2318	5	1695
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 कुल (1+2+3)	**383**	**97284**	**167**	**38840**	**276**	**90836**	**41**	**11883**	**63**	**18579**
4.1 पब्लिक	316	82174	129	32582	207	79130	37	11603	52	17908
4.2 राइट्स	67	15110	38	6258	69	11706	4	280	11	671

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24	2023	2024				
			सितं	मई	जून	जुला	अग	सितं
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	285750	330220	293508	282865	290409	289724
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	437072	34408	39598	35163	33838	34615	34570
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	53631	67598	45824	43399	48669	39585
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	84157	6458	8106	5490	5192	5801	4723
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	232119	262621	247684	239466	241740	250139
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	352915	27950	31492	29673	28646	28814	29847
2 आयात	₹ करोड़	5616042	452485	518017	473149	480403	539791	463563
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	678215	54485	62118	56684	57468	64340	55312
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	116268	166303	125581	115934	92408	104687
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	178733	14000	19942	15045	13869	11015	12491
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	336217	351715	347568	364469	447383	358876
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	499482	40485	42176	41639	43600	53326	42821
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-166735	-187798	-179641	-197538	-249381	-173840
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-241143	-20077	-22520	-21521	-23630	-29725	-20743
3. 1 तेल	₹ करोड़	-783382	-62637	-98705	-79757	-72535	-43739	-65103
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94576	-7542	-11836	-9555	-8677	-5213	-7768
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-104098	-89093	-99884	-125003	-205642	-108737
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-146567	-12535	-10684	-11966	-14953	-24512	-12975

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2023	2024					
		नवं 03	सितं 20	सितं 27	अक्तू 04	अक्तू 11	अक्तू 18	अक्तू 25
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**₹ करोड़**	**4920453**	**5785706**	**5900138**	**5887828**	**5803872**	**5786531**	**5757912**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**590783**	**692296**	**704885**	**701176**	**690430**	**688267**	**684805**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4346726	5061914	5157443	5144410	5061364	5029601	4992326
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	521896	605686	616154	612643	602101	598236	593751
१.२ स्वर्ण	₹ करोड़	384148	531633	550741	552160	551932	567032	576181
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	46123	63613	65796	65756	65658	67444	68527
	मात्रा (मैट्रिक टन)	803.58	853.64	853.64	858.31	863.12	866.85	866.85
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13681	13702	13702	13702	13702	13702	13702
	₹ करोड़	149706	154941	155249	154715	154157	153610	153190
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	17975	18540	18547	18425	18339	18271	18219
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	39873	37218	36706	36543	36419	36288	36215
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	4789	4458	4387	4352	4333	4316	4307

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।

टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2023	2024		2023-24	2024-25
		सितं	अग	सितं (अ)	अप्रै-सितं	अप्रै-सितं (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**151879**	**143070**	**158945**	**161623**	**5418**	**10192**
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	21284	29204	31080	1920	5347
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	96458	100543	100924	1617	2651
1.3 एनआरओ	27522	25328	29198	29619	1880	2195

अ: अनंतिम।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (अ)	2023	2024 (अ)	
		अप्रै-सितं	अप्रै-सितं	सितं	अग	सितं
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**10129**	**3894**	**3561**	**631**	**1742**	**-3057**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**26807**	**10398**	**14309**	**1920**	**3950**	**-1042**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**71279**	**33512**	**42103**	**6149**	**8614**	**5984**
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	21143	30350	4200	6504	4119
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	191	380	15	56	3
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	31826	15177	20625	2587	4273	2488
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	5120	8787	1486	2064	1516
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	654	558	111	111	111
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	9280	9636	1580	1580	1580
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5694	3089	2116	368	530	286
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**44472**	**23114**	**27794**	**4229**	**4665**	**7026**
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	21628	26689	4093	4527	6934
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	1486	1104	136	138	92
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**16678**	**6505**	**10749**	**1289**	**2207**	**2016**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	3547	6372	607	1104	691
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	2893	2947	482	482	482
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	2417	3125	488	724	1022
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	2352	1695	288	103	179
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**44081**	**20677**	**20037**	**-2226**	**4325**	**9659**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	21375	19954	-2113	4270	9595
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	698	-83	113	-55	-64
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**54210**	**24571**	**23597**	**-1595**	**6067**	**6601**

अ: अनंतिम।

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023	2024		
		सितं	जुला	अग	सितं
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**31735.74**	**3492.91**	**2754.05**	**3211.54**	**2758.25**
1.1 जमाराशियाँ	916.45	118.56	41.68	45.56	43.00
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	29.13	24.54	22.49	25.47
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	208.45	120.86	125.30	135.08
1.4 उपहार	3580.27	383.70	275.26	244.41	221.67
1.5 दान	11.31	0.91	0.68	0.67	0.87
1.6 यात्रा	17006.27	1765.07	1662.13	2013.30	1713.06
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	4611.53	559.79	337.40	315.40	281.24
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	4.85	8.62	7.65	7.89
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	396.08	272.16	416.39	320.10
1.10 अन्य	298.24	26.37	10.72	20.36	9.88

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2022-23	2023-24	2023	2024	
			अक्तू	सितं	अक्तू
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 आरईईआर	91.20	90.73	91.69	90.39	90.93
1.2 एनईईआर	102.78	103.70	105.13	105.34	107.21
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 आरईईआर	93.01	93.11	94.01	93.07	93.51
2. 2 एनईईआर	101.10	101.21	102.41	102.68	104.28
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 आरईईआर	85.93	83.62	84.50	81.54	81.99
1.2 एनईईआर	101.80	101.66	103.07	102.52	104.38
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 आरईईआर	100.00	97.31	98.33	94.89	95.42
2.2 एनईईआर	100.00	99.86	101.24	100.71	102.53

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	81	99	95
1.2 राशि	29461	2200	5460	3776
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	2	3	1
2.2 राशि	19748	564	449	1065
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	83	102	96
3.2 राशि	49209	2764	5909	4841
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षो में)	5.60	5.20	4.50	4.40
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारित औसत मार्जिन	1.66	1.82	1.49	1.36
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-15.00	0.01-10.00	0.00-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	130	1452	378
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	712	1042	328
ए) परिवहन	1505	281	0	0
बी) ऊर्जा	3513	331	983	15
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	0
डी) संचार	6309	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	0	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	100	0	313
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	0	59	0
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	495	372	437
IV. अन्य संस्थाएं	1728	0	0	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	1	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	1727	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	0
VII. एनबीएफसी	13361	1402	3009	3578
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	1193	773	2777
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	13	18	31
सी) एनबीफसी - अन्य	5096	196	2218	770
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	25	34	120

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।
@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**403470**	**379039**	**24432**	**506715**	**501489**	**5226**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**221636**	**230603**	**-8967**	**241638**	**251403**	**-9765**
1.1 पण्य	**104936**	**161637**	**-56701**	**111175**	**176297**	**-65122**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**116700**	**68967**	**47734**	**130463**	**75106**	**55357**
1.2.1 सेवाएं	80569	45449	35121	88466	48740	39725
1.2.1.1 यात्रा	6412	9489	-3077	7352	9171	-1819
1.2.1.2 परिवहन	7408	7693	-285	8507	8609	-102
1.2.1.3 बीमा	761	591	170	903	593	310
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	159	250	-91	161	309	-147
1.2.1.5 विविध	65830	27427	38404	71542	30058	41484
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	38172	4243	33928	41926	4479	37447
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	21831	15203	6627	23000	16625	6375
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1891	1152	739	2215	1267	948
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	831	324	507	519	444	75
1.2.2 अंतरण	27117	4279	22838	29519	3169	26350
1.2.2.1 आधिकारिक	20	255	-235	18	266	-248
1.2.2.2 निजी	27097	4024	23073	29502	2904	26598
1.2.3 आय	9014	19239	-10225	12478	23196	-10718
1.2.3.1 निवेश आय	7187	18372	-11185	10341	22218	-11878
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1827	868	959	2137	978	1159
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**181834**	**148018**	**33816**	**264492**	**250086**	**14406**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**109054**	**88595**	**20459**	**183279**	**176019**	**7259**
2.1.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	19278	14551	4728	23435	17120	6315
2.1.1.1 भारत में	17790	10427	7362	22287	12171	10116
2.1.1.1.1 इक्विटी	11266	9351	1915	16402	11673	4729
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4541	0	4541	4897		4897
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1983	1077	906	988	498	490
2.1.1.2 विदेश में	1489	4123	-2634	1147	4949	-3801
2.1.1.1.1 इक्विटी	1489	1864	-375	1147	2346	-1199
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1500	-1500
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	813	-813	0	1102	-1102
2.1.2 संविभाग निवेश	89775	74045	15731	159844	158899	945
2.1.2.1 भारत में	88743	72654	16089	159240	158343	897
2.1.2.1.1 एफआईआई	88743	72654	16089	159240	158343	897
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	77174	63525	13649	139824	140833	-1009
2.1.2.1.1.2 ऋण	11569	9129	2440	19416	17510	1906
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1032	1391	-358	604	556	48
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**30359**	**28188**	**2171**	**31905**	**25940**	**5965**
2.2.1 बाह्य सहायता	3032	1603	1429	3641	2271	1371
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	49	-40	8	30	-22
2.2.1.2 भारत को	3023	1553	1470	3634	2241	1393
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	15452	9721	5731	12618	10951	1667
2.2.2.1 भारत द्वारा	2212	2071	140	4138	4255	-117
2.2.2.2 भारत को	13241	7650	5591	8481	6696	1785
2.2.3 भारत को अल्पावधि	11875	16864	-4989	15645	12718	2927
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	11875	14352	-2477	13572	12718	854
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2512	-2512	2073	0	2073
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**33279**	**20339**	**12940**	**36380**	**33511**	**2870**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	33107	20339	12769	36259	33511	2749
2.3.1.1 आस्तियां	13315	3382	9934	10705	13570	-2865
2.3.1.2 देयताएं	19792	16957	2835	25554	19941	5614
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	18896	16688	2208	23426	19401	4025
2.3.2 अन्य	172	0	172	121	0	121
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	**0**	**62**	**-62**	**0**	**61**	**-61**
2.5 अन्य पूंजी	**9143**	**10834**	**-1691**	**12928**	**14556**	**-1627**
3 भूल-चूक	**0**	**418**	**-418**	**585**	**0**	**585**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**24432**	**-24432**	**0**	**5226**	**-5226**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	24432	-24432		5226	-5226

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3316497**	**3115671**	**200826**	**4227182**	**4183585**	**43597**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1821831**	**1895540**	**-73709**	**2015823**	**2097284**	**-81461**
1.1 पण्य	**862564**	**1328641**	**-466077**	**927458**	**1470724**	**-543266**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**959267**	**566900**	**392367**	**1088365**	**626560**	**461805**
1.2.1 सेवाएं	662275	373584	288691	738010	406609	331401
1.2.1.1 यात्रा	52702	77997	-25295	61335	76511	-15177
1.2.1.2 परिवहन	60895	63237	-2342	70965	71816	-851
1.2.1.3 बीमा	6251	4854	1398	7535	4950	2585
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1305	2051	-746	1346	2575	-1229
1.2.1.5 विविध	541121	225445	315676	596830	250757	346073
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	313769	34880	278889	349760	37363	312397
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	179448	124971	54477	191873	138694	53178
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	15546	9473	6073	18478	10572	7906
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	6827	2663	4165	4331	3702	629
1.2.2 अंतरण	222898	35170	187728	246261	26440	219821
1.2.2.1 आधिकारिक	160	2094	-1934	150	2216	-2066
1.2.2.2 निजी	222738	33076	189662	246112	24225	221887
1.2.3 आय	74093	158146	-84052	104093	193510	-89417
1.2.3.1 निवेश आय	59076	151014	-91938	86265	185352	-99087
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	15018	7132	7886	17829	8158	9670
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1494666**	**1216698**	**277968**	**2206479**	**2086302**	**120178**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**896414**	**728246**	**168169**	**1528971**	**1468411**	**60560**
2.1.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	158467	119605	38862	195500	142821	52679
2.1.1.1 भारत में	146230	85713	60517	185930	101538	84392
2.1.1.1.1 इक्विटी	92604	76861	15743	136835	97382	39453
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	37323	0	37323	40849	0	40849
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	16303	8853	7450	8246	4156	4090
2.1.1.2 विदेश में	12237	33892	-21654	9570	41283	-31713
2.1.1.2.1 इक्विटी	12237	15322	-3085	9570	19574	-10004
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	11889	-11889	0	12515	-12515
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	6681	-6681	0	9194	-9194
2.1.2 संविभाग निवेश	737947	608641	129306	1333471	1325590	7881
2.1.2.1 भारत में	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
2.1.2.1.1 एफआईआई	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	634364	522169	112195	1166461	1174878	-8416
2.1.2.1.1.2 ऋण	95097	75040	20058	161973	146071	15901
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8486	11432	-2946	5037	4641	396
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**249550**	**231703**	**17847**	**266160**	**216400**	**49760**
2.2.1 बाह्य सहायता	24921	13173	11749	30377	18943	11433
2.2.1.1 भारत द्वारा	72	404	-331	64	247	-184
2.2.1.2 भारत को	24849	12769	12080	30313	18696	11617
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	127016	79909	47107	105264	91357	13907
2.2.2.1 भारत द्वारा	18179	17027	1153	34517	35497	-980
2.2.2.2 भारत को	108837	62882	45955	70747	55860	14887
2.2.3 भारत को अल्पावधि	97612	138621	-41009	130519	106100	24420
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	97612	117969	-20357	113225	106100	7125
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	20652	-20652	17295	0	17295
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**273549**	**167181**	**106367**	**303498**	**279556**	**23942**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	272138	167181	104957	302487	279556	22931
2.3.1.1 आस्तियां	109451	27797	81653	89303	113205	-23902
2.3.1.2 देयताएं	162687	139384	23304	213184	166351	46833
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	155328	137175	18153	195426	161851	33575
2.3.2 अन्य	1410	0	1410	1011	0	1011
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**512**	**-512**	**0**	**508**	**-508**
2.5 अन्य पूंजी	**75153**	**89057**	**-13904**	**107850**	**121427**	**-13577**
3 भूल-चूक	**0**	**3432**	**-3432**	**4880**	**0**	**4880**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**200826**	**-200826**	**0**	**43597**	**-43597**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	200826	-200826	0	43597	-43597

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**221635**	**230581**	**-8945**	**241638**	**251377**	**-9739**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**185505**	**207085**	**-21580**	**199641**	**225037**	**-25396**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**104936**	**161637**	**-56701**	**111175**	**176297**	**-65122**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	104497	151939	-47442	111136	166784	-55648
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	438	0	438	39	0	39
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	9698	-9698		9512	-9512
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**80569**	**45449**	**35121**	**88466**	**48740**	**39725**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	481	42	439	268	22	246
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	47	431	-385	81	238	-157
1.अ.ख.3 परिवहन	7408	7693	-285	8507	8609	-102
1.अ.ख.4 यात्रा	6412	9489	-3077	7352	9171	-1819
1.अ.ख.5 निर्माण	870	697	174	1478	563	915
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	761	591	170	903	593	310
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1891	1152	739	2215	1267	948
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	381	3647	-3266	341	4448	-4107
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	39091	4859	34231	42541	5215	37326
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	21831	15203	6627	23000	16625	6375
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	968	1279	-312	1175	1249	-74
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	159	250	-91	161	309	-147
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	272	116	156	444	432	12
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**9014**	**19239**	**-10225**	**12478**	**23196**	**-10718**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1827	868	959	2137	978	1159
1.आ.2 निवेश आय	5777	17935	-12158	8448	21594	-13146
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2355	9950	-7595	3173	12343	-9170
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	208	2250	-2042	70	2411	-2341
1.आ.2.3 अन्य निवेश	517	5546	-5029	1110	6620	-5510
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	2697	189	2508	4095	220	3876
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1410	436	973	1892	624	1268
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**27116**	**4256**	**22860**	**29519**	**3144**	**26376**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	27097	4024	23073	29502	2904	26598
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	26325	2680	23645	28644	1989	26655
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	772	1343	-571	857	914	-57
1.इ.2 सामान्य सरकार	19	232	-214	18	240	-222
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**150**	**145**	**5**	**185**	**146**	**40**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	12	51	-39	4	45	-41
2.2 पूँजी अंतरण	138	94	44	182	101	81
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**181685**	**172328**	**9358**	**264307**	**255192**	**9114**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**19278**	**14551**	**4728**	**23435**	**17120**	**6315**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	17790	10427	7362	22287	12171	10116
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	15806	9351	6456	21299	11673	9626
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11266	9351	1915	16402	11673	4729
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4541	0	4541	4897		4897
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1983	1077	906	988	498	490
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1983	1077	906	988	498	490
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1489	4123	-2634	1147	4949	-3801
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1489	3310	-1822	1147	3847	-2699
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1489	1864	-375	1147	2346	-1199
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	1446	-1446		1500	-1500
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	813	-813	0	1102	-1102
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	813	-813		1102	-1102
3.2 संविभाग निवेश	**89775**	**74045**	**15731**	**159844**	**158899**	**945**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	88743	72654	16089	159240	158343	897
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	77174	63525	13649	139824	140833	-1009
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11569	9129	2440	19416	17510	1906
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1032	1391	-358	604	556	48
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5013**	**5736**	**-723**	**6053**	**9666**	**-3613**
3.4 अन्य निवेश	**67619**	**53565**	**14053**	**74976**	**64281**	**10694**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	19068	16688	2380	23547	19401	4146
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	172	0	172	121	0	121
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	18896	16688	2208	23426	19401	4025
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	32695	14974	17720	29093	27331	1762
3.4.3अ भारत को ऋण	30474	12854	17621	24948	23046	1901
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2220	2120	100	4145	4285	-139
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	38	168	-130	47	133	-86
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	11875	16864	-4989	15645	12718	2927
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	3943	4871	-928	6643	4698	1945
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**24432**	**-24432**	**0**	**5226**	**-5226**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	24432	-24432	0	5226	-5226
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**181685**	**172328**	**9358**	**264307**	**255192**	**9114**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	100552	83480	17072	168975	166708	2266
4.2 ऋण लिखत	77190	59545	17645	88689	78560	10129
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	3943	29302	-25359	6643	9924	-3281
5. निवल भूल-चूक	**0**	**418**	**-418**	**585**	**0**	**585**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अप्रै - जून 2023			अप्रै - जून 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**1821825**	**1895356**	**-73531**	**2015820**	**2097068**	**-81248**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1524839**	**1702225**	**-177386**	**1665468**	**1877333**	**-211865**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**862564**	**1328641**	**-466077**	**927458**	**1470724**	**-543266**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	858960	1248927	-389967	927134	1391370	-464235
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3604	0	3604	324	0	324
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	79714	-79714	0	79355	-79355
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**662275**	**373584**	**288691**	**738010**	**406609**	**331401**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	3955	345	3610	2234	183	2051
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	382	3546	-3164	676	1983	-1307
1.अ.ख.3 परिवहन	60895	63237	-2342	70965	71816	-851
1.अ.ख.4 यात्रा	52702	77997	-25295	61335	76511	-15177
1.अ.ख.5 निर्माण	7153	5726	1427	12327	4693	7635
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6251	4854	1398	7535	4950	2585
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	15546	9473	6073	18478	10572	7906
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3128	29977	-26849	2843	37103	-34261
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	321321	39942	281380	354891	43507	311384
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	179448	124971	54477	191873	138694	53178
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	7953	10515	-2562	9803	10418	-615
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1305	2051	-746	1346	2575	-1229
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2235	950	1285	3706	3604	102
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**74093**	**158146**	**-84052**	**104093**	**193510**	**-89417**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	15018	7132	7886	17829	8158	9670
1.आ.2 निवेश आय	47486	147426	-99940	70478	180146	-109668
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	19356	81790	-62434	26468	102971	-76503
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	1710	18491	-16781	582	20112	-19530
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4252	45590	-41337	9262	55229	-45968
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	22167	1555	20612	34166	1833	32333
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	11590	3588	8002	15787	5206	10581
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**222893**	**34986**	**187907**	**246259**	**26225**	**220034**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	222738	33076	189662	246112	24225	221887
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	216392	22033	194358	238960	16597	222364
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6346	11042	-4696	7151	7628	-477
1.इ.2 सामान्य सरकार	155	1910	-1755	147	2000	-1852
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1232**	**1188**	**44**	**1547**	**1214**	**333**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	100	418	-319	32	375	-343
2.2 पूँजी अतंरण	1132	770	362	1515	839	675
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1493440**	**1416520**	**76920**	**2204934**	**2128900**	**76035**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**158467**	**119605**	**38862**	**195500**	**142821**	**52679**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	146230	85713	60517	185930	101538	84392
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	129927	76861	53067	177683	97382	80301
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	92604	76861	15743	136835	97382	39453
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	37323	0	37323	40849	0	40849
3.1.अ.2 ऋण लिखत	16303	8853	7450	8246	4156	4090
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	16303	8853	7450	8246	4156	4090
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	12237	33892	-21654	9570	41283	-31713
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12237	27211	-14974	9570	32089	-22519
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	12237	15322	-3085	9570	19574	-10004
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	11889	-11889	0	12515	-12515
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	6681	-6681	0	9194	-9194
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	6681	-6681	0	9194	-9194
3.2 संविभाग निवेश	**737947**	**608641**	**129306**	**1333471**	**1325590**	**7881**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	729461	597209	132252	1328434	1320949	7485
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	634364	522169	112195	1166461	1174878	-8416
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	95097	75040	20058	161973	146071	15901
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8486	11432	-2946	5037	4641	396
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**41207**	**47148**	**-5941**	**50493**	**80637**	**-30144**
3.4 अन्य निवेश	**555819**	**440301**	**115518**	**625470**	**536255**	**89216**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	156738	137175	19563	196437	161851	34586
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	1410	0	1410	1011	0	1011
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	155328	137175	18153	195426	161851	33575
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	268748	123088	145661	242702	228005	14697
3.4.3अ भारत को ऋण	250497	105658	144839	208121	192261	15861
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	18252	17430	821	34581	35744	-1164
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	308	1380	-1072	396	1109	-714
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	97612	138621	-41009	130519	106100	24420
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	32413	40037	-7624	55416	39189	16227
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**200826**	**-200826**	**0**	**43597**	**-43597**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	200826	-200826	0	43597	-43597
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1493440**	**1416520**	**76920**	**2204934**	**2128900**	**76035**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	826529	686201	140328	1409641	1390737	18904
4.2 ऋण लिखत	634499	489457	145042	739877	655377	84500
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	32413	240863	-208450	55416	82786	-27370
5. निवल भूल-चूक	**0**	**3432**	**-3432**	**4880**	**0**	**4880**

टिप्पणीः प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023		2024			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542777	228227	532278	242271	542777	246072	552178
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	143893	501412	153343	511142	156042	520277
1.2 अन्य पूंजी	88927	31635	84334	30866	88927	31635	90029	31900
2. संविभाग निवेश	12162	277118	14511	258539	12162	277118	12103	277272
2.1 इक्विटी	10644	162061	12567	152928	10644	162061	10367	160898
2.2 ऋण	1517	115057	1944	105611	1517	115057	1736	116374
3. अन्य निवेश	128450	571045	105256	531184	128450	571045	141261	590312
3.1 व्यापार ऋण	33450	123659	29658	119317	33450	123659	32874	126577
3.2 ऋण	13578	221886	13037	206940	13578	221886	16837	225023
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	52803	154787	33117	144069	52803	154787	57032	160628
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	28619	48804	29443	38848	28619	48804	34518	56319
4. आरक्षित निधियाँ	646419		595051		646419		651997	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1029301	1390940	943044	1322001	1029301	1390940	1051433	1419761
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361639		-378956		-361639		-368329	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं		सितं	अग	सितं
	1	-2	-1	0	5	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.73	3.88	4.08	259206893	21104039	23205978	23840258
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.52	1.62	1.57	170464587	13723954	15544033	14750412
1.1.1 आउटराइट	9.51	0.93	0.99	0.99	13463848	1211320	1468219	1468346
1.1.2 रेपो	4.94	0.41	0.41	0.37	76718788	5629136	6391039	6038102
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.19	0.22	0.21	80281951	6883498	7684775	7243965
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.10	2.13	2.40	80984671	6811643	6911072	8415273
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.11	0.13	0.11	7757636	568441	750873	674573
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	213.94	237.53	233.33	170886670	14545183	15910436	17786483
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	212.80	236.33	232.21	152406168	12960210	14385410	16027655
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.13	1.19	1.12	18480503	1584974	1525025	1758828
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	119215.72	166465.50	166626.30	67542859	5340256	6408703	6384754
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.31	0.31	0.30	261	21	13	14
2.2 एपीबीएस $	25888.17	1818.74	2783.25	2342.41	390743	17943	35283	35550
2.3 आईएमपीएस	60053.35	4728.97	4533.37	4299.36	6495652	507497	577888	565233
2.4 एनएसीएच जमा $	16227.27	1512.78	1534.87	1657.93	1525104	109472	144196	122079
2.5 एनईएफटी	72639.50	5598.05	7983.23	7908.83	39136014	3126190	3590588	3597885
2.6 यूपीआई @	1311294.68	105556.87	149630.47	150417.47	19995086	1579133	2060736	2063995
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.52	1.45	1.31	352	37	15	14
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1514.68	1774.78	1805.36	1687658	138748	177162	180707
3.1 भीम आधार पे @	193.59	13.87	19.06	18.81	6112	441	576	568
3.2 एनएसीएच नामे $	16426.49	1371.81	1621.10	1651.69	1678769	138081	176386	179945
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	129.00	134.62	134.86	2777	226	199	193
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	4578.47	5323.13	5275.26	2423563	189186	211744	216304
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	2739.43	3900.68	3921.62	1831134	142320	168202	176202
4.1.1 पीओएस आधारित $	18614.08	1420.96	2023.83	1980.89	651911	49440	63208	61033
4.1.2 अन्य $	16996.08	1318.47	1876.85	1940.73	1179223	92879	104994	115169
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1839.04	1422.45	1353.64	592429	46866	43542	40102
4.2.1 पीओएस आधारित $	16477.95	1325.79	1061.41	995.07	393589	30512	29346	25777
4.2.2 अन्य $	6381.69	513.26	361.04	358.58	198840	16355	14196	14324
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	6143.16	5466.90	5476.69	283048	23668	16555	17489
5.1 वालेट	63256.69	4927.10	4092.83	4054.95	234353	19944	11599	11889
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1216.07	1374.07	1421.74	48695	3724	4956	5600
5.2.1 पीओएस आधारित $	8429.87	707.39	710.24	721.65	11247	842	908	858
5.2.2 अन्य $	7088.84	508.67	663.82	700.09	37447	2882	4048	4743
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	538.35	508.49	484.94	7212333	575021	568848	543387
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	538.35	508.49	484.94	7212333	575021	568848	543387
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	131990.38	179538.79	179668.56	79149461	6266879	7383012	7342641
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	132204.32	179776.32	179901.89	250036131	20812062	23293447	25129124
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	131665.97	179267.83	179416.95	242823799	20237041	22724600	24585737

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		सितं	अग	सितं		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	101214.61	144031.16	143569.44	30687088	2434721	3188004	3161365
1.1 अंतबैंक $	83000.56	6606.30	9171.14	9081.76	5676805	446014	598931	601330
1.2 अंतर-बैंक $	1169598.65	94608.31	134860.02	134487.68	25010283	1988707	2589074	2560036
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3650.26	3912.80	3847.73	102117736	8219961	9520832	10092959
2.1 अंतबैंक @	12033.28	988.10	1157.09	1101.62	53247042	4179061	4883018	5123573
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2662.16	2755.71	2746.11	48870694	4040900	4637815	4969386
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	66440.72	5377.22	5157.20	4949.81	3259388	260514	255021	245223
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	95.80	7.85	8.46	8.02	4648	380	434	417
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	66001.01	5340.70	5128.53	4922.18	3241538	259072	253703	243930
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	343.90	28.67	20.20	19.62	13202	1062	883	876
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	15.18	0.97	0.30	0.27	148	9	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	15.06	0.96	0.28	0.25	147	9	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.12	0.01	0.02	0.01	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	991.43	972.97	975.12	314003	25477	23935	23389
5.1 एईपीएस @	11754.95	991.43	972.97	975.12	314003	25477	23935	23389

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2023	2024	
		सितं	अग	सितं
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10713.04	10912.03	10968.31
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	930.17	1054.92	1061.13
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9782.86	9857.10	9907.18
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	16718.12	15182.14	15339.88
2.1 वालेट @	13381.80	13588.07	11322.72	11381.79
2.2 कार्ड @	3361.82	3130.05	3859.42	3958.09
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.58	2.55	2.55
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.23	2.23	2.20	2.20
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.35	0.35	0.35	0.35
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	14.87	14.42	14.45
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	83.03	93.01	93.43
6 भारत क्यूआर @	62.50	59.82	63.97	64.16
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	2950.06	5912.10	6069.95

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधनं के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सामयिक श्रृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2023	2024		
			जून	अप्रै	मई	जून
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**232460**	**21300**	**17030**	**15054**	**16131**
	बकाया	**1865029**	**1693172**	**1881643**	**1896249**	**1911978**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**161344**	**14690**	**14570**	**11554**	**12719**
	बकाया	**1298795**	**1177156**	**1313366**	**1324921**	**1337639**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	1612	4085	-332	1333
	बकाया	191692	206919	195777	195445	196778
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	1825	3020	2348	2056
	बकाया	157611	94113	160631	162980	165035
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	2709	1701	2048	1788
	बकाया	269007	251221	270708	272755	274544
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	4162	2202	2475	2536
	बकाया	175472	151990	177674	180150	182685
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	1783	2686	3724	3389
	बकाया	305776	285638	308463	312186	315575
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	128180	142346	145006	147449
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	9955	12218	12538	12859
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	7998	9068	9263	9445
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	139505	144831	145379	145822
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	2634	909	1335	1645
	बकाया	197134	185313	198043	199378	201023
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-35	-33	-44	-29
	बकाया	1754	1629	1721	1677	1648
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	0	0	1
	बकाया	349	333	349	350	351
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**56069**	**6435**	**2886**	**3486**	**3343**
	बकाया	**418021**	**382241**	**420490**	**423527**	**426469**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1417	1051	1404	1325
	बकाया	183905	169782	184956	186360	187686
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	2209	1022	1115	1169
	बकाया	220560	206066	221582	222698	223866
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	2809	813	967	849
	बकाया	18277	6275	19090	20056	20906
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	118	-5138	-5587	-5989
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**15047**	**175**	**-426**	**14**	**69**
	बकाया	**148213**	**133775**	**147787**	**147801**	**147870**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**9898751**	**10383607**	**10538792**	**10740389**	**10946860**
1. वाणिज्यिक बैंक	36.58	37.96	37.55	37.66	37.52
2. सहकारी बैंक	1.56	1.52	1.49	1.47	1.42
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.73	0.66	0.67	0.66	0.70
4. बीमाकृत कंपनियां	26.21	26.05	26.16	25.98	26.11
5. म्यूच्युअल फंड	2.69	3.02	3.03	2.90	2.87
6. भविष्य निधियां	4.59	4.42	4.57	4.47	4.41
7. पेंशन निधि	4.18	4.32	4.44	4.52	4.74
8. वित्तीय संस्थाएं	1.20	0.54	0.55	0.55	0.57
9. कॉरपोरेट	1.22	1.21	1.33	1.35	1.44
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.59	1.61	1.92	2.34	2.34
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.78	13.06	12.54	12.31	11.92
12. अन्य	5.67	5.64	5.74	5.79	5.97
12.1 राज्य सरकार	2.03	2.04	2.07	2.04	2.13

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**5050874**	**5161642**	**5338587**	**5646219**	**5727482**
1. वाणिज्यिक बैंक	34.13	33.87	33.90	34.14	33.85
2. सहकारी बैंक	3.68	3.60	3.53	3.39	3.38
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.50	0.61	0.63	0.60	0.59
4. बीमाकृत कंपनियां	26.73	26.97	26.64	26.14	25.85
5. म्यूच्युअल फंड	2.08	1.86	2.00	2.09	2.08
6. भविष्य निधियां	21.19	21.70	22.00	22.35	22.94
7. पेंशन निधि	4.84	4.82	4.56	4.76	4.87
8. वित्तीय संस्थाएं	1.82	1.65	1.63	1.59	1.58
9. कॉरपोरेट	1.92	1.87	2.03	2.02	2.03
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.02	0.02	0.03	0.07	0.05
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.70	0.69	0.66	0.63	0.62
12. अन्य	2.39	2.34	2.37	2.20	2.17
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2023			2024	
	जून	सितं	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**1012301**	**925317**	**849151**	**871662**	**858193**
1. वाणिज्यिक बैंक	47.64	56.35	57.18	58.53	47.79
2. सहकारी बैंक	1.20	1.20	1.28	1.67	1.49
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.99	0.54	1.70	1.66	2.69
4. बीमाकृत कंपनियां	4.93	5.26	5.50	5.06	5.78
5. म्यूच्युअल फंड	17.04	12.74	11.21	11.89	14.50
6. भविष्य निधियां	1.46	1.52	0.08	0.15	0.60
7. पेंशन निधि	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	7.96	4.10	5.34	7.16	6.56
9. कॉरपोरेट	4.42	4.00	4.58	4.50	4.79
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.12	0.10	0.07	0.01	0.20
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	13.23	14.17	13.06	9.36	15.59
12.1 राज्य सरकार	10.33	11.36	9.26	5.88	11.55

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है।
बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।
राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।
वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।
अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।
सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7098451**	**8376972**	**9045119**
1.1 विकास संबंधी	2882758	3074492	3823423	4189146	5073367	5426440
1.1.1 राजस्व	2224367	2446605	3150221	3255207	3838714	3836447
1.1.2 पूंजी	596774	588233	550358	861777	1146013	1471534
1.1.3 ऋण	61617	39654	122844	72163	88639	118460
1.2 गैर-विकास संबंधी	2078276	2253027	2442941	2810388	3188699	3490946
1.2.1 राजस्व	1965907	2109629	2271637	2602750	2988556	3277722
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	894520	955801	1060602	1226672	1403183	1589435
1.2.2 पूंजी	111029	141457	169155	175519	196688	208268
1.2.3 ऋण	1340	1941	2148	32119	3455	4957
1.3 अन्य	79713	83368	86995	98916	114906	127733
2. कुल प्राप्तियां	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7156342**	**8258187**	**9149787**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3797731	3851563	3688030	4823821	5706246	6337126
2.1.1 कर प्राप्तियां	3278947	3231582	3193390	4160414	4837048	5477428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2030050	2012578	2076013	2626553	2967610	3372525
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1246083	1216203	1114805	1530636	1865298	2100430
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2814	2800	2572	3225	4140	4473
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	518783	619981	494640	663407	869198	859698
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	36273	31137	33448	35250	37974	45199
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	140287	110094	64994	44077	88273	119373
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	44667	59515	16951	27665	25661	34501
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	95621	50578	48044	16412	62611	84872
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2230553**	**2582453**	**2588620**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	387091	571872	890012	627255	687904	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	325987	190241	107493	350911	529	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	710119	868676	1640143	1567151	1870675	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	795845	971378	1696012	1213169	1776747	1902862
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	88961	209232	458801	526693	403838	441189
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	51004	38280	41273	28100	36454	37114
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-18298	10411	4545	42153	3524	24429
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	66289	-14227	25682	42203	82485	58404
3ख.1.6 नकद शेष	17395	-323279	-43802	-57891	118784	-104667
3ख.1.7 अन्य	96014	548753	347643	399980	136748	207172
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*26.7*	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*31.1*	*30.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*26.6*	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*30.6*	*30.3*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*21.2*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*9.6*	*8.6*

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बज़ट अनुमान।
स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।
टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।
1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।
3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।
3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।
नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।
3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2024 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5842.45	30	2140.89	19	1426.07	4
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	1121.53	10	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	68.06	5	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	466.72	16	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	169.58	5	-	-
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	489.95	15	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1490.67	30	2060.82	29	732.26	18
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	102.66	27	239.97	27	39.80	13
17	मेघालय	371.41	30	87.97	4	-	-
18	मिज़ोरम	91.74	15	-	-	-	-
19	नगालैंड	64.66	11	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	4053.86	30	690.70	17	-	-
23	राजस्थान	2800.20	28	1322.97	16	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4713.44	30	2061.20	30	1188.11	17
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	714.67	30	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां : 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5) -: नगण्य।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2024 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11336	1116	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2694	7	0	2350
3	असम	7865	89	0	0
4	बिहार	12218	-	0	11500
5	छत्तीसगढ़	7641	479	0	8005
6	गोवा	1029	448	0	0
7	गुजरात	14971	654	0	5000
8	हरियाणा	2281	1673	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2353	-	0	750
12	कर्नाटक	19884	734	0	47438
13	केरल	3045	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1249	0	0
15	महाराष्ट्र	70297	1708	0	0
16	मणिपुर	68	137	0	0
17	मेघालय	1245	106	0	0
18	मिज़ोरम	449	62	0	0
19	नगालैंड	1852	45	0	0
20	उड़ीसा	17797	2004	115	10877
21	पुदुचेरी	568	-	0	900
22	पंजाब	8942	0	0	0
23	राजस्थान	1157	-	129	6700
24	तमिलनाडु	3364	-	0	2897
25	तेलंगाना	7740	1695	0	0
26	त्रिपुरा	1198	26	0	325
27	उत्तरप्रदेश	4913	207	0	0
28	उत्तराखंड	10417	-	89	15000
29	पश्चिम बंगाल	12914	1013	239	0
	कुल	**228257**	**13472**	**572**	**111742**

टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों के बाजार उधार

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में ली गई कुल राशि	
						जुला.		अग		सितं			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	10000	10000	3000	2000	4000	-1000	44000	30918
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	-	-	-	-	-	-	-	-146
3	असम	17100	16105	18500	16000	1000	1000	2000	1500	1750	1750	7750	6800
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	-	-	6000	6000	6000	3922	12000	9922
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	-	-	1500	-550	2000	2000	3500	700
6	गोवा	1350	500	2550	1560	200	100	150	-50	300	300	650	50
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	-	-	2500	2500	-	-1000	4500	500
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	3500	3345	4500	3500	3000	1700	19500	14470
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	500	350	500	350	700	700	4600	3350
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	3000	2700	1550	1550	-	-	9350	8450
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	-	-2000	-	-	3000	1000	3000	-3500
13	केरल	30839	15620	42438	26638	4500	3000	6000	4300	3753	2253	24253	14853
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	-	-2200	10000	10000	5000	3950	15000	10400
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	6000	3800	24000	21600	24000	17000	64000	46900
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	200	200	200	200	-	-	600	540
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	400	400	-	-	150	-258	1050	562
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	90	90	90	90	90	40	541	431
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	-	-	-	-	-	-	300	100
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-500	-	-	-	-	-	-1000
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	-	-	-	-	-	-200	250	-50
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	4993	4993	3200	3200	2000	1888	26893	22439
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	7000	5500	5000	3750	6000	3500	36500	24438
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	-	-	-	-130	-	-	-	-130
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	12000	9500	8000	6000	9000	7875	50000	34625
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	8000	8000	6000	6000	4500	2500	31500	25582
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	-	-	-	-	-	-	-	-4233
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	-	-	-	-	-	-	1400	1400
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	7000	5500	5000	3500	7000	5000	24500	14900
	कुल	758392	518829	1007058	717140	68383	53778	89190	75310	82243	52920	385637	263271

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रुप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**583412.7**	**554437.6**	**463583.5**	**679174.4**	**2280608.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.0*	*11.7*	*8.5*	*11.8*	*11.5*
I. वित्तीय आस्तियां	**788786.3**	**592945.3**	**633317.9**	**1047276.1**	**3062325.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.3*	*12.5*	*11.6*	*18.2*	*15.4*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**297412.4**	**278631.7**	**158172.2**	**506213.3**	**1240429.7**
(ए) बैंक जमाराशि	**281191.3**	**264565.3**	**147096.0**	**507719.3**	**1200571.8**
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	462689.8	1147292.5
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	45029.5	53279.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**16221.1**	**14066.4**	**11076.3**	**-1506.0**	**39857.9**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**11040.9**	**8886.2**	**5896.0**	**-6686.2**	**19137.0**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1441.0	3763.0	3514.8	3521.2	12240.0
ii. आवास वित्त कंपनियां	9599.9	5123.2	2381.3	-10207.3	6897.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	**124387.9**	**143462.2**	**157535.1**	**142216.5**	**567601.8**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**114496.3**	**107087.9**	**105344.6**	**175769.3**	**502698.2**
4. मुद्रा	**202432.7**	**21286.9**	**91456.0**	**66800.5**	**381976.1**
5. निवेश	**6249.8**	**-12956.4**	**67659.3**	**63624.0**	**124576.7**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**42751.6**	**54377.4**	**52095.1**	**91597.0**	**240821.1**
II. वित्तीय देयताएँ	**205373.6**	**38507.7**	**169734.4**	**368101.7**	**781717.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.4*	*3.9*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**205490.3**	**38624.3**	**169851.0**	**368219.1**	**782184.7**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**211058.8**	**13213.0**	**139622.0**	**276579.8**	**640473.6**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	240050.4	605037.9
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**-5568.6**	**25411.3**	**30229.0**	**91639.4**	**141711.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	64881.1	86979.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**33.0**	**134.4**
3. सामान्य सरकार	**-150.4**	**-150.4**	**-150.4**	**-150.4**	**-601.7**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**370115.8**	**334234.9**	**489774.4**	**503089.0**	**1696155.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.2*	*6.0*	*7.9*	*7.7*	*7.2*
I. वित्तीय आस्तियां	**364661.7**	**527896.1**	**818355.4**	**887657.3**	**2597511.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.1*	*9.4*	*13.1*	*13.6*	*11.1*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**-82726.1**	**204033.6**	**426977.3**	**277625.7**	**824852.1**
(ए) बैंक जमाराशि	**-106428.9**	**197105.1**	**422392.9**	**264882.9**	**777952.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	-107940.7	195441.8	418267.0	262326.1	768094.3
ii. सहकारी बैंक	1511.8	1663.4	4125.9	2556.8	9857.8
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**23702.8**	**6928.5**	**4584.5**	**12742.8**	**46900.0**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**16950.0**	**170.7**	**-2178.3**	**5960.0**	**20902.3**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4972.6	-765.5	73.3	4211.8	8492.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	11977.3	936.2	-2251.6	1748.2	12410.1
2. जीवन बीमा निधियाँ	**114711.5**	**127449.8**	**103248.6**	**121541.6**	**466951.5**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**127624.0**	**115463.1**	**98146.0**	**221372.4**	**562605.5**
4. मुद्रा	**128660.2**	**-68631.2**	**62793.3**	**146845.0**	**269667.4**
5. निवेश	**24929.6**	**82305.4**	**69760.9**	**50972.1**	**227967.9**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**50405.2**	**66218.1**	**56372.0**	**68243.2**	**241238.4**
II. वित्तीय देयताएँ	**-5454.1**	**193661.2**	**328581.0**	**384568.3**	**901356.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*-0.1*	*3.5*	*5.3*	*5.9*	*3.8*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**-5562.3**	**193553.0**	**328472.8**	**384460.1**	**900923.7**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**21436.5**	**138722.6**	**267950.7**	**348360.4**	**776470.2**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26978.6	140268.7	265271.5	337009.8	769528.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**-26998.8**	**54830.4**	**60522.2**	**36099.7**	**124453.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-34757.9	28876.8	29476.5	-2163.2	21432.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	826.7	4554.5
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**33.8**	**135.1**
3. सामान्य सरकार	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**74.4**	**297.4**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**297770.4**	**293705.1**	**279460.1**	**505937.8**	**1376873.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.6*	*4.5*	*4.0*	*7.0*	*5.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**586920.5**	**646714.8**	**750856.7**	**974558.5**	**2959050.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*9.0*	*9.8*	*10.8*	*13.6*	*10.9*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**183072.0**	**315216.2**	**276593.9**	**324746.6**	**1099628.6**
(ए) बैंक जमाराशि	**163162.9**	**299545.0**	**256363.7**	**307491.6**	**1026563.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4549.6	-1020.1	7903.8	22523.6	33956.9
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**19909.1**	**15671.3**	**20230.2**	**17255.0**	**73065.5**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6314.4**	**2076.7**	**6635.6**	**3660.4**	**18687.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4040.2	3267.2	1800.9	5372.2	14480.5
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73669.9**	**152049.5**	**167894.1**	**141206.6**	**534820.1**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**155604.2**	**132126.0**	**140204.4**	**235093.2**	**663027.7**
4. मुद्रा	**66438.9**	**-54579.3**	**76760.1**	**148990.2**	**237609.8**
5. निवेश	**51603.2**	**48630.6**	**49879.2**	**64168.5**	**214281.5**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54375.1**	**51114.5**	**37367.7**	**58196.2**	**201053.5**
II. वित्तीय देयताएँ	**289150.0**	**353009.7**	**471396.5**	**468620.7**	**1582177.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.4*	*5.4*	*6.8*	*6.5*	*5.8*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**289141.6**	**353001.2**	**471388.1**	**468612.3**	**1582143.3**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**234845.3**	**263782.5**	**368167.4**	**349555.0**	**1216350.1**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	365304.6	331292.5	1188146.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**54296.3**	**89218.8**	**103220.8**	**119057.3**	**365793.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	29281.6	54439.6	75878.8	80295.9	239895.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	2015.6	8880.3
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**135.0**
3. सामान्य सरकार	**-25.3**	**-25.3**	**-25.3**	**-25.3**	**-101.3**

टिप्पणियां:
1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय आस्तियों से हैं, जिन्हें वित्तीय आस्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता हैं।
2. 2022-23 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2022-23 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**20405824.2**	**21066027.8**	**21906338.5**	**22874301.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*107.2*	*111.5*	*114.0*	*115.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**9977865.6**	**10242430.9**	**10389526.9**	**10897246.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10060984.6
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	836261.6
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**180857.4**	**189743.6**	**195639.6**	**188953.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	51463.0	55226.1	58740.8	62262.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	129394.4	134517.6	136898.8	126691.5
(सी) जीवन बीमा निधि	**4102000.7**	**4274424.9**	**4551882.0**	**4752932.3**
(डी) मुद्रा	**2434693.7**	**2455980.6**	**2547436.6**	**2614237.0**
(ई) म्यूचुअल फंड	**1343752.0**	**1443784.4**	**1648999.0**	**1730461.0**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**663478.0**	**671884.3**	**678997.2**	**742189.5**
(जी) पेंशन निधि	**464705.0**	**494930.0**	**548913.0**	**578025.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1238471.7**	**1292849.1**	**1344944.2**	**1370257.1**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7767405.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.5*	*39.2*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**5728735.3**	**5741948.3**	**5881570.2**	**6158150.0**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5620260.7
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	536494.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1461975.5**	**1487386.9**	**1517615.9**	**1609255.3**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	790073.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9
iii.बीमा निगम	101213.7	102122.8	103382.2	104804.4

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**23318920.4**	**23991428.3**	**24700622.2**	**25435684.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*110.7*	*109.3*	*108.7*	*108.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**10790817.3**	**10987922.4**	**11410315.3**	**11675198.2**
i. वाणिज्यिक बैंक	9953043.9	10148485.7	10566752.7	10829078.8
ii. सहकारी बैंक	837773.4	839436.7	843562.6	846119.4
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**205903.4**	**206074.1**	**203895.8**	**209855.7**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67234.6	66469.1	66542.3	70754.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	138668.8	139605.0	137353.4	139101.6
(सी) जीवन बीमा निधि	**4929725.2**	**5142278.8**	**5213527.2**	**5357350.2**
(डी) मुद्रा	**2742897.3**	**2674266.1**	**2737059.4**	**2883904.4**
(ई) म्यूचुअल फंड	**1855000.1**	**2064363.5**	**2126112.0**	**2152140.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**757397.8**	**762264.0**	**767287.3**	**834147.6**
(जी) पेंशन निधि	**616517.0**	**667379.0**	**699173.0**	**736592.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1420662.3**	**1486880.4**	**1543252.3**	**1586495.5**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7755119.8**	**7868215.0**	**8256715.7**	**8668329.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.8*	*35.9*	*36.3*	*36.9*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**6172863.3**	**6231128.1**	**6559106.7**	**6934620.2**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5640516.1	5700327.0	6025626.4	6389789.3
ii. सहकारी बैंक	530937.1	529376.2	532040.6	543376.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1582256.5**	**1637086.9**	**1697609.1**	**1733708.8**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755315.1	784191.9	813668.4	811505.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7
iii.बीमा निगम	105431.4	106981.2	108532.1	109358.8

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**25689017.4**	**26240728.5**	**27208717.9**	**28083947.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*103.2*	*101.5*	*102.4*	*103.1*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**11911196.2**	**11956360.9**	**12421907.5**	**12701761.3**
i. वाणिज्यिक बैंक	11060527.2	11106712.0	11564354.7	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	850669.0	849648.9	857552.8	880076.4
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**216170.2**	**218246.9**	**224882.5**	**228542.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.4	78061.6	79862.5	85234.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	**5325967.3**	**5559681.9**	**5786592.6**	**6038630.4**
(डी) मुद्रा	**2950343.2**	**2895763.9**	**2972524.0**	**3121514.2**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2048097.3**	**2260209.7**	**2355315.8**	**2367792.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**851913.4**	**858591.1**	**864730.6**	**939814.6**
(जी) पेंशन निधि	**744459.2**	**799889.0**	**853412.0**	**898342.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1640870.6**	**1691985.1**	**1729352.9**	**1787549.1**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**8957470.6**	**9310471.8**	**9781859.9**	**10253472.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.0*	*36.0*	*36.8*	*37.6*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**7169465.5**	**7433248.0**	**7801415.3**	**8153970.3**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7246643.0	7580935.6
ii. सहकारी बैंक	547894.8	550354.8	553201.4	571339.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1788005.1**	**1877223.8**	**1980444.6**	**2099501.9**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	840786.9	895226.5	971105.3	1051401.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii.बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118239.1

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आकंड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।

3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।
3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डेटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2024	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2023-24 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 44, सं. 2, 2023	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022-23	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-जून 2024	आरबीआई बुलेटिन जुलाई, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्तूबर 2024	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2024 में शामिल है।	
12. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in

2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।

3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।

4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।

5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, वहां भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।